बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 151

चीन पर निर्भरता

केंद्र सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र में काम करने वाले चीनी तकनीशियनों की वीजा मंजूरी प्रक्रिया को तेजी प्रदान करने और सुसंगत बनाने का निर्णय लिया है। यह स्वागतयोग्य है। इस पहल से जटिलताओं को सहज बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। खासतौर पर उन 14 क्षेत्रों के लिए ऐसा किया जा रहा है जो उत्पादन से संबद्ध योजनाओं (पीएलआई) के तहत आते हैं। इस महीने प्रभावी हो रहे नए मानकों के अनुसार किसी कंपनी के आवेदन करने के बाद उसे मंजूरी के लिए संबंधित सरकारी विभागों तक भेजा जाएगा और उन्हें अपनी प्रतिक्रिया 28 दिन के भीतर गृह मंत्रालय के पास भेजनी होगी। उम्मीद है कि इस प्रक्रिया में एक से डेढ़ महीने का वक्त लगेगा और कारोबारी ई-वीजा छह महीने के लिए वैध होगा। कई कारोबारों का कहना है कि वीजा संबंधी मसले उनके उत्पादन और उनकी उत्पादकता को प्रभावित कर रहे हैं। यह उम्मीद की जानी चाहिए कि यह पहल इन चिंताओं को दूर करेगी और उन कंपनियों के लिए भी वीजा जारी किए जाएंगे जो पीएलआई योजनाओं के अधीन नहीं आतीं।

सरकार ने वीजा की समस्या को दूर किया है लेकिन बहस का एक अन्य बड़ा मुद्दा है चीनी निवेश, खासकर नवीनतम आर्थिक समीक्षा में की गई टिप्पणियों के संदर्भ में। चूंकि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में चीन की स्थिति मजबूत है इसलिए भारत के लिए स्वतंत्र रूप से इन नेटवर्क का अनिवार्य हिस्सा बन पाना असंभव है। चीन के विनिर्माण का दायरा इतना व्यापक है कि भारत द्वारा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भूमिका बढ़ाने का कोई भी प्रयास चीन के हितों और परिचालन से टकराएगा। वीजा का मसला भी इस बात को रेखांकित करता है। हालात को देखते हुए भारत के पास दो विकल्प हैं- चीन की आपूर्ति श्रृंखला के साथ अधिक गहराई से जुड़ाव अथवा विनिर्माण क्षेत्र में चीन के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देना। सर्वेक्षण बाद वाले विकल्प के हित में है। उसने तुर्किये और ब्राजील का उदाहरण लिया है और तर्क दिया है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देने से घरेलू विनिर्माण को गति मिलेगी और निर्यात में बढ़ोतरी होगी।

भारत में चीन के निवेश से उत्पादन में इजाफा होगा और इससे व्यापार घाटा कम करने में मदद मिलेगी। इतना ही नहीं इससे हम तकनीक संपन्न होंगे, प्रबंधन क्षमता में सुधार होगा और उत्पादन लागत में सुधार होगा। बहरहाल, ये लाभ कई चिंताओं और जोखिम के साथ आते हैं। चीन की पूंजी की आवक और उसका प्रभाव कई जोखिम अपने साथ लाएगा। उदाहरण के लिए डेटा सुरक्षा में सेंध लगने से राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक संप्रभुता के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। सरकार ने 2020 में कहा था कि भारत के साथ भूसीमा साझा करने वाले देशों से आने वाले निवेश को मंजूरी की आवश्यकता होगी। हालांकि अभी जो हालात हैं उनमें अहम क्षेत्रों मसलन सेमीकंडक्टर, ऑटोमोबाइल और दूरसंचार आदि के लिए कच्चे माल के मामले में भारत की चीनी आयात पर निर्भरता लगातार बढ़ रही है। 2023-24 में हमारा व्यापार घाटा बढ़कर 85 अरब डॉलर हो चुका है। केवल व्यापार घाटा पूरी तस्वीर नहीं दिखाता है क्योंकि चीन की कंपनियां अपनी आपूर्ति को वियतनाम जैसे देशों के रास्ते से भी भेज सकती हैं। मौजूदा नियमन और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं की नजर से यह एक जटिल माहौल है। भूराजनीतिक हालात को देखते हुए सरकार के लिए चीनी निवेश के लिए राह खोलना आसान नहीं होगा। परंतु जैसा कि वीजा संबंधी निर्णय बताता है, यह भी सच है कि अगर भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला में सार्थक ढंग से जुड़ना है तो चीन की अनदेखी नहीं की जा सकती है। हमारे पास उपरोक्त सवालों के आसान जवाब नहीं हैं। आर्थिक समीक्षा की सराहना की जानी चाहिए कि उसने इस बहस की शुरुआत की जो शायद हमें स्वीकार्य हल तक पहुंचने में मदद पहुंचाएगी।

अजय मोहंती

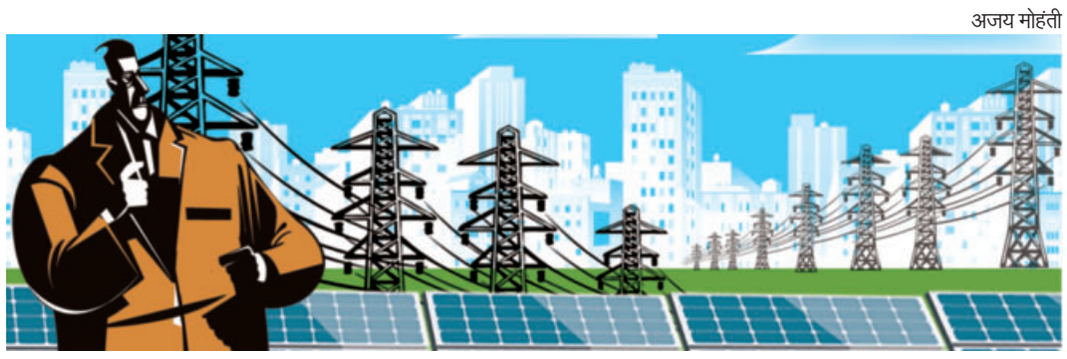

बिजली क्षेत्र के लिए सधी रणनीति की जरूरत

भारत में बिजली एवं वित्तीय क्षेत्रों में सुधार के लिए बड़े कदम उठाने की आवश्यकता बता रहे हैं अजय शाह, अक्षय जेटली और के पी कृष्णन

कार्बन (जीवाश्म ईंधन) का युग समाप्त होने को है। अब हम इस बात पर चर्चा कर सकते हैं कि भारत में जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल कब बंद होगा। परंतु वर्ष 2070 तक विशुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना है तो वर्ष 2050 तक कार्बन रहित ऊर्जा तंत्र मजबूती से खड़ा करना होगा। एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न इस सोच के साथ जुड़ा है कि आगे परिस्थितियां कैसी रहने वाली हैं। वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया में अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण और ऊर्जा सक्षमता जैसे चमत्कारिक उपलब्धियां जन मानस को दी ही हैं। अब असली मसला इन्हें बढ़ावा देने का है।

कभी-कभी बिजली क्षेत्र के विशालकाय आकार से हमारा ध्यान हट जाता है। आइए, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी (सीएमआईई) की पूंजीगत व्यय की सूची में दी गई उन परियोजनाओं पर नजर डालते हैं, जिनका क्रियान्वयन हो रहा है। इनकी समीक्षा के बाद पता चलता है कि इस समय बिजली से इतर सभी निजी परियोजनों का जितना कुल मूल्य है, उतना तो अकेले बिजली उत्पादन क्षेत्र का ही है। जीवाश्म ईंधन को छोड़कर नवीकरणीय (अक्षय) ऊर्जा अपनाने की दिशा में कदम बढ़ाने की मुहिम (उदाहरण के लिए इलेक्ट्रिक वाहन) को समर्थन देने और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि में योगदान देने के लिए भारतीय बिजली उद्योग को काफी तेजी से प्रगति करनी होगी।

निजी क्षेत्र समझ चुका है कि जीवाश्म ईंधन समस्याएं पैदा कर रहा है और इसका इस्तेमाल धीरे-धीरे घटता जाएगा। सबसे बड़ी भारतीय कंपनियों को इसका भान हो चुका है, इसलिए उन्होंने अपनी रणनीति भी बदल ली है। जैसे ही जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचता दिखेगा, उसमें श्रम, पूंजी एवं उद्यम सभी की दिलचस्पी कम होती जाएगी। भारत में जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल तो घटता जा रहा है मगर अक्षय ऊर्जा का ढांचा पूरी तरह तैयार नहीं हो पाया है। इस क्षेत्र में भारत तीन प्रकार के पूर्वग्रह या आत्मसंतुष्टि के भाव से ग्रस्त है।

पहली, जो कुछ जरूरी है, उसे सरकार गैर-जिम्मेदाराना तरीके से कोयले का अंधाधुंध इस्तेमाल कर बना लेगी। बिजली की जरूरी मांग पूरी करने के लिए लोक निधि एवं प्रबंधन तंत्र पर्याप्त नहीं होंगे फिर भी एनटीपीसी ताप विद्युत संयंत्रों पर भारीभरकम निवेश करेगी। जब दुनिया के महत्त्वपूर्ण देश भारत पर कार्बन उत्सर्जन कम करने का दबाव डालना शुरू करेंगे तो लागत बढ़ती जाएगी। भारत जलवायु परिवर्तन से होने वाले खतरे के मुहाने पर खड़ा है और इस लिहाज से दुनिया भर में होने वाले सालाना उत्सर्जन का दसवां हिस्सा उत्सर्जित करना हमारे हित में नहीं है। एक अन्य सोच भी अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में हमारी प्रगति को प्रभावित कर रही है। हमारे दिमाग में यह बात घर कर गई है कि हम अच्छा कर रहे हैं और निजी क्षेत्र पर्याप्त मात्रा में अक्षय ऊर्जा का स्रोत तैयार कर रहा है। निजी क्षेत्र सरकारी कंपनियों को बिजली बेचने से परहेज करता है, इसलिए अक्षय ऊर्जा गतिविधियां व्यावसायिक एवं औद्योगिक खरीदारों पर अधिक केंद्रित हैं। उन तक बिजली पहुंचाना व्यावहारिक है। अक्षय ऊर्जा के लिए वर्तमान ऊर्जा ढांचे पर गहराई से विचार करना होगा।

अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में जिस लचीलेपन की जरूरत है वह तैयार करने और पारेषण एवं वितरण को नई दिशा देने के लिए बड़े निवेश की जरूरत है। ये कठिनाइयां आंकड़ों में भी झलक रही हैं। भारत में सालाना अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं मौजूदा समस्याओं की तुलना में तेजी से तैयार नहीं हो पा रही हैं। भारत में कुल बिजली उत्पादन में अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़कर लगभग 20 प्रतिशत हो गई है, मगर दूसरे देशों से तुलना करें तो यह कम ठहरती है। इसे सालाना 3 प्रतिशत की दर से वृद्धि करनी होगी जबकि मौजूदा दर लगभग 30 आधार अंक प्रति वर्ष है।

यह धारणा भी हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही है कि 'हम पिछले कई वर्षों से तमाम बाधाओं के बीच आगे बढ़ रहे हैं और आगे भी कोई न कोई रास्ता निकल जाएगा'। अधिकारी पिछले 20 वर्षों से आगे कदम बढ़ाने के एक साथ कई उपाय करते रहे हैं। हम समस्या सुलझाने में उनकी रचनात्मक सोच की प्रशंसा की जा सकती है, मगर अब कई दिशाओं से दबाव बढ़ने लगा है और आगे ऐसा करते रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो नहीं हो सकता वह नहीं ही होता है। आर्थिक वृद्धि सुस्त होने के कारण बिजली की मांग अधिक नहीं बढ़ पाई है मगर हम सभी को यह उम्मीद करनी चाहिए कि इस स्थिति में तेजी से बदलाव होगा।

दिन में धूप तेज होती है और बिजली की जरूरत पूरी हो जाती है मगर मगर शाम के समय पुरानी व्यवस्था घुटने टेकने लगती है। तो फिर क्या उपाय किया जा सकता है? रणनीतिक तौर पर सोचें तो दो समस्याएं नजर आ रही हैं। सबसे पहले बिजली क्षेत्र में बदलाव की जरूरत है ताकि बिजली का पर्याप्त उत्पादन हो सके। साथ ही अक्षय ऊर्जा उत्पादन की हिस्सेदारी सालाना 3 प्रतिशत अंक दर से बढ़ाई जाए। बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की भी आवश्यकता होगी। यह जरूरत पूरी करने के लिए वित्तीय क्षेत्र में बदलाव की जरूरत होगी।

बिजली और वित्त दोनों ही मामलों में यथास्थिति ठीक नहीं मानी जा सकती और हमारे सामने कई बड़े लक्ष्य आ गए हैं जिन्हें साधना है। बिजली नीति पर क्या रणनीति अपनाई जा सकती है? पुरानी बिजली व्यवस्था में केंद्रीय स्तर पर नियंत्रण अधिक है। तकनीक, उत्पादन एवं मूल्य पर सरकार का नियंत्रण है। मगर यह ढर्रा अब पुराना पड़ चुका है। बिजली नीति के केंद्र में मौजूद समस्या इस प्रणाली से मूल्य-प्रणाली की तरफ बढ़ने से जुड़ी है। मूल्य प्रणाली में निजी कंपनियां कीमतों पर विचार करती हैं और यह तय करती हैं कि उत्पादन, भंडारण, पारेषण या वितरण में कहां और कब निवेश किया जाए।

उदाहरण के लिए जब आपूर्ति एवं मांग के हिसाब से कीमत कम-ज्यादा होती हैं और दोपहर में बिजली सस्ती तथा शाम को महंगी रहती है तो इससे कंपनियां अपने हित साधने की कोशिश करती हैं। वे भंडारण कंपनियां तैयार करने लगती हैं, जो दोपहर में बैटरी चार्ज करेंगी और शाम में बिजली बेचेंगी। ये सभी निर्णय निजी स्तर पर मूल्य प्रणाली द्वारा निर्धारित होने चाहिए न कि अधिकारियों द्वारा।

जलवायु के लिए वित्त जुटाने की आगे क्या रणनीति हो सकती है? ऊर्जा प्रणाली दोबारा विकसित करने के लिए विशाल संसाधनों की जरूरत है और जलवायु परिवर्तन से जुड़े कई अन्य खंडों में भी निवेश करना होगा। इनके लिए पूंजी वैश्विक पूंजी बाजार से आसानी से उपलब्ध हो पाएगी। मगर इस पहल को भारतीय अर्थव्यवस्था में अंजाम तक पहुंचाना एक चुनौती है। इसके लिए वित्तीय क्षेत्र में सुधार के वास्ते बहुत काम करने होंगे। बुनियादी क्षेत्र में निवेश की पहली लहर (1996-2011) अब गुजर चुकी है क्योंकि इसमें वित्तीय प्रणाली से पूंजी येन केन प्रकारेण हासिल कर ली जाती थी। यह तरीका अब काम नहीं करेगा। इसका एक कारण यह है कि कई लोग नुकसान उठा चुके हैं और दूसरा कारण यह है कि इसमें बड़े स्तर पर प्रयासों की जरूरत होती है। अब एक वास्तविक बाजार-आधारित वित्तीय प्रणाली की जरूरत है जहां बड़े निवेश अपने हितों से प्रेरित इकाइयों के माध्यम से किए जाते हैं। वित्तीय क्षेत्र की नीति मूल्य-प्रणाली पर आधारित होना चाहिए। इस प्रणाली में ऐसी इकाइयां परिसंपत्ति कीमतों पर विचार कर अपने पोर्टफोलियो का निर्माण करती हैं।

सुधारकों की एक पीढ़ी ने भारतीय वित्तीय प्रणाली में सुधार किए हैं जिनमें सीमा पार गतिविधि के लिए सीमित उदारीकरण भी शामिल है। अब इस कार्य को आगे बढ़ाने की अति आवश्यकता है।

जलवायु के लिए वित्त कार्यक्रम में भी कार्बन उत्सर्जन व्यापार के लिए वित्तीय बाजारों की जानकारियों का लाभ उठाया जाता है। इसके अलावा इस कार्यक्रम में सूक्ष्म-विवेकपूर्ण (माइक्रो-प्रूडेंशियल) नियमन में ऐसे बदलाव करना भी शामिल हैं, जिनसे तटीय रियल एस्टेट या जीवाश्म ईंधन जैसी परिसंपत्तियों से जुड़े खतरों को आसानी से भांपा जा सकें।

(शाह एक्सकेडीआर फोरम में शोधकर्ता हैं, जेटली ट्राईलीगल में पार्टनर एवं ट्रस्टब्रिज के संस्थापक हैं तथा कृष्णन प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं)

वृद्धि पर चिंता नहीं, मुद्रास्फीति में राहत नहीं

बैंकिंग साख

तमाल बंद्योपाध्याय

वैश्विक बाजारों में हालिया उथल-पुथल और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा आगामी सितंबर में यानी चार सालों में पहली बार दर कटौती की संभावना के बीच कई लोग उम्मीद कर रहे थे कि भारतीय रिजर्व बैंक दरें घटा देगा। इसके साथ ही रुख में बदलाव की भी संभावना थी। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बाजार से केवल दो शब्द कहेः धैर्य रखिए। लगता है बाजार ने उनकी बात सुनी। नीति में कोई बदलाव नहीं होता देख बॉन्ड यील्ड और मुद्रा दोनों में गतिविधियां थम सी गईं।

जाहिर है कि केंद्रीय बैंक फिलहाल वृद्धि के बारे में चिंतित नहीं है और मुद्रास्फीति के मोर्चे पर भी राहत नहीं है। यानी लगातार नवीं नीति में यथास्थिति बरकरार है। रीपो दर या फिर रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को धन देते समय ली जाने वाली ब्याज की दर 6.5 फीसदी ही बनी हुई है। बैंक का रुख भी पहले की तरह है यानी छूट और राहत कम करते हुए यह सुनिश्चित करना कि मुद्रास्फीति धीरे-धीरे लक्ष्य के साथ तालमेल बिठा लेगी और इस दौरान वृद्धि को मदद मिलती रहे।

अतीत की तरह दास ने भविष्य के बारे में कुछ कहने से परहेज किया। जो लोग रुख में बदलाव की अपेक्षा कर रहे थे, वे निराश हैं किंतु उन लोगों ने राहत की सांस ली है जिन्हें लग रहा था कि सख्ती अपनाते हुए अतिरिक्त नकदी निकाल ली जाएगी। उस लिहाज से नीति सभी के लिए सुखद रही। रिजर्व बैंक के वृद्धि अनुमान तथा चालू वर्ष के लिए मुद्रास्फीति संबंधी अनुमान अपरिवर्तित हैं लेकिन कुछ मामूली रद्दोबदल किया गया।

उदाहरण के लिए वित्त वर्ष 25 के लिए जीडीपी वृद्धि दर 7.2 फीसदी है यानी जून में घोषित आंकड़ों में कोई बदलाव नहीं किया गया। परंतु पहली तिमाही में वृद्धि दर अनुमान को 7.3 फीसदी से कम करके 7.1 फीसदी कर दिया गया। वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही के लिए इसे 7.2 फीसदी रखा गया। इसी प्रकार वर्ष के लिए खुदरा मुद्रास्फीति अनुमान को 4.5 फीसदी के स्तर पर अपरिवर्तित रखा गया। परंतु दूसरी तिमाही के अनुमान को 3.8 फीसदी से बढ़ाकर 4.4 फीसदी और तीसरी तिमाही के अनुमान को 4.6 फीसदी से बढाक़र 4.7 फीसदी किया गया। चौथी तिमाही के अनुमान को कम करके 4.5 फीसदी से 4.3 फीसदी किया गया। पहली बार रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही के खुदरा मुद्रास्फीति अनुमान को 4.4 फीसदी रखा। यकीनन वृद्धि का कथानक मजबूत है और मुद्रास्फीति में कमी आ रही है लेकिन अपस्फीति की दर असमान और धीमी है। दास ने घबराहट का कोई संकेत नहीं दिया लेकिन यह स्पष्ट किया कि मुद्रास्फीति अब भी हमारा प्रमुख निशाना है और रिजर्व बैंक इसे नियंत्रित करने तक अपना रुख नहीं बदलेगा। यकीनन बदलती वैश्विक तस्वीर इस पर असर डालेगी यह भी तय है।

परंतु चालू खाते का घाटा सहज स्तर पर है और 675 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार तथा मजबूत वृहद आर्थिक परिदृश्य होने के कारण चिंता की कोई बात नहीं। भले ही बाहरी कारक कमजोर पड़ रहे हों। फिलहाल मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने कहा है कि जब तक शीर्ष मुद्रास्फीति लक्ष्य के करीब आकर टिक नहीं जाती है तब तक अपस्फीतिकारी रुख बरकरार रखा जाएगा। मुद्रास्फीति को लक्षित करने की जो लचीली व्यवस्था करीब आठ वर्ष पहले शुरू की गई थी उसके तहत चार फीसदी का लक्ष्य तय किया गया था, जिसमें दो फीसदी ऊपर-नीचे की गुंजाइश रखी गई थी। पिछली नीति की तरह इस बार भी एमपीसी के छह सदस्यों में से दो असहमत थेः आशिमा गोयल और जयंत आर वर्मा। दोनों ने इस बात की वकालत की कि नीति में परिवर्तन कर उसे निरपेक्ष किया जाए और दरों में चौथाई फीसदी की कटौती की जाए। वर्तमान एमपीसी की यह अंतिम बैठक थी। अक्टूबर तक गोयल, वर्मा और शशांक भिड़े का कार्यकाल पूरा हो जाएगा और तीन नए सदस्य इसमें शामिल होंगे।

अगर वैश्विक वृद्धि को गहरा झटका नहीं लगता, बाजार में अस्थिरता घर नहीं कर जाती और अमेरिकी फेडरल रिजर्व सितंबर में भारी कटौती नहीं करता तो ऐसा नहीं लगता कि रिजर्व बैंक की एमपीसी 2024 में कटौती करेगी। हालांकि रुख में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौद्रिक नीति से संबंधित किसी अन्य कदम के अभाव में यह नीति गैर मौद्रिक उपायों को अपनाने के लिए चर्चा में रहेगीः

■ रिजर्व बैंक ने डिजिटल लेंडिंग ऐप (डीएलए) का एक सार्वजनिक स्रोत तैयार करने का प्रस्ताव रखा है। एक बार जब विनियमित संस्थाएं अपने डीएलए के बारे में सूचना देना शुरू कर देंगी तो उपभोक्ताओं के लिए ऋण देने वाले अवैध ऐप की पहचान करना मुश्किल नहीं होगा।

■ उसने ऋण सूचना केंद्रों से ऋण संबंधी सूचनाओं की जानकारी हर पखवाड़े या उससे भी कम अंतरा पर देने का भी प्रस्ताव रखा है। एक बार ऐसा होने के बाद कर्जदारों को ऋण सूचना तेजी से अपडेट किए जाने का फायदा होगा। खासतौर पर तब जब वे अपने ऋण चुकाएंगे। कर्जदाता भी जोखिम का बेहतर आकलन कर सकेंगे। फिलहाल यह जानकारी हर महीने दी जाती है।

■ इस समय कुछ श्रेणियों के अलावा यूपीआई से लेनदेन की सीमा एक लाख रुपये है। अब इसके जरिये कर्ज भुगतान की सीमा एक लाख रुपये से पांच लाख रुपये करने का निश्चय किया गया है। यह तथा ऐसे अन्य उपाय डिजिटल भुगतान व्यवस्था को मजबूत करेंगे।

■ आखिर में रिजर्व बैंक की योजना चेकों को निरंतर क्लियर करने की है। फिलहाल चेक क्लियर करने में दो दिनों तक का समय लगता है। नई व्यवस्था बन गई तो चेक कुछ घंटों में क्लियर कर दिए जाएंगे।

रिजर्व बैंक ने कुछ मुद्दों पर गंभीर चिंता भी जताई हैः

■ गत वर्ष नवंबर में पर्सनल लोन के जोखिम भार या पूंजी आवश्यकता में इजाफे के कारण ऋण में इजाफा कम हुआ है लेकिन कुछ क्षेत्रों में व्यक्तिगत ऋण बढ़ा है। खुदरा कर्ज के माध्यम से खपत बढ़ाने की सावधानीपूर्वक निगरानी जरूरी है।

■ आवास ऋण के टॉप अप में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। कुछ कर्जदाता गोल्ड लोन पर भी टॉप अप दे रहे हैं और इस दौरान जोखिम का आकलन नहीं किया जा रहा और यह भी नहीं देखा जा रहा कि रकम का इस्तेमाल किस काम में हो रहा है। इस पैसे का दुरुपयोग संभव है। रिजर्व बैंक इस पर कड़ी नजर रख रहा है।

आपका पक्ष

रेलवे हादसे रोकने में क्या सक्षम होगी कवच प्रणाली

देश में रेल हादसे रोकने के लिए 'कवच प्रणाली' पर बड़े पैमाने पर तेजी से काम किया जा रहा है। इस परियोजना में सबसे पहले 20 हजार लोको इंजनों को कवच प्रणाली तकनीक से लैस किया जाएगा। इसका यह लाभ होगा कि जैसे-जैसे रेल लाइनों और स्टेशनों पर इस कवच प्रणाली के उपकरण लगाए जाएंगे वैसे-वैसे यह कवच प्रभावी रूप से काम करना शुरू कर देगा जिससे वहां रेल हादसों में कमी आने की संभावना बनी रहेगी।

यही कारण है कि इस कवच प्रणाली के लिए 1,100 करोड़ रुपये के बड़े बजट का प्रावधान किया गया है। कवच प्रणाली से उस रेलवे नेटवर्क पर ट्रेनों को टक्कर रोधी हादसों से 100 प्रतिशत सुरक्षा मिल सकेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि रेलवे ने कवच 4.0 के संस्करण को अब अंतिम मंजूरी दे दी है तथा इस तकनीक के पांच उपकरणों को पांच जगहों पर लगाकर इसका परीक्षण किया गया है।

रेलवे ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बड़ी कवायद कर रहा है। ट्रेन दुर्घटनाएं रोकने के लिए यह कवच प्रणाली जिन इंजनों पर लगाई जाएगी उससे एक ही पटरी पर ट्रेनों के टकराने की घटनाएं अब रुक सकेंगी। पिछले 10 वर्षों में देश में काफी रेल दुर्घटनाएं हुई हैं जिनमें काफी जानमाल का नुकसान हुआ है। अतः रेल दुर्घटनाएं रोकने के लिए सभी ट्रेनों में कवच प्रणाली लगाने की आवश्यकता है।

रेल पटरियों की मरम्मत और समय-समय पर जांच भी जरूरी है। कवच प्रणाली एक ही पटरी पर ट्रेनों को आपस में टकराने से रोकेगा लेकिन अगर पटरियां कमजोर हुई तो ट्रेनों के पटरी से उतरने का भी खतरा रहेगा।

मनमोहन राजावतराज, शाजापुर

गोवा के पास शुक्रवार को एक मालगाड़ी के बेपटरी होने के कारण दक्षिण पश्चिम रेल मार्ग पर ट्रेनों की आवाजाही रुक गई

शिक्षा को अफसरशाही से पहुंचा काफी नुकसान

देश में एक बड़ी समस्या यह है कि हमने अफसरशाही प्रशासन और अकादमिक प्रशासन के अंतर को पहचानने से इनकार कर दिया है। जो उच्च शैक्षिक पद 1975-80 तक शिक्षविदों के पास होते थे, अब वे सब केवल अफसरशाहों के पास हैं। राज्यों में पाठ्यपुस्तक निगम, स्कूल बोर्ड तथा राष्ट्रीय स्तर पर सीबीएसई, नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन के शीर्ष पदों पर शिक्षाविद् क्यों नियुक्त नहीं हो सकते हैं?

अफसरशाही का हमेशा से ही शिक्षा पर प्रभुत्व रहा है। इससे शिक्षा को काफी नुकसान पहुंचा है। अफसरशाही हमेशा से सुधारों अथवा नवाचारों के बीच एक दीवार बनकर खड़ी है। हर अच्छे कार्य का विरोध होता रहा है। बड़े-बड़े आयोगों के सुझावों को अफसरशाही द्वारा नकार दिया जाता है। इस प्रकार अच्छे से अच्छे सुझाव कुचल दिए जाते हैं और इन सबका जिम्मेदार शिक्षकों को ही ठहराया जाता है। शायद बड़े-बड़े अफसर केवल अपना प्रभाव स्थापित किए रहना चाहते हैं। इससे शिक्षा को बहुत हानि पहुंचती है। शिक्षा और प्रशासन में अनावश्यक देरी या निष्क्रियता होती है।

सुधीर कुमार सोमानी, देवास

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

भारतीय तट रक्षक बल के जहाज सी-428 एएनसी ने बीच समुद्र से एमवी ओलंपिया मालवाहक जहाज के चालक दल के 39 वर्षीय घायल सदस्य को पोर्ट ब्लेयर के एक अस्पताल में पहुंचाया। माल वाहक जहाज हल्दिया बंदरगाह से इंडोनेशिया के लिए रवाना हुआ था। फिलिपींस के कर्मी जहाज के इंजन रूम में काम करते वक्त घायल हो गए थे।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

अराजकता का राज

यूनुस को बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा बंद करनी चाहिए

टी नोबेल पुरस्कार विजेता और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने गुरुवार को पेरिस से ढाका पहुंचने के बाद जनता से पहली अपील की कि वे "देश को अराजकता और हिंसा से बचाएं"। माइक्रो-नेंस के 80 वर्षीय अग्रणी देश की कमान ऐसे समय संभाल रहे हैं, जब देश में सबसे उथल-पुथल भरा दौर चल रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री और अवामी लीग की नेता शेख हसीना के इस्तीफा देने और हिंसक जन-विरोध के बीच देश छोड़ने के कुछ दिनों बाद, 170 मिलियन लोगों का देश अभी भी तनाव में है, क्योंकि हिंसा कम होने का नाम नहीं ले रही है। कानून लागू करने वाले अधिकारी गायब हैं और सरकार की अनुपस्थिति में राज्य की नौकरशाही निष्क्रिय हो गई है। चरमपंथी वर्गों ने अराजकता का इस्तेमाल हिंदुओं, इस्लाम में अल्पसंख्यक संप्रदाय अहमदियों और अवामी लीग के पदाधिकारियों को निशाना बनाने के लिए किया है।

बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद के अनुसार, कई जिलों में अल्पसंख्यकों के घरों और दुकानों को लूट लिया गया।

अवामी लीग के कार्यकर्ताओं के घरों में तोड़फोड़ की गई और दर्जनों पार्टी पदाधिकारियों और समर्थकों की हत्या कर दी गई। गुरुवार को शपथ लेने वाले श्री यूनुस ने हिंसा की निंदा की और शांति की अपील की।

चूंकि बैंकर एक प्रशासक के रूप में अपनी भूमिका शुरू कर रहे हैं, इसलिए उनकी चुनौती बांग्लादेश को संकट से उबारना और कानून का शासन बहाल करना होगी।

श्री यूनुस को नियुक्त करके, जो छात्र प्रदर्शनकारियों और राजनीतिक विपक्ष के लिए स्वीकार्य हैं, सेना और बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने सुलह के संकेत दिए हैं। ऐसे समय में जब राजनीतिक दलों के बीच बहुत दुश्मनी है, एक टेक्नोक्रेट के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार एक व्यावहारिक पहला कदम है। लेकिन श्री यूनुस के पास उनका समर्थन करने के लिए राजनीतिक मशीनरी नहीं है और उन्हें मुख्यधारा की पार्टियों या भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन पर निर्भर रहना होगा। उन्हें तीन महत्वपूर्ण मध्यम अवधि की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है।

सबसे पहले, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि सेना बैरकों में रहे। सेना का अतीत बदनाम रहा है और 1990 में तानाशाही को खत्म करने के लिए सुश्री हसीना और बीएनपी नेता खालिदा जिया के नेतृत्व में कई वर्षों तक जन आंदोलन चला। दूसरे, श्री यूनुस को बांग्लादेश की राजनीति में कम से कम अस्थायी शांति स्थापित करनी होगी। सुश्री हसीना के पतन ने जमात और बीएनपी को सशक्त बनाया है। जमात, एक बहुसंख्यक इस्लामी समूह है, जिसका अतीत विशेष रूप से खूनी रहा है, जबकि बीएनपी के सत्ता में रहने के वर्षों में राजनीतिक हिंसा और प्रतिशोध की भावना रही है।

अंत में, श्री यूनुस के प्रशासन को जल्द से जल्द स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने चाहिए। केवल एक चुनी हुई सरकार ही लोकप्रिय वैधता के साथ देश को आज की परेशानियों से बाहर निकाल सकती है।

बांग्लादेश के विद्रोह की सफलता देश के नए शासकों की इन चुनौतियों से निपटने की इच्छाशक्ति और क्षमता पर निर्भर है।

आश्वस्त करने वाला संकल्प

यदि खुदरा बिक्री पर नियंत्रण नहीं किया गया तो विकास धीमा ही रहेगा

टी आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने लगातार नौवीं बैठक में बेंचमार्क ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है क्योंकि यह खुदरा मुद्रास्फीति से जूझ रही है जो 57 महीनों से लगातार 4% के अपने मध्यम अवधि लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है और उपभोक्ताओं का भरोसा कम करने लगी है। तर्क देते हुए, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने जोर देकर कहा कि लगातार बढ़ते खाद्य मूल्य दबावों से परिवारों की मुद्रास्फीति अपेक्षाओं और व्यापक मौद्रिक नीति विश्वसनीयता के लिए उत्पन्न जोखिमों को देखते हुए आत्मसंतुष्टि की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बढ़ी हुई खाद्य कीमतों ने न केवल अप्रैल-जून तिमाही में विघटन को धीमा कर दिया बल्कि जुलाई में भी अपनी गति को बढ़ा दिया है क्योंकि उच्च आवृत्ति वाले खाद्य मूल्य डेटा प्रमुख सब्जी की कीमतों में महीने-दर-महीने बड़ी वृद्धि का संकेत दे रहे हैं। खाद्य पदार्थों की कीमतें, जिनका कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में लगभग 46% का भार है, को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता, न केवल मुख्य मूल्य सूचकांक पर उनके प्रभाव के लिए बल्कि इससे भी अधिक महत्वपूर्ण रूप से इसलिए क्योंकि उपभोक्ता मासिक घरेलू बजट पर खाद्य पदार्थों की कीमतों के प्रभाव से सबसे अधिक जुड़े हुए हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से इसका संदर्भ दिए बिना संकेत दिया कि आर्थिक सर्वेक्षण में नीति निर्माताओं से खाद्य पदार्थों की कीमतों को मूल्य लक्ष्यीकरण ढांचे से अलग करने पर विचार करने का आग्रह करने वाला सुझाव इन परिस्थितियों में बहुत कम समझ में आता है।

एमपीसी, जिसने ब्याज दरों को बनाए रखने और नीतिगत रुख को लक्ष्य के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए समायोजन को वापस लेने पर केंद्रित रखने के लिए 4-2 बहुमत से मतदान किया, ने जुलाई-सितंबर तिमाही में हेडलाइन खुदरा मुद्रास्फीति के लिए अपने अनुमान को भी बढ़ाकर 4.4% कर दिया, जो जून में अनुमानित 3.8% की दर से 60 आधार अंक अधिक है। दर पैनल ने तीसरी मौद्रिक तिमाही में पहले की तुलना में थोड़ा तेज़ वृद्धि का भी अनुमान लगाया, अनुमान को 10 आधार अंकों से बढ़ाकर 4.7% कर दिया, जो स्पष्ट संकेत है कि निकट अवधि के मुद्रास्फीति दृष्टिकोण दो महीने पहले की तुलना में कम आश्वस्त करने वाले प्रतीत होते हैं। और जबकि श्री दास ने उल्लेख किया कि जून में सब्जियों की कीमतों ने हेडलाइन मुद्रास्फीति में लगभग 35% का योगदान दिया था, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने एक विश्लेषण में सब्जियों में मूल्य दबाव को 'नवंबर की शुरुआत तक त्योहारी सीज़न में अच्छी तरह से बनाए रखने' का अनुमान लगाया, जिससे खुदरा मुद्रास्फीति पर दबाव बढ़ गया।

एमपीसी के अनुसार कोर इनेशन भी अपने निचले स्तर पर पहुंच गया है, जिसने खाद्य कीमतों से होने वाले नुकसान के जोखिम को कम किया है, साथ ही मोबाइल टैरिफ संशोधनों का व्यापक गैर-खाद्य इनेशन पर पड़ने वाले प्रभाव को भी कम किया है। नीति निर्माताओं ने उत्साहपूर्वक इस सत्य को दोहराया कि स्थायी मूल्य स्थिरता सुनिश्चित किए बिना, विकास सबसे खराब हो सकता है।

शरणार्थियों के अधिकार, विस्थापन की लिंग आधारित प्रकृति

आरुषि मलिक
दिल्ली स्थित अधिवक्ता। यह लेख विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी में रिसर्च फेलो के रूप में लिखा गया है।

ए संघर्ष, हिंसा, मानवाधिकारों का हनन और उत्पीड़न दुनिया भर में लाखों लोगों को जीवित रहने के लिए अपने घर और मातृभूमि छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं, और इस प्रक्रिया में 'विस्थापित लोग' बन जाते हैं।

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर) के अनुसार, 2023 के अंत तक, दुनिया भर में 11.73 करोड़ लोग उत्पीड़न, संघर्ष, हिंसा, मानवाधिकार उल्लंघन या सार्वजनिक व्यवस्था को गंभीर रूप से बाधित करने वाली घटनाओं के कारण जबरन विस्थापित हो चुके होंगे। इनमें से 3.76 करोड़ शरणार्थी थे। तब से लेकर अब तक इजरायल-हमास युद्ध में वृद्धि हुई है, यूक्रेन-रूस युद्ध जारी है और म्यांमार में रोहिंग्याओं को नए खतरों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में दुनिया भर में शरणार्थियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है।

शरणार्थियों की जनसांख्यिकी में महिला चेहरा भारत को ऐतिहासिक रूप से एक 'शरणार्थी-प्राप्त' राष्ट्र के रूप में माना जाता है, जिसने अपनी स्वतंत्रता के बाद से 2,00,000 से अधिक विविध शरणार्थी समूहों की मेजबानी की है। 31 जनवरी, 2022 तक, 46,000 शरणार्थी और शरण चाहने वाले UNHCR भारत के साथ पंजीकृत थे। इस आबादी का 46% हिस्सा महिलाओं और लड़कियों का है, जो एक असमान रूप से बोझिल और कमजोर समूह है। उन्हें बच्चों के लिए पूरी तरह से जवाबदेह बनाया जाता है, वे अक्सर सबसे आखिर में जन्म लेती हैं, उन पर बूढ़े और छोटे दोनों की देखभाल करने की ज़िम्मेदारी होती है, और अक्सर उन्हें परिवार के भरण-पोषण की ज़िम्मेदारी अकेले ही उठानी पड़ती है।

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने स्वीकार किया है कि "विस्थापन का चेहरा महिला है"। विस्थापन की लैंगिक प्रकृति महिलाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ-साथ उनकी भलाई को भी प्रभावित करती है। शरणार्थी महिलाओं पर कई तरह के तनावों का असर पड़ता है, जैसे कि साथी और बच्चों की मृत्यु, शिविर जीवन की कठिनाइयाँ, पारिवारिक गतिशीलता में जटिल परिवर्तन, सामुदायिक नेटवर्क तक सीमित पहुँच और कम सुरक्षा। लंबे समय तक संघर्ष, संघर्ष के बाद लिंग भूमिका में बदलाव, पारंपरिक सामाजिक सहायता प्रणालियों का टूटना और विस्थापन से जुड़ी सामाजिक-आर्थिक चुनौतियाँ सामूहिक रूप से शरणार्थी महिलाओं को लिंग आधारित दुर्व्यवहार के बढ़ते जोखिम के लिए उजागर करती हैं, जिसमें लेन-देन संबंधी सेक्स जैसी प्रथाएँ शामिल हैं।

शारीरिक और यौन संपर्क में वृद्धि उल्लंघन उन्हें मनोवैज्ञानिक और मनोसामाजिक स्थितियों जैसे पोस्ट-ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD), चिंता विकार और अवसाद के लिए अनुचित रूप से अतिसंवेदनशील बनाता है। विस्थापित महिलाओं में PTSD के लक्षण दिखने की संभावना उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में दोगुनी और अवसाद प्रदर्शित करने की संभावना चार गुना अधिक होती है। सूडान के डारफुर में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि 72% विस्थापित महिलाएँ दर्दनाक घटनाओं और शिविरों में रहने की स्थिति के कारण PTSD और सामान्य संकट जैसी स्थितियों से प्रभावित थीं। साक्ष्य इंगित करते हैं कि पुरुष शरणार्थियों की तुलना में महिला शरणार्थियों में निदान योग्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों के विकसित होने का अधिक जोखिम होता है

सामाजिक और लैंगिक असमानताएं, विशेषकर जब शरणार्थी आबादी पितृसत्तात्मक समाजों से संबंधित होती है, तो विस्थापित महिलाओं के अनुभवों और साक्ष्यों को खारिज कर दिया जाता है।

इस ज्ञानात्मक अन्याय के परिणामस्वरूप उनकी स्थिति अक्सर अनदेखी हो जाती है। मनोवैज्ञानिक कमज़ोरियों वाली विस्थापित महिलाएँ भी कलंकित और अलग-थलग पड़ जाती हैं। अपने सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए, शरणार्थी परिवार मानसिक स्वास्थ्य की तुलना में शारीरिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हैं, और महिलाओं की तुलना में पुरुषों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हैं। नतीजतन, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि मनोवैज्ञानिक विकलांगता वाली विस्थापित महिलाओं को शायद ही कभी, यदि कभी, आवश्यक सहायता मिलती है। मानसिक स्वास्थ्य सेवा का उपयोग शरणार्थियों के बीच स्थानीय आबादी की तुलना में कम और महिलाओं के बीच पुरुषों की तुलना में कम बताया गया है।

स्थिति तब और भी खराब हो जाती है जब मेजबान समाज भी पारंपरिक रूप से पितृसत्तात्मक होता है, जैसा कि भारत के मामले में है। भारत में, सामुदायिक भागीदारी मुख्य रूप से पुरुष-प्रधान है, जिससे शरणार्थी महिलाओं को विदेशी भूमि में अलग-थलग छोड़ दिया जाता है और उन्हें अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए कोई मंच नहीं मिलता। इसके अलावा, मनोसामाजिक विकलांगताओं से जुड़ा व्यापक कलंक उनकी जानकारी तक पहुँच को सीमित करता है।

मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ आमतौर पर सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध होती हैं, जहाँ प्रतीक्षा अवधि लंबी होती है या (अनियमित) गैर-सरकारी संगठनों द्वारा सहायता सेवाओं के माध्यम से। इन सेवाओं की मांग अक्सर तभी की जाती है, जब समस्याएँ गंभीर रूप से बढ़ जाती हैं। इन सीमित विकल्पों की तलाश में भी शरणार्थी महिलाओं को कलंक, शर्म की भावना, संचार बाधाओं और सीमित मानसिक स्वास्थ्य साक्षरता और उपलब्ध सेवाओं के बारे में जागरूकता जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

कन्वेंशन, अधिकार और भारत की भूमिका विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (यूएनसीआरपीडी), 'दीर्घकालिक मानसिक या बौद्धिक विकलांगताओं को मान्यता देता है, जो विभिन्न बाधाओं के साथ मिलकर समाज में पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में बाधा डाल सकती हैं' को 'मनोवैज्ञानिक विकलांगता' के रूप में मान्यता देता है; यह प्रभावित व्यक्तियों को बहुत सारे अधिकारों की गारंटी देता है। यूएनसीआरपीडी यह भी मानता है कि 'विकलांग महिलाओं और लड़कियों के साथ कई तरह के भेदभाव किए जाते हैं' और 'उनके द्वारा सभी मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं का पूर्ण और समान आनंद' सुनिश्चित करने के लिए उपायों को अनिवार्य बनाता है (अनुच्छेद 6)। इन गारंटियों को बिना किसी भेदभाव के सभी को सुरक्षित करने की आवश्यकता है (अनुच्छेद 5)।

> शरणार्थी औरत, विशेष रूप से विकलांग लोगों को कुछ अधिकारों की गारंटी दी जाती है, लेकिन उनके सामने आने वाली अनेक बाधाओं के कारण वे शायद ही कभी उन्हें प्राप्त कर पाते हैं

भारत ने यूएनसीआरपीडी की रेटिंग प्राप्त की और तत्पश्चात, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (RPWDA) को अधिनियमित किया, जो विकलांग व्यक्तियों को संगत गारंटी प्रदान करता है। जबकि 'मनोवैज्ञानिक विकलांगता' शब्द अभी तक देश की विधायी शब्दावली का हिस्सा नहीं है, "मानसिक बीमारी" का उपयोग 'सोच, मनोदशा, धारणा, अभिविन्यास या स्मृति का एक बड़ा विकार है जो निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता को पहचानने की क्षमता या जीवन की सामान्य मांगों को पूरा करने की क्षमता को बुरी तरह से प्रभावित करता है...' विकलांग व्यक्तियों की एक श्रेणी के रूप में 'मानसिक बीमारी' वाले व्यक्ति हैं

आरपीडब्ल्यूडीए के तहत कई अधिकारों की गारंटी दी गई है, जिसमें स्वास्थ्य सेवा का अधिकार भी शामिल है, जिसमें निःशुल्क और बाधा रहित पहुंच के अलावा उपचार और देखभाल में प्राथमिकता शामिल है (धारा 25)। आरपीडब्ल्यूडीए राज्य को यह सुनिश्चित करने का भी अधिकार देता है कि विकलांग महिलाएं दूसरों के समान अपने अधिकारों का आनंद लें (धारा 4)।

हालाँकि, उनके न होने के कारण ही भारतीय नागरिक, मनोवैज्ञानिक विकलांगता वाली शरणार्थी महिलाएं इस गारंटी के क्रियान्वयन से बाहर हैं। यह अधिकारों और सेवाओं के वितरण में गैर-नागरिकों की कानूनी और प्रशासनिक रूपरेखा की निगरानी, सामाजिक कलंक और भेदभाव, जागरूकता की कमी, भाषा संबंधी बाधाएं और वित्तीय बाधाओं जैसे कारकों के कारण है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत शरणार्थियों के जीवन के अंतर्निहित अधिकार पर लगातार बल दिया है, जिसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है।
हालांकि, शरणार्थियों की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बेहद सीमित है और मुख्य रूप से सरकारी अस्पतालों तक ही सीमित है। नागरिकों के लिए उपलब्ध अधिकांश सार्वजनिक स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों से उन्हें बाहर रखा जाता है, और उनके सीमित साधनों को देखते हुए, निजी अस्पताल बेहद महंगे हैं। नतीजतन, विकलांग शरणार्थियों को RPWDA के दायरे में लाने या UNCRPD (अनुच्छेद 6, 11 और 18) के अनुसार उनके हितों की रक्षा करने की किसी भी स्पष्ट गारंटी के अभाव में, 'मनोसामाजिक विकलांगता' या "मानसिक बीमारी" से पीड़ित शरणार्थी महिलाएँ स्वास्थ्य के अधिकार की गारंटी के बावजूद इसे प्राप्त करने में असमर्थ रहती हैं। उनके जीवन के अधिकार का उल्लंघन न केवल न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों का खंडन करता है, बल्कि UNCRPD के आदेश को भी खोखला और निरर्थक बना देता है।

संरचनात्मक अंतराल को भरना भारत न तो 1951 के शरणार्थी सम्मेलन और उसके 1967 के प्रोटोकॉल का पक्षकार है, न ही उसके पास शरणार्थियों से संबंधित कोई विशेष घरेलू कानून है, विकलांग शरणार्थियों की तो बात ही छोड़िए।

देश में शरणार्थियों की विशाल आबादी को देखते हुए, एक समान, संहिताबद्ध ढांचा स्थापित करना आवश्यक है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त भाषा प्रदान करे।

यह सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के लिए भी आवश्यक है, जो विकलांग व्यक्तियों और शरणार्थियों सहित कमजोर आबादी को सशक्त बनाने पर जोर देता है।

उपर्युक्त गारंटियों के कार्यान्वयन को सुरक्षित करने के लिए, विकलांग शरणार्थियों को सुलभ तरीके से प्रासंगिक नीतियों और कार्यक्रमों में एकीकृत करना महत्वपूर्ण है। प्रभावी नीति-निर्माण भी उनकी स्वास्थ्य स्थितियों पर अलग-अलग डेटा के संग्रह पर निर्भर करता है, जिसके लिए त्वरित और व्यवस्थित पहचान और पंजीकरण प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है।

यह देखना अभी बाकी है कि यह कैसे और कब होगा तब तक, अहम सवाल यह है कि क्या उन्हें धीरज रखना चाहिए या फिर उम्मीद खोकर हार मान लेनी चाहिए।

कोई जनगणना नहीं - महत्वपूर्ण डेटा के बिना अंधेरे में

एस. इरुदया राजन
अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन एवं विकास संस्थान (आईआईएमएडी), तिरुवनंतपुरम, केरल

यू.एस. मिश्रा
विजिटिंग प्रोफेसर, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन एवं प्रवासन संस्थान विकास, तिरुवनंतपुरम, केरल

टी भारतीय दशकीय जनगणना की गई है अनेक चिंताओं के बावजूद इसमें तीन वर्ष से अधिक की देरी हो चुकी है जनगणना न होने के दुष्परिणामों के बारे में सवाल उठाए गए। वास्तव में, जनगणना के स्थान पर जनसंख्या की गणना के लिए वैकल्पिक तरीकों और साधनों को अपनाने के बारे में अधिकारियों के बीच भारी गलतफ़हमी है।

जनगणना एक निश्चित जनसंख्या तक सीमित नहीं है गणना। इसमें स्थान संबंधी, पारिवारिक और व्यक्तिगत जानकारी की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है जो बदलती जनसंख्या गतिशीलता को उसकी संपूर्णता में समझने में मदद करती है। जनगणना से बचने की पहली और सबसे बड़ी सीमा हमारे सभी बड़े पैमाने के सर्वेक्षणों जैसे कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की विश्वसनीयता में निहित है, जो डेढ़ दशक पुराने जनगणना फ्रेम पर किए गए हैं।

कई बदलावों को समझने की जरूरत इसके अलावा, यह डेढ़ दशक न केवल जनसंख्या गणना और उसकी संरचना में बल्कि शिक्षा, व्यवसाय, रोजगार, स्वास्थ्य (कोविड-19) और आजीविका से संबंधित कई अन्य विशेषताओं में भी संभावित परिवर्तन का दौर रहा है। इन विशेषताओं की जांच करने के महत्व को देखते हुए, जनगणना में देरी करना सबसे गैरजिम्मेदाराना लगता है। जनगणना के विकल्प के बारे में सोचना भोलापन है। हालांकि, विकास योजना से ज्यादा राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जाति जनगणना कराने पर सार्वभौमिक प्रतिध्वनि है, जो निस्संदेह जनगणना की उपयोगिता और मानव कल्याण के लिए कई अनुमानित रणनीतियों में पाठ्यक्रम सुधार के लिए इसकी प्रासंगिकता पर सीमित समझ को प्रकट करता है।

2021 की जनगणना में शामिल न होना कभी भी कोई बड़ी बात नहीं हो सकती यह बहाना इसलिए दिया गया क्योंकि आम चुनाव सभी अनिश्चितताओं के बीच आयोजित किया गया था। जनगणना के लिए आवश्यक मशीनरी शायद चुनाव के लिए आवश्यक मशीनरी से काफी मिलती जुलती है।

इसलिए, ऐसा लगता है कि जनगणना में देरी होने के बजाय, अनुचित कारणों से इसे टाला जा रहा है।

> जनगणना केवल जनसंख्या गणना तक सीमित नहीं है; इसमें महत्वपूर्ण स्थान संबंधी, पारिवारिक और व्यक्तिगत जानकारी की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है

हालाँकि, सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के कवरेज और परिणामी प्रभाव के संदर्भ में उनके मूल्यांकन पर राय की कमी नहीं है।

दुर्भाग्यवश, उचित मापदण्ड के बिना किसी भी कार्यक्रम की सफलता की निगरानी करना भ्रामक होगा।

जनगणना की तत्काल आवश्यकता और इसमें और देरी न करने के पीछे कई तर्क हैं, खास तौर पर तेज़ जनसांख्यिकीय बदलाव और उसके परिणामस्वरूप जनसांख्यिकीय लाभांश। पारिवारिक संरचनाओं, स्थानिक वितरण और व्यावसायिक संरचना के साथ-साथ इन परिवर्तनों को प्रकट करने के लिए जनसंख्या जनगणना बहुत ज़रूरी है।

इसके अलावा, जनगणना ढांचे की अनुपस्थिति में, किए गए सर्वेक्षण कम विश्वसनीय और प्रतिनिधि होंगे जो एसडीजी संकेतकों की एक पूरी श्रृंखला बनाने का आधार रहे हैं। और इन संकेतकों के आधार पर एसडीजी में प्रगति का दावा किया गया माप, उनकी सांख्यिकीय अपर्याप्तता के कारण जांच के दायरे में हो सकता है।

विश्व जनसंख्या की संभावनाएं अद्वितीय खुलासा करती हैं जनसंख्या परिवर्तन की विशेषताएं और अच्छे जनसांख्यिकीय डेटा, जो दुनिया के अन्य क्षेत्रों की तुलना में भारत और चीन जैसे जनसंख्या दिग्गजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। यह देखते हुए कि विश्व जनसंख्या परिदृश्य भारतीय जनसंख्या विशेषताओं से बहुत प्रभावित है, यह आवश्यक है कि जनगणना में इसकी जनसंख्या विशेषताओं की वास्तविकता प्राप्त की जाए, न कि पिछले रुझानों के आधार पर अनुमानित मूल्यों का अनुमान लगाया जाए जो अनुमानों और अनुमानों पर निर्भर करते हैं। जनगणना अभ्यास को केवल जनसंख्या गणना के रूप में प्रस्तुत करना एक गलत धारणा है जिसे व्यापक दर्शकों के लिए दोहराया जाना चाहिए।

मौजूदा एसडीजी परिवेश में, उप-राष्ट्रीय स्तर से नीचे विघटन के साथ संकेतकों की एक विस्तृत श्रृंखला के सृजन के संबंध में जुनून रहा है। ऐसे संकेतक कई आयामों से संबंधित हैं जिन्हें जनसंख्या गणना (न केवल समग्र बल्कि आयु के अनुसार खंडित गणना) द्वारा मानकीकृत करने की आवश्यकता है।

लिंग और कई अन्य विशेषताओं के आधार पर जनगणना नहीं होने से यह समस्या उत्पन्न हो जाती है।
अनुमानित संख्याएं या सर्वेक्षण-आधारित अनुमान बदलती वास्तविकताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए काफी अपर्याप्त हैं।

जाति जनगणना का रोना हालांकि जनगणना की तत्काल आवश्यकता और तात्कालिकता क्षितिज पर नहीं दिखती है, लेकिन राजनीतिक आका अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जाति जनगणना की आवश्यकता को बढ़ाने में लगे हुए हैं। वास्तव में, ऐसे समय में जब हम दावा करते हैं कि सब कुछ ठीक है, भारत में जाति की ऑडिटिंग बेमानी लगती है।

जनगणना अभ्यास का इतिहास यह स्पष्ट करता है कि इस तरह की ऑडिटिंग इसके शुरुआती चरणों में की गई थी, और इसे बंद करने का कोई कारण अवश्य रहा होगा। किसी को भी यह गुमराह नहीं होना चाहिए कि जाति ऑडिटिंग विभिन्न जाति समूहों को शामिल करने के वास्तविक इरादे से समर्थित है। यह मुख्य रूप से प्रतिनिधित्व की कमी और वंचना का हवाला देते हुए विभेदक अधिकार स्थापित करने के लिए है। हालाँकि, मूर्त बंदोबस्ती शायद शिक्षा और व्यवसाय जैसे अमूर्त क्षेत्रों का आकलन करने के बजाय वंचना का निदान करने का एक सीमित तरीका है। दुर्भाग्य से, इतने लंबे समय तक निरंतर हथियारबंद कार्रवाई के बावजूद जाति की धुरी के खिलाफ शिक्षा और व्यवसाय के उक्त क्षेत्रों में गतिशीलता के किसी भी व्यवस्थित मूल्यांकन का पूर्ण अभाव है।

अंततः जनगणना को टालना ही शायद उचित होगा संकेतकों की गणना में उचित हर के बिना केवल अंशों के आधार पर प्रगति और बेहतरी का दावा करना राज्य के हित में है। इसलिए, वैज्ञानिक समुदाय को बिना किसी देरी के जनगणना की आवश्यकता बतानी चाहिए ताकि इस भ्रम से बाहर निकला जा सके कि सर्वेक्षण और कई अन्य प्रशासनिक आँकड़े जनगणना की जगह ले लेते हैं। इसलिए मुख्य आशंका बनी हुई है: क्या जनगणना में देरी हुई है? या क्या जनगणना को टालने का कोई ठोस प्रयास किया जा रहा है?

संपादक के नाम चिठी

बोली का समय?

यह थोड़ा हास्यास्पद है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे साजिद वाजेद जॉय ने कहा कि लोकतंत्र बहाल होते ही उनकी मां ढाका वापस आ जाएंगी ('वर्ल्ड' पेज, 9 अगस्त)।

सुश्री हसीना ऐसा नहीं करतीं बांग्लादेश छोड़ दिया था उनके शासन काल में लोकतंत्र की भावना प्रबल रही।

सीजी कुरियाकोस,
कोठमंगलम, केरल

भारत और ओलंपिक नीरज चोपड़ा ने विश्व मंच पर एक बार फिर अपनी असाधारण प्रतिभा साबित की है।

आइये हम अरशद नदीम की उत्कृष्ट उपलब्धि को भी स्वीकार करें। नीरज की सफलता का जश्न मनाते हुए, खेल भावना को पहचानना और सभी एथलीटों के प्रयासों की सराहना करना आवश्यक है ('स्पोर्ट' पेज, "अरशद के 92.97 मीटर ने नीरज को हराया", 9 अगस्त)।

संजीत पाल सिंह,
इच्छापुर, पश्चिम बंगाल

एक ऐसे राष्ट्र के लिए जिसे पीड़ा से गुजरना और शीर्ष पहलवान विनेश फोगट की अयोग्यता का आघात, भाला फेंक में नीरज चोपड़ा की शानदार जीत और पेरिस में भारतीय हॉकी टीम की जीत, वास्तव में सुखदायक और ताजगी देने वाली होनी चाहिए।

नीरज चोपड़ा की यह जीत उनके धैर्य और दृढ़ संकल्प का सही उदाहरण है। अथक कड़ी मेहनत.

बी. सुरेश कुमार, कोयंबटूर

पूरे पृष्ठ के डेटा-ग्राफ़िक से यह स्पष्ट है कि न केवल ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन दुखद रहा है, बल्कि यह भी स्पष्ट है कि हम

इसमें बहुत संभावनाएं हैं ओलंपिक जैसे (राय पृष्ठ, "एक व्यापक ओलंपिक क्वेस्ट", 9 अगस्त)। 1.4 बिलियन से अधिक की आबादी के साथ, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अधिकांश अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में हमारी उपस्थिति बहुत कम है। इसके विपरीत, चीन पदक तालिका में आगे बढ़ गया है। अब समय आ गया है कि हम यह समझें कि खेल किसी राष्ट्र के विकास का हिस्सा है।

रघुनाथ मेनन, हैदराबाद

https://t.me/AllNewsPaperPaid

अभिमत

आधुनिक व रासायनिक खेती के कारण यह बरसों पुरानी परंपराएं कमजोर हो रही हैं। खेत व बैल का रिश्ता भी टूट रहा है। इसका नतीजा हो रहा है कि मवेशी सड़कों पर घूम रहे हैं। पिछले कुछ सालों से न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि देश भर में जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, परंपरागत खेती का चलन बढ़ रहा है। इसमें देशी बीज, गोबर खाद, केंचुआ खाद, जैव कीटनाशक का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि रासायनिक खेती के दुष्परिणाम स्पष्ट रूप से सामने आ गए हैं। इसलिए किसानों का भी रुझान इस ओर बढ़ रहा है।

अच्छी सेहत के लिए पौष्टिक भोजन जरूरी

नवाचार

■ **बाबा मायाराम**

हाल ही में मेरा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के गनियारी कस्बे में जाना हुआ। वहां स्वास्थ्य का अनूठा काम हो रहा है। यह न केवल इलाज व दवाओं से संभव है, बल्कि अच्छी सेहत के लिए अच्छा भोजन भी जरूरी है। इसके लिए जैविक खेती पर भी जोर दिया जा रहा है। आज के इस कॉलम में इस पर चर्चा करना उचित होगा।

गनियारी के जन स्वास्थ्य सहयोग संस्था है। इस संस्था का काम वर्ष 1999 में इस जिले में स्वास्थ्य पर शुरू हुआ। देश की मौजूदा स्वास्थ्य सेवाओं की हालत से चिंतित दिल्ली के कुछ मेधावी डाक्टरों ने इसकी शुरूआत की थी। इस संस्था ने एक अध्ययन के दौरान यह पाया कि ज्यादातर बीमारियों का संबंध कुपोषण से है, तबसे संस्था ने अपना कृषि कार्यक्रम शुरू किया।

जन स्वास्थ्य सहयोग ने उनकी एक डेढ़ एकड़ की भाटा (कमजोर) ज़मीन पर बिना रासायनिक वाली जैविक खेती शुरूआत की, जो अब साढ़े चार एकड़ में फैल चुकी है। यहां धान की 450 किस्में संग्रहीत हैं जिनमें 65 सुगंधित, 30 लाल चावल वाली, 40 जल्द पकने वाली, 2 किस्में काले चावल की। और बाकी 110-115 दिन की मध्यम अवधि में पकने वाली किस्में हैं। इसके अलावा, मड़िया की 6, कांग 2, ज्वार 1, मक्का 2 और अरहर की 9 किस्में हैं। चना, अलसी, कुसुम, मटर, भिंडी, उड़द आदि देशी किस्में भी हैं।

रंग-बिरंगे देशी बीज न केवल सौंदर्य से भरपूर हैं बल्कि स्वाद में भी बेजोड़ हैं। औषधि गुणों से सम्पन्न हैं और स्थानीय मिट्टी पानी और हवा के अनुकूल हैं। आखिर मनुष्य ने ही जंगलों से तरह-तरह की फसलों के गुणधर्मों की पहचान कर खेतों में उन्हें उगाया है। इसी के परिणामस्वरूप आज हम बीजों के मामले में समृद्ध हैं।

गनियारी में एक-दो डिसमिल की छोटी-छोटी क्यारियों में देशी धान का प्रयोग करीब डेढ़ दशक से चल रहा है। मैं कई बार इस फार्म को देख चुका हूं और इसके प्रमुख कार्यकर्ता होम प्रकाश से चर्चा की है। होम प्रकाश ने बताया कि धान की कई किस्में हैं जिनमें हरून धान 70 से 100 दिन वाली, मध्यम 100 से 120 दिन वाली और गहरून 120 से 145 दिन वाली हैं। जो अलग-अलग किस्म की मिट्टी वाली ज़मीन में होती हैं।

उन्होंने बताया कि धान की नई मेडागास्कर पद्धति के प्रयोग हमने देशी धान बीजों से किए जिसमें उत्पादन औसत धान से दोगुना तक पाया गया। यहां जैविक तरीके से देशी धान (मोटा) 25 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ और सुगंधित धान 20-25 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन पाया गया है।

मेडागास्कर पद्धति की खास बात यह है कि इसमें बीज कम लगता है, पानी कम लगता है और उत्पादन अधिक होता है। हाथ से चलाने वाले बीडर से निंदाई की जा सकती है। इस पद्धति में खेत में पानी भरकर रखना जरूरी नहीं है। खेत में पानी नहीं रहने पर मिट्टी में वायु संचार होता है जिससे पौधा स्वस्थ और मजबूत होता है। फलस्वरूप पौधे में ज्यादा कंसा निकलते हैं और बालियां भी अधिक लगती हैं। यानी उत्पादन ज्यादा होता है। इस पद्धति को अफ्रीकी देश मेडागास्कर में ईजाद किया गया था।

मेडागास्कर पद्धति की खास बात यह है कि इसमें बीज कम लगता है, पानी कम लगता है और उत्पादन अधिक होता है। हाथ से चलाने वाले बीडर से निंदाई की जा सकती है। इस पद्धति में खेत में पानी भरकर रखना जरूरी नहीं है। खेत में पानी नहीं रहने पर मिट्टी में वायु संचार होता है जिससे पौधा स्वस्थ और मजबूत होता है। फलस्वरूप पौधे में ज्यादा कंसा निकलते हैं और बालियां भी अधिक लगती हैं। यानी उत्पादन ज्यादा होता है। इस पद्धति को अफ्रीकी देश मेडागास्कर में ईजाद किया गया था।

वे आगे बताते हैं कि यह अरहर उत्तरप्रदेश से आई है, मडिया बस्तर से। कुसुम से तेल निकलता है और काबुली चना का दाना बड़ा होता है। धान की कई किस्में सुगंधित हैं और कई बिना पानी वाली। मुंगलानी (राजगिर) पौष्टिक होता है और ज्वार की रोटी हाजमे के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है।

हाल ही में उन्होंने पानी की कमी को देखते हुए एक दिन में कुआं खोद डाला और जब पानी हो गया तो गाय खरीद ली। उनके खेत में थोड़ा ढलान है और आसपास तालाब भी है, इसलिए पानी बहुत उथले में निकल आता है। कुछ समय पहले गोबर गैस प्लांट भी लगाया है। यह बहुत छोटा है, और घर की गाय के गोबर से ही चलता है। इससे बल्ब और रसोई गैस की जरूरत भी पूरी हो जाती है।

मैंने यहां घूमते-घूमते एक नजर खेत पर डाली। मेड़ पर अरहर के पौधे लहलहा रहे थे। बेर के पेड़ों के नीचे बच्चे खेल रहे थे। एक खेत में सब्जियां लगी थीं। मूली, भटा, टमाटर, धनिया, मिर्ची, बरबटी, प्याज और भिंडी।

होमप्रकाश बताते हैं कि खेती के लिए ज़मीन का स्वास्थ्य भी सुधारना जरूरी है। रासायनिक खेती के कारण ज़मीन की उर्वरा शक्ति कमजोर होती जा रही है और उर्वर बनाने वाले सूक्ष्म जीवाणु खत्म होते जा रहे हैं। बेजा रासायनिक खाद के इस्तेमाल से ज़मीन सख्त होती जा रही है। भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए मिश्रित फ़सलों को खेतों में बोया जाता है। यह परंपरागत तरीका है।

इसके अलावा, हरी खाद ढनढनी, सन, सोल, चरौरा को भी बोकर फिर मिट्टी में सड़ा दिया जाता है, जिससे ज़मीन उत्तरोत्तर उर्वर बनती जाती है। उन्होंने बताया कि इस भाटा कमजोर ज़मीन को हरी खाद से ही उर्वर बनाया है।

कोटा के पास फुलवारीपारा नामक गांव में डबरी निर्माण का काम किया गया है, जिससे आदिवासी किसान सब्जी बाड़ी लगाते हैं। और खुद भी हरी सब्जी खाते हैं और अतिरिक्त होने पर बेचते भी हैं, जिससे उनकी आमदनी हो जाती है।

सामुदायिक कृषि कार्यक्रम के महेश शर्मा ने बताया कि अब हमारा यह प्रयोग न केवल गनियारी में बल्कि कई गांवों में फैल चुका है।

किसान कार्यकर्ता भुवन सिंह ने बताया कि धान की रासायनिक खेती में प्रति एकड़ 5-6 हजार रूपए लागत आती है और जैविक खेती में एक से डेढ़ हजार रूपए जबकि उत्पादन दोगुना मिलता है। अगर मेड़ पर पौधे लगाएं तो इससे हमें लकड़ी, फल, शुद्ध हवा, और ज़मीन को पानी सब कुछ मिलेंगे।

इस संस्था का एक पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम भी चल रहा है। इसमें गांव के ही कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर मवेशियों का टीकाकरण और छोटी-मोटी बीमारियों का इलाज किया जाता है। दवाओं भी स्थानीय जड़ी-बूटियों से बनाई जाती हैं। कुछ दवाएं जरूरत पड़ने पर खरीदी भी जाती हैं। संस्था की इस पहल से पशुओं का स्वास्थ्य बेहतर होता है, और लोगों की आमदनी में भी इजाफा होता है।

खेती और पशुपालन का अटूट रिश्ता है। छत्तीसगढ़ में पशुपालन की बहुत ही अच्छी परंपरा है। खेती और पशुओं के साथ कई तीज-त्यौहार जुड़े हैं। पोला बैलों का त्यौहार है। इस दिन उनकी पूजा होता है। अक्ति त्यौहार भी खेती से जुड़ा है। दीपावली और होली भी।

लेकिन आधुनिक व रासायनिक खेती के कारण यह बरसों पुरानी परंपराएं कमजोर हो रही हैं। खेत व बैल का रिश्ता भी टूट रहा है। इसका नतीजा हो रहा है कि मवेशी सड़कों पर घूम रहे हैं।

पिछले कुछ सालों से न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि देश भर में जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, परंपरागत खेती का चलन बढ़ रहा है। इसमें देशी बीज, गोबर खाद, केंचुआ खाद, जैव कीटनाशक का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि रासायनिक खेती के दुष्परिणाम स्पष्ट रूप से सामने आ गए हैं। इसलिए किसानों का भी रूझान इस ओर बढ़ रहा है।

छत्तीसगढ़ की यह पहल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ सालों से यहां सघन धान की खेती को बढ़ावा मिल रहा है। अन्य मिश्रित फसलें पीछे छूट रही हैं। जबकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए मिश्रित फसलों का होना जरूरी है। जबकि रासायनिक खेती में मिट्टी और पानी जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और यह खेती स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर डालती है।

कुल मिलाकर, यह कहा जा सकता है कि यह प्रयोग अनूठा है, छत्तीसगढ़ में एक मौन क्रांति की तरह है जो सराहनीय होने के साथ अनुकरणीय है। अच्छी सेहत के लिए अच्छा भोजन जरूरी है। और स्वस्थ भोजन के लिए जैविक खेती, जो देशी बीजों, गोबर खाद व हल-बैल की खेती से होती है, वह जरूरी है। इस तरह की खेती से मिट्टी, पानी और पर्यावरण के संरक्षण के साथ छत्तीसगढ़ की ग्रामीण संस्कृति भी बचेगी। जैव विविधता के साथ आजीविका का भी संरक्षण होगा।

बीता सप्ताह

3 अगस्त

- पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने आस्ट्रेलिया टीम को पूल बी के मैच में 3-2 से हरा दिया।
- राहुल गांधी ने कहा कि संसद में उनके चक्रव्यूह वाले भाषण पसंद नहीं आने पर केंद्र शासन मेरे खिलाफ ईडी (एसबीआई) छापेमारी की तैयारी कर है।
- हिमाचल में बादल फटने से छः छात्रों की बह जाने से मौत हो गई।
- छतरपुर मध्यप्रदेश में कुएं से जहरीली गैस रिसाव होने के कारण चार लोगों की मौत हो गई।

4 अगस्त

- अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए डेमोक्रिटिक पार्टी की उम्मीदवार बनी कमला हैरिस।
- पेरिस ओलंपिक में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कोरिया की यांग जिन ने गोल्ड मेडल जीता।
- इंटरमेशनल बॉक्सिग एसोसिएशन ने (आईबीए) इटली की एंजिला कैरिबी को 50000 डॉलर पुरस्कार राशि देने का ऐलान किया।
- वायनाड भूस्खलन में मृतकों की संख्या कुल 344 हुई।

5 अगस्त

- मध्यप्रदेश के सागर में दीवार गिरने से नौ लोगों की मौत हो गई।
- भारत ने ग्रेट ब्रिटेन को पेरिस ओलंपिक की हॉकी प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में शूटआउट में 4-2 से पराजित कर फाइनल में जगह बनाया। 0 वक्फ बोर्ड के अधिकारों पर लगाम लगाने केंद्र सरकार मौजूदा वक्फ अधिनियम में संशोधन करेगी।
- आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर बस-कार में टक्कर होने से 7 लोगों की मौत हो गई।

6 अगस्त

- बांग्लादेश में तख्ता पलट, पीएम शेख हसीना ने इस्तीफा दिया, देश छोड़ा, हिंडन एयर बस से भारत पहुंची।
- सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापनों के लिए लगाई फटकार, आयुष औषधि निर्माता, विज्ञापनदाता एवं विज्ञापन एजेंसियों को दिए निर्देश।
- भारत ने बांग्लादेश में तख्ता पलट होने से कोलकाता, ढाका एवं खुलना के लिए चलने वाली रेल सेवाएं स्थगित कीं।
- शेयर बाजार में 2222 अंक लुढ़कने से निवेशकों के 16 लाख करोड़ रूपए डूब गए।

7 अगस्त

- बांगलादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने संसद भंग कर दी तथा देश के पूर्व पीएम खालिदा जिया को भी रिहा कर दिया।
- फिजी के राष्ट्रपति रातू बिलियाये मैवलीली कटोनिवेरे ने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कैपेनियन ऑफ द आर्डर आफ फिजी से सम्मानित किया।
- केन्द्र सरकार के वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में कहा कि कोरोनाकाल के दौरान केन्द्रीय कर्मियों और पेंशनरो के रोके गए 18 प्रतिशत डीए का भुगतान अब नहीं किया जाएगा।
- अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार कमला हैरिस ने सिलेसोटा राज्य के गवर्नर टिम वातज को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया है।

8 अगस्त

- भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में 100 ग्राम ज्यादा वजन पाए जाने पर आयोग्य घोषित कर दिया गया।
- पेरिस ओलंपिक 2024 में डबल पदक विजेता मनु भाकर स्वदेश भारत लौटी। दिल्ली में शानदार स्वागत हुआ।
- 5 सितम्बर 2024 को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी की।
- हमास ने याह्या सिनवार को सैन्य संगठन और अपना राजनीतिक प्रमुख घोषित किया। वे इस्माइल हानिया की जगह लेंगे।

9 अगस्त

- बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के रूप में नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनूस ने शपथ ली।
- भारतीय महिला पहलवान पेरिस ओलंपिक में फाइनल में आयोग्य घोषित होने के बाद कुश्ती से सन्यास की घोषणा की।
- संसद में वक्फ बिल लाया गया जो सर्वसम्मत नही होने पर जेपीसी को भेजा गया।
- पं. बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो गया।

हिंदुत्व का खेल और राजनीति

वीडी. सावरकर ने अपनी किताब 'हिंदुत्व हू इज हिंदू' (1923) में हिंदुत्व के तीन लक्षण बताए हैं- एक राष्ट्र, एक जाति और एक संस्कृति। उनकी नजर में हिन्दू वही है जो 'हिन्दुस्थान' को पितृभूमि ही नहीं पुण्यभूमि भी मानता हो। हिंदुत्व के विचारक सावरकर ने मुसलमानों, ईसाइयों और कम्युनिस्टों को हिंदुत्व का दुश्मन करार दिया। सावरकर द्विराष्ट्रवाद के पहले सिद्धांतकार भी हैं। सावरकर ने 30 सितम्बर 1937 को हिन्दू महासभा के अध्यक्षीय भाषण में कहा कि 'एक प्रमुख राष्ट्र में दो राष्ट्र हैं 'भारत में हिन्दू और मुस्लिम'। इसके एक साल बाद 1938 में उन्होंने कहा कि भारत में हिंदू राष्ट्र है और मुस्लिम एक अल्पसंख्यक समुदाय है। सावरकर का विचार देश विभाजन ना होकर मुसलमानों को हिंदुओं के अधीन रखने का था। दरअसल, इसी विचार ने विभाजन की बुनियाद पैदा की। सावरकर के अनुसार भारत हिंदुओं का देश है। सावरकर ने अपने पितृभूमि और पुण्यभूमि वाले विचार से बौद्ध, जैन और सिक्खों को हिंदुओं के भीतर समेट लिया था। वस्तुतः, सावरकर बौद्ध, जैन और सिख धर्म को हिन्दू धर्म के सम्प्रदाय मानते हैं, स्वतंत्र धर्म नहीं। इसके अलावा मुसलमान सहित सभी धर्म भारत में अल्पसंख्यक बनकर रहेंगे। यानि उन्हें समान अधिकार नहीं मिलेंगे। इसी वजह से मुसलमानों के मन में भय और पहचान का संकट पैदा हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना ने सावरकर के द्विराष्ट्रवाद सिद्धांत के आधार पर हिंदुओं और मुसलमानों को दो अलग कौमें मानते हुए एक स्वतंत्र राष्ट्र की मांग की। परिणामस्वरूप, देश का विभाजन हुआ।

प्रो. रविकांत

भारत से विभाजित होकर इस्लाम के आधार पर पाकिस्तान का निर्माण हुआ। पाकिस्तान बनने के बाद भारत में रह रहे मुसलमानों पर तमाम आक्षेप लगने लगे। बंटवारे के बाद आरएसएस की ताकत अचानक बढ़ती चली गई। पाकिस्तान से आने वाले हिंदू और सिखों को आरएसएस ने भड़काया। अपनों को खोने और घर-खेत छूट जाने के जख्मों को कुरेदकर उनको मुसलमानों पर हमला करने के लिए उकसाया गया। हमलों से डर के कारण दिल्ली के मुसलमानों ने लाल किले में शरण ली।

भारत से विभाजित होकर इस्लाम के आधार पर पाकिस्तान का निर्माण हुआ। पाकिस्तान बनने के बाद भारत में रह रहे मुसलमानों पर तमाम आक्षेप लगने लगे। बंटवारे के बाद आरएसएस की ताकत अचानक बढ़ती चली गई। पाकिस्तान से आने वाले हिंदू और सिखों को आरएसएस ने भड़काया। अपनों को खोने और घर-खेत छूट जाने के जख्मों को कुरेदकर उनको मुसलमानों पर हमला करने के लिए उकसाया गया। हमलों से डर के कारण दिल्ली के मुसलमानों ने लाल किले में शरण ली। लेकिन जवाहरलाल नेहरू भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने के लिए संकल्पबद्ध थे। 1951-52 का पहला चुनाव नेहरू ने भारत को 'पाकिस्तान नहीं बनने देने' के मुद्दे पर लड़ा और बड़ी जीत हासिल की। अल्पसंख्यकों में विश्वास और उचित साझेदारी की भावना पैदा करने के लिए नेहरू ने 29 सितम्बर 1953 और 15 जून 1954 को भेजे गए अपने पत्रों में मुख्यमंत्रियों को संबोधित करते हुए लिखा, 'अगर भारत को एक धर्मनिरपेक्ष, स्थाई और मजबूत राष्ट्र बनाना है तो हमारा पहला काम यह होना चाहिए कि हम अपने अल्पसंख्यकों को बिना भेदभाव के उनका उचित हिस्सा प्रदान करें और इस तरह से उन्हें भारत में पूर्ण रूप से पारिवारिक एहसास दिलाएं।

विभाजन के समय सांप्रदायिक दंगों को लेकर गांधीजी बेहद चिंतित थे। सीमा-सरहद के इलाकों में हो रहे भीषण नरसंहार को रोकने के लिए गांधी लगातार सक्रिय थे। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजादी का जश्न मना रहा था, गांधीजी नोआखली (बंगाल) में मुस्लिम हमलावरों के सामने अपनी जान हथेली पर लेकर अहिंसा और सद्भाव के लिए संघर्षरत थे। नोआखली के मुस्लिम हमलावरों ने गांधी के पैरों पर अपने हथियार डाल दिए और माफी मांगी। लेकिन एक कट्टरपंथी हिंदू ने 78 साल के बूढ़े गांधी के पैर छूकर उनके सीने में तीन गोलियां उतार दीं। गांधी की हत्या के कारण कुछ समय के लिए आरएसएस पृष्ठभूमि में चला गया। लेकिन नेहरू इन ताकतों को बखूबी समझते थे। 1959 में भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि 'ध्यान रखिए, भारत को खतरा साम्यवाद से नहीं है, बल्कि हिन्दू दक्षिणपंथी साम्प्रदायिकता से है।' 1960 के दशक में पुनः सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। 1980 के दशक में शुरू हुए राम मंदिर आंदोलन ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत का गुबार पैदा किया।

राममंदिर आंदोलन में खुलेआम साम्प्रदायिकता फैलाई गई। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया। इसके बाद देशभर में सांप्रदायिक दंगे हुए, जिनमें हजारों लोग मारे गए। मरने वालों में अधिकांश मुसलमान थे। पॉल रिचर्ड ब्रॉस ने भारत में सांप्रदायिक हिंसा पर गहन अध्ययन किया है। 2004 में उनकी किताब प्रकाशित हुई, जिसका शीर्षक है- 'द प्रोडक्शन आफ हिंदू-मुस्लिम वायलेंस इन कंटेंपरेरी इंडिया'। पॉल ब्रॉस का कहना है कि भारत में 'दंगे भड़काने की एक संस्थागत प्रणाली है'। तीन चरणों में दंगा भड़काने की कार्रवाई की जाती है। पॉल ब्रॉस का निष्कर्ष है कि चुनाव दर चुनाव साम्प्रदायिक दंगों का फायदा दक्षिणपंथी भाजपा को हुआ। साम्प्रदायिक दंगों के कारण मुसलमान बहुत असुरक्षित महसूस करने लगे। 1990 का दशक अल्पसंख्यकों के दमन का काल है। इस दशक में ईसाई अल्पसंख्यकों पर भी अत्याचार बढ़े। ईसाइयों को धर्मांतरण के लिए कटघरे में खड़ा किया गया।

1990 के दशक में सैकड़ों सांप्रदायिक दंगे हुए। इस दशक में विश्व हिंदू परिषद ने जोर शोर से 'घर वापसी' अभियान चलाया। सन 2000 के बाद दंगों की जगह सामूहिक नरसंहार ने ले ली। 2002 में गोधरा ट्रेन आगजनी के बाद गुजरात में बड़े पैमाने पर मुसलमानों का नरसंहार हुआ। भाजपा शासित राज्यों में हिंसा की यह नई शैली विकसित हुई। इतना ही नहीं सीमा पार के आतंकवाद की आड़ में प्रज्ञा सिंह ठाकुर, स्वामी असीमानंद, कर्नल पुरोहित जैसे हिंदुत्ववादियों पर आतंकवादी हमला करने के आरोप हैं। इन हमलों का मकसद मुसलमानों को बदनाम करना और उनको क्षति पहुंचाना था। समझौता एक्सप्रेस और मालेगांव जैसे हमलों में ज्यादातर मुस्लिम मारे गए।

2014 में केंद्र में भाजपा सरकार आने के बाद हिंदुत्ववादी संगठनों की बाढ़ आ गई। गाय के नाम पर मुसलमानों और दलितों की लिंचिंग की गई। लव जिहाद, लैंड जिहाद, कोरोना जिहाद जैसे शब्दों के जरिए मुसलमानों का पैशाचीकरण किया गया। ईसाई चर्चों पर हमले हुए। ननों के साथ बलात्कार की घटनाएं सामने आईं। सरेआम मुसलमानों का नरसंहार करने की मुनादी की जाने लगी। मुस्लिम महिलाओं के बलात्कारियों का स्वागत किया गया। मुस्लिम महिलाओं को अपमानित करने के लिए सुल्ली-बुल्ली ऐप बनाए गए। अल्पसंख्यकों के साथ खड़े होने वाले बुद्धिजीवियों को प्रताड़ित किया गया। मुसलमानों को पाकिस्तानी और आतंकवादी कहना आम बात हो गई। नफरती और हिंसक गिरोहों को कानून का कोई डर नहीं रहा। सत्ता उनके साथ खड़ी नजर आने लगी। इस बीच सीएए के जरिए मुसलमान को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश हुई।

सावरकर का हिंदुत्ववादी एजेंडा देश पर थोपने के लिए बाबा साहब डॉ. अंबेडकर के संविधान को हटाने की मुहिम छेड़ दी गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में 'अबकी बार 400 पार' के नारे के साथ संविधान बदलने का एजेंडा बनाया गया। अल्पसंख्यकों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाना इसका लक्ष्य हो गया। लेकिन अंबेडकर और गांधी, नेहरू के विचारों और मूल्यों पर चलने वाले दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों ने भाजपा को झटका दिया। इस चुनाव में देश के लोगों ने बता दिया कि अल्पसंख्यकों और दलितों-आदिवासियों को गुलाम बनाने की साजिश नहीं चलेगी। जिस राममन्दिर के नाम पर पिछले तीन दशक से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, उस अयोध्या में भाजपा की हार हिंदुत्व की पूरी राजनीति की पराजय बन गई।

समझना होगा नौकरियों के पारिस्थितिकीय यथार्थ को

आज भारत के सामने विकास की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, लाखों बेरोजगारों को अच्छी नौकरियां मुहैया कराना, खास तौर पर ग्रामीण भारत में। यह भी स्पष्ट है कि कॉर्पोरेट पूंजी के बड़े निवेश पर निर्भर 'ट्रिकल डाउन' अर्थव्यवस्था में अडिग विश्वास के साथ 'सामान्य रूप से व्यवसाय' प्रतिमान इन नौकरियों को बनाने में विफल रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि कॉर्पोरेट पूंजी की रोजगार लोच बहुत कम है, जबकि नौकरियों की मांग बहुत तेज गति से बढ़ रही है। कई कारणों से निजी पूंजी का निवेश नहीं हो रहा है, जिसमें एक तरफ घरेलू बाजार के आकार के विस्तार की कमी की ओर इशारा करने वाले संरचनात्मक मुद्दे शामिल हैं, जिसके परिणामस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं की निरंतर कम खपत मांग है, तो दूसरी तरफ नीति के प्रति निजी क्षेत्र की दुविधा और भारत की विकास गाथा के प्रति संदिग्ध प्रतिबद्धता है। सार्वजनिक क्षेत्र भी पर्याप्त नौकरियां नहीं बना सकता। भले ही सभी पीएसयू और सरकारी रिक्तियों को भर दिया जाए, लेकिन नौकरी की समस्या का समाधान कहीं नहीं है। यह और भी गंभीर होने वाली है, विशेष कर ग्रामीण भारत में, जहां बार-बार सूखा और बाढ़ आती रहती है, और इसलिए कृषि क्षेत्र अनिश्चित प्रदर्शन वाला बना हुआ है।

शिक्षित बेरोजगारों को समग्र रूप से देखते हुए नौकरियों की चुनौती को अलग रंग में देखा जा सकता है, विशेष रूप से देश के ग्रामीण इलाकों में फैले लोगों को। ये युवा अब अक्सर कम पेशेवर इनपुट के साथ अजीबोगरीब स्थिति में स्थानीय नौकरियों में आंशिक रूप से स्व-नियोजित हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, कम पूंजी वाले उद्यमशीलता उपक्रमों का समर्थन करने और परिदृश्य को बदलने के लिए नए रास्ते खोल सकते हैं। यह कम पूंजी आधारित लेकिन कुशल स्थानीय विकास प्रक्रिया की क्षमता है। यह प्रक्रिया तथाकथित 'आला संरचना' को देखकर सामूहिक उद्यमशीलता संरचना जैसे नए मॉडल के माध्यम से रोजगार सृजन के वैकल्पिक तरीके की मांग करती है।

प्रो. सुनील रे

एकमात्र उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नीचे से ऊपर तक विकसित करके राज्य की अर्थव्यवस्था को विकसित करना है। इसके लिए एकमात्र रास्ता है सामूहिक उद्यमशीलता संरचना के निर्माण के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में कई कम पूंजी आधारित गतिविधियों के विकास के आधार पर ग्रामीण युवाओं के लिए स्थायी रोजगार और आय का सृजन।

आला संरचना मूल रूप से एक पारिस्थितिक सिक्का है जो प्रजातियों के सह-अस्तित्व को समझाने के प्रयासों के हिस्से के रूप में आया था। सिद्धांत रूप में, एक-दूसरे को बाहर करने की उनकी प्रवृत्ति के बावजूद आला संरचना में अंतर सह-अस्तित्व को स्थिर करने वाले कारकों के रूप में कार्य करते हैं। प्रजातियां अपने आप में आला संरचना बनाकर पर्यावरण को बदल सकती हैं और ऐसा करके, उक्त प्रजाति अपने आप विकसित होती है, लेकिन दूसरों को भी प्रभावित करती है। इसके साथ ही परिवर्तन और विकास को भी प्रेरित करती है।

इस लेखक ने हाल ही में अपनी पुस्तक 'रूटलेज इंडिया' के अध्याय 'डीपनिंग डेमोक्रेसी' में विशिष्ट संरचना के निर्माण के माध्यम से विकेंद्रीकृत स्तर पर रोजगार सृजन में इस पर चर्चा की है, जिसमें कहा गया है कि 'उचित संरचनात्मक परिवर्तन लाने के लिए देश के बहुसंख्यक लोगों के जीवन की भौतिक स्थितियों की गहरी समझ के आधार पर रोजगार सृजन का एक वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य आवश्यक है।'

आर्थिक संदर्भ में समुदाय के भीतर से स्वयं संगठित विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए एक नई सामूहिक उद्यमशीलता संरचना या सामूहिक उद्यम प्रणाली एक आला संरचना की तरह काम करती है। इस तरह की संरचना विनिर्माण, प्रसंस्करण, मरम्मत, निर्माण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा, व्यापार, विपणन, व्यवसाय आदि जैसी सभी प्रकार की गतिविधियों में असंख्य संबद्ध उत्पादकों के स्व-संगठनों को जन्म दे सकती है। वे सामूहिक उद्यम हैं (व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं), लेकिन पारंपरिक अर्थों में महत्वपूर्ण रूप से सहकारी भी नहीं हैं। वे कम पूंजी आधार के साथ काम करते हैं और मुख्यधारा की आर्थिक संरचना के अनुलग्नक के रूप में नहीं, सापेक्ष स्वायत्तता बनाए रखते हैं। यह श्रमिकों की सहकारी समितियों का एक नया आविष्कार है। श्रमिकों का एक स्वतंत्र निर्माण, न कि सरकार या बड़ी पूंजी के संरक्षण में। यह राज्य का समर्थन भी ले सकता है लेकिन पूरी तरह से सचेत रहते हुए कि यह उसके द्वारा शासित नहीं है। यहां, श्रमिक स्वयं मालिक हैं।

महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई व्यक्ति भौतिक संसाधनों के उपयोग और रोजगार सृजन को किस तरह से मापता है। उत्पादन प्रक्रियाओं और सेवाओं को हरित प्रौद्योगिकी के साथ विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। ये छोटे पैमाने के उद्यम हैं, लेकिन ऊर्जा-कुशल, गैर-प्रदूषणकारी और समुदाय-उन्मुख हैं। इनमें हरित प्रौद्योगिकियों में निवेश के माध्यम से स्थानीय रोजगार सृजित करने की क्षमता है। कृषि, प्राकृतिक, मानव और पशु संसाधनों से युक्त स्थानीय संसाधन आधार से पारंपरिक रूप से समझी जाने वाली चीजों से कहीं अधिक स्व-प्रबंधित सामूहिक उद्यमशीलता गतिविधियों की विविधताओं को खोलने के लिए व्यापक गुंजाइश प्रदान करने की उम्मीद है।

इस महत्वाकांक्षी योजना को बहु-चरणीय मॉडल के तहत तैयार किया गया है, जिसकी शुरुआत जिला परिषद में जनप्रतिनिधियों, तकनीकी विशेषज्ञों और सरकारी अधिकारियों की समिति से होती है। इसके बाद स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र और संसाधन आधार पर नई उद्यमशीलता गतिविधियों के लिए कई कृषि जलवायु क्षेत्रों को चिन्हित करने का काम आता है। प्राकृतिक, कृषि तथा पारंपरिक कुशल मानव संसाधनों के अलावा प्रशिक्षित कुशल मानव संसाधनों, बेरोजगार शिक्षित युवाओं, पशु संसाधनों और उनके उप-उत्पादों, विनिर्माण, सेवा व प्रसंस्करण और व्यापार की स्थिति, स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, प्राथमिक विद्यालय से लेकर कोचिंग सेंटर तक की शैक्षणिक सेवाएं, मरम्मत कार्य, कृषि विपणन की स्थिति, पशुओं एवं उनके उप-उत्पादों के विपणन की स्थिति को शामिल करते हुए संसाधन मानचित्रण का काम करना होगा।

गतिविधियों के अच्छे संकेत के साथ सरकार को परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने के लिए एक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए जिसमें उपयुक्त प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान (सीएफटीआरआई), केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (सीएसआईआर), कृषि विश्वविद्यालयों या किसी अन्य तकनीकी-वैज्ञानिक संस्थानों जैसे वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी संस्थानों को शामिल किया जाना चाहिए। मूल उद्देश्य यह पता लगाना है कि इस संबंधित 'पारिस्थितिक' क्षेत्र में कौन सी नई उत्पाद प्रसंस्करण या सेवा लाइनें आ सकती हैं और प्रस्तावित उद्यमशीलता सम्बन्धी गतिविधियों, कृषि और गैर-कृषि दोनों के लिए कौन सी उपयुक्त तकनीक की आवश्यकता है।

आपूर्ति और मांग पक्ष से व्यवहारिकता का अध्ययन, सामूहिक गठन में शामिल होने के इच्छुक बेरोजगार युवाओं की पहचान तथा सार्वजनिक-निजी भागीदारी प्रणाली में बीज पूंजी का निवेश और प्रबंधन किया जाएगा। भले ही प्रारंभिक निवेश आंशिक रूप से सरकार द्वारा किया जाता है, यह सस्ते ऋण के रूप में हो सकता है। यह केवल इस स्तर पर है कि लक्षित कौशल विकास कार्यक्रम इस सामूहिक उद्यम में शामिल होने के इच्छुक लोगों पर गुणात्मक प्रभाव डालेंगे। कौशल विकास के लिए राज्य के पास उपलब्ध बुनियादी ढांचा यहां पूरी क्षमता से काम कर सकता है।

इसका एकमात्र उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नीचे से ऊपर तक विकसित करके राज्य की अर्थव्यवस्था को विकसित करना है। इसके लिए एकमात्र रास्ता है सामूहिक उद्यमशीलता संरचना के निर्माण के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में कई कम पूंजी आधारित गतिविधियों के विकास के आधार पर ग्रामीण युवाओं के लिए स्थायी रोजगार और आय का सृजन। यहीं पर हम भारत सरकार द्वारा अपने बजट में किए गए वादे के अनुसार रोजगार सृजन योजनाओं की अत्यधिक उपयोगिता पा सकते हैं।

राष्ट्रीय बजट में प्रावधान की गई नयी रोजगार सृजन योजनाओं में व्यवहार में इस मॉडल को विश्वसनीयता प्रदान करने के कारण हैं। यह बढ़ती खपत मांग का एक महत्वपूर्ण स्रोत साबित होगा (विशेष रूप से जब छोटे और मध्यम उद्यमों में पिछले कुछ वर्षों से लगातार गिरावट देखी जा रही है), जिसकी कमी निवेश प्रवाह और इसी कारण से रोजगार और रोजगार सृजन को बाधित कर रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो निम्न स्तर के संतुलन के जाल में फंस गई है, तब खुद को बाहर निकालने का रास्ता खोज सकती है।

(लेखक एएन सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान, पटना के पूर्व निदेशक और विकास अध्ययन संस्थान, जयपुर में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। वे दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष और सामाजिक विज्ञान संकाय के डीन भी रह चुके हैं। *सिंडिकेट: द बिलियन प्रेस*)

https://t.me/AllNewsPaperPaid

प्रकाशक, मुद्रक : राजीव रंजन श्रीवास्तव द्वारा पत्रकार प्रकाशन प्रा. लि. के लिए 506, आई.एन.एस. बिल्डिंग, 9, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित एवं बीएफएल इंफोटेक लि., सी 9, सेक्टर-3, नोएडा से मुद्रित। सम्पादक : राजीव रंजन श्रीवास्तव,
(पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार)। आर.एन.आई. नं. DELHIN/2008/24216. दिल्ली कार्यालय :फोन: 011-23718195,23357784, फैक्स: 011-43581404, नोएडा कार्यालय: फोन: 0120-4114404 फैक्स: 0120-4273770
ई-मेल: deshbandhudelhi@gmail.com वेब: www.deshbandhu.co.in

युवा क्रांति के साथ शांति के नये छंद रचें

अन्तर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 अगस्त 2024 पर विशेष

-ललित गर्ग

युवा क्रांति का प्रतीक है, ऊर्जा का स्रोत है, इस क्रांति एवं ऊर्जा का उपयोग रचनात्मक एवं सृजनात्मक हो, इसी ध्येय से सारी दुनिया प्रतिवर्ष 12 अगस्त को अन्तर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाता है। सन् 2000 में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन आरम्भ किया गया था। यह दिवस मनाने का मतलब है कि युवाशक्ति का उपयोग विध्वंस में न होकर निर्माण में हो। युवा, शांति और सुरक्षा पर सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 2250 (9 दिसंबर 2015) शांति को बढ़ावा देने और उग्रवाद का मुकाबला करने में युवा शांति निर्माताओं को शामिल करने की तत्काल आवश्यकता की अभूतपूर्व स्वीकृति का प्रतिनिधित्व करता है, और स्पष्ट रूप से युवाओं को वैश्विक प्रयासों में महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में स्थान देता है। पूरी दुनिया की सरकारें युवा के मुद्दों और उनकी बातों पर ध्यान आकर्षित करें। न केवल सरकारें बल्कि आम-जनजीवन में भी युवकों की स्थिति, उनके सपने, उनका जीवन लक्ष्य आदि पर चर्चाएं हो। युवाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इन्हीं मूलभूत बातों को लेकर यह दिवस मनाया जाता है।

स्वामी विवेकानन्द ने भारत के नवनिर्माण के लिये मात्र सौ युवकों की अपेक्षा की थी। क्योंकि वे जानते थे कि युवा विजनरी होते हैं और उनका विजन दूरगामी एवं बुनियादी होता है। उनमें नव निर्माण करने की क्षमता होती है। नया भारत निर्मित करते हुए नरेन्द्र मोदी को भी युवाशक्ति को आगे लाना होगा। युवा किसी भी देश का वर्तमान और भविष्य हैं। वो देश की नींव हैं, जिस पर देश की प्रगति और विकास निर्भर करता है। लेकिन आज भी बहुत से ऐसे विकसित और विकासशील राष्ट्र हैं, जहाँ नौजवान ऊर्जा व्यर्थ हो रही है। कई देशों में शिक्षा के लिए जरूरी आधारभूत संरचना की कमी है तो कहीं प्रच्छन्न बेरोजगारी जैसे हालात हैं। युवा अनेक विसंगतियों एवं

बुराइयों से घिरे हैं। विशेषतः युवा अपनी वृद्ध पीढ़ी की उपेक्षा के कारण भी निशाने पर है। विश्व की गम्भीर समस्याओं में प्रमुख है नशीले पदार्थों का उत्पादन, तस्करी और सेवन की निरंतर हो रही वृद्धि। युवापीढ़ी इस जाल में बुरी तरह कैद हो चुकी है। आज हर तीसरा युवक किसी न किसी नशे का आदी हो चुका है। अगर यही प्रवृत्ति रही तो सरकार, सेना और समाज के ऊंचे पदों के लिए शरीर और दिमाग से स्वस्थ युवा नहीं मिलेंगे। एक नशेड़ी पीढ़ी का देश कैसे अपना पूर्व गौरव प्राप्त कर सकेगा? इन स्थितियों के बावजूद युवाओं को एक उन्नत एवं आदर्श जीवन की ओर अग्रसर करना वर्तमान की सबसे बड़ी जरूरत है। युवा सपनों को आकार देने का अर्थ है सम्पूर्ण मानव जाति के उन्नत भविष्य का निर्माण। यह सच है कि हर दिन के साथ जीवन का एक नया लिफाफा खुलता है, नए अस्तित्व के साथ, नए अर्थ की शुरूआत के साथ, नयी जीवन दिशाओं के साथ। हर नई आंख देखती है इस संसार को अपनी ताजगी भरी नजरों से। इनमें जो सपने उगते हैं इन्हीं में नये समाज की, नयी आदमी की नींव रखी जाती है। यौवन को प्राप्त करना जीवन का सौभाग्य है। जीने की तीन अवस्थाएं बचपन, यौवन एवं बुढ़ापा हैं, सभी युवावस्था के दौर से गुजरते हैं, लेकिन जिनमें युवकत्व नहीं होता, उनका यौवन व्यर्थ है। उनके निस्तेज चेहरे, चेतना-शून्य उच्छ्वास एवं निराश सोच मात्र ही उस यौवन की साक्षी बनते हैं, जिसके कारण न तो वे अपने लिये कुछ कर पाते हैं और न समाज एवं राष्ट्र को ही कुछ दे पाते हैं। वे इतना सतही जीवन जीते हैं कि व्यक्तिगत स्पर्द्धाओं एवं महत्वाकांक्षाओं में उलझकर अपने ध्येय को विस्मृत कर देते हैं। उनका यौवन कार्यकारी तो होता ही नहीं, खतरनाक प्रमाणित हो जाता है। युवाशक्ति जितनी विराट् और उपयोगी है, उतनी ही खतरनाक भी है। इस परिप्रेक्ष्य में युवाशक्ति का रचनात्मक एवं सृजनात्मक उपयोग करने की जरूरत है।

गांधीजी से एक बार पूछा गया कि उनके मन की आश्वस्ति और निराशा का आधार क्या है? गांधीजी बोले- इस देश की मिट्टी में अध्यात्म के कण हैं, यह मेरे लिये सबसे बड़ा आश्वासन है। पर इस देश की युवापीढ़ी के मन में करुणा का स्रोत सूख रहा है, यह सबसे बड़ी चिन्ता का विषय है। गांधीजी की यह चिन्ता सार्थक थी। मूल प्रश्न है कि क्या हमारे आज के नौजवान भारत को एक सक्षम देश बनाने का स्वप्न देखते हैं? या कि हमारी वर्तमान युवा पीढ़ी केवल उपभोक्तावादी संस्कृति से जन्मी आत्मकेन्द्रित पीढ़ी है? दोनों में से सच क्या है? दरअसल हमारी युवा पीढ़ी महज स्वप्नजीवी पीढ़ी नहीं है, वह रोज यथार्थ से जूझती है, उसके सामने भ्रष्टाचार, आरक्षण का बिगड़ता स्वरूप, महंगी होती जाती शिक्षा, कैरियर की चुनौती और उनकी नैसर्गिक प्रतिभा को कुचलने की राजनीति विसंगतियां जैसी तमाम विषमताओं और अवरोधों की ढेरों समस्याएं भी हैं। उनके पास कोरे स्वप्न ही नहीं, बल्कि आंखों में किरकिराता सच भी है। इन जटिल स्थितियों से लौहा लेने की ताकत युवक में ही हैं। क्योंकि युवक शब्द क्रांति का प्रतीक है।

विचारों के नभ पर कल्पना के इन्द्रधनुष टांगने मात्र से कुछ होने वाला नहीं है, बेहतर जिंदगी जीने के लिए मनुष्य को संघर्ष आमंत्रित करना होगा। वह संघर्ष होगा विश्व के सार्वभौम मूल्यों और मानदंडों को बदलने के लिए। सत्ता, संपदा, धर्म और जाति के आधार पर मनुष्य का जो मूल्यांकन हो रहा है मानव जाति के हित में नहीं है। दूसरा भी तो कोई पैमाना होगा, मनुष्य के अंकन का, पर उसे काम में नहीं लिया जा रहा है। क्योंकि उसमें अहं को पोषण देने की सुविधा नहीं है। क्योंकि वह रास्ता जोखिम भरा है। क्योंकि उस रास्ते में व्यक्तिगत स्वार्थ और व्यामोह की सुरक्षा नहीं है। युवापीढ़ी पर यह दायित्व है कि संघर्ष को आमंत्रित करे, मूल्यांकन का पैमाना बदले, अहं को तोड़े, जोखिम का स्वागत करे, स्वार्थ और व्यामोह से ऊपर उठे। युवा दिवस मनाने का मतलब है-एक दिन युवकों के नाम। इस दिन पूरे विश्व में युवापीढ़ी के संदर्भ में चर्चा होगी, उसके ह्रास और विकास पर चिंतन होगा, उसकी समस्याओं पर विचार होगा और ऐसे रास्ते खोजे जायेंगे, जो इस पीढ़ी को एक सुंदर भविष्य दे सकें। इसका सबसे पहला लाभ तो यही है कि संसार भर में एक वातावरण बन रहा है युवापीढ़ी को अधिक सक्षम और तेजस्वी बनाने के लिए। युवकों से संबंधित संस्थाओं को सचेत और सावधान करना होगा और कोई ऐसा सकारात्मक कार्यक्रम हाथ में लेना होगा, जिसमें निर्माण की प्रक्रिया अपनी गति से चलती रहे। विशेषतः राजनीति में युवकों की सकारात्मक एवं सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करना होगा। अर्नोल्ड टायनबी ने अपनी पुस्तक सरवाइविंग द फ्यूचर में नवजवानों को सलाह देते हुए लिखा है हमारी दम तक जवानी के जोश को कायम रखना। उनको यह इसलिये कहना पड़ा क्योंकि जो जोश उनमें भरा जाता है, यौवन के परिपक्व होते ही उन चीजों को भावुकता या जवानी का जोश कहकर भूलने लगते हैं। वे नीति विरोधी काम करने लगते हैं, गलत और विध्वंसकारी दिशाओं की ओर अग्रसर हो जाते हैं। इसलिये युवकों के लिये जरूरी है कि वे जोश के साथ होश कायम रखें। इसीलिये सुकरात को भी नवयुवकों पर पूरा भरोसा था। वे जानते थे कि नवयुवकों की दिमाग उपजाऊ जमीन की तरह होता है। उन्नत विचारों का जो बीज बो दें तो वही उग आता है। एथेंस के शासकों को सुकरात का इसलिए भय था कि वह नवयुवकों के दिमाग में अच्छे विचारों के बीज बोने की क्षमता रखता था। आज की युवापीढ़ी में उर्वर दिमागों की कमी नहीं है मगर उनके दिलो दिमाग में विचारों के बीज पल्लवित कराने वाले स्वामी विवेकानन्द और सुकरात जैसे लोग दिनोंदिन घटते जा रहे हैं। कला, संगीत और साहित्य के क्षेत्र में भी ऐसे कितने लोग हैं, जो नई प्रतिभाओं को उभारने के लिए ईमानदारी से प्रयास करते हैं? हेनरी मिलर ने एक बार कहा था- मैं जमीन से उगने वाले हर तिनके को नमन करता हूं। इसी प्रकार मुझे हर नवयुवक में वट वृक्ष बनने की क्षमता नजर आती है। महादेवी वर्मा ने भी कहा है बलवान राष्ट्र वही होता है जिसकी तरुणाई सबल होती है। इसीलिये युवापीढ़ी पर यह दायित्व है कि वह युवा दिवस पर कोई ऐसी क्रांति घटित करे, जिससे युवकों की जीवनशैली में रचनात्मक परिवर्तन आ सके, हिंसा-आतंक-विध्वंस की राह को छोड़कर वे निर्माण की नयी पगडंडियों पर अग्रसर हो सकें।

क्या होती है जेपीसी और क्या होते है उसके परिणाम?

अशोक भाटिया

विपक्षी पार्टियों के विरोध के कारण केंद्र सरकार ने वक्फ (संशोधन) बिल, 2024 को संयुक्त संसदीय समिति (खडढ) के पास भेजने की सिफारिश की है। केंद्रीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने 8 अगस्त गुरुवार को लोकसभा में इस संशोधन बिल को पेश किया था। बिल के पेश होते ही विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष का कहना है कि ये बिल संविधान पर हमला है और इससे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। सांसदों ने इस बिल को तुरंत वापस लेने की मांग की। वैसे वक्फ कानून, 1995 में सुधार के दावों के साथ लाया गया ये संशोधन विधेयक पिछले कई दिनों से विवादों में है। सरकार का दावा है कि इस कानून में लंबे समय से बदलाव की मांग हो रही थी। बदलाव के जरिये राज्यों के वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं और गैर-मुस्लिमों को शामिल किए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा मौजूदा कानून की धारा-40 को खत्म करने का भी प्रावधान है। कोई संपत्ति वक्फ बोर्ड की संपत्ति होगी, इस धारा के तहत बोर्ड को ही फैसला लेने की शक्ति दी गई है।

रिजिजू के अनुसार इस बिल में जो भी प्रावधान हैं, आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक किसी रिलीजियस बॉडी का जो फ्रीडम है, उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। न ही संविधान के किसी भी अनुच्छेद का इसमें उल्लंघन किया गया है। इस विधेयक से किसी भी धार्मिक संस्था की स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। हालांकि अपना पक्ष रखने के बाद उन्होंने बिल को जेपीसी के पास भेजने की सिफारिश की। बताया गया था कि अब इस बिल पर चर्चा के लिए स्पीकर ओम बिरला एक संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी का गठन करेंगे। इस कमेटी में सत्ताधारी और विपक्षी दलों के सांसदों को शामिल किया जाता है। ज्ञात हो कि संसद में मुख्य रूप से दो तरह की समितियां होती हैं। 1, स्थायी समिति यानी स्टैंडिंग कमेटी 2, तदर्थ समिति यानी एडहॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी वो होती हैं, जिनका गठन समय-समय पर संसद के अधिनियम की प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियम के हिसाब से किया जाता है। इन कमेटियों का कार्य अनवरत प्रकृति का होता है। यानी काम चलता रहता है।वहीं, कई समितियां तय समय सीमा के लिए गठित की जाती हैं। एडहॉक कमेटी वो होती हैं, जो किसी बिल या मुद्दे की जांच या विशेष प्रयोजन के लिए बनाई जाती हैं। जब ये कमिटी अपनी रिपोर्ट जमा कर देती हैं, तब उनका अस्?तित्?व समा?त हो जाता है। जेपीसी भी इसी श्रेणी में आती है।

जेपीसी में राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के सदस्य शामिल किए जाते हैं।वहीं किसी भी मामले में जेपीसी गठित करने के लिए बाकायदा संसद में एक सदन द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाता है। दूसरे सदन द्वारा इस पर सहमति ली जाती है। जेपीसी गठित होने के बाद सांसदों की टीम मामले की पूरी जांच करती है। पार्टियां अपने सदस्यों के नाम जेपीसी के लिए आगे बढ़ाती हैं और फिर उन्हें अप्रूव किया जाता है।

जेपीसी में सदस्यों की संख्या तय नहीं होती है। सदस्यों की संख्या उस दल की ताकत के हिसाब से देखी जाती है। यानी अगर आज किसी मामले में जेपीसी गठित होती है तो उसमें सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते भाजपा के सबसे ज्यादा सदस्य होंगे। लोकसभा स्पीकर ही कमिटी के अध्यक्ष को चुनते हैं। ज्यादातर समय ये जिम्मा सत्ताधारी पार्टी के सांसद को ही मिलता है।

जेपीसी गठित हो गई तो उसे मामले की गहनता से जांच के लिए विशेषाधिकार मिल जाते हैं। इनका इस्तेमाल कर वो जरूरी जानकारी हासिल कर सकती है। जेपीसी, एक्सपर्ट, सरकारी संस्थाओं और विभागों से जानकारियां हासिल कर सकती है।जेपीसी और अन्य समितियों की सिफारिशों के आधार पर की गई कार्रवाई पर सरकार को संसद में रिपोर्ट पेश करनी होती है। किसी मुद्दे की जांच में अगर सबूत जुटाने के लिए मामले से जुड़े व्यक्ति को कमिटी बुलाना चाहे तो उसे पेश होना होता है। पेश नहीं होने पर उसे संसद की अवमानना मानी जाती है।वहीं, बिल से जुड़े मसलों पर ये कमिटी एक्सपर्ट से सुझाव लेती है। सुझावों या आपत्तियों को कमिटी अपनी रिपोर्ट में शामिल कर सकती है।कमिटी के सुझाव सरकार के लिए सलाह के तौर पर होते हैं। जरूरी नहीं कि सरकार उसे माने ही। चूंकि कमिटियों में ज्यादातर सांसद और अध्यक्ष सत्ताधारी पार्टी के होते हैं, इसलिए अक्सर सुझाव मान लिए जाते हैं।

जेपीसी के गठन के बाद लोकसभा के स्पीकर जेपीसी का एक अध्यक्ष नियुक्त करते हैं, जिसका फैसला सर्वमान्य होता है। आमतौर पर सत्ताधारी पार्टी के सांसद ही जेपीसी के अध्यक्ष होते हैं। बाकी इसमें सभी दलों के सांसद शामिल किए जाते हैं, जिससे निष्पक्ष रिपोर्ट सामने आए। समिति के अधिकतर सदस्य किसी मामले को दबाने की भी कोशिश करते हैं, तो दूसरे सदस्य आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। बोफोर्स केस में ऐसा ही हुआ था, जब एआईडीएमके के सांसद ने जांच के खिलाफ अपना आपत्ति नोट दर्ज कराया था। बिल के यहां पहुंचने के बाद उस पर चर्चा होती है। इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के होने पर रिपोर्ट निष्पक्ष आती है। चर्चा सिर्फ सदस्यों तक सीमित नहीं रखी जाती। इसमें कई पॉइंट्स बताए जाते हैं, जिनकी जांच की जाती है और चर्चा होती है। सम्बंधित क्षेत्र विशेषज्ञों और समूहों को आमंत्रित किया जाता है। इसके अलावा कुछ मामलों में जनता से भी सलाह ली जा सकती है।

समिति का उद्देश्य किसी मुद्दे, विधेयक के प्रावधानों या घोटाले आदि की जांच करना होता है। भारत की संसदीय प्रणाली में जेपीसी एक शक्तिशाली जांच निकाय के रूप में काम करती है। जेपीसी को जिस काम के लिए बनाया जाता है, उससे जुड़े सबूत और तथ्य जुटाने के लिए किसी भी व्यक्ति, संस्था या पक्ष को बुलाने और उससे पूछताछ करने का अधिकार होता है। अगर कोई मामला जनहित का न हो तो आमतौर पर समिति की कार्यवाही और इसके निष्कर्ष को गोपनीय ही रखा जाता है। अमूमन जेपीसी के पास जांच के लिए अधिकतम तीन महीने का समय होता है। इसके बाद यह अपनी रिपोर्ट पेश करते है और इसका अस्तित्व खत्म हो जाता है।

समिति की रिपोर्ट पर कार्रवाई के लिए वैसे तो सरकार बाध्य नहीं होती है पर अगर इसकी सिफारिशों पर कार्रवाई करती है तो इसकी रिपोर्ट सदन को देनी होती है। समितियों की कार्रवाई रिपोर्ट पर संसद में चर्चा हो सकती है और इससे जुड़े सवाल भी उठाए जा सकते हैं। देश के इतिहास में अब तक कई बार जेपीसी का गठन किया जा चुका है। यह जानना भी दिलचस्प है कि पांच बार जेपीसी का गठन करने के बाद सत्तारूढ़ दल अगला चुनाव हार गया।

साल 1987 में स्वीडन की हथियार बनाने वाली कंपनी बोफोर्स के साथ भारत सरकार ने 1437 करोड़ रुपए का एक रक्षा सौदा किया था। तभी वहां की मीडिया में खबर आई थी कि बोफोर्स ने रक्षा सौदों के लिए कई देशों की सरकारों को रिश्वत दी है। इस पर भारत में भी खूब हंगामा हुआ। खुद राजीव गांधी के करीबी मंत्री रहे वीपी सिंह ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। ऐसे में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को बोफोर्स सौदे की जांच के लिए जेपीसी बनानी पड़ी थी, जिसके अध्यक्ष कांग्रेस सांसद बी। शंकरानंद थे। इस समिति ने रिपोर्ट पेश की तो राजीव गांधी को क्लीन चिट दे दी गई थी। इस पर विपक्ष ने काफी हंगामा किया था। इसके बाद साल 1989 में हुए चुनाव में राजीव गांधी को हार का सामना करना पड़ा था, जबकि 1984 में उन्होंने लोकसभा की 414 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। वहीं, बोफोर्स घोटाले को उठाने वाले वीपी सिंह प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए थे

शेयर बाजार में बिग बुल के नाम से मशहूर रहे ब्रोकर हर्षद मेहता साल 1992 में सुर्खियों में आ गए थे। तब आरोप लगा था कि शेयर बाजार में 4000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। मेहता पर आरोप थे कि वह बैंक से कर्ज लेकर शेयर बाजार में पैसा लगाता है और फिर फायदा कमाने के बाद पैसा बैंक को वापस कर देता है। इसके लिए हर्षद और बैंक अधिकारियों के बीच सांठगांठ की खबरें आईं तो शेयर बाजार गिरता चला गया। तब हर्षद मेहता पर 72 आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे। इस पर मेहता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि उसने प्रधानमंत्री को भी एक करोड़ रुपए की रिश्वत दी है। इसको लेकर विपक्ष ने संसद में काफी हंगामा किया। इसके बाद तत्कालीन केंद्र सरकार ने इस मामले में जेपीसी बनाई थी, जिसके मुखिया कांग्रेस सांसद राम निवास मिर्धा थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को इस मामले में क्लीन चिट मिल गई थी पर 1996 के चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था।

साल 2001 में एक और शेयर ब्रोकर केतन पारेख का नाम उछलने लगा। उस पर 2 लाख करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगा था। इससे अहमदाबाद की माधवपुरा मर्केंटाइल सहकारिता बैंक पूरी तरह से डूब गया था। इसका दाग तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार पर भी लगा तो भाजपा सांसद प्रकाश मणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में जेपीसी बनाई गई थी। इस समिति ने सरकार को तो क्लीन चिट दे दी थी पर शेयर बाजार के नियमों में फेरबदल के लिए सिफारिश की थी।

साल 2004 में कोका कोला और पेप्सी जैसी सॉफ्ट ड्रिंक में पेस्टीसाइड की मात्रा अधिक होने का मामला उठा। संसद में भी यह मुद्दा खूब उछला। इस पर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जेपीसी बना दी, जिसका अध्यक्ष विपक्ष के शरद पवार को बनाया गया था। इस जेपीसी ने माना था कि सॉफ्ट ड्रिंक और फ्रूट जूस में पेस्टीसाइड मिलाया जा रहा है। इसके बाद हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था और कांग्रेस की अगुवाई में यूपीए की सरकार बनी थी।

साल 2009-10 में 2जी स्पैक्ट्रम आवंटन में रिश्वत लेने का मुद्दा उठा तो तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा को जेल तक जाना पड़ा। इसी मुद्दे पर कई दिन संसद ठप रही। इसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार ने साल 2011 में जेपीसी बना दी, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस सांसद पीसी चाको को दी गई थी। समिति ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम को क्लीन चिट दी थी पर इस रिपोर्ट का 15 सांसदों ने विरोध कर दिया। इसके बाद साल 2013 में समिति की फाइनल रिपोर्ट आई, जिसमें 2जी स्पैक्ट्रम घोटाले का सारा दोष तत्कालीन दूरसंचार मंत्री पर मढ़ा गया था।

इनके अलावा नागरिकता संशोधन विधेयक-1955 में संशोधन के लिए साल 2016 में लाए गए विधेयक की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया था। इस पर समिति ने देश में अवैध रूप से रहने वाले विदेशियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा करार दिया था। साथ ही उन्हें वापस भेजने की गति बेहद धीमी होने पर चिंता जताई थी। वहीं, साल 2019 में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक संसद में पेश किया गया था। तभी इस विधेयक को जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया था। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य वीवीआईपी के लिए भारत सरकार ने हेलिकॉप्टर खरीदने के लिए अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी के साथ 3,700 करोड़ रुपए से ज्यादा का सौदा किया था। इस पर आरोप लगा था कि कंपनी ने इस सौदे के लिए नेताओं और अधिकारियों को रिश्वत दी थी। इस पर मनमोहन सिंह की सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए साल 2013 में जेपीसी के गठन का प्रस्ताव रखा था, जो राज्यसभा से पास हो गया था पर मुख्य विपक्षी दल भाजपा, जेडीयू और तृणमूल कांग्रेस के बहिष्कार के कारण इसका गठन नहीं हो पाया था।

अराजकता की पराकाष्ठा को लांघ चुके कट्टरपंथी बांग्लादेशी वहशी दरिंदों का आका कौन?

-प्रोफेसर डॉ. सरोज व्यास

मगध साम्राज्य में नंद वंश के सम्राट धनानंद के विषय में कहा जाता है कि वह धन के भंडार भरने का आदी था। एक बार भरी सभा में मद (अहंकार) में अंधे अभिमानी धनानंद ने स्वाभिमानी प्रखर बुद्धिमान एवं ब्राह्मण शिरोमणि, चाणक्य के रंग-रूप एवं वेशभूषा को देखकर उनका उपहास करते हुए अपमानित करके राजमहल से निकाल दिया। उसी समय कौटिल्य (चाणक्य) ने क्रोधित होकर अपनी शिखा (चोटी) खोलकर यह प्रतिज्ञा ली कि जब तक वह नंद वंश का नाश नहीं कर देंगे, तब तक अपनी शिखा नहीं बांधेंगे। किवदंतियों के अनुसार चाणक्य ने एक गरीब चरवाहे के पुत्र की प्रतिभा को देखकर, उसकी माता से उसके लालन-पालन, शिक्षा-दीक्षा और प्रशिक्षण हेतु स्वयं को सौंपे जाने का निवेदन किया। माता की अनुमति से चाणक्य उसे अपने साथ ले गए। धनानंद की सभा में ली गई प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए उन्होंने बालक को राजनीति, कूटनीति और युद्धनीति में पारंगत किया। आचार्य चाणक्य द्वारा प्रशिक्षित उस शिष्य ने धनानंद के साम्राज्य का पतन तथा चाणक्य की प्रतिज्ञा को पूर्ण किया। यह कोई और नहीं, अपितु विक्रमादित्य साम्राज्य के संस्थापक और भारत के अधिकांश भाग को एक शासन के सूत्र में एकीकृत करने वाले पहले शासक चंद्रगुप्त मौर्य (लगभग 321-297 ईसा पूर्व) थे।

चाणक्य को विश्व भर में लोकप्रिय अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और सफल कूटनीतिज्ञ के रूप में याद किया जाता है। शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं - आचार्य चाणक्य के इस कथन की सत्यता पर संदेह नहीं किया जा सकता। व्यक्तिगत और व्यवसायिक स्तर पर विगत 26 वर्षों से अध्ययन-अध्यापन के क्षेत्र में अनेकों ऐसे अनुभव हुए और इस वक्तव्य को धरातल पर चरितार्थ होते देखा। चाणक्य ने स्वयं अपने कथन के एक पक्ष (निर्माण) को शिष्य चंद्रगुप्त के माध्यम से भारत में सत्यापित कर दिखाया।

दूसरे पक्ष (प्रलय) को समझने के लिए बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति को गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। पश्चिमी पाकिस्तान की तत्कालीन सरकार के अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध 26 मार्च 1971 को भारत के सहयोग से एक रक्त-रंजित युद्ध के बाद पूर्वी पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश के रूप में अस्तित्व में आया। वहाँ के संस्थापक और प्रथम राष्ट्रपति बंगबन्धु शेख मुजीबुर्रहमान की पुत्री शेख हसीना 1996 से 2001 और 2009 से 2024 तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के पद पर आसीन रहीं। 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की सेना ने उनको जबरन त्याग-पत्र देने को बाध्य किया। शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ने के लिए मात्र 45 मिनिट का समय दिया गया और उन्होंने भागकर अपनी जान बचाने के लिए भारत में शरण ली` बांग्लादेश में उत्पन्न राजनैतिक संकट और देशव्यापी अराजकता के लिए विश्वपटल पर अमेरिका तथा चीन की भूमिका को भी संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा हैं।

5 अगस्त से निरंतर समाचार-पत्रों, न्यूज चैनलों, साक्षर-निरक्षर, शिक्षित जनसामान्य तथा भारतीय लोकतंत्र का शीर्ष नेतृत्व (प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, विदेशी मंत्री, रक्षामंत्री से लेकर विपक्ष के नेता), बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति पर नजर बनाए हुए है। यद्यपि सामर्थ्य अनुसार प्रत्येक स्तर पर राजनीति तथा कूटनीति पूर्ण सहयोग, सुझाव एवं सहायता भी प्रदान की जा रही है। तथापि वहाँ की भयावह स्थिति का वर्णन करना संभव ही नहीं है। आरक्षण को कम-अधिक किए जाने पर सरकार के विरुद्ध छात्रों का आक्रोश स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, लेकिन जलते, सुलगते, लुटते, पीटते और कटते हुए बांग्लादेश की आरक्षण नीति की यह कैसी परिणीति है ? यदि कुछ हद तक इसे स्वीकार कर भी लिया जाए तो, क्या शेख हसीना के पदच्युत होकर राष्ट्र से जान बचाकर भागने के बाद प्रधानमंत्री आवास में लुटपाट और अमानवीय आचरण सही था ? महिला प्रधानमंत्री के अंतः वस्त्रों को सार्वजनिक रूप से लहराते हुये तांडव करना कहा तक न्यायोचित था ? हिन्दू मंदिरों में (इस्कॉन एवं काली मंदिर) आगजनी, लूट-खसोट एवं बेकसूर बांग्लादेशी हिन्दू नागरिकों की निर्मम हत्या एवं बलात्कार जैसे जघन्य अपराध किस लिए ? अराजकता एवं अन्याय से त्रस्त होकर युद्ध की विभीषिका को झेल कर पाकिस्तान से स्वतंत्र हुये बांग्लादेश को आखिर कौन जला रहा है ? क्या समस्त घटनाक्रम की पटकथा वास्तव में तीन छात्र नेताओं द्वारा लिखी गयी ? नाहिद इस्लाम, आसिफ महमूद और अबू बकर मजूमदार (छात्र नेता) को ढाल बनाकर पलय को गोद में कौन पाल रहा था ?

अनसुलझे प्रश्नों को चिंतन-मनन के लिए सुधी पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ साथ ही एक दृष्टि बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर - राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने संसद को भंग कर दिया और देश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को रिहा। अंतरिम सरकार का गठन हो गया, नोबल पुरुस्कार विजेता अर्थशास्त्री, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस बन गये` उन्होंने न्यूज चैनलों पर दिए गये अपने वक्तव्य मे कहा कि - मैं छात्रों की इच्छा का सम्मान करता हूँ, और उनके आग्रह पर लोकतंत्र की बहाली तथा देशहित में सौंपे गये पद एवं दायित्व को सहर्ष स्वीकार करता हूं। उन्होंने आंदोलन का हिस्सा रहे प्रदर्शनकारी छात्रों को बधाई दी और कहा कि - मैं बहादुर छात्रों को देश को दूसरा विजय दिवस मनाने का अवसर देने पर बधाई देता हूँ। शेख हसीना सरकार ने जनवरी में उन्हें श्रम कानून के उल्लंघन के लिए छह महीने की जेल की सजा सुनाई थी, हालांकि उन्हें जमानत मिल गई थी। बांग्लादेश की सरकार (शेख हसीना) को दिए गये सहयोग और मैत्री के लिए भी उन्होंने भारत की आलोचना की हैं` शायद जनाब यूनुस भूल गये की जिस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख वह बनें है, उसके अस्तित्व की नींव असंख्य भारतीय सैनिकों के बलिदान की ऋणी है।

भारत सनातन संस्कृति का पोषक है तथा सत्य, अहिंसा, त्याग और परोपकार सनातन के मूल मंत्र हैं। इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि चाणक्य के वक्तव्य में व्यक्त प्रकृति के दोनों रूपों में से निर्माण को चाणक्य ने मानवता की रक्षा और सुशासन के लिए चुना। इसके विपरीत, इतिहास गवाह है कि धार्मिक कट्टरपंथियों द्वारा सदैव घर, परिवार और राष्ट्रीय स्तर पर पलय और पतन का मार्ग अपनाया गया है। वर्तमान में बांग्लादेश, पाकिस्तान, यूक्रेन और रूस इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढे लिखे को फारसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं चाहिए।

सब कागज की ही माया

सर्किट हाउस मेंं कुछ नेता बतिया रहे थे कि नर्मदापुरम आध्यात्मिक शहर है किन्तु इस शहर के किस मोहल्ले, गली मकान मेंं आध्यात्म निवास करता है, उसका पता इन निठल्ले उल्लूनुमा नेताओं के पास नहीं था। जैसे इस शरीर मेंं आत्मा है, पर कोई नहीं बता सकता कि वह सिर से लेकर पाँव तक मेंं शरीर के किस अंग, नाड़ी, हड्डी, मांस मज्जा मेंं किस जगह रहती है? यहाँ अनेक साधु संतो का प्रवचन सुना, आपने भी सुना होगा सब ब्रम्हाड का ज्ञान देते है किन्तु ब्रम्ह का पता किसी के पास नहीं है, अगर वे ब्रम्ह्ज्ञानी हैं तो उन्हे ब्र्म्ह जरूर मिलना चाहिए पर मिलता नहीं है। देश मेंं प्रजातन्त्र है नेताओं को देश के विकास के सिवाय कुछ दिखाई नही देता इसलिए वे विकास के सिवाय कुछ नही देखते पर विकास कहाँ हुआ है उन्हे पता नहीं ओर जनता तो अपने गली मोहल्ले से लेकर राजधानी तक विकास देखने निकलती है उन्हे विकास नही दिखाई देता किन्तु नेता

-आत्माराम यादव पीव वरिष्ठ पत्रकार

कि आँखों पर विकास का चश्मा है उसे विकास दिखाई देता है। मेरा नाता अखबार से रहा है, अखबार यानि कागज।आज सारी दुनिया कागज कि दीवानी है, कागज ने सभी को भरमा रखा है, दुनिया मेंं एसा कौन व्यक्ति होगा जिसके मन मेंं कागज न हो। जिसको देखों उसके हाथ मेंं कागज, पाकेट मेंं कागज, घर मेंं कागज तिजोरी मेंं कागज ओर बैंक मेंं कागज। ये सब कागज कि ही माया है जो गांधी छाप कागज कि दीवानी है।

यह देश विचारकों का देश है जहां विचारकों मेंं खुर्राट ओर प्रेक्टिकल किस्म के लोग होते थे जिनके विचारों को राजा लोग मान लिया करते थे। इन्ही विचारकों को मंत्री बनाया जाता ओर उनकी सलाह से राजपाट चलते ओर अनेक राजवंश इन्ही की सलाहों के कारण डूब गए। आज भले राजपाट नहीं है पर मंत्री तो है? मजे की बात यह है की अब मंत्री देश या राज्यों के नही विभागों ओर पार्टी के मंत्री है इसलिए मंत्री की दो किस्में है एक सरकारी मंत्री तो दूसरा जिस संगठन की सरकार हो उस संगठन का मंत्री। देश मेंं मंत्री, प्रदेशों मेंं मंत्री ओर जिलों मेंं प्रभारी मंत्री ओर विरोधी दलों के मंत्री। देश मेंं प्रजातन्त्र है ओर प्रजा को काट्रोल करने के लिए उन्हे रोजी रोटी शिक्षा स्वस्थ्य उपलब्ध कराने के लिए या तमाम मंत्री मधुमक्खी की तरह प्रजा का नीबू निचोड़ शहद भक्षण कर रहे है। मंत्रियो के पास विभाग है, विभाग के पास अफसर है अफसर विभाग को डुबो रहे है ओर मंत्री देश को, यानि विकास होगा भी कैसे? क्या मेरे जैसे पत्रकार या आप जैसे संपादक के आठ कालम का अखवार निकालना, उसमें लिखना ओर प्रजातन्त्र का विश्वास हासिल करने से, नहीं इसका उत्तर खुद प्रजा को पता है जिसके हाथों मेंं प्रतिदिन अखबार होता है ओर अखबार मेंं वे खबरों को तलाशते हो ओर खबर न मिले तब वे समझ लेते है की दे अखबार देश को डुबो रहे नेता के साथ है अथवा विभागों को डुबो रहे अधिकारियों के साथ है।

कागज का विचार प्रजा भी करती है। अखबार कागज का टुकड़ा है अथवा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक की आजादी का फरमान है जिसके दम पर देश डूब रहा हो, विभाग डूब रहे हो ओर कागज के टुकड़ों की उनकी दीवानगी लैला मजनू के प्यार को मात दे जाये तो समझ ले की अखबार सड़े गले कागज के दुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं। अगर अखबार पूँजीपतियों के विज्ञापनों ओर सरकारी विज्ञापनों से शून्य दिखे तो समझ लीजिये कि यह सभी राजनेताओं की कुंडलियों से भयभीत नही ओर वह सच को सच लिखे तो समझ लीजिएगा उस अखवार को इन नेताओं की आंखो से अंगारों की तरह बहने वाली आग का भय नहीं ओर वह आग से सुरक्षित रहने वाले मूषकराज की तरह इनके कान कुतरने को अपना धर्म समझता है। आध्यात्म से बात शुरू हुई थी ओर आध्यात्म के सभी सूत्र ओर सारा ज्ञान प्रजा के लिए है। प्रजा न हो तो आध्यात्म अर्थहीन है ठीक वैसे ही जैसे कागज की माया के बिना सारा जगत लाभ हानी से वंचित हो। अखबार का चरित्र तब उत्कर्ष पर होता है जब वह अपने फर्ज को पूरी निष्ठा से निभाता है। आज अखबार के आगे पीछे कई चुनोती होती है जिसमें मंत्री के आगे मंत्री मंत्री के पीछे मंत्री। आगे मंत्री पीछे मंत्री अर्थात मंत्री पर मंत्री। चाहे वे सरकार के हो या संगठन के, सभी चरित्रवान की तरह छपने के लिए एक अभिनेता की तरह अपना पार्ट अदा करने को तत्पर है। कहना नहीं चाहिए पर यह भी देखा गया है कि जिस तरह नेता एक विचित्र पागलपन मेंं अपने को प्रस्तुत करता है ठीक उसी तरह उसे उठाने के लिए पत्रकार भी कोई कसर नही छोडता है। मंत्रीनुमा नेता के सामने सर सर करते थकता नहीं किन्तु जहां पत्रकार के सम्मान की, अधिकार की बात आए तो ये सभी कन्नी काट लेते है पर माँ वीणापाणि के सच्चे सपूत ये पत्रकार मालिक की डपट सुनकर भी आधे अधूरे वेतन व कमीशन पाकर उनकी जय जयकार करते है। यही पत्रकार का आध्यात्मिक ज्ञान है जिससे वह कागज में डूबा तो रहता है पर कागज के लिए कागज की माया से खुद को बचाए रखता है, किन्तु अपने उन मित्रों के निजी जीवन के विषय में मौन रहता है जो कागज की दीवानगी में कागज को मन में, कागज को दिल में ओर कागज को जिगर मेंं बसाये अपने हाथों मेंं अपनी तिजोरी को गांधी छाप कागजों से भरे रखता है।

दैनिक इबादत सम्पादकीय

दुर्घटनाओं में तय हो जिम्मेदारी

जिस तरह से भीड़ का अपराध या भीड़ में किसने कौन अपराध किया, ये तय कर पाना हमेशा ही दुरूह कार्य होता है। ठीक ऐसा ही होता है किसी भी दुर्घटना के लिए जिम्मेदार आरोपियों को पहचानना और यदि ये सरकारी महकमा हुआ तो ये और अधिक कठिन बल्कि बेहद दुष्कर हो जाता है। एक विभाग का नाम आते ही उसके सहयोगी अन्य किसी न किसी विभाग पर भी उँगली उठती है। जितने विभाग उनके उतने कर्मचारी अधिकारी जो, सभी सम्बंधित हैं या फिर कागजातों में सबके नाम आ जाते हैं। ऐसे में फिर सब एक दूसरे को बचाने में लग जाते हैं। नाले में गिर कर मृत्यु वाले हादसे मामले में मुकदमे की सुनवाई करते हुए आखिरकार न्यायालय को सख्त रुख अपनाना पड़ा है और उसने सीधे सीधे जांच एजेंसी और दोषी संस्थाओं से आरोपियों की पहचान कर उन पर कार्यवाही करने अन्यथा अदालत द्वारा स्वयं आदेश देकर ऐसा किए जाने की सख्त चेतावनी दी गई है। जब दुर्घटनाओं के लिए किसी की जिम्मेदारी तय करने में हम उलझे रह जाते हैं तो फिर दुर्घटना के कारणों और उस दुर्घटना से सीख लेकर भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं न हों इसके लिए विचार और उपाय आदि पर काम करना तो बहुत दूर की कौड़ी होती है। असल में हालात तो ये है कि कोई भी दुर्घटना का समाचार और लोगों का उससे सरोकार भी सिर्फ और सिर्फ तभी तक रहता है जब तक कोई और नई दुर्घटना हमारे सामने नहीं आ जाती। ये देश ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलता रहा है। दिल्ली के कोचिंग सेंटर दुर्घटना मामले को देख कर इसे आसानी से समझा जा सकता है, जहां पुलिस ने जांच के नाम पर कोचिंग संस्थान के गेट को उखड़वा कर उसकी मजबूती जांच परख कर रही है वहीं दोषी के रूप में पकड़ लिया एक वाहन चालक को, बकौल पुलिस जिसकी तेज़ रफ़्तार के कारण ही जलभराव का पानी बेसमेंट में भर गया और छात्र डूब कर मर गए। जांच में कोचिंग संस्थान के मालिक, उस केंद्र के संचालक, मैनेजर, व्यवस्थापक, भवन में अवैध रूप से पुस्तकालय बनाने, इसकी अनुमति देने वाले और ऐसा होते देने रहने वाले तमाम, इन दर्जन भर लोगों को छोड़कर दोषी हुई वो कार जिसके हिचकोले से कोचिंग संस्थान का गेट टूट गया। अदालत ने भी ये सब देखकर पुलिस और जांच एजेंसियों को कड़ी फटकार लगाई। ऐसी ही एक दूसरी दुर्घटना जिसमें दिल्ली नगर निगम ने एक बड़े नाले की मरम्मत करते हुए उसे खुला छोड़ दिया जहां बारिश के जलभराव में एक महिला और उसकी बच्ची की गिर कर मृत्यु हो गई और अभी तक दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम के बीच एक दुसरे को दोषी ठहराने की कवायद जारी है। दुर्घटना के पीड़ितों को आर्थिक सहायता के नाम पर कुछ अनुदान राशि देने की घोषणा और उसके साथ ही दुर्घटना की जांच करने के लिए किसी जांच दल, आयोग का गठन करके रिपोर्ट आने पर दोषियों को बख्शे नहीं जाने का दावा। जबकि असलियत में इन तमाम दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार संस्था, अधिकारी या विभाग तक की पहचान करके उसे क़ानून की चौखट तक ले जाना ही सबसे असंभव कार्य हो जाता है।

बारिश के मौसम में डेंगू का डंक

– बाल मुकुन्द ओझा

बारिश का मौसम अपने साथ कई प्रकार की बीमारियां लेकर आता है। इस मौसम में सबसे ज्यादा मच्छर और कीड़े पनपते हैं। बारिश में डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी हो जाती है। यही कारण है कि प्रतिवर्ष 10 अगस्त को डेंगू निरोधक दिवस मनाया जाता है। यह दिवस लोगों में डेंगू के प्रति जागरुकता फैलाने तथा इसके प्रति सचेत रहने के लिए मनाया जाता है। इसी कारण प्रतिवर्ष मानसून के बाद देशभर में डेंगू के कई हजार मामले सामने आते हैं। डेंगू प्राय: दो से पांच दिनों के भीतर गंभीर रूप धारण कर लेता है।

गर्मियों की शुरुआत के साथ रही घरों में और आसपास मच्छरों की संख्या बढ़ने लगती है। ये मच्छर कई रोग की वजह बन सकते हैं। मच्छरों से डेंगू–मलेरिया फैलता है। खासकर बारिश में डेंगू का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि डेंगू के मच्छर पानी में पनपते हैं। डेंगू एक ऐसी बीमारी है, जिसका इलाज शुरू से नहीं हुआ तो यह जानलेवा हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, हाल के दशकों में दुनिया भर में डेंगू के मामलों में अप्रत्यासित रूप से वृद्धि हुई है। दुनिया की लगभग आधी आबादी अब डेंगू के खतरे में है और हर साल अनुमानित 100–400 मिलियन संक्रमण होते हैं। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है देश में पिछले वर्ष लगभग एक लाख डेंगू के केस दर्ज किये गए। इनमें केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र सहित तीन प्रमुख राज्यों में अधिकतम मामले दर्ज किए गए, जबकि केरल और उत्तराखंड में इस वायरल बीमारी के कारण सबसे अधिक मौतें दर्ज की गईं। जो मच्छरों को नए वातावरण में बेहतर ढंग से अनुकूलित करने और संक्रमण के जोखिम को भौगोलिक रूप से आगे फैलाने की अनुमति देते हैं।

हाल के वर्षों में डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। डेंगू के मामलों में वृद्धि तेजी से शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि, वैश्वीकरण, जलवायु परिवर्तन, सामाजिक–आर्थिक विकास और जीवन शैली में बदलाव के कारण एडीज वेक्टर की शुरुआत के कारण देखी गई है। मौसम परिवर्तन और बीमारियों का चोली दामन का साथ है। तापमान में भी घटत बढ़त होता है। इस वर्ष मौसम के अजब गजब नज़ारे देखने को मिल रहे है। कभी गर्मी कभी आंधी और बारिश तो कभी ठण्ड ने मौसम का मिज़ाज़ बिगाड़ रखा है। इस वर्ष मार्च और अप्रैल में भीषण गर्मी देखने को मिली। मई माह के पहले पखवाड़े में तापमान 45 डिग्री को पार कर गया। इसी के साथ डेंगू जैसी बीमारियां फैलते देर नहीं लगी। यह सर्व विदित है डेंगू मच्छर के कारण फैलता है और मच्छर गंदगी और ठहरे हुए पानी में पनपते हैं, तो आवश्यक है कि अपने आसपास स्वच्छता का पर्याप्त ध्यान रखा जाए।

जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर किसी को तीन से चार दिन तक उल्टी, तेज बुखार और चक्कर आ रहे हैं तो इसे नजरंदाज न करें। तुरंत ब्लड सैंपल की जांच कराएं। जांच में डेंगू की पुष्टि हुई है तो इलाज कराएं। इस मामले में बिलकुल भी लापरवाही न बरतें। डेंगू फीवर जिसे 'हड्डी तोड़ बुखार भी कहां जाता हैं, भारत में तेजी से अपने पैर पसार रहा है। हर साल इस खतरनाक बीमारी के अनियंत्रित हो जाने का मुख्य कारण यह हैं कि इसकी वैक्सीन अभी तक उपलब्ध नहीं हैं। डेंगू की भयावहता का अंदाजा इसी पहलू से लगाया जा सकता है कि समय से उपचार न मिलने के कारण रोगी की मौत भी हो जाती है। विशेषकर जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है वे मौसमी बीमारियों का शिकार हो जाते है। देशभर से मिलने वाली खबरों के मुताबिक मौसम परिवर्तन के साथ ही मौसमी बीमारियां और वायरल बुखार का प्रकोप पैर पसारने लगा है, जिसके चलते चिकित्सालय में मरीजों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। मौसम परिवर्तन के साथ ही सर्दी, खांसी– जुकाम, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, स्क्रब डेंगू, वायरल बुखार, उल्टी– दस्त के रोगियों की संख्या बढ़ी है। मच्छरों का प्रकोप भी बीमारियां बढ़ाने में सहायक हो रहा है। डॉक्टरों के अनुसार तापमान में उतार–चढ़ाव के चलते मौसमी बीमारियां बढ़ी हैं। इस मौसम में जोड़ों में दर्द, बदन दर्द, सिरदर्द, खांसी, जुकाम एवं बुखार होता है। बदलते मौसम में खान पान में सतर्कता रखनी जरूरी है।

(वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर)

व्यंग्य : गलत इंजेक्शन

एक रिसर्च का विषय है ये गलत इंजेक्शन आखिर बनता कौन है ? ये होता कैसा है? दिखने में कैसा लगता है ? निश्चित ही इसकी शक्ल बिलकुल साक्षात् यमराज जैसी ही कुछ होगी ! जो भी फार्मा कंपनी इसे बनाती है,जहाँ से आपूर्ति होती है,उस पर सरकार कार्यवाही क्यों नहीं करती है ? ऐसे कई सवालों के घेरे में सरकार भी आ गयी ! सरकार ने तुरत फुरत इस पर आयोग बिठाया।

– डॉ मुकेश असीमित

शहर का एक निजी अस्पताल आज फिर सुर्खियों में आ गया है। अस्पताल के किसी स्टाफ ने गलत इंजेक्शन लगा दिया है और एक मरीज की मौत हो गई है। ब्रेकिंग न्यूज़ सोशल मीडिया में डालने और अखबार में छपने से पहले ही पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। महीने भर से निठल्ले बैठे गुंडा, मवाली, छुटभैये नेता जी के आदमी, फिरौती एक्सपर्ट, अखबार वाले, अलाना न्यूज़ चैनल और फलाना न्यूज़ चैनल वाले, यूट्यूबिये पत्रकार और फेसबुकिये पत्रकार सभी इस 'मौताना उत्सव' में शामिल है। ऐसे समय में सभी गुट एक साथ मिल जाते हैं और एक निर्गुट सम्मेलन का सा आयोजन होता है।

पक्ष प्रतिपक्ष के समर्थक छुटभैये गले से गला मिलाकर गला फाड़ रहे हैं– डॉक्टर को हिरासत में लो, डॉक्टर हत्यारा है, 'बस एक ही चर्चा है कि मरीज को इंजेक्शन लगा है या नहीं, अगर लगा है तो निश्चित ही गलत इंजेक्शन लगा है। ये निजी अस्पताल वाले जब भी कोई इंजेक्शन लगाते हैं वो गलत ही लगाते हैं, ये तो मरीज की किस्मत होती हैं कि कभी कभार वो ठीक हो जाते हैं, ज्यादातर तो बाबा की भभूत, देसी गाय के गोबर की लीद के लेप, सूअर के घी के सेवन से ही होते हैं, डॉक्टर तो सिर्फ लूटने के लिए गलत इंजेक्शन लगाते हैं, कभी कभार डिस्टिल वॉटर का इंजेक्शन लगा देते हैं लेकिन ज्यादातर गलत इंजेक्शन ही लगाते हैं ! वो तो मरीज की किस्मत है साहब की कई बार वो ठीक हो जाता है। अपना पेट काटकर इन डॉक्टरों का पेट भरकर इलाज कराता है ! ये डॉक्टर लोग तो मरीज की जान लेने में कसर नहीं छोड़ते। क्या करें मजबूरी में इनके पास आना पड़ता है। इससे बढ़िया तो सरकारी डॉक्टर है, मरीज के हाथ ही नहीं लगाते, गलत इंजेक्शन लगाने की तो दूर की बात, मरीज को दूर से ही छूकर पता लगा लेते है कि ये मर्ज यहां ठीक नहीं होने वाला, इसको तो हायर सेंटर रेफर करना पड़ेगा। कोई लोभ लालच नहीं साहब ! ये तो मजबूरी में यहां निजी अस्पतालों में लाना पड़ता है। हायर सेंटर यहां से एक सौ तीस किलो मीटर दूर, बीच में मरीज मर जाएगा तो, लेकिन यहां पर भी मरीज मर जाता है, क्योंकि ये अपना गलत इंजेक्शन तैयार रखते हैं, बस आते ही ठोक देते हैं। बड़ी लूटपाट मचा रखी है साहब, इनसे बढ़िया तो झोला छाप डॉक्टर है बेचारे, गलत इंजेक्शन लगाने का अधिकार केवल उनको है, क्योंकि वो गलत इंजेक्शन लगाते हैं लेकिन बदले में लेते क्या है बेचारे दस या बीस रु का इंजेक्शन। उनके गलत इंजेक्शन में इतनी मारक क्षमता नहीं होती है, दस ठुकवा लो फिर भी। वहां इंजेक्सन एक ही रेट के मिलते हैं, सभी माल दस रु में। रंग बिरंगे इंजेक्सन। देखते ही ठुकवाने का मन करे। निजी अस्पतालों के इंजेक्सन तो देखने में ही डिस्टिल वाटर के से लगते हैं। बोतल में लगाते है तो बोतल के पानी का रंग ही नहीं बदलता। ये झोला छाप हमारे परिवारों से ही आते है, हमारी भाषा बोलते हैं, हामरे जैसे गरीब दीखते हैं, हमारी जात के होते हैं। वहां उधार खाता भी चलता है साहब। फिर इतने सस्ते ठुकवाने में कोई हर्ज भी नहीं है, दस भी ठुकवाएंगे तो भी सौ रु के होंगे ! अगर वहां मरीज मर भी जाए तो भाई जात का मामला है, बिरादरी का मामला है, बेक़सूर है बेचारा, और अगर हो हल्ला करें भी तो बेचारे झोला छाप डॉक्टर से क्या मिलेगा, 'नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या'। गलत इंजेक्शन लगाने का अधिकार सिर्फ इनको है, ये हॉस्पिटल वाले अगर लगाएंगे तो हरजाना देना पड़ेगा। इस देश में जहां सरकार रोजगार नहीं दे रही है वहां आत्मनिर्भर बनना पड़ता है ! ये मौताने पर फिरौती मांगने का धंधा मेक इन इंडिया की तहत स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रूप में दर्ज होना चाहिए। इस पर सरकार को सब्सिडी देनी चाहिए। इस संगठित धंदे के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए, इसमें पुलिस वाले, अखबार वाले, नेता जी के आदमी, सभी अपनी अपनी पार्टनरशिप के द्वारा इसे पनपाएं।

एक दम हो हल्ला बढ़ गया, भीड़ आवेश में आ गई। इसी बीच एक कुख्यात गिरोह जो शहर में 'मौताना मांगने वाला गिरोह 'नाम से प्रसिद्ध है, काफी दिनों से हाथ पे हाथ धरे बैठा था सक्रिय हो गया। उसके कुछ लोग परिजन के पास आ गए, लाश को किसी भी हालत में नहीं उठाने देन की धमकी दे गए हैं। 'हम बात करते हैं डॉक्टर से, तुम्हें बीस लाख दिलवाएंगे तसल्ली रखो।' अंदर डॉक्टर और उसका स्टाफ बंधक बना हुआ है, डील होती है पचास लाख में। दूसरी तरफ पुलिस वाले भी अपनी हथकड़ी की तलवार लिए डॉक्टर की गरदन पर सवार है। अखबार वाले अपने कैमरे और माइक को डॉक्टर और स्टाफ के मुंह में ठूंसकर जुर्म कबूल करने के लिए विवश कर रहे हैं, पुलिस का आधा काम तो मीडिया वाले ही कर देते हैं, ऑन स्पॉट ट्रायल फैसला, कल के अखबार में फैसला हेडलाइन बनेगा, 'डॉक्टर हत्यारा, न जाने कितने मरीजों की ले चुका है जान, गलत इंजेक्शन से एक और मरीज की मौत।' मालमा तय हो गया है, एक दम जादुई परिवर्तन। डॉक्टर साला बड़ा हरामी है यार, इसे गुर आ गए गुरु, कैसे धंधा करना है ! साला इसको पता है एक महीने अस्पताल बंद रहा तो इतना नुकसान होगा, सब कैलकुलेट कर लिया है। अखबार वालों की बदनामी, पुलिस का डंडा अलग, इस से बढ़िया है मामला सेट करो, कल से दुबारा गलत इंजेक्शन लगाने का काम शुरू कर सके। पचास लाख में से बीस लाख परिजन को देकर गिरोह सटक लिया है। पुलिस वालों ने एक हाथ से लेकर दूसरे हाथ से अभयदान दे दिया है। दूसरे दिन चमत्कार हुआ, अखबार में खबर तक नहीं आई, शहर एक बार फिर इस खास ब्रेकिंग न्यूज से वंचित रह गया।

एक रिसर्च का विषय है ये गलत इंजेक्शन आखिर बनता कौन है ? ये होता कैसा है? दिखने में कैसा लगता है ? निश्चित ही इसकी शक्ल बिलकुल साक्षात् यमराज जैसी ही कुछ होगी ! जो भी फार्मा कंपनी इसे बनाती है, जहाँ से आपूर्ति होती है, उस पर सरकार कार्यवाही क्यों नहीं करती है ? ऐसे कई सवालों के घेरे में सरकार भी आ गयी ! सरकार ने तुरत फुरत इस पर आयोग बिठाया। आयोग की रिपोर्ट के विलम्ब पर एक और आयोग बिठाया। आयोग ने जांच के नाम पर सारे फार्मा कंपनियों को हडकाया और जितनी भी कंपनियां इंजेक्शन बनाती है उन्हें सभी गलत इंजेक्शन बनाने का नोटिस थमा दिया ! जबाबी कार्यवाही हुई ! उन्हें सही इंजेक्शन बताने के नाम पर इंजेक्शन बनाने के प्रॉफिट में आधा हिस्सा लेकर उन्हें सही साबित करने की मशक्कत की गयी। रिपोर्ट सरकार को सोंप दी गयी ! रिपोर्ट लोकतान्त्रिक लीक प्रणाली के तहत लीक भी हो गयी, मेरे पास आ गयी है, सोर्स अज्ञात है, अब आपको आम खाने हैं या पेड़ गिनने है तो आप रिपोर्ट पढ़ें ' फार्मा कंपनी जो इंजेक्शन बना रही हैं वो तो सही बना रही हैं, ये निजी अस्पतालों में, खासकर छोटे अस्पताल जो छोटे शहर और कस्बों में चल रहे हैं, वहां इनमें मिलावट की जाती है, वहां जाकर ये सभी गलत इंजेक्शन हो जाते हैं। साफ साफ इसमें निजी अस्पतालों की मिली भगत की बू आ रही है। बाकी सरकारी अस्पताल में तो इंजेक्शन सड़ रहे हैं, वहां तो कोई लगाता ही नहीं है, वहां से भी ये निजी अस्पतालों में सप्लाई हो रहे हैं इनके गलतीकरण के लिए।'

(लेखक अस्थि एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ हैं तथा व्यंग्य, संस्मरण और हास्य रचनाएं भी लिखते हैं, गंगापुर सिटी, राजस्थान)

आपातकाल में भी देश ने आपा नहीं खोया तो अब क्या खोएंगे ?

– गुलाब कुमावत खीमेल

आजाद भारत में पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा लगाया गया आपातकाल शायद ही कोई हिंदुस्तानी भूल पाया हो और कोई भूल पाएगा। दर्द तो तब होता है जब लोकतंत्र और संविधान की दुआई देने वाले ही खुद आपातकाल थोपने वाले हो और जनता के सामने अपने आपको सबसे ज्यादा संविधान का रखवाला बताने का स्वांग रचते हो.... जेलों में ठुसना और कलम पर पहरा कौन भुला है। आपातकाल से ज्यादा लोकतंत्र पर करारा प्रहार और क्या हो सकता है।

इससे ज्यादा देश की क्या विडंबना हो सकती है। देश में लोकतंत्र की मजबूती देखिए.... आपातकाल थोपने के बाद भी वो पार्टी आज भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की भागीदार बनी हुई है जो सुखद संकेत है। लोगो को पता है की गुलामी और तानाशाही क्या होती है। हिंदुस्तान ने गुलामी भुगती है इसलिए अपने लोकतंत्र को कभी कमजोर होने नही दिया और आगे भी नही होने देंगे। जटिल परिस्थितियो में अपनी बात भी रखी, आंदोलन किए, सरकारों को वोट की चोट से हराया और मजबूत विपक्ष भी दिया लेकिन सब कुछ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत न तो किसी के उकसावे में आए और न ही किसी के बहकावे में... कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद और सज्जन कुमार के अलावा विपक्ष के कई नेता बांग्लादेश में भड़की हिंसा की आड़ में अपनी राजनैतिक रोटियां सेंकने पर उतारू है पर उनको पता नही आपके आकाओं ने आपातकाल थोपा तब भी देश ने आपा नही खोया था। बांग्लादेश में वर्तमान हालातो की तुलना हमारे देश से करना मानसिक दिवालियापन और ओछी मानसिकता ही दर्शाता है। बांग्लादेश के युवाओं ने जो हिंसक प्रदर्शन किया क्या हम उसका समर्थन कर रहे है। अगर कर रहे है तो यह हमारे संविधान की रक्षा नही उसका हम पतन कर रहे है। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ वो भी हिंसक घटनाओं के सहारे इसका सभ्य समाज शायद समर्थन नही करेगा। हिंदुस्तान का युवा अपनी बात रखते समय अपने राजनेताओं के आचरण को भी ध्यान में रखता है। पिछली सरकारों ने महंगाई और कितने युवाओं को रोजगार दिया यह हर युवा जानता है।

राजस्थान में दस दिन में कर्जा माफ करने की घोषणा करने वाले पांच साल राज करके घर चले गए। किसानों को एम एस पी देने का राग अलापने वाले राजनेता अपने प्रदेशों में अपनी सरकारों से नही दिलवा पा रहे है। वर्तमान प्रधान मंत्री खुद गुजरात के मुखमंत्री रहते किसानों को उनकी फसल का न्यून तम समर्थन मूल्य देने के पक्ष में थे पर अब क्यों मुकर रहे है यह समझ से परे है। बेशक मोदी सरकार महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर विफल रही तो जनता ने भू नही बक्शा और लोकतांत्रिक तरीके से नकेल कस दी। हिंदुस्तान न तो बांग्लादेश जैसे हालातो से गुजरेगा न ही कोई संभावना है। विपक्ष को आग में घी डालने की बजाय अपनी सोच मजबूत करनी होगी अन्यथा आने वाले चुनावों में जो सीटे आई वो भी कही कम न हो जाए। सरकार और विपक्ष दोनों को लोकतंत्र की मजबूती पर जोर देना चाहिए।

बेतुके बयान देने वाले राजनेताओं को भी अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए.... राजनेताओं को यह बात ध्यान रखनी चाहिए की आपको बोलने की आजादी है जहर घोलने की नही है। हिंदुस्तान गुलामी और आपातकाल दोनो दौर से गुजर चुका है इसलिए उसे कैसे और कब, किस समय, किसको क्या सबक सिखाना है यह अच्छी तरह से पता है। लोकतंत्र मजबूत है और वो रहेगा। किसी सरकार की नीतियों से न तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमजोर होगी न होने वाली है।

(लेखक वरिष्ठ राजनैतिक विश्लेषक है, सांचौर, राजस्थान)

कविता

हर तरफ़ गिद्ध ही गिद्ध बैठे हैं

एक युवा दे रहा
इस उम्मीद में
साक्षात्कार।
उसका होगा चयन,
मिलेगा नौकरी का
उपहार।
पूछ रहा था समय,
होकर वो निर्भय।
नौ घंटे का उसे
समय देना हैं,
चार अंकों में
सैलरी पाना है।
ज़ब जाहिर हुई शर्तें,
तब खुली अंदर की
परतें।
अवकाश लेने की,
हमें पूर्व सूचना देनी
होगी।
गर पाँच मिनट देरी हुई,
तब एक छुट्टी कट
जाएगी।
बिना सूचित किए
अगर की छुट्टी तो
दो दिन की
तनख्वाह लेंगे हम
काट,
माह के अंत में लेंगे बाँट।
क्योंकि पीएफ भारी हैं,
दोनों तरफ़ का लेंगे काट।
युवा ने सोचा सभी
एक से एक सिद्दहस्त
बैठे हैं,
ये सभी नियोक्ता नहीं।
नोचने को यारों
हर तरफ़ गिद्ध ही
गिद्ध बैठे हैं।

संजय एम. तराणेकर
(कवि, लेखक व समीक्षक, इंदौर, मध्यप्रदेश)

आबादी के लिहाज़ से छोटे से मुल्क ऑस्ट्रेलिया की अकेली खिलाड़ी एम्मा मैकेन ने टोक्यो ओलंपिक-2021 में 4 गोल्ड व 3 ब्रॉन्ज़ मैडल जीते। ऑस्ट्रेलिया में उसे कोई पूछने तक नहीं आया,क्योंकि वहां के लोगों या सरकार के लिए या राजनेताओं के लिए यह उपलब्धि कोई खास मायने नहीं रखती। और दूसरी तरफ हम 140 करोड़ भारतीय सिर्फ एक मैडल पर ही पागल हुए जा रहे हैं। एक-एक मेडल के लिए तरसते; इस देश में जब हमारे स्टार खिलाड़ी सब कुछ मिलने के बाद राजनीति का स्वाद भी लेना चाहते हैं तो मन खट्टा हो ही जाता है।

स्टार बनने की चाह में मैडल के लिए तरसते हम

– प्रियंका सौरभ

ओलिंपिक 2024 में सभी देशों को टक्कर देता इकलौता विश्वविजेता देश जापान आज हम सभी के लिए ज्योतिपुंज है। 14 साल का जापानी युवा गोल्ड मेडल ला रहा है और हम, 140 करोड़ आबादी का देश एक मैडल पर राजनीति श्रेय लेने की होड़ में वाह –वाही कर रहे हैं। हर खिलाड़ी की व्यक्तिगत जीत देश के लिए न्यौछावर है लेकिन हम कहाँ हैं ये जानना ज़रूरी है मैडल लिस्ट में। जहां कॉलेज और स्कूल स्टूडेंट्स ओलंपिक मैडल ले आते हैं उनको बचपन से फोकस, ज़िम्मेवारी और निपुणता कैसे लानी है सिखाया जाता है।

आज तक के हर ओलंपिक की यह तस्वीर आप खुद देखिए अब आगे क्या कहूं? एक–एक मेडल के लिए तरसते इस देश में जब हमारे स्टार खिलाड़ी सब कुछ मिलने के बाद राजनीति का स्वाद भी लेना चाहते हैं तो मन खट्टा हो ही जाता है। देश की हालात देखिये ओलिंपिक में मेडल के लिए तरसते है और कोई एक मेडल जीत जाए तो राजनीतिक लाभ लेने के लिए पैसो की बारीश कर देते है लेकिन जो खिलाडी अभ्यास कर रहे होते है उनके लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराते। भारत जैसा देश शायद ही कोई दूसरा होगा। इन्ही कारण से आज देश के सफल लोग देश छोड़े जा रहे है। अपने देश मे योग्यता तो जन्म के साथ जाति विशेष मे पैदा होने से ही आ जाती है, 9वीं फेल भी जाति आधार पर योग्यता के सर्टिफिकेट बांटते मिल जायेंगे लेकिन 140 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या वाला देश 1947 मे देश की आजादी के बाद भी ओलम्पिक जैसे विश्व स्तरीय खेलो मे एक एक गोल्ड मैडल के लिए तरसते आए है जबकि वहाँ कोई रिजर्वेशन भी नहीं है कि योग्यता के ठेकेदार लोगों को रोक रखा हो। हे महानुभावो, जिस फितुर को आप योग्यता मान रहे हो, असल मे तो वो देश की सामूहिक बदनामी है और हजारो अयोग्यताओ की जड़ है।

जातियों मे महानता खोजना योग्य नहीं अयोग्य लोगो की पहचान है। ये जो ग्रेट सजाति बनने की बीमारी लोगों मे लगी है, ये कोढ़ से भी ज्यादा घातक है। कोढ़ तो शरीर पर हमला करता है, जातियो मे महानता तो सीधा दिमाग मे कोढ़ लगाता है। आदमी कब नफरत का आदी हो जाता है, कब अपराधी होने मे गर्व तलाशने लगता है – पता भी नही लगता। खिलाड़ी एक खिलाड़ी होता है और देश का प्रतिनिधित्व करता है फिर क्यों एक विशेष जाति के नारे हावी हो जाते है। यहीं हम हार जाते है। पता नहीं हम कब सुधरेंगे ? आबादी के लिहाज़ से छोटे से मुल्क ऑस्ट्रेलिया की अकेली खिलाड़ी एम्मा मैकेन ने टोक्यो ओलंपिक–2021 में 4 गोल्ड व 3 ब्रॉन्ज़ मैडल जीते। ऑस्ट्रेलिया में उसे कोई पूछने तक नहीं आया,क्योंकि वहां के लोगों या सरकार के लिए या राज नेताओं के लिए यह उपलब्धि कोई खास मायने नहीं रखती। और दूसरी तरफ हम 140 करोड़ भारतीय सिर्फ एक मैडल पर ही पागल हुए जा रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर सहित तमाम छुटभैये नेता रोटियां सेंक रहे हैं। इस एक मैडल की आड़ लेकर जात धर्म के ठेकेदार ज़हरीले नाग बेख़ौफ़ फुंफकारते घूम रहे हैं। ऐसा यूँ है कि इस देश में चढ़ते सूरज को नमस्कार किया जाता है। गरिमा, गौरव और प्रतिष्ठा के बिना ही यहाँ जीवन चलता रहता है। आज भी यहाँ चीन का सामान खरीदा जाता है। जो फिल्मी कलाकार तुर्की जाकर शूटिंग करते हैं उनका बहिष्कार तक करने की किसी की हिम्मत तक नहीं होती है। यहाँ विदेशी लुटेरों को पूजा जाता है। विदेशी आक्रांताओं के अधीन रहने से हमें तिल–तिल कर मरने की आदत पड़ गई है। इसीलिये सत्ता के विरुद्ध आवाज उठाना नहीं आता है। जो भी हो रहा है वो सब भगवान की मर्जी मान कर जीने की कला सीख ली है। शत्रुता या मारक भाव के अभाव के कारण पता ही नहीं चलता कि कौन हितैषी है और कौन विद्वेषी। विश्वसनीयता के नाम पर हम हमेशा देश हित से ऊपर जाति, वर्ग, धर्म, परिवार–कुटुम्ब, गाँव, प्रदेश, क्षेत्र, सम्प्रदाय, व्यवसाय और व्यक्तिगत लाभ को रखते हैं। खिलाड़ी जीत कर आयें तो उन्हें करोडों मिलते हैं, लेकिन जो देश की रक्षा के लिए अपने परिवार की परवाह न करते हुऐ अपनी जान न्यौछावर कर दें उन्हें बस 1 मैडल..? मैं मैडल की तुलना पैसों से नहीं कर रहा हूँ, यह तो अनमोल है, लेकिन जो देश के लिए अपने घर वालों को छोड़कर चला गया उनकी फैमली बच्चे माता पिता की ज़िम्मेदारी किसकी..? सच तो ये है कि, आज पैसों से ही सब होता है। भावनाओं और सम्वेदनाओं से जीवन यापन नहीं किया जा सकता.. यह भी सत्य है कि दोनों चाहे खिलाड़ी हो या जवान देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। फिर उनके साथ ऐसा अन्याय क्यों..? सिस्टम को सोचने की ज़रूरत है। खिलाडियों को खिलाड़ी रहने दें। युद्ध के नायक न

बनाए।

(रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस, कवयित्री, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार, उब्बा भवन, आर्यनगर, हिसार (हरियाणा)

भारतीय गगन यात्री शुभांशु शुक्ला का चयन

– मनमोहन राजावतराज, शाजापुर

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारत के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का चयन अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए किया है जो भारत अमेरिकी मिशन पर आगामी उड़ान भरने के लिए अंतरिक्ष में जाएंगे, ऐसी घोषणा इसरो ने की है अत: हम उन्हें बधाई देना चाहते हैं इसके पूर्व भी रूस द्वारा भेजी गई अंतरिक्ष उड़ान के लिए राकेश शर्मा का चयन किया गया था जिसके अंतर्गत फिर उन्होंने अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा भी की थी तब उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पूछने पर कि वहां से भारत कैसा दिखाई देता है, राकेश शर्मा का कहना था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा। अब गगन यात्री शुभांशु शुक्ला इसी सप्ताह मिशन के लिए प्रशिक्षण शुरू करेंगे। इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र का आगामी एक्सि ओम–4 मिशन के लिए अमेरिका स्थित एक्सि ओंम स्पेस के साथ समझौता हुआ है। विदित हो कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले फरवरी में भारतीय अंतरिक्ष मिशन से संबंधित यात्रियों के नाम की घोषणा की थी जिसके कारण हमारे यहां चार अंतरिक्ष यात्रियों का चयन इसरो के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन के तहत पृथ्वी की निचली कक्षा में भारत अंतरिक्ष मिशन के तहत जाने वालों के नामों की घोषणा की भी गई थी परंतु यह उड़ान तो अमेरिकी भारत सहयोग से होने जा रही है, यानी हमारा मिशन भी आगामी समय में संभावित है, अत: तब हम अपने भारतीय गगन यात्री शुभांशु शुक्ला को इस भारत अमेरिकी मिशन पर उड़ान भरने के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं यह राकेश शर्मा के बाद अब दूसरे यात्री बनेंगे जो अंतरिक्ष में जाने वाले हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

कैसे देश जीतेगा जंग नशे के खिलाफ

आर.के. सिन्हा

आज भारत बुरी तरह से नशे की समस्या से जूझ रहा है। यह बेहद जटिल और बहुआयामी मुद्दा है जो देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक ताने बाने को क्षति पहुँचा रहा है। नशीली दवाओं की लत लगातार बढ़ने से निजी जीवन में अवसाद, पारिवारिक कलह, पेशेवर अकुशलता और सामाजिक सह-अस्तित्व की आपसी समझ में कमी की समस्याएं सामने आ रही हैं।

भारत में सिगरेट और बीड़ी पीने का सिलसिला न जाने कब से चल रहा है। इनके पैकटों पर वैधानिक चेतावनी देने का भी कोई असर नहीं हुआ। अब सूखा नशा लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। यह एक ऐसी बुराई है जो व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति को पूरी तरह से बिगाड़ देती है। यह आदतें न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि समाज के ताने बाने पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। विभिन्न स्रोतों और सर्वे के नतीजे बताते हैं कि राजधानी दिल्ली में ही कम से कम 10 से 20 फीसदी युवा नशे की चीजों के आदी हो चुके हैं। सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंध के बावजूद इसको रोकने के लिए अभी तक की गई कोशिशें नाकाम साबित हुई हैं।

नशे की गिरफ्त में आकर लोग अक्सर अपनी जिम्मेदारियों को लापरवाही पूर्वक नजरअंदाज कर देते हैं। इसके प्रभाव से बचने के लिए उचित शिक्षा और सक्रिय जागरूकता की परम आवश्यकता है। साथ ही नशे के खिलाफ ठोस आन्दोलन प्रयास करने की भी जरूरत है। केवल व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास ही इस समस्या को समाप्त कर सकते हैं। अकेले, सरकार के बस का तो यह होने से रहा। आपको देश का शायद ही कोई शहर मिले, जहां के अत्यधिक सुरक्षित क्षेत्रों, हाई प्रोफाइल इलाकों और एलीट जोनों, बड़े मार्केटों में नशा उपलब्ध न हो। नशे पर पूरी तरह से बैन ही नहीं लग पा रहा है। राजधानी दिल्ली तो नशे के कारोबार का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। इसके पीछे नशीले पदार्थों की आसान उपलब्धता तथा गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक तनाव के चलते हो रहे डिप्रेशन को कम करने में मदद मिलने जैसी बड़ी वजह भी है। इसके साथ ही मौजूदा पारिवारिक ढांचा और शिक्षा की कमी से हो रहे भटकाव तथा अज्ञानता भी नशे को बढ़ावा देने में मददगार बन रहा है। इसका सबसे बुरा असर हमारे कम उम्र के स्कूल और कॉलेज जाने वाले लड़के-लड़कियों पर भी बुरी तरह पड़ रहा है। थोड़ी सी मस्ती, अति उत्साह और सामाजिक आचार-विचार के प्रति बेरुखी के चलते खुद को बिंदास, बेपरवाह दिखाने के लिए ड्रिंक्स, स्मोकिंग, च्युइंग एडिक्शन जैसी आदतें अपनाने को वह अपने को आधुनिक और प्रगतिशील सिद्ध करने के लिये जरूरी मान बैठे हैं।
दिल्ली और देश के शेष भागों में सूखे नशे में केवल तंबाकू या गुटखा ही नहीं इस्तेमाल हो रहा है। तस्करी चोरी के जरिए बड़े पैमाने पर गांजा, हेरोइन, स्मैक, चरस, कोकेन, मिथाइलीनडाइऑक्सी मेथाम्फेटामाइन (एमडीएमए), एक्स्टसी सिंथेटिक टैबलेट और पाउडर, मेफेड्रोन पाउडर और कैप्सूल तथा कोडीन मिला हुआ कफ सिरप को भी लाकर भी बेचा जा रहा है। एमडीएमए एक तरह का सिंथेटिक ड्रग है, जो उत्तेजक और बुद्धिभ्रष्ट कारक है। इस ड्रग के इस्तेमाल मात्र से शरीर पर बदलाव आने लग जाते हैं। सिंथेटिक ड्रग्स का उदय एक महामारी के रूप में हो रहा है जो कई लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही है, खासकर युवा लोगों को नए जमाने में सुरक्षा के नाम पर ई-सिगरेट का भी प्रचलन भी बढ़ता जा रहा है। इसमें धुआं भले ही न हो, लेकिन निकोटीन होने से स्वास्थ्य के लिए नुकसान में जरा सी भी कमी नहीं है।

राजधानी के प्रतिष्ठित गंगा राम अस्पताल दिल्ली में वरिष्ठ चिकित्सक, मेडिसिन डॉ. मोहसिन वली कहते हैं, ₹भारत में तंबाकू सेवन करने वालों, विशेष रूप से धूम्रपान करने वालों की बढ़ती संख्या के चलते इस पर नियंत्रण के लिए बनाई गई नीतियों की तुरंत समीक्षा की जरूरत है। निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी (एनआरटी), गर्म तम्बाकू उत्पाद (एचटीपी) और स्नस (धुआं रहित तंबाकू) जैसे वैज्ञानिक रूप से सुरक्षित विकल्पों के इस्तेमाल से नशे पर रोक लगाने में महत्वपूर्ण कामयाबी मिली है। हालांकि एनआरटी को मेडिकल स्टोर पर केवल डॉक्टरों के प्रिस्क्रिप्शन पर ही लिया जा सकता है, जिसके कारण इसकी सरल उपलब्धता अब मुश्किल हो गई है। अब इसे सीधे कोई आसानी नहीं ले सकता है।' जानकारों का कहना है कि अधिकांश लोग एनआरटी का उपयोग तब बंद कर देते हैं, जब उन्हें लगता है कि अब उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है। एनआरटी में निकोटीन की मात्रा सिगरेट की तुलना में वैसे तो कम होती है। निकोटीन को मस्तिष्क तक पहुँचने और इंसान को निकोटीन का प्रभाव देने में भी काफी समय लगता है। इसका मतलब यह है कि धूम्रपान छोड़ने की तुलना में एनआरटी का उपयोग बंद करना बहुत आसान है। सबसे बेहतर बात ये है कि एनआरटीके साइड इफेक्ट भी ज्यादा खतरनाक नहीं हैं।

इसके साथ ही अब गुटखा को खाने वालों की तादाद चक्रवद्धि ब्याज की रफ्तार से बढ़ती ही चली जा रही है। इसमें तंबाकू की कितनी मात्रा हो, इसको लेकर कोई गाइडलाइंस नहीं है। इसको खाना अगर जरूरी ही है तो बिना तंबाकू वाले इसके इलायची आदि के स्वादिष्ट फ्लेवर क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं, जिससे इसको खाने का मजा तो आए, लेकिन स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर नहीं पड़े।

कुछ समय पहले राजधानी के बीएलके-मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट, पल्मोनरी मेडिसिन डॉ. पवन गुप्ता कह रहे थे-, 'सबसे गंभीर बात यह है कि आम लोगों में तंबाकू का प्रचलन बढ़ रहा हैं, क्योंकि देश भर में सड़क के आसपास बनी दुकानों में तंबाकू आसानी से उपलब्ध है। मौजूदा सरकारी नीतियां तंबाकू के बढ़ती लत को रूकवाने में विफल रही हैं। अब इस मसले को रोकने के लिए विकसित देशों में अपनाए गये वैज्ञानिक रूप से सुरक्षित विकल्पों पर विचार करना जरूरी है। इससे तंबाकू के सेवन पर रोक लगाने में कारगर सफलता मिल सकती है।'
आज भारत बुरी तरह से नशे की समस्या से जूझ रहा है। यह बेहद जटिल और बहुआयामी मुद्दा है जो देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक ताने बाने को क्षति पहुँचा रहा है। नशीली दवाओं की लत लगातार बढ़ने से निजी जीवन में अवसाद, पारिवारिक कलह, पेशेवर अकुशलता और सामाजिक सह-अस्तित्व की आपसी समझ में कमी की समस्याएं सामने आ रही हैं। मुझे लगातार इस तरह के परिवारों के बारे में पता चलता है जो अपने किसी सदस्य के नशे का दास बनने से परेशान है। हमारे युवा नशे की लत के ज्यादा शिकार हो रहे हैं। युवावस्था में करियर को लेकर एक किस्म का दबाव और तनाव रहता है। ऐसे में युवा इन समस्याओं से निपटने के लिए नशीली दवाओं का सहारा लेता है और अंततः नशे के कुचक्र में फंस जाता है। इसके साथ ही युवा एक गलत पूर्वधारणा का भी शिकार होते हैं। उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर धुएँ के छल्ले उड़ाना और महँगी पार्टीज में शराब के सेवन करना उच्च सामाजिक स्थिति का प्रतीक भी जान पड़ता है। दरअसल नशे के बढ़ने के कई आयाम हैं। इसके खिलाफ सारे देश को मिलकर लड़ना होगा। वर्ना तो नशे की लत का विस्तार जारी ही रहेगा।
(लेखक वरिष्ठ संपादक, स्तंभकार और पूर्व सांसद हैं)

संपादकीय

सदमे में भारत

भारतीय खिलाड़ियों के एक-के-बाद एक पोड़ियम पर चढ़ने से पहले ही हारने से देशवासियों में बनती जा रही मायूसी को विनेश फोगाट की घटना ने दोगुना कर दिया है। मनु भाकर के दो कांस्य पदकों सहित निशानेबाजी में तीन पदक आने से देश में खुशी का जो माहौल बना था; वह दिग्गजों के फ्लॉप शो की वजह से ठंडा पड़ता जा रहा था। इस बीच विनेश फोगाट के महिला कुश्ती ने किए प्रदर्शन देश का माहौल फिर से खुशनुमा बना दिया था। एक ही दिन में वह लगातार तीन मुकाबले जीतकर 50 किग्रा वर्ग की कुश्ती के फाइनल में पहुंच गई थीं। वह यह उपलब्धि पाने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान थीं। उन्होंने जिस तरह से टोक्यो ओलंपिक की स्वर्ण पदक विजेता और 82 मुकाबलों से अजेय बनी हुई सुसाकी को पहले राउंड में हराया, उससे देशवासियों को पहली बार सोने का तमगा आने का भरोसा हो गया था, लेकिन सौ ग्राम वजन ज्यादा आने पर उन्हें अयोग्य करके पदक से ही वंचित किए जाने से देश में सदमे जैसी स्थिति बन गई है। हालांकि अभी विनेश के सीएएस में अपील करने से रजत पदक मिलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। अब सवाल यह है कि इतने देखभाल करने वालों के रहते वजन कैसे बढ़ गया? इस बात की जांच भी होनी ही चाहिए। हम सभी जानते हैं कि विनेश 53 किग्रा वर्ग में लड़ती रहीं हैं। वह वजन घटाकर इस वर्ग में लड़.रहीं थीं। इस तरह की खिलाड़ी का तो और भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए थे। विनेश को बहुत ही पक्के इरादे वाली पहलवान माना जाता है। यह वह कुश्ती फेड़रेशन के अध्यक्ष के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला चलाकर दिखा चुकी हैं। इसके अलावा कभी कोई घटना उन्हें विचलित नहीं कर सकी। पर इस घटना ने उन्हें एकदम से तोड़.दिया है और इस कारण उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इन हालात में देश के माहौल को अब पुरुष हाकी में कांस्य पदक और नीरज चोपड़ा का जेवेलिन में स्वर्ण पदक ही खुशनुमा बना सकता है। इससे पदक तालिका में भारत की स्थिति थोड़ी.सम्मानजनक हो जाएगी। अन्यथा हम 2016 के रियो ओलंपिक जैसे प्रदर्शन की तरफ बढ़ ही रहे हैं। रियो में भारत एक रजत और एक कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में 67वें स्थान पर रहा था। निश्चित रूप से विनेश फोगाट की घटना ने देशवासियों को हैरान-परेशान कर दिया।

चिंतन-मनन

सम्यक दृष्टिकोण की जरूरत

आज मानवता को बचाने से अधिक कोई करणीय काम प्रतीत नहीं होता। मनुष्य औद्योगिक और यांत्रिक विकास कर पाए या नहीं, इनसे मानवता की कोई क्षति नहीं होने वाली है, किंतु उसमें मानवीय गुणों का विकास नहीं होता है तो कुछ भी नहीं होता है। एक मानवता बचेगी तो सब कुछ बचेगा। जब इसकी सुरक्षा नहीं हो पाई तो क्या बचेगा? और उस बचने का अर्थ भी क्या होगा? मनुष्य एक सर्वाधिक शक्तिशाली प्राणी है, इस तथ्य को सभी धर्मो ने स्वीकार किया है।पर मानव जाति का दुर्भाग्य यह रहा कि उसकी शक्ति मानवता के विकास में खपने के स्थान पर उसके ह्रास में खप रही है। मानवता की सुरक्षा के लिए जिस ऊर्जा को संग्रहीत किया गया था, वह हथियार का रूप लेकर उसका संहार कर रही है।मनुष्य के मन की धरती पर उगी हुई करुणा की फसल व्रूरता से भावित होकर धीरे-धीरे समाप्त हो रही है।यह एक ऐसा भोगा हुआ यथार्थ है, जिसे कोई भी संवेदनशील व्यक्ति नकार नहीं सकता।
पानी को जीवनदाता माना जाता है, सर्वोत्तम तत्व माना जाता है; फिर भी उसके स्वभाव की विचित्रता यह है कि वह ढलान का स्थान प्राप्त होते ही नीचे की ओर बहने लगता है।दूसरों को जीवन देने वाला जल भी जब नीचे की ओर जाने लगे तो उसके कौन रोक सकता है? यही स्थिति आज के मनुष्य की है।सर्वाधिक शक्तिशाली होकर भी यदि वह स्वयं का दुश्मन हो जाए, करुणा को भूलकर व्रूर बन जाए तो उसे कौन समझा सकता है। इस बात को सब मानते हैं कि विज्ञान ने बहुत तरक्की की है।यह बहुत अच्छी बात है।किंतु हमें इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि विज्ञान में तारक और मारक दोनों शक्तियां होती हैं। कोई आदमी उसकी तारक शक्ति को भूलकर मारक शक्ति को ही काम में लेने लगे, इसमें विज्ञान का क्या दोष।उसके पास मानवता या मानव जाति को बचाने की जो विलक्षण शक्ति है, उसे भुला दिया गया और संहार की भयानक शक्ति को उजागर किया गया।इस स्थिति को बदलने के लिए सम्यक दृष्टिकोण के निर्माण की आवश्यकता है।

पडोसी देशों में भारत-विरोधी सरकारों के गठन की चिन्ता

ललित गर्ग

भारत के पडोसी देशों में अस्थिरता एवं अराजकता का माहौल चिन्ताजनक है। बांग्लादेश के साथ-साथ भारत के पड़ोसी मुल्कों में हुए हालिया अराजक, हिंसक एवं अस्थिरता के घटनाक्रमों से एक तस्वीर बनती है एवं एक सन्देश उभर कर आता है, वह है, चीनी के द्वारा भारत विरोधी सरकारों के गठन की साजिश। सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, बल्कि मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका में राजनीतिक उथल-पुथल और तख्तापलट के बाद अस्तित्व में आई सरकारों ने भारत के लिए चुनौतीपूर्ण हालात पैदा कर दिए हैं। भारत को सतर्क एवं सावधानी बरतने की जरूरत है। अब सवाल ये उठते हैं कि भारत के पड़ोसी देशों में हो रही इस अराजकता एवं अस्थिरता के कारण क्या हैं? यह सिर्फ एक संयोग है या फिर साजिश? क्या इसके पीछे चीन का हाथ है? क्या पाकिस्तान भी इसके लिये जिम्मेदार है? पड़ोसी देशों में पनप रही इस राजनीतिक अस्थिरता का भारत पर क्या असर होगा? इसकी भरी-पूरी आशंका है कि चीन ने पाकिस्तानी तत्वों के जरिये शेख हसीना विरोधी आंदोलन को हवा दी। निश्चित ही शेख हसीना की छवि एक अधिनायकवादी शासक की बनी और पश्चिमी देश विशेषकर अमेरिका उनकी निंदा करने में मुखर हो उठा। अमेरिका उनकी नीतियों से पहले से ही खफा था, क्योंकि वह मानवाधिकार और लोकतंत्र पर उसकी नसीहत सुनने को तैयार नहीं थीं। उनका सत्ता से बाहर होना भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है, बांग्लादेश में एक अर्से से भारत विरोधी ताकतें सक्रिय हैं। उनका भारत विरोधी चेहरा आरक्षण विरोधी आंदोलन के दौरान भी दिखा। यह ठीक नहीं कि हिंसक प्रदर्शनकारी अभी भी हिंदुओं और उनके मंदिरों के साथ भारतीय प्रतिष्ठानों को निशाना बना रहे हैं। लगभग ऐसी ही स्थितियां चीन और पाकिस्तान ने मालदीव, नेपाल, अफगानिस्तान और श्रीलंका में खड़ी की है।
हसीना का जाना या उनका निष्कासन चीन एवं पाकिस्तान की साजिशों का परिणाम है, जो भारत के लिए कई मायनों में झटका है। इसका यह मतलब भी है कि भारत ने पड़ोस में अपने इकलौते स्थिर साथी को अब खो दिया है। भारत अपने चारों ओर से बदहाल, कट्टरवादी, अराजक एवं अस्थिर पड़ोसियों से घिरा है। हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान है, जिस पर कट्टरपंथी तालिबान का राज है। भारत-विरोधी समूहों को समर्थन देने का उसका एक काला इतिहास रहा है। पाकिस्तान तो भारत का दुश्मन देश ही है। एक बेहद अशांत पड़ोस, जो कट्टरपंथियों, सैन्य शासकों, दिवालिया अर्थव्यवस्थाओं और जलवायु-परिवर्तन के कारण डूबते देशों में अग्रणी है। अपनी आर्थिक बदहाली के बावजूद वह भारत विरोधी षडयंत्र रचता ही रहता है। वह राजनीतिक अस्थिरता का पर्याय है। विडम्बना देखिये कि पाकिस्तान के एक भी वजीरे-आजम ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। हमेशा वहां की फौज ने उनके कार्यकाल में टांग डाली है। दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव हैं। श्रीलंका 2022 में दिवालिया हो गया था। वहां से सामने आई तस्वीरें एवं घटनाक्रम आज के बांग्लादेश से काफी मिलती-जुलती रही हैं। वहां भी प्रदर्शनकारियों ने बड़ा जनआंदोलन किया और जनता ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया, जिस कारण राष्ट्रपति गोटाबाया को देश छोड़कर भागना पड़ा था। आर्थिक दिवालियेपन का शिकार यह देश चीन के कर्ज के जाल में फंसा हुआ है। श्रीलंका के कर्ज का एक बड़ा हिस्सा चीन का था, जिस कारण चीन ने यहां के हंबनटोटा बंदरगाह पर कब्जा कर लिया था। हालात यह हो गए थे कि श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो गया था।
मालदीव एक समय भारत का सहयोगी हुआ करता था। वहां की अर्थव्यवस्था चीन और भारत पर निर्भर है। हालांकि, मालदीव की भारत से नजदीकी हमेशा चीन को खटकती थी, जिस कारण उसने इस देश को अपने कर्ज के जाल में फंसाया। धीरे-धीरे इस देश की माली हालत बुरी होने लगी, जिसके बाद यहां चीन समर्थक और इंडिया आउट का नारा देने वाले मोहम्मद मुइज्जू की सरकार बनी। पाकिस्तान एवं चीन के दबाव में उनके नए राष्ट्रपति के सुर बदले हुए हैं। वहां भारत-विरोधी स्वर उग्रतम बने हुए हैं। मुइज्जू ने राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे पहले चीन का ही दौरा किया था और इसके बाद उन्होंने कई भारत विरोधी फैसले किए, जिसमें मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी भी शामिल थी। वहां भारत-विरोधी स्वर उग्रतम बने हुए हैं।
नेपाल बीते कई सालों से राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। हाल ही में यहां एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन हुआ और प्रो-भारत माने जाने वाली प्रचंड सरकार सत्ता से बाहर हो गई। अब यहां चीन समर्थक केपी शर्मा ओली की सरकार है। ओली इससे पहले 2015-16 में नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उस समय भारत और नेपाल के संबंध काफी तनावपूर्ण रहे थे। नेपाल में गत 16 वर्षों में 14 सरकारें बदल चुकी हैं। हालात इतने बदहाल हैं कि वहां पर कुछ लोग राजशाही को फिर से बहाल करना चाहते हैं। नेपाल में भी चीन ने जाल बिछा रखा है। चीन विस्तारवादी, अलोकतांत्रिक और अपने आस-पड़ोस के देशों के साथ धौंस-डपट करने वाला देश है। वह भारत के भूखंडों पर अपनी मिल्कियत जताता रहता है। भूटान में घरेलू राजनीति स्थिर है, लेकिन वह चीन के साथ सीमा-समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहता है, और यह भारत के लिए चिंता का बड़ा कारण है।
भारतीय उपमहाद्वीप के मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भुटान और श्रीलंका के बाद अब बांग्लादेश में उत्पन्न होने वाली प्रतिकूल परिस्थितियों को दुनिया चुपचाप सब देख रही है, वहीं भारत इसके लिए खुद को तैयार कर रहा है, क्योंकि बांग्लादेश की घटनाओं का उस पर सीधा असर होगा। भारत शांति कायम रखने एवं पडोसी देशों से मित्रता कायम रखने के अपने संकल्पों एवं रणनीतियों के लिए इन देशों पर भरोसा नहीं कर सकता। हमारे इर्द-गिर्द मची उथलपुथल, अस्थिरता एवं अराजकता हमारे वैश्विक एजेंडे को भी बाधित करती है। भारत की आबादी 1.4 अरब है। उसके सभी पड़ोसियों की कुल आबादी 50 करोड़ है। अर्थव्यवस्था के साथ भी ऐसा ही है। भारत की जीडीपी तीन ट्रिलियन डॉलर है। बाकी सब मिलाकर लगभग एक ट्रिलियन हैं। भारत समर्थ है, शक्ति सम्पन्न है, दुनिया की तीसरी अर्थ-व्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, इसलिये उसे अधिक बलों की तैनाती, अधिक रक्षा खर्च और सीमाओं पर अधिक बुनियादी ढांचों का निर्माण करना होगा। क्योंकि भारत के सभी पडोसी देशों पर चीन का दबदबा है और उसके दबाव में भारत के लिये कभी भी संकट बन सकते हैं। बांग्लादेश के घटनाक्रम पर भारत की सतर्कता, विवेक एवं समझदारी सराहनीय है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार पडोसी देशों में उत्पन्न हालातों पर समझ एवं संयम से कदम उठाती रही है। बांग्लादेश की तख्तापलट घटनाओं पर भी उसने पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई, विपक्षी दलों ने महत्वपूर्ण भूमिका के साथ अपनी बात रखी। ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर सर्वसम्मति बनना जीवंत लोकतंत्र का प्रमाण है। ऐसा अनुकरणीय उदाहरण पडोसी देशों में न मिलना ही उनकी अस्थिरता एवं अराजकता का बड़ा कारण है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में ऐसी स्थिति कतई नहीं बननी चाहिए कि जहां राजनीतिक दलों के बीच दूरियां इस कदर बढ़ जायें कि फौज का दखल देना पड़े या पडोसी देश अपनी स्वार्थों की रोटियां सेंकने में सफल हो जाये। भारत के पडोसी देशों के लोग केवल बुराइयों से लड़ते नहीं रह सकते, वे व्यक्तिगत एवं सामूहिक, निश्चित सकारात्मक लक्ष्य के साथ जीना चाहते हैं। अन्यथा जीवन की सार्थकता नष्ट हो जाएगी।
इन पडोसी देशों के नेता दो तरह के हैं- एक वे जो कुछ करना चाहते हैं, दूसरे वे जो कुछ होना चाहते हैं। असली नेता को सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी होकर, प्रासंगिक और अप्रासंगिक के बीच भेदरेखा बनानी होती है। संयुक्त रूप से कार्य करें तो सभी पडोसी देश मिलकर विश्व में एक बड़ी ताकत बन सकते हैं। लेकिन उन्होंने सहचिन्तन को शायद कमजोरी मान रखा है। नेतृत्व के नीचे शून्य तो सदैव खतरनाक होता ही है पर यहां तो ऊपर-नीचे शून्य ही शून्य है। इन पडोसी देशों के स्तर पर तेजस्वी और खरे नेतृत्व का नितान्त अभाव है। भारतीय उपमहाद्वीप के देशों के केनवास पर शांति, प्रेम, विकास और सह-अस्तित्व के रंग भरने की अपेक्षा है। भारत इस स्थिति में है, उसे मनोबल के साथ पडोसी देशों में स्थिरता, शांति, लोकतंत्र एवं आपसी समझ की ज्योत जलाने के लिये तत्पर रहना चाहिए, जो उन देशों के साथ भारत के लिये भी जरूरी है।
(खक, पत्रकार, स्तंभकार)

कौसर जहां : संशोधन से आएगी पारदर्शिता

प्रह्लाद सबनानी

केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन करके एक पारदर्शी, जवाबदेह और समान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था के साथ प्रभावी कानून बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ाया है।
संशोधनों के तहत मुस्लिम समुदाय में भी सभी वर्गों की भागीदारी का इंतजाम किया गया है। वहीं इक्कीसवीं सदी की सबसे महत्त्वपूर्ण आवश्यकता को रेखांकित करते हुए महिलाओं के समान प्रतिनिधित्व का ख्याल रखा है। वक्फ की संपत्तियों का दुरुपयोग नहीं हो, उनका सही मूल्यांकन करते हुए उस अनुपात में राजस्व की व्यवस्था हो और सबसे जरूरी इन संपत्तियों का दुरुपयोग नहीं हो इसकी ज्यादा सक्षम व्यवस्था संशोधनों में की गई है। कोई भी बोर्ड या निकाय अगर जवाबदेह नहीं है और पारदर्शी नहीं है तो वहां भ्रष्टाचार की आशंका बढ़ जाती है। साथ ही वह संस्था और उसका संचालन करने वाले लोग भी निरंकुश हो जाते हैं। नये प्रावधानों में यह व्यवस्था की गई है कि वक्फ संपत्ति को निष्पक्ष तरीके से चिह्नित किया जाए और अगर कोई विवाद है तो उसका समुचित कानूनी निस्तारण हो। मेरा मानना है इन संशोधनों से वक्फ बोर्ड ज्यादा सक्षम होगा। ज्यादा जिम्मेदार होगा। ज्यादा जवाबदेह होगा।
सरकार ने संशोधन के दो बिल तैयार किए हैं। पहले बिल के जरिए मुसलमान वक्फ कानून 1923 को समाप्त किया जाएगा जबकि दूसरे बिल के जरिए वक्फ कानून 1995 में महत्त्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। वक्फ कानून 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 किया गया है। इसके तहत केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में मुस्लिम और गैर मुस्लिम का उचित प्रतिनिधित्व होगा। मुस्लिम समुदायों में अन्य पिछड़ा वर्ग; शिया, सुन्नी, बोहरा, आगाखानी का प्रतिनिधित्व होगा।
इसके साथ ही महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। केंद्रीय परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में दो महिलाओं को रखना अनिवार्य होगा। वास्तव में यह क्रांतिकारी कदम है। नये भारत में विकसित भारत की यात्रा का संकल्प पूरा करना है तो महिलाओं की भागीदारी हर स्तर पर जरूरी है। मैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की आभारी हूं कि उनकी सोच देश की आधी आबादी को हर स्तर पर आगे लाने की है।
वक्फ कानून में संशोधनों के तहत एक केंद्रीय पोर्टल और डेटाबेस के माध्यम से वक्फ के पंजीकरण के तरीके को सुव्यवस्थित किया जाएगा। इसके साथ ही दो सदस्यों के साथ ट्रिब्यूनल संरचना में सुधार किया जा रहा है। वहीं, ट्रिब्यूनल के आदेशों के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील के लिए नब्बे दिनों की मियाद निर्धारित की गई है। इससे विवाद कम होंगे।
वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण के लिए सर्वे कमिश्नर का अधिकार कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा नामित डिप्टी कलेक्टर को होगा। यह सभी कदम वक्फ को ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनाएंगे। साथ ही विवाद की गुंजाइश कम होगी। बोहरा और आगाखानियों के लिए अलग बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया गया है। किसी भी संपत्ति को वक्फ के रूप में दर्ज करने से पहले सभी संबंधितों को उचित नोटिस दिया जाएगा। मुझे लगता यह न्यायसंगत कदम है और इससे बोर्ड पर सवाल भी नहीं उठेंगे।
वक्फ परिषद में केंद्रीय मंत्री, तीन सांसद, मुस्लिम संगठनों के तीन नुमाइंदे, मुस्लिम कानून के तीन

जानकारङ्क सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के दो पूर्व जज, एक प्रसिद्ध वकील, राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चार लोग, भारत सरकार के अतिरिक्त या संयुक्त सचिव आदि होंगे। इनमें दो महिलाओं का होना जरूरी होगा। यह समान प्रतिनिधित्व का सर्वोत्तम मॉडल है।
'2013 में, वक्फ अधिनियम में संशोधन करके वक्फ बोर्डों को वक्फ संपत्ति के मामले में असीमित अधिकार दिए गए थे, जिसे किसी भी अदालत में चुनौती भी नहीं दी जा सकती। यह एक तरह से जवाबदेही और पारदर्शिता के खिलाफ था और इसमें आम मुसलमान का भी कोई लाभ नहीं था। नये प्रावधान में सभी चिंताओं का समाधान किया गया है।

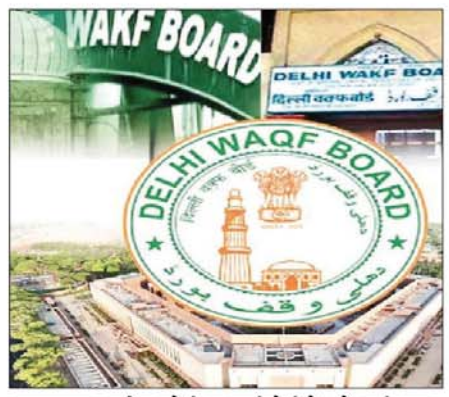

https://t.me/AllNewsPaperPaid

सम्पादकीय

आरबीआई की एमपीसी बैठक के फैसले से हैरानी नहीं, मगर महंगाई दर के लक्ष्य पर रहेगी नजर

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की 50वीं बैठक के नतीजे से किसी को कोई हैरानी नहीं हुई। इसका अंदाजा पहले से था कि एमपीसी की बैठक में नीतिगत दरें यथावत रहेंगी और केंद्रीय बैंक के नजरिये में भी कोई बदलाव नहीं होगा। ऐसा हुआ भी और आरबीआई ने रीपो दर 6.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखी। एमपीसी ने आर्थिक वृद्धि और मुद्रास्फीति के अनुमानों में भी कोई बदलाव नहीं किया। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वृद्धि दर भी 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। एमपीसी को लगता है कि समग्र मुद्रास्फीति (हेडलाइन इन्फ्लेशन) चालू वित्त वर्ष में औसतन 4.5 प्रतिशत के स्तर पर रह सकती है। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में समग्र मुद्रास्फीति 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है। यद्यपि, मौद्रिक नीति से संबंधित घोषणाओं में अधिकांश बातें अनुमानों के अनुरूप ही रहीं परंतु मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करने के तरीके, मौद्रिक नीति संचालन एवं वित्तीय स्थिरता का खास तौर पर जिक्र किया गया। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इन तीनों विषयों से जुड़ी मौलिक बातों का उल्लेख किया। नवीनतम आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि 'भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करते समय खाद्य वस्तुओं को बाहर रखना चाहिए, अर्थात इस पर विचार नहीं करना चाहिए'। इसके पीछे मुख्य तर्क यह दिया गया कि खाद्य मुद्रास्फीति प्राय: मांग पर निर्भर नहीं करती है और आपूर्ति मोर्चे पर होने वाली हलचल इसे अधिक प्रभावित करती है। समीक्षा में कहा गया कि मांग में वृद्धि से मूल्यों में होने वाले परिवर्तन से अल्प अवधि के नीतिगत उपायों से बेहतर तरीके से निपटा जा सकता है। इस सप्ताह के शुरू में इस समाचार पत्र ने तर्क दिया था कि खाद्य मुद्रास्फीति को नजरअंदाज करना उचित नहीं है।

आरबीआई गवर्नर ने सभी बातों पर स्थिति स्पष्ट कर दिया है। इससे किसी भी तरह के संदेह के समाधान में मदद मिलनी चाहिए। इनमें कुछ व्यापक बिंदुओं पर चर्चा करना आवश्यक है। समग्र उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति दर का लक्ष्य तय करना आरबीआई का प्रमुख ध्येय है। इस सूचकांक में खाद्य मुद्रास्फीति का भारांश लगभग 46 प्रतिशत है, इसलिए इसे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उपभोक्ता मुद्रास्फीति को अन्य बातों की तुलना में खाद्य कीमतों के संदर्भ में अधिक समझते हैं। ध्यान देने योग्य है कि मई और जून में समग्र मुद्रास्फीति में खाद्य महंगाई की हिस्सेदारी 75 प्रतिशत से अधिक रही। खाद्य मुद्रास्फीति घरेलू बजट को भी प्रभावित करती है, जिसका भविष्य में वास्तविक मुद्रास्फीति की दशा-दिशा पर असर पड़ता है। पिछले कुछ महीनों में घरेलू मुद्रास्फीति से जुड़ी चिंता बढ़ गई है। खाद्य मुद्रास्फीति लगातार ऊंचे स्तर पर रहने से परिवारों का बजट बिगड़ सकता है और यह प्रमुख मुद्रास्फीति दर को भी प्रभावित कर सकता है। परिवारों में व्यवहार के स्तर पर बदलाव से मुद्रास्फीति समस्या का कारण बन सकती है और इससे आर्थिक लागत भी बढ़ जाएगी।

क्या होती है जेपीसी और क्या होते है उसके परिणाम?

रिजिजू के अनुसार इस बिल में जो भी प्रावधान हैं, आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक किसी रिलीजियस बॉडी का जो फीडम है, उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। न ही संविधान के किसी भी अनुच्छेद का इसमें उल्लंघन किया गया है। इस विधेयक से किसी भी धार्मिक संस्था की स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। हालांकि अपना पक्ष रखने के बाद उन्होंने बिल को जेपीसी के पास भेजने की सिफारिश की। बताया गया था कि अब इस बिल पर चर्चा के लिए स्पीकर ओम बिरला एक संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी का गठन करेंगे। इस कमेटी में सत्ताधारी और विपक्षी दलों के सांसदों को शामिल किया जाता है।

अशोक भाटिया

विपक्षी पार्टियों के विरोध के कारण केंद्र सरकार ने वक्फ (संशोधन) बिल, 2024 को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की सिफारिश की है। केंद्रीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने 8 अगस्त गुरुवार को लोकसभा में इस संशोधन बिल को पेश किया था । बिल के पेश होते ही विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष का कहना है कि ये बिल संविधान पर हमला है और इससे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। सांसदों ने इस बिल को तुरंत वापस लेने की मांग की। वैसे वक्फ कानून, 1995 में सुधार के दावों के साथ लाया गया ये संशोधन विधेयक पिछले कई दिनों से विवादों में है। सरकार का दावा है कि इस कानून में लंबे समय से बदलाव की मांग हो रही थी। बदलाव के जरिये राज्यों के वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं और गैर-मुस्लिमों को शामिल किए जाने प्रावधान है। इसके अलावा मौजूदा कानून की धारा-40 को खत्म करने का भी प्रावधान है। कोई संपत्ति वक्फ बोर्ड की संपत्ति होगी, इस धारा के तहत ही बोर्ड को फैसला लेने की शक्ति दी गई है। ज्ञात हो कि संसद में मुख्य रूप से दो तरह की समितियां होती हैं। 1, स्थायी समिति यानी स्टैंडिंग कमेटी 2, तदर्थ समिति यानी एडहॉक कमेटी। स्टैडिंग कमेटी वो होती हैं, जिनका गठन समय-समय पर संसद के अधिनियम की प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियम के हिसाब से किया जाता है। इन कमेटियों का कार्य अनवरत प्रकृति का होता है। यानी काम चलता रहता है।वहीं, कई समितियां तय समय सीमा के लिए गठित की जाती हैं। एडहॉक कमेटी वो होती हैं, जो किसी बिल या मुद्दे की जांच या विशेष प्रयोजन के लिए बनाई जाती हैं। जब ये कमिटी अपनी रिपोर्ट जमा कर देती हैं, तब उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जेपीसी भी इसी श्रेणी में आती है।

जेपीसी में राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के सदस्य शामिल किए जाते हैं।बाद में किसी भी मामले में जेपीसी गठित करने के लिए बाकायदा संसद के एक सदन द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाता है। दूसरे सदन द्वारा इस पर सहमति ली जाती है। जेपीसी गठित होने के बाद सांसदों की टीम मामले की पूरी जांच करती है। पार्टियां अपने सदस्यों के नाम जेपीसी के लिए आगे बढ़ाती हैं और फिर उन्हें अप्रूव किया जाता है। जेपीसी में सदस्यों की संख्या तय नहीं होती है। सदस्यों की संख्या उस दल की ताकत के हिसाब से देखी जाती है। यानी अगर आज किसी मामले में जेपीसी गठित होती है तो उसमें सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते भाजपा के सबसे ज्यादा सदस्य होंगे। लोकसभा स्पीकर ही कमिटी के अध्यक्ष को चुनते हैं। ज्यादातर समय ये जिम्मा सत्ताधारी पार्टी के सांसद हो ही मिलता है। जेपीसी गठित हो गई तो उसे मामले की गहनता से जांच के लिए विशेषाधिकार मिल जाते हैं। इनका इस्तेमाल कर वो जरूरी जानकारी हासिल कर सकती है। जेपीसी, एक्सपर्ट, सरकारी संस्थाओं और विभागों से जानकारियां हासिल कर सकती है। जेपीसी और अन्य समितियों की सिफारिशों के आधार पर की गई कार्रवाई पर सरकार को संसद में रिपोर्ट पेश करनी होती है। किसी मुद्दे की जांच में अगर सबूत जुटाने के लिए मामले से जुड़े व्यक्ति को कमिटी बुलाना चाहे तो उसे पेश होना होता है। पेश नहीं होने पर उसे संसद की अवमानना मानी जाती है।वहीं, बिल से जुड़े मसलों पर ये कमिटी एक्सपर्ट से सुझाव लेती है। सुझावों या आपत्तियों को कमिटी अपनी रिपोर्ट में शामिल कर सकती है।कमिटी के सुझाव सरकार के लिए सलाह के तौर पर होते हैं। जरूरी नहीं कि सरकार उसे माने ही। चूंकि कमिटियों में ज्यादातर सांसद और अध्यक्ष सत्ताधारी पार्टी के होते हैं, इसलिए अक्सर सुझाव मान लिए जाते हैं। जेपीसी के गठन के बाद लोकसभा के स्पीकर जेपीसी का एक अध्यक्ष नियुक्त करते हैं, जिसका फैसला सर्वमान्य होता है। आमतौर पर सत्ताधारी पार्टी के सांसद ही जेपीसी के अध्यक्ष होते हैं। बाकी इसमें सभी दलों के सांसद शामिल किए जाते हैं, जिससे निष्पक्ष रिपोर्ट सामने आए। समिति के अधिकतर सदस्य किसी मामले को दबाने की भी कोशिश करते हैं, तो दूसरे सदस्य आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। बोफोर्स केस में ऐसा ही हुआ था, जब एआईडीएमके के सांसद ने जांच के खिलाफ अपना आपत्ति नोट दर्ज कराया था। बिल के यहां पहुंचने के बाद उस पर चर्चा होती है। इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के होने पर रिपोर्ट निष्पक्ष आती है। चर्चा सिर्फ सदस्यों तक सीमित नहीं रखी जाती। इसमें कई पॉइंट्स बताए जाते हैं, जिनकी जांच की जाती है और चर्चा होती है। सम्बंधित क्षेत्र विशेषज्ञों और समूहों को आमंत्रित किया जाता है। इसके अलावा कुछ मामलों में जनता से भी सलाह ली जा सकती है। समिति का उद्देश्य किसी मुद्दे, विधेयक के प्रावधानों या घोटाले आदि की जांच करना होता है। भारत की संसदीय प्रणाली में जेपीसी एक शक्तिशाली जांच निकाय के रूप में काम करती है। जेपीसी को जिस काम के लिए बनाया जाता है, उससे जुड़े सबूत और तथ्य जुटाने के लिए किसी भी व्यक्ति, संस्था या पक्ष को बुलाने और उससे पूछताछ करने का अधिकार होता है। अगर कोई मामला जनहित का न हो तो आमतौर पर समिति की कार्यवाही और इसके निष्कर्ष को गोपनीय ही रखा जाता है। अमूमन जेपीसी के पास जांच के लिए अधिकतम तीन महीने का समय होता है। इसके बाद यह अपनी रिपोर्ट पेश करते है और इसका अस्तित्व खत्म हो जाता है।समिति की रिपोर्ट पर कार्रवाई के लिए वैसे तो सरकार बाध्य नहीं होती है पर अगर इसकी सिफारिशों पर कार्रवाई करती है तो इसकी रिपोर्ट सदन को देनी होती है। समितियों की कार्रवाई रिपोर्ट पर संसद में चर्चा हो सकती है और इससे जुड़े सवाल भी उठाए जा सकते हैं। देश के इतिहास में अब तक कई बार जेपीसी का गठन किया जा चुका है। यह जानना भी दिलचस्प है कि पांच बार जेपीसी का गठन करने के बाद सत्तारूढ़ दल अगला चुनाव हार गया। साल 1987 में स्वीडन की हथियार बनाने वाली कंपनी बोफोर्स के साथ भारत सरकार ने 1437 करोड़ रुपए का एक रक्षा सौदा किया था। तभी वहां की मीडिया में खबर आई थी कि बोफोर्स ने रक्षा सौदों के लिए कई देशों की सरकारों को रिश्वत दी है। इस पर भारत में भी खूब हंगामा हुआ। खुद राजीव गांधी के करीबी मंत्री रहे वीपी सिंह ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। ऐसे में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को बोफोर्स सौदे की जांच के लिए जेपीसी बनानी बड़ी थी, जिसके अध्यक्ष कांग्रेस सांसद बी। शंकरानंद थे। इस समिति ने रिपोर्ट पेश की तो राजीव गांधी को क्लीन चिट दे दी गई थी। इस पर विपक्ष ने काफी हंगामा किया था। इसके बाद साल 1989 में हुए चुनाव में राजीव गांधी को हार का सामना करना पड़ा था, जबकि 1984 में उन्होंने लोकसभा की 414 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। वहीं, बोफोर्स घोटाले को उठाने वाले वीपी सिंह प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए थे । शेयर बाजार में बिग बुल के नाम से मशहूर रहे ब्रोकर हर्षद मेहता साल 1992 में सुर्खियों में आ गए थे। तब आरोप लगा था कि शेयर बाजार में 4000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। मेहता पर आरोप थे कि वह बैंक से कर्ज लेकर शेयर बाजार में पैसा लगाता है और फिर फायदा कमाने के बाद पैसा बैंक को वापस कर देता है। इसके लिए हर्षद और बैंक अधिकारियों के बीच सांठगांठ की खबरें आईं तो शेयर बाजार गिरता चला गया।

शख्सियत

संसार को कर्मभूमि कहा गया है, हमारे कर्म ही हमारी पहचान बनते हैं। पीड़ित मानव की सेवा से बढ़कर कुछ नहीं शायद इसलिए जमीन से जुड़कर भी लोग आसमां छूं लेते हैं यदि मन साफ और निश्छिल हो तो..........

नमस्कार साथियों हमारी आज की शख्सियत कॉलम के स्टार हैं बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. दिलीप सेठी। जोकि हमारे आर्दश भी हैं। अलवर में बाल रोग के लिए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्टिपल का सपना इन्होनें ही साकार किया था जब नवजात शिशु को दिल्ली या जयपुर लेकर भागना पड़ता था लेकिन अब जटिल से जटिल समस्या का उपचार यहां सेठी हॉस्पिटल में डॉ.दिलीप सेठी कर रहे हैं। इनका जन्म 22 जून 1956 को अलवर के टहला गाँव में हुआ। प्राथमिक शिक्षा सरकारी विद्यालय टहला में हुई आगामी शिक्षा-यशवंत स्कूल, अलवर से की एमबीबीएस. - 1973 बैच एसएमएस मेडिकल कॉलेज से की और एमडी 1983, एसएमएस मेडिकल कॉलेज से की। काफी लम्बे समय इन्होंने 1983-1992 तक -कोटपूतली, भरतपुर, अलवर जिलाअस्पताल में अपनी शानदार सेवाए दी।1993 में खुद का हॉस्पिटल खोला। बच्चों के अस्पताल में सेठी चिल्ड्रन हॉस्पिटल (जिला अस्पताल से इस्तीफा देने के बाद)। (अलवर जिले में सबसे बड़ा डिस्टिकेटेड (एली)लॉडियाट्रिक अस्पताल) के माध्यम से जनसेवा की यही नहीं आरएसएस व भारत विकास परिषद से भी जुडे हुए है। डॉ.दिलीप सेठी बहुत होनहार डॉ.के रूप में जाने जाते रहे हैं। शिशु रोग में बेहतरीन चिकित्सा के माध्यम से हजारों नौनिहालों की जान बचाए जाने का जीता जागता नाम है डॉ.दिलीप सेठी। लगभग अपने जीवन के सात दशक निकालने के

डॉ. दिलीप सेठी
(डायरेक्टर सेठी हॉस्पिटल,अलवर)

बाद भी कार्य के प्रति उर्जा और समर्पण का भाव आपकों दिलीप बनाता है। अपने साथ काम करने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों के साथ बेहतरीन तालमेल व अनुशासन प्रिय डॉ.दिलीप सेठी का नाम शुमार है। दैनिक बढ़ता राजस्थान की टीम इनके स्वास्थ्य जीवन व दिर्गायु जीवन की कामना करती है।

जय हिन्द

विशेष आलेख

देश के आर्थिक विकास में नवप्रवर्तन की प्रगतिशीलता ही से ही वैश्विक अस्तित्व

संजीव ठाकुर

जीवन है चलने का नाम,गति का नाम ही जीवन है। सभी समाज एवं राष्ट्र की संस्कृतियों ने यह माना है कि मनुष्य और जानवरों के बीच विभेद करने वाला प्रमुख कारक मस्तिष्क है, और मस्तिष्क ही मनुष्य को सृजनात्मक शक्ति प्रदान करता है। मनुष्य के रचनात्मक विचार नयापन लाते हैं उसे पूर्व काल से पृथक करते हुए प्रगति के पथ प्रदर्शक बनते हैं। इसे ही नवप्रवर्तन माना जाता है। नवप्रवर्तन और कुछ नहीं बल्कि समाज की परंपरागत और प्रगतिशील मानसिकता के बीच एक बड़ी लाइन खींचना है। इसीलिए यह माना जाता है कि नवप्रवर्तन समाज मैं 3त्न नवाचार का निर्धारित है, शेष 97 प्रतिशत परंपरावादी विचारों के लिए है। पुराने समय से ही आर्थिक समृद्धि में नवप्रवर्तन की भूमिका को स्वीकार किया गया है चाहे वह मनुष्य के खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक में परिवर्तन हो या फिर 18वीं सदी में यूरोप की वाणिज्य क्रांति का औद्योगिक क्रांति में बदलना इन सभी में नवप्रवर्तन ने प्रेरक का काम किया है। हम चौथी क्रांति की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए कहा जाता है कि विचारों को कभी सुसुप्त होने या मरने ना दिया जाए। हो सकता है आपके विचार करोड़ों डॉलर के हो । वर्तमान अर्थव्यवस्था में समृद्धि के इंजन माने जाने वाले सनराइज उद्योग, सॉफ्टवेयर, खाद्य संस्करण, इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक के विकास के पीछे भी नवप्रवर्तन का हाथ है। इसी के आधार पर नगरों को स्मार्ट नगरों में बदला जा रहा है। नवप्रवर्तन या नवाचार से मैं सिर्फ मानव जीवन की परेशानियों को न्यूनतम किया है, बल्कि मानव जीवन को आसान और सुखमय भी बनाया जा रहा है। नवप्रवर्तन और मस्तिष्क की खोज के कारण ही जापान में 6.5 रेक्टर का भूकंप सामान्य माना जाता है,जबकि भारत में यह तबाही ला सकता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पेनिसिलिन जैसी प्रतिजैविक (एंटीबायोटिक) के अविष्कार ने रोगों की संभावना को कम कर दिया एवं स्वास्थ्य प्रणाली के भावी विकास को एक गति प्रदान की है। जेनेरिक औषधि, रोबोटिक सर्जरी, जीन एडिटिंग जैसी प्रक्रिया स्वास्थ्य सुधार हेतु एक मजबूत आधार मानी जाती है। सामाजिक विकास आर्थिक समन्वयक और न्याय प्रणाली में पारदर्शिता लाने का प्रयास नवप्रवर्तन के योगदान से ही आया है। सोशल मीडिया जैसे नवीन प्लेटफार्म ने व्यक्ति की अभिव्यक्ति के अधिकार को स्वतंत्र किया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के ग्रामीण से आधुनिक रूपांतरण में कृषी क्षेत्र से भारी उद्योगों पर बल देने में किसानों के देश को सॉफ्टवेयर उद्योग का सिरमौर बनाने में नवप्रवर्तन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारतीय कृषि में भी आधुनिकीकरण और पाश्चात्य उपकरण का प्रादुर्भाव भी नवीन नवाचार के कारण संभव हुआ है। भारतीय राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य से लोगों के सशक्तिकरण करने वाले राज्य में बदलने की नवप्रवर्तन की भूमिका अत्यंत सराहनीय है। इसके कारण भार मानी जाने वाली महिलाएं अब भार ढोने वाली की भूमिका में आ चुकी हैं। इसी तरह न्यायिक क्षेत्र में जनहित याचिका की अवधारणा ने न्याय की अवधारणा को सर्वांगीण बनाने में सहायता प्रदान की है।

यह अलग बात है कि केवल नवप्रवर्तन को ही एकमात्र निर्धारक कारक के रूप में नहीं माना जा सकता क्योंकि नवीन विचारों को स्वीकार करना और आगे बढ़ना बहुत हद तक समाज पर निर्भर करता है। पश्चिमी देशों में नवीन विचारों को जगह देने के कारण वहां पुनर्जागरण आया है। हमें समाज को नव परिवर्तन की तरफ जागरूक करने की आवश्यकता होगी और नवप्रवर्तन में ज्यादा से ज्यादा आर्थिक मदद देकर उस और और ज्यादा विचार-विमर्श कर नीति बनाने की आवश्यकता होगी। इस तरह हमें महात्मा बुद्ध के कथन अनुसार अपने या दूसरों के विचारों नवप्रवर्तनों को तर्क बुद्धि पर देखे जाने की जरूरत है, और फिर आगे बढ़ने का प्रयास किया जाना चाहिए।

आज का इतिहास

10 अगस्त की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

- असीरियाई सम्राज्य के राजा शिनशारिसकुन की हत्या 612 में हुई, निनेवह नगर का पतन हुआ।
- पुर्तगाली समुद्र जहाज के कैप्टन डियागो डियाज मैडागास्कर को 1500 में देखने वाले पहले यूरोपीय बने।
- पुर्तगाजी सैनिकों ने 1511 में मलेशियाई राज्य मलक्का के एक हिस्से पर कब्जा किया।
- ओटोमन सम्राज्य और ऑस्ट्रिया ने 1664 में शांति के लिए वसवार की संधि पर हस्ताक्षर किए।
- इंग्लैंड के राजा चार्ल्स ने 1675 में ग्रीनविच वेधशाला की आधारशिला रखी।
- हालैंड और फ्रांस के बीच 1678 में निजम्गेन शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
- कर्लोस तृतीय 1759 में स्पेन का सम्राट बना।
- अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा करने वाले दस्तावेज की प्रति औपचारिक रूप से 1776 को लंदन पहुंचे।
- तुर्की ने 1787 में रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा की।
- पेरिस में 1793 को लूव्र संग्रहालय का उद्घाटन हुआ। 200 साल पुराने पश्चिमी कला इतिहास इस संग्रहालय में दर्ज है और इनमें से एक है मोनालीसा।
- इक्वाडोर ने 1809 में स्पेन से स्वतंत्रता हासिल की।
- मिसौरी 1821 में अमेरिका का 24वां राज्य बना।
- सीरिया में 1822 को आये विनाशकारी भूकंप से 20,000 लोगों की मौत हुई।
- कैरेबियाई द्वीप समूह बारबाडोस में 1831 को चक्रवाती तूफान से डेढ़ हजार लोगों की मौत हुई।
- अमेरिकी कांग्रेस ने 1846 में स्मिथसोनिया इंस्टीट्यूट स्थापित करने के विधेयक को मंजूरी दी।
- बच्चों के चहेता स्पाइडरमैन कॉमिक बुक 1962 में अमेजिंग फैंटेसी में नजर आया था।
- प्रथम विश्व युद्ध में 1920 को पराजित होने के बाद उसमानी शासन ने सीवरेस समझौते पर हस्ताक्षर किये।
- इटली और स्पेन के बीच 1926 में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
- द्वितीय विश्व युद्ध में 1945 को जापान की पराजय के बाद कोरिया का उत्तरी भाग रुस की लाल सेना के अधिकार में चला गया और कुछ दिनों बाद कोरिया का दक्षिणी भाग अमरीका के अधिकार में चला गया।
- अमेरीका के अंतरिक्ष अधिकारियों ने 1966 में केप केनेडी से अंतरिक्ष में रॉकेट उतारने की लिए उपयुक्त स्थान का चित्र लेने हेतु पहला अंतरिक्ष यान भेजा। जो 29 अक्तूबर को चंद्रमा पर दुर्घटनाग्रस्त होकर तबाह हो गया।
- उपग्रह एसएलवी-3 का प्रक्षेपण 1979 को किया गया।
- पंद्रह महीने की यात्रा के बाद मगैलन अंतरिक्ष यान 1990 में शुक्र पर पहुंचा था। शुक्र पर उतरने से पहले कुछ देर तक के लिए उसका संपर्क कैलिफ़ोर्निया स्थित संचालन केंद्र से टूट गया था।
- चेचेन्या में इस्लामिक भूरा ने 1999 में दागिस्तान को स्वतंत्र घोषित किया।
- श्रीलंका में 2000 को सिरीमावो भंडारनायके का प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा, आर। विक्रमानयके श्रीलंका के नये प्रधानमंत्री नियुक्त, जिनेवा में आत्मनिर्णय के अधिकार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन।
- अमेरिकी प्रक्षेपास्त्र प्रणाली को 2001 में रूस का सशर्त समर्थन।
- यूरी मालेनचेंको पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने अंतरिक्ष में 2003 को शादी रचाई थी।

आज का राशिफल

हमारे अनुभवी ज्योतिषियों की टीम के अनुसार आप कई विविध लक्ष्यों को पूरा करेंगे। क्या आप यह जानना चाहते है कि आपके जीवन के ऐसे कौनसे क्षेत्र है, जहां आपके सितारे बुलंद रहेंगे और दूसरी तरफ, आपको किस बातों से सावधान रहना चाहिए। हम न सिर्फ हमारे काम में और जटिल मुद्दों को सुलझाते वक्त सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करेंगे, बल्कि पारम्परिक संबंधों में भी, जहां यह स्थानान्तरण हमें संताप और बातचीत में लाभ प्रदान करेगा

मेष
साथी कर्मचारियों का सहयोग मिलेगा। विरोधियों पर विजय मिलेगी। आज का दिन आपके लिए थोड़ी सावधानी रखने का है। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। किसी भी नए काम की शुरुआत के लिए दिन अच्छा नहीं है।

वृष
विदेश या कहीं दूर से अच्छे समाचार मिलने के योग हैं। दांपत्य जीवन में मधुरता छलकेगी। आकस्मिक धन लाभ होगा। आज आप का दिन बहुत अच्छा गुजरने वाला है। घर में शांति और आनंद का वातावरण रहेगा।

मिथुन
वाणी पर संयम रखना पड़ेगा। मन के आवेश पर अंकुश रखना पड़ेगा। दुर्घटना से संभलना होगा। शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। मित्रों, संबंधियों से की गई भेंट से आपका दिन आनंदपूर्वक गुजरेगा।

कर्क
अपने स्वभाव में जिद्दीपन छोड़ दें। नौकरीपेशा लोग चिंतित रह सकते हैं। शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ आनंदपूर्वक समय बिताएंगे। स्वजनों से भेंट या उपहार मिल सकता है। कहीं आकस्मिक धन खर्च होगा।

सिंह
आनंददायी प्रवास संभव होगा। दोस्तों के साथ बाहर जाने का कार्यक्रम बनेगा। आज का दिन आपके लिए कठिनाई भरा हो सकता है। परिजनों के साथ बहस होगी। किसी से उग्र व्यवहार के कारण मन दुखी हो सकता है।

कन्या
समाज में मान-सम्मान मिलेगा। आज आप का मनोबल कमजोर रहेगा। किसी निर्णय पर जाना कठिन हो सकता है। नए काम की शुरुआत ना करें और महत्वपूर्ण निर्णय आज न लें। परिजनों के साथ वाद-विवाद हो सकता है। सुखमय प्रसंग बनेगा।

तुला
आज आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। मानसिक प्रसन्नता का अनुभव होगा। परिजन तथा निकट के लोगों के साथ अधिक समय गुजरेगा। सामाजिक जीवन में आप सफलता और यश प्राप्त कर पाएंगे।

वृश्चिक
आर्थिक लाभ की संभावना है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। काम में यश की प्राप्ति होगी। मित्रों से मुलाकात होगी। रुके हुए काम आसानी से बन पाएंगे। क्रोध की मात्रा अधिक रहेगी। व्यर्थ उग्रता को टालें, नहीं तो काम बिगड़ सकता है।

धनु
घर में स्वजनों के साथ गलतफहमी हो सकती है। माता के साथ किसी बात पर विवाद हो सकता है। घर की महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। सरकारी तथा संपत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण पत्रों पर सही या मुहर लगाने में सावधानी रखें।

मकर
आप का आज का दिन आध्यात्मिक दृष्टि से आपको अनूठी अनुभूति कराने वाला रहेगा। आपको रहस्यमयी विद्या आपको आकर्षित करेगी। दूसरों के प्रति नफरत की भावना पर संयम रखें। नए काम की शुरुआत ना करें।

कुंभ
मानसिक अशांति और उद्वेग आपके मन पर छाया रहेगा। खिन्नता रहेगी। पेट दर्द, अजीर्ण से आप परेशान रहेंगे। आकस्मिक धन खर्च होगा। प्रिय दोस्त आपके दिल को चोट पहुंचा सकते हैं। आज यात्रा, प्रवास टाल दें।

मीन
किसी भी काम में सोच-समझकर आगे बढ़ें। भाई-बहनों के साथ प्यार भरा संबंध बना रहेगा। मित्रों, स्वजनों के साथ मुलाकात होगी। प्रत्येक काम में सफलता मिलने की संभावना है। आर्थिक लाभ की संभावना भी अधिक है। आज का दिन शुभ फलदायी है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक श्रीमती कमलेश विजयवर्गीय द्वारा बढ़ता राजस्थान प्रिंटिंग प्रेस,हमीदपुरा रोड खण्डवा,निवाई टोंक (राज.) से मुद्रित एवं 185/ 116 ''प्रतीक्षा'' सेक्टर-18, प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर से प्रकाशित, संपादक-तनुजा पठान*। प्रधान संपादक-राम बिलास विजयवर्गीय मो. 9414242258, 9214048888,जयपुर फोन नं.0141-2796794,795 टोंक कार्यालय-बाईपास निवाई, टोंक फोन नं.01432-244881 निवाई 01438-222201,202,203 अलवर कार्यालय-मेहताब सिंह का नोहरा,अलवर मो. 7733000123,कोटा कार्यालय-छावनी मेन रोड,कोटा मो.9414823448 । ई मेल-badhatarajasthan@yahoo.com *पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार

मोहम्मद यूनुस

व्यापक चुनौती

नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख की जिम्मेदारी संभाल ली है। उनके सामने देश में कानून-व्यवस्था ठीक कर शांति बहाली की व्यापक चुनौती है। तुलनात्मक रूप से युवा राष्ट्र बांग्लादेश एक बार फिर अस्थिरता का सामना कर रहा है। अशांति के नए अध्याय की शुरुआत शेख हसीना का तख्तापलट और बाद में नोबेल पुरस्कार विजेता के सत्ता संभालने से हुई है। मोहम्मद यूनुस के सत्ता संभालने के समय देश भय और अनिश्चितता का शिकार है जिसके चलते सैकड़ों नागरिक भारत में शरण चाहते हैं। हालिया महीनों में राजनीतिक हिंसा, विरोध प्रदर्शनों और विरोधियों पर लगाम लगाने के कारण बांग्लादेश में एक अस्थिर परिवेश पैदा हुआ जिससे शेख हसीना का तख्तापलट हुआ तथा ढाका की सड़कों पर अस्थिरता व्याप्त है। 'माइक्रोफाइनेंस' पर अपने काम तथा 'ग्रामीण बैंक' के संस्थापक के रूप में विश्व स्तर पर सम्मानित मोहम्मद यूनुस द्वारा सत्ता पर कब्जे की घोषणा एक नाटकीय परिवर्तन के रूप में सामने आई है। मोहम्मद यूनुस लंबे समय से हसीना सरकार की नीतियों के आलोचक रहे हैं और हालिया वर्षों में उनको अनेक राजनीतिक और विधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।

देश में राजनीतिक उथलपुथल से जनता व खासकर अल्पसंख्यकों में भय का वातावरण पैदा हो गया है। खबरों से संकेत मिलता है कि अपनी सुरक्षा के लिए चिन्तित सैकड़ों बांग्लादेशी सीमा पर कर भारत आने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश का राजनीतिक परिदृश्य अनिश्चितता से भरा है। मोहम्मद यूनुस राजनीतिक

सुधार व पारदर्शिता के पैरोकार रहे हैं। उनका नेतृत्व भ्रष्टाचार-विरोधी उपायों तथा लोकतांत्रिक व्यवहारों पर ध्यान दे कर सुशासन का नया युग ला सकता है। लेकिन इन परिवर्तनों को अत्यधिक विभाजित राजनीतिक व्यवस्था में लागू करना बहुत बड़ी चुनौती होगा। इसके साथ ही बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था कुप्रबंधन व भ्रष्टाचार के कारण बहुत दबाव में है। आर्थिक विकास और माइक्रोफाइनेंस में मोहम्मद यूनुस की विशेषज्ञता अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने, उद्यमिता को प्रोत्साहन देने तथा रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। जहां कुछ लोग उनको 'उद्धारक' के रूप में देख सकते हैं, वहीं दूसरे उनको बिना राजनीतिक अनुभव वाला 'बाहरी' समझ सकते हैं। ऐसे में विश्वास तथा व्यापक समर्थन प्राप्त करना उनके प्रशासन की सफलता के लिए जरूरी होगा। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती शांति तथा कानून-व्यवस्था की बहाली होगा। परिवर्तन के इस समय में कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करना सबसे ज्यादा जरूरी है। मोहम्मद यूनुस को सेना तथा कानून लागू करने वाली एजेंसियों की सहायता लेनी होगी ताकि स्थायित्व ला कर हिंसा पर लगाम लगाई जाए। मोहम्मद यूनुस के शिखर पर पहुंचने के साथ बांग्लादेश एक नए राजनीतिक युग में प्रवेश कर रहा है, लेकिन उसका भावी रास्ता अनिश्चित है। उनकी तत्कालीन प्राथमिकता जनता का भय दूर करना तथा खासकर अल्पसंख्यकों में सुरक्षा की भावना बहाल करना होगा। लेकिन इन सारी चीजों के साथ चुनावों की घोषणा तक सेना का वर्चस्व बना रहेगा और अंतरिम सरकार के भविष्य के बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। आने वाले दिन यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे कि क्या मोहम्मद यूनुस का नेतृत्व देश को स्थिरता और समृद्धि की ओर ले जा सकता है अथवा क्या बांग्लादेश और अधिक अराजकता व अस्थिरता का शिकार बन जाएगा।

बांग्लादेश में राजनीतिक उथलपुथल

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के समक्ष कानून-व्यवस्था बहाल करने, स्वतंत्र एवं स्वच्छ चुनाव कराने, भ्रष्टाचार से संघर्ष करने तथा जनता का विश्वास प्राप्त करने की चुनौती है।

के. एस. तोमर
(लेखक, राजनीति विश्लेषक हैं)

ब्रिटिश मनोविज्ञानी सियेला एलिजाबेथ ग्रीन के अनुसार, 'तानाशाही में एक व्यक्ति का आदेश लागू होता है, विशिष्ट तंत्र में कुछ लोगों के आदेश लागू होते हैं, जबकि लोकतंत्र में किसी के आदेश नहीं लागू होते हैं।' यह बात बांग्लादेश की सत्ताच्युत प्रधानमंत्री शेख हसीना के मामले में पूरी तरह लागू होती है जिन्होंने अपने पतन के स्पष्ट संकेत पहचानने से इनकार कर दिया था। षडयंत्र की बात की जा रही है जिससे पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी।

इस षडयंत्र में अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए, पाकिस्तानी आईएसआई तथा चीन शामिल थे जो पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के नेतृत्व में सरकार बनाना चाहते थे क्योंकि इससे उनको भविष्य में सत्ता तक पहुंचने का अवसर मिलता। एक और दृष्टिकोण के अनुसार चीन और पाकिस्तान ढाका में भारत-विरोधी सरकार बनाना चाहते थे ताकि दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय संतुलन बदला जा सके। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से बाहर करने के प्रयासों के बारे में अनेक अनुमान और आरोप लगाए जा रहे हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि अमेरिका मानवाधिकारों, लोकतांत्रिक व्यवहारों तथा क्षेत्रीय सुरक्षा स्थितियों के प्रति चिन्ता के कारण ढाका में ज्यादा समर्थक सरकार चाहता था। आलोचकों का कहना है कि दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए 'अमेरिकन हित' ऐसे षडयंत्र में शामिल हो सकते हैं।

लेकिन शेख हसीना के खिलाफ षडयंत्र में अमेरिकन संलिप्तता के कोई ठोस प्रमाण नहीं हैं। आधिकारिक रूप से अमेरिका सरकार ने बांग्लादेश में लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रोत्साहन देते हुए स्वतंत्र चुनावों की बात कही है। सार्वजनिक रूप से अमेरिकन अधिकारियों ने हसीना सरकार के नेतृत्व में राजनीतिक दमन तथा चुनाव प्रक्रियाओं की स्वच्छता की बात कही है, पर उन्होंने किसी सरकार परिवर्तन का कभी समर्थन नहीं किया है। शेख हसीना के प्रशासन ने इन आरोपों का लाभ राष्ट्रवादी भावनायें उभारने तथा अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए उठाया और स्वयं को विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ मजबूत शक्ति के रूप में प्रदर्शित किया। इस विमर्श को अनेक बांग्लादेशियों ने स्वीकार कर राष्ट्रीय संप्रभुता के खिलाफ बाहरी खतरों की भावना को बढ़ावा दिया। जहां शेख हसीना की सरकार गिराने के षडयंत्रों में अमेरिका की प्रत्यक्ष सहभागिता के दावे अनुमानों पर आधारित रहे और इनकी कोई पुष्टि नहीं हुई। लेकिन घरेलू नीतियों तथा बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय संबंधों से एक जटिल स्थिति जरूर पैदा हुई।

हसीना के नाटकीय पतन ने शायद उनको छोड़ कर बहुत से लोगों को आश्चर्यचकित नहीं किया। उन्होंने जनता में बढ़ती निराशा तथा निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा किए जा रहे षडयंत्रों को अनदेखा किया जो दक्षिण एशिया में अपना प्रभुत्व जमाने तथा भारत को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे। जनवरी, 2024 के चुनाव में 300 में से 288 सीटों पर विजय, विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियों तथा विरोध के दमन से हसीना की विश्वसनीयता को भारी धक्का पहुंचा था। इसका परिणाम व्यापक विद्रोह तथा अंतत: उनके खिलाफ तख्तापलट के रूप में सामने आया। शेख हसीना लोकतंत्र-समर्थक नेता थीं जिन्होंने अपने स्वर्गीय पिता शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार का बांग्लादेश में बलिदान देखा।

लेकिन अब सत्ता गंवाने के बाद उन्होंने देश को कट्टरपंथियों, भारत-विरोधी तथा चीन-समर्थक तत्वों के प्रभुत्व वाली संभावित सरकार के लिए छोड़ दिया है। इस प्रकार संभवत: अब बांग्लादेश भविष्य में दो शक्तियों के बीच परेशानियों से घिरा देश बन जाएगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को अनेक चुनौतियों का सामना करना होगा। अंतरिम सरकार को राजनीतिक स्थायित्व बहाल करने के लिए तटस्थ आधार तैयार कर सभी राजनीतिक समूहों से संवाद कर शांतिपूर्ण व लोकतांत्रिक हस्तांतरण सुनिश्चित करना होगा। आगामी चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से सुनिश्चित करने के साथ ही उसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता का विश्वास बहाल करना होगा।

अंतरिम सरकार को न्यायोचित ढंग से भ्रष्टाचार-विरोधी अभियान चला कर हाईप्रोफाइल राजनेताओं और बिजनेसमैनों पर निशाना लगाना होगा। उसे कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए विरोध प्रदर्शनों और नागरिकों में अशांति से सावधानी से निपटना होगा। इसके साथ ही उसे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सुरक्षा बल संयम से काम करें तथा मानवाधिकार उल्लंघनों से बचें। उसे व्यवस्था और मानवाधिकारों के सम्मान के बीच संतुलन बनाए रखते हुए तानाशाही से बचना होगा। जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिए पारदर्शिता, प्रभावी संवाद तथा समावेशी नीतियां जरूरी होंगी। अंतरराष्ट्रीय संगठनों, दानदाता देशों तथा क्षेत्रीय शक्तियों से लगातार समर्थन तथा निवेश प्राप्त करना भी सरकार के लिए जरूरी होगा। पिछले 13 महीनों से बांग्लादेश में जारी राजनीतिक उथलपुथल के कारण नागरिक बहुत परेशान हैं और वे भावनात्मक रूप से उत्तेजित हैं। विशेषज्ञ हिंसक भावनाओं के उभार को राष्ट्र की 'पहचान' पर पैदा टकराव का परिणाम मानते हैं। देश के बचे रहने के लिए इस टकराव का सफल प्रबंधन व इसे संबोधित करना जरूरी है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि शेख हसीना बांग्लादेश में एक सेक्युलर व सुधारवादी शक्ति थीं।

उनकी सरकार ने सुरक्षा के साथ आर्थिक प्रगति सुनिश्चित कर बांग्लादेश को एक सबसे तेज प्रगति करने वाले विकासशील देश में बदल दिया था। इसके बावजूद उनके नेतृत्व पर चुनाव में धोखाधड़ी, विपक्ष के दमन तथा मानवाधिकार उल्लंघनों का आरोप था जिसके कारण जनता में निराशा थी। अभूतपूर्व हिंसा तथा सड़कों पर प्रदर्शनों के कारण संकट अपने शिखर पर पहुंचा। आरोप है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई, जमाते इस्लामी बांग्लादेश की छात्र शाखा तथा खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी-बीएपी व चीनी खुफिया नेटवर्कों की संक्रिय सहभागिता इस संकट को बढ़ाने में शामिल थी।

इस उथलपुथल के बीच नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को सैनिक नेताओं तथा अन्य पक्षों ने परस्पर विचार-विमर्श के बाद अंतरिम सरकार का प्रमुख चुना है। विशेषज्ञों तथा प्रमुख पूर्व राजनयिकों का मानना है कि वर्तमान उथलपुथल हसीना के खिलाफ जनता के गुस्से का उत्पाद थी जो भारत की सहायता से देश छोड़ कर भाग गईं। अब वे यूरोप में राजनीतिक शरण चाहती हैं और ब्रिटेन उनका संभावित ठिकाना है, लेकिन इस बारे में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। बांग्लादेश में 2024 में शेख हसीना के पतन तथा 2022 में श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ तख्तापलट में अनेक समानतायें हैं। दोनों घटनाओं में राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक आयाम शामिल हैं। शेख हसीना की आलोचना विरोध को कुचलने तथा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचाने के लिए हुई। इसी प्रकार गोटाबाया राजपक्षे के प्रशासन पर भी तानाशाही और भाई-भतीजावाद के आरोप लगे थे। दोनों देश आर्थिक संकट, भयानक महंगाई और बेरोजगारी का सामना कर रहे थे जिससे जनता में व्यापक निराशा थी और वह सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रही थी। बांग्लादेश पर कर्ज बढ़ रहा था और वह विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन में कठिनाई का अनुभव कर रहा था, इसी प्रकार श्रीलंका को विदेशी मुद्रा की कमी तथा भारी महंगाई का सामना करना पड़ रहा था जिससे जनता में भारी गुस्सा पैदा हो गया था।

शेख हसीना सरकार का तख्तापलट होने से भारत को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे एक खाली स्थान पैदा हो गया है जिसे ऐसे तत्व भर सकते हैं जो भारत के लिए कम मैत्रीपूर्ण हों। इससे भारत-विरोधी भावनायें भड़क सकती हैं जिससे द्विपक्षीय संबंध प्रभावित हो सकते हैं। राजनीतिक परिवर्तनों से सहयोग व सीमा प्रबंधन, अवैध आप्रवास में संभावित वृद्धि, मानव व्यापार तथा आतंकवाद में वृद्धि हो सकती है। बांग्लादेश के नए नेतृत्व का चीन की ओर झुकाव हो सकता है जिससे बांग्लादेश में चीन की बढ़ती उपस्थिति चिन्ता का कारण बन सकती है।

भारत को इन चुनौतियों से निपटने के साथ ही फिलहाल देखो और प्रतीक्षा करो की नीति पर चलना होगा। बांग्लादेश को अपने समक्ष आई चुनौतियों का सामना करने के लिए तात्कालिक स्थिरीकरण उपायों तथा दीर्घकालीन लोकतांत्रिक सुशासन के बीच समुचित संतुलन बनाना होगा। अंतरिम सरकार की सफलता इन मुद्दों के समुचित प्रबंधन पर निर्भर करेगी जो बांग्लादेश को स्थायित्व देने के दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

शेख हसीना के निष्कासन से भारत को झटका

> मौजूदा अंतरिम सरकार के सहयोगी ऐसे हैं जिनमें चरमपंथी तत्व घुसे हुए हैं, जिनके साथ भारत को अतीत में कड़वे अनुभव रहे हैं।

कुमारदीप बनर्जी
(लेखक नीति विश्लेषक हैं)

इस सप्ताह की शुरुआत में प्रधानमंत्री शेख हसीना को हटाए जाने के साथ ही भारत के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। भारत के पहले से ही संकटग्रस्त पड़ोस में अब तीन देश सशस्त्र बलों की मजबूत पकड़ में हैं। पाकिस्तान, म्यांमार और अब बांग्लादेश, अब सेना द्वारा शासित तिकड़ी हैं, जो चीन के बहुत करीब जाने की फिसलन भरी ढलान पर हैं। इन दोनों में से, बांग्लादेश ही भारत की पड़ोस पहले नीति का मुकुट रत्न रहा है, जहाँ पिछले डेढ़ दशक से स्पष्ट रूप से भारत समर्थक सरकार रही है। पाकिस्तान चीन का छद्म राज्य रहा है जो भारतीय हितों के खिलाफ काम कर रहा है, जबकि म्यांमार भी सेना के शासन के कारण चीन के करीब चला गया है। इस बीच, मालदीव में एक चीन समर्थक (पढ़ें भारत विरोधी) नेता, नेपाल में एक बहुत ज्यादा दिल्ली-अनुकूल शासन, हाल के इतिहास में भारतीय कूटनीति को अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक के रूप में पेश करता है।

पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपनी तानाशाही शासन शैली के बावजूद भारत में द्विदलीय समर्थन प्राप्त था। उन्होंने नरेंद्र मोदी और भारत में विपक्षी नेताओं के साथ अपने संबंधों का इस्तेमाल भारत के हितों के खिलाफ बांग्लादेशी धरती पर सक्रिय चरमपंथी ताकतों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए किया।

यह कोई संयोग नहीं है कि पूर्व प्रधानमंत्री हसीना एक साल में तीन बार नई दिल्ली आई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने में उनके प्रयासों की सराहना की, जब वह केंद्र में नई सरकार के तहत पहली बार राजकीय यात्रा पर आईं। शेख हसीना के डेढ़ दशक के शासन के दौरान भारत-बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंध लगातार

मजबूत होते गए, जिसमें भारत द्वारा महत्वपूर्ण दीर्घकालिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का संचालन किया गया और दोनों पड़ोसियों के बीच नए पारगमन और व्यापार गलियारों में वृद्धि हुई। भारत बांग्लादेश के साथ लगभग 4000 किलोमीटर लंबी भूमि सीमा साझा करता है, जो इसके पांच राज्यों को पड़ोसी के साथ अद्वितीय निकटता प्रदान करता है। यह भूमि सीमा, दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी भूमि सीमा है, जो सौहार्दपूर्ण समय के दौरान माल और लोगों की आवाजाही के लिए एक छिद्रपूर्ण नाली के रूप में कार्य करती है, क्योंकि सरकारें एक-दूसरे के हितों को ध्यान में रखते हुए कड़ी निगरानी रखती हैं। यह शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान स्पष्ट रूप से देखा गया था, जब सीमा पार से तस्करी और आतंकवाद लगभग समाप्त हो गया था। इसने भारतीय राजनयिकों के लिए एक बहुत ही आरामदायक स्थिति बनाई है, क्योंकि उन्होंने भारतीय हितों को ध्यान में रखने के लिए एक मैत्रीपूर्ण शासन पर भरोसा किया है। हालाँकि, शेख हसीना के चले जाने और बांग्लादेश के राजनीतिक क्षेत्र में उनके कभी वापस न आने की संभावना के साथ, चीजें बदलने वाली हैं। भारत ने स्थानीय बांग्लादेशी राजनीति में अपने लिए द्विदलीय समर्थन नहीं बनाया है।

इसने शेख हसीना की सरकार के साथ सहज रहना चुना है और बांग्लादेश में प्रमुख विपक्षी दल के प्रस्तावों को बेपरवाही से निपटाया है। डर यह था कि बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी के प्रति किसी भी तरह का लगाव शेख हसीना को पसंद न आए। इसलिए एक सार्वजनिक कूटनीति कथा सामने आई, कि शेख हसीना भारत के साथ 'बहुत करीब' थीं और अपने देश के हितों के खिलाफ काम कर रही थीं। बांग्लादेश में एक पिंजरे में बंद विपक्ष ने चीन और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से बाहरी समर्थन हासिल करने में कामयाबी हासिल की, दोनों की ही इस क्षेत्र के भू-राजनीतिक मामलों में भारत को लगातार तनाव में रखने में बहुत बड़ी दिलचस्पी है। बांग्लादेश में जमीनी हालात फिलहाल भारत के खिलाफ हैं।

मौजूदा अंतरिम सरकार के सहयोगी ऐसे हैं जिनमें चरमपंथी तत्व घुसे हुए हैं, जिनके साथ भारत को अतीत में कड़वे अनुभव रहे हैं। विरोध प्रदर्शनों की प्रकृति और उसके बाद शेख हसीना को सत्ता से बेदखल किए जाने से यह सुनिश्चित हो गया कि भारत समर्थक होने सहित उनकी कोई भी नीति बांग्लादेशी नागरिकों को पसंद नहीं आएगी।

शेख हसीना विरोधी भावना को आसानी से भारत विरोधी भावना में बदला जा सकता है, जो लंबे समय से चले आ रहे गहरे द्विपक्षीय संबंधों के लिए हानिकारक होगा। बांग्लादेश में नए नेताओं को काम पर लगाना और पूर्वी पड़ोसी के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक सहयोगी बने रहना भारत के लिए एक चुनौती होगी।

आप की बात

मोहम्मद यूनुस से उम्मीद

मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया का पद संभाल लिया। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन के बाद आशा है कि वहां पर शीघ्र ही सामान्य स्थिति बहाल हो जाएगी। मोहम्मद युनुस ने अपने बयान में साफ किया है कि वह भारत से रिश्ते सामान्य बनाए रखने को प्राथमिकता देंगे। उनके इस बयान से दोनों देशों के बीच आशंकाएं खत्म होने की उम्मीद की जा सकती है। मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं की पूरी सुरक्षा के लिए भी शीघ्र कदम उठाने चाहिए। बांग्लादेश की स्थिति सामान्य होते ही चुनाव करवा कर चुनी हुई सरकार के हाथों में सत्ता सौंपी जानी चाहिए। 84 वर्षीय नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस से सबको बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन देखना होगा कि वे वास्तव में कितने प्रभावशाली हो पाएंगे। शेख हसीना की मुख्य विरोधी बेगम जिया की पार्टी बीएनपी ने भारत को धमकी दे डाली है कि वह शेख हसीना को संरक्षण न दे। देखना होगा कि अंतरिम सरकार पर सेना, बीएनपी, चीन-समर्थक तत्वों तथा पाकिस्तान-समर्थक तत्वों का कितना प्रभाव रहता है। ऐसे में यह आशंका है कि कहीं मोहम्मद यूनुस केवल मुखौटा तो नहीं हैं और देखना होगा कि राजनीतिक उथलपुथल में यह मुखौटा भी कब तक बना रहता है।

–**सुभाष बुडावन वाला,** रतलाम

योगी आदित्यनाथ का आह्वान

योगी आदित्यनाथ ने हिन्दुओं से आह्वान किया कि वे आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट हो जाए। योगी आदित्यनाथ का यह आह्वान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वे गोरखनाथ मठ के महंत होने के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। पिछले कुछ समय से भारत के पड़ोसी देशों में भारतीयों विशेषकर हिन्दुओं पर अत्याचार बढ़े हैं। पाकिस्तान में मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हर महीने 20-25 हिंदू लड़कियों का अपहरण कर उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है। वहां 1947 से अब तक सैकड़ों हिन्दू मंदिर नष्ट किये जा चुके हैं। हिंदुओं के सबसे पवित्र स्थलों में से एक हिंगलाज माता मंदिर भी चरमपंथियों के निशाने पर रहा है। जब 1947 में पाकिस्तान का निर्माण हुआ था तब वहाँ हिंदुओं की आबादी लगभग 15 प्रतिशत थी जो1998 तक 1.6 प्रतिशत रह गयी। यही हाल अफ़ग़ानिस्तान का भी है। तालिबानी शासन आने के बाद से वहाँ मुश्किल से 1000 हिंदू परिवार ही बचे हैं। बांग्लादेश में शेख़ हसीना के तख्तापलट के बाद हिन्दुओं को चुन-चुन कर मारा जा रहा है और मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। विडंबना है कि बांग्लादेश की हालिया घटनाओं से मोदी को डराने का प्रयास करने वाले विपक्षी हिंदुओं की हत्याओं पर मौन हैं।

– **पुनीत कुमार,** मेरठ

वक्फ कानून में संशोधन

सरकार द्वारा संसद में पेश वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन और विरोध हो रहा है। हालांकि, वक्फ का इतिहास बहुत पुराना है, पर देश की आजादी के बाद से यह कुछ अमीर व भूतपूर्व जमींदार मुसलमानों की जमीन-जायदाद बचाने का माध्यम बन गया है। जहां जमींदारी उन्मूलन कानून से हिंदुओं की जमींदारियां उनके आसामियों या छोटे किसानों में बांट दी गई थीं, वहीं मुस्लिम जमींदारों ने वक्फ का सहारा लेकर अपना वर्चस्व बनाए रखा। कांग्रेस सरकार ने 1995 व 2013 में वक्फ को असीमित अधिकार दे कर कई मामलों में उनको उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से भी बाहर कर दिया। इसके कारण आज अनेक वक्फ संपत्तियों पर भू-माफिया का कब्जा है और उनको गरीब मुसलमानों के कल्याण के बजाय निहित स्वार्थों के चलते परोक्ष रूप से हस्तांतरित किया जा रहा है। अनेक इस्लामी देशों ने भी वक्फ संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण किया है या वक्फ बोर्डों की शक्तियां बहुत सीमित की हैं। लेकिन विडंबना है कि भारत में इसे मुस्लिमों की धार्मिक भावनाओं से जोड़ कर कुछ राजनीतिक दल अपने मुस्लिम वोटबैंक को बचाने का माध्यम बना रहे हैं। इससे देश और मुसलमानों का भला नहीं होगा।

– **महेश नेनावा,** इंदौर

बांग्लादेश में हिंसा

हसीना सरकार के तख्तापलट और बांग्लादेश में भारी हिंसा के बाद भारत की सीमा पर सैकड़ों उत्पीड़ित बांग्लादेशी हिंदू भारत में शरण लेने के लिए एकत्र हो रहे हैं। हालांकि, अंतरिम सरकार के गठन से कुछ उम्मीदें जगी हैं, पर देखना होगा कि इस सरकार की बागडोर कौन संभाल रहा है और उसके पीछे किसका सपोर्ट है। आशंका है कि चीन-पाकिस्तान बांग्लादेश में आई इस आपदा में अपने लिए अवसर खोज रहे हैं। पाकिस्तान और चीन ऐसी मुखौटा सरकार का गठन बांग्लादेश में करना चाहते हैं जो उनके इशारे पर नाचे तथा बांग्लादेश की जनता को भारत के खिलाफ भड़काने का काम करे। ये देश भारत के खिलाफ बांग्लादेश की सत्ता, जनता और जमीन को खड़ा करना चाहते हैं। तख्तापलट के बाद भी वहां अनेक हिंदुओं के साथ ही अवामी लीग नेताओं और सांसदों की हत्या की गई है। हिंदू मंदिरों और हिंदू बस्तियों में जमकर विध्वंस किया जा रहा है। यह एक सोची समझी साजिश है। भारत सरकार को बॉर्डर पर सख्ती और निगरानी बढ़ाने के साथ ही वहां उत्पीड़ित हिंदुओं को राहत दिलाने के प्रयास करने चाहिए।

– **विभूति बुपक्या,** खाचरोद

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

विचार

एवं व्यवसिते लोके बहुदोषे युधिष्ठिर ।
आत्ममोक्षनिमित्तं वै यतेत मतिमान् नरः ।।

भावार्थ: श्रीकृष्ण कहते हैं- हे धर्मराज युधिष्ठिर! मनुष्य को अपने दोषों को स्वीकार करते हुए अपने मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यही किसी व्यक्ति के वास्तविक बुद्धिमान होने का लक्षण है।

संसद में चर्चा का स्तर

तय समय से पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित संसद के अंतिम दिन राज्यसभा में सपा सांसद जया बच्चन और सभापति जगदीप धनखड़ के बीच जो तीखी तकरार हुई, वह यही बताती है कि सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच संबंध कितने अधिक कटुतापूर्ण हो गए हैं। सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच कटु संबंध केवल राज्यसभा में ही नहीं, बल्कि लोकसभा में भी देखने को मिल रहे हैं। गत दिवस जया बच्चन सभापति जगदीप धनखड़ से इसलिए नाराज हो गईं, क्योंकि उन्हें उनका लहजा पसंद नहीं आया। उन्होंने उनके लहजे पर आपत्ति जताई तो सभापति ने भी उन्हें मर्यादा में रहने का पाठ पढ़ा दिया। इससे वह आपे से बाहर हो गईं। संसद के भीतर और बाहर उनकी तुनकमिजाजी नई नहीं है। वह कभी अपने आधिकारिक नाम जया अमिताभ बच्चन कहे जाने से चिढ़ जाती हैं और कभी इस पर गर्व करने लगती हैं। इस पर हैरानी नहीं कि विपक्ष ने जया बच्चन का साथ देना बेहतर समझा। उसने न केवल सदन का बहिष्कार कर दिया, बल्कि सभापति को हटाने के लिए प्रस्ताव लाने पर भी विचार करने लगा। इसके जवाब में नेता सदन जेपी नड्डा विपक्ष के आचरण के खिलाफ निंदा प्रस्ताव ले आए। फिलहाल कहना कठिन है कि विपक्ष सभापति को हटाने को लेकर कितना गंभीर है और इस मामले में वह कहां तक जाएगा, लेकिन यह स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में दोनों पक्षों के रिश्तों में और अधिक कड़वाहट घुल सकती है। यह कड़वाहट पहले भी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद वह और अधिक बढ़ गई है। इसका असर संसद के कामकाज पर भी पड़ रहा है।

अब संसद में ऐसे सदस्यों की संख्या बढ़ती दिख रही है, जो हंगामा करने की कोशिश में रहते हैं और संसद के नियम-कानूनों और पीठासीन अधिकारी के आदेश-निर्देश की कहीं कोई परवाह नहीं करते। संसद में अब किसी भी विषय पर कठिनाई से ही कोई सार्थक बहस होती है। अधिकांश समय पक्ष-विपक्ष के सदस्य आपस में उलझे रहते हैं। किसी विषय पर धीर-गंभीर चर्चा करने के बजाय वे छींटाकशी करने, मिथ्या आरोप लगाने और एक-दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में रहते हैं। अब तो संसद में अपनी बात कहने के स्थान पर नारेबाजी करने पर अधिक जोर दिया जाने लगा है। कभी-कभी ऐसा लगता है कि यह सब इस कारण अधिक होता है, क्योंकि संसद की कार्यवाही का सीधा प्रसारण होता है। चूंकि संसद में सार्थक चर्चा करने और कराने की कोई ठोस पहल नहीं होती, इसलिए वहां हंगामा और शोर-शराबा ही अधिक होता है। यदि संसद में लोक महत्व के विषयों पर गंभीर चर्चा नहीं होगी तो जनता से यह अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए कि वह उसे अपनी आकांक्षाओं का मंच और लोकतंत्र का मंदिर माने। यह भी तय है कि यदि संसद में सार्थक चर्चा नहीं होगी तो उसका असर विधेयकों की गुणवत्ता पर भी पड़ेगा।

जर्जर भवनों पर नरमी

जर्जर भवनों के गिरने से हुई दुर्घटनाओं के बावजूद प्रशासन जाग नहीं रहा है। पिछले दिनों गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में मकान की दीवार गिरने से पति-पत्नी की जान चली गई थी। वहीं बच्चा घायल हो गया था। मध्यप्रदेश के सागर जिले में जर्जर मकान में दबकर नौ बच्चों की मौत हो चुकी है। वर्षाकाल के चार महीने में जर्जर भवन सबसे अधिक खतरनाक होते हैं। वर्षा के दौरान पानी रिसने से दीवार भीगने से भरभराकर गिरने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए ऐसे जर्जर भवनों को गिराना ही एकमात्र उपाय है। मगर इस मामले में हर स्तर पर लापरवाही हो रही है। सबसे पहले भवनों मालिकों को ही इसकी पहल करना चाहिये। प्रशासन को ही सख्ती करना चाहिये। मगर ऐसा होता नजर नहीं आता है। अकेले राजधानी रायपुर में 137 जर्जर भवनों की सूची निगम ने तैयार कर ली है, लेकिन कार्रवाई के नाम शून्य है। शहर की मुख्य सड़क पर फूल चौक, सद्दाणी चौक, रामनगर में कई जर्जर भवन हैं, जिन्हें तत्काल तोड़ना चाहिये। मगर नगर निगम केवल नोटिस की औपचारिकता पूरी कर खामोश हो जाता है। निगम का यह रवैया कहीं से भी उचित नहीं है। ज्यादातर भवन रोड के किनारे हैं और उनसे सटकर कई और मकान हैं। इस वजह से हमेशा जनहानि की आशंका बनी रहती है। जर्जर स्कूल भवनों में हुए हादसे के बाद शासन की नींद खुली जरूर है। ऐसे भवनों में कक्षा लगाने पर रोक लगाई गई है। साथ ही उन भवनों की जांच भी हो रही है। जर्जर भवनों के मामले में शासन-प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारियों को किसी भी तरह की नरमी नहीं बरतना चाहिये। ऐसे भवनों को चिन्हित कर शीघ्र से शीघ्र ध्वस्त कर देना चाहिये। आम आदमी की जान के लिए खतरा बन चुके ऐसे भवनों को यूं ही छोड़ देना, किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। प्रशासन को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए।

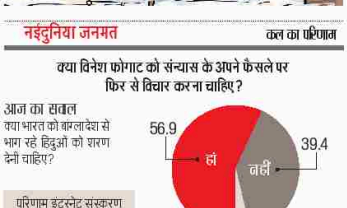

अकेले राजधानी रायपुर में 137 जर्जर भवनों की सूची निगम ने तैयार कर ली है, लेकिन कार्रवाई के नाम शून्य है। शहर की मुख्य सड़क पर फूल चौक, सद्दाणी चौक, रामनगर में कई जर्जर भवन है, जिन्हें तत्काल तोड़ना चाहिये।

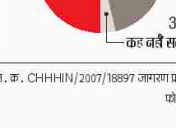

कह के रहेंगे

माधव जोशी

नईदुनिया जनमत

कल का परिणाम

क्या विनेश फोगाट को संन्यास के अपने फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए?

आज का सवाल
क्या भारत को बांग्लादेश से भाग रहे हिंदुओं को शरण देनी चाहिए?

परिणाम इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

पराभव की ओर बढ़ता ब्रिटेन

हर्ष वी. पंत

हालिया दंगे यही दर्शाते हैं कि दुनिया को लोकतांत्रिक मूल्यों पर उपदेश देने वाला ब्रिटेन अपना ही घर दुरुस्त नहीं रख पा रहा है।

अवधेश राजपूत

बीते कुछ दिनों के दौरान ब्रिटेन के तमाम हिस्सों में बड़े पैमाने पर दंगे भड़क गए। दंगों की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन पर काबू पाने में करीब सप्ताह भर का समय लग गया। सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी और तमाम कड़े कदम उठाने के बावजूद स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। पता नहीं कहां विवाद की छोटी सी चिंगारी किसी विकराल दंगे का रूप धारण कर ले। हालिया प्रकरण 29 जुलाई को एक नृत्य कार्यक्रम के बाद शुरू हुआ। उत्तरी इंग्लैंड के साउथपोर्ट में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान तीन बच्चियों की हत्या कर दी गई। जबकि कुछ अन्य घायल हो गए। हमलावर के बारे में इंटरनेट मीडिया पर यह अफवाह उड़ी कि वह मुस्लिम समुदाय से जुड़ा है, जो ब्रिटेन में शरण पाने वाला एक अप्रवासी है। इसके बाद मुस्लिम समुदाय और अप्रवासी स्थानीय लोगों के निशाने पर आ गए। हालांकि बाद में यह स्पष्ट हुआ कि 17 वर्षीय मुख्य हमलावर एक्सल रुदाकुबाना वेल्स में ही पैदा हुआ है, जिसके माता-पिता रवांडा से ब्रिटेन आए थे। जब तक तस्वीर साफ होती, उससे पहले ही लोगों ने साउथपोर्ट में एक मस्जिद को निशाना बनाने का प्रयास किया।

हमलावर भले ही पकड़ लिया गया हो, मगर इस मामले ने ब्रिटिश लोगों को भड़का दिया। आक्रोशित भीड़ ने रादरम में उस होटल पर भी हमला बोला, जिसमें राजनीतिक शरण मांगने वालों को रखा जाता है। इतना ही नहीं, लिवरपूल, ब्रिस्टल, मैनचेस्टर और ब्लैकपूल में भी हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। ऐसे करीब 20 वाकयों में कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। इस प्रकार के हिंसक प्रदर्शन भले ही एक तात्कालिक प्रतिक्रिया हों, लेकिन इसकी सुगबुगाहट ब्रिटिश समाज में काफी पहले से महसूस की जा रही थी। यही कारण है कि सरकार संवेदनशील वर्गों को लेकर सक्रिय हुई है। मिसाल के तौर पर अप्रवासी मामलों को देखने वाले वकीलों की सुरक्षा को लेकर भी उठते सवालों पर ध्यान दिया जा रहा है। देखा जाए तो सतही तौर पर कानून एवं व्यवस्था से संबंधित दिखने वाले इस मामले की जड़ें अप्रवास विरोध और ब्रिटिश समाज में गहराती विभाजक रेखाओं से जुड़ी हैं। आने वाले दिनों में इसके और घातक परिणाम देखने को मिल सकते हैं।

अप्रवासियों को लेकर ब्रिटेन में पिछले कुछ समय से असंतोष बढ़ रहा है। तमाम ब्रिटिश नागरिक ऐसा सोचते हैं कि अप्रवासियों की बढ़ती संख्या के चलते हाउसिंग, शिक्षा, और स्वास्थ्य से जुड़ी सरकारी कल्याणकारी योजनाओं में उनके हितों में सेंधमारी हो रही है। उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन में यूरोपीय संघ से अलग होने वाले ब्रेक्जिट अभियान को भी इसी पहलू के चलते सफलता मिली थी कि इससे अप्रवासियों पर अंकुश लगाने के साथ नीति-निर्माण में ब्रिटिश स्वायत्तता बढ़ेगी। हालांकि कंजरवेटिव पार्टी ने अप्रवासियों के चलते पनप रहे असंतोष पर काबू पाने के लिए कुछ उपाय जरूर किए, लेकिन लगता नहीं कि ब्रिटिश जनता उन उपायों से संतुष्ट हुई होगी। हालिया चुनावों में लेबर पार्टी की जीत ने भी इस मामले में उन दक्षिणपंथी समूहों को भावनाएं भड़काने की गुंजाइश दी होगी, जिन्हें ब्रिटिश प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर बीते दिनों हुए दंगों का दोषी ठहरा रहे हैं। ऐसी धारणा है कि लेबर पार्टी अप्रवासियों के प्रति अपेक्षाकृत नरम रवैया रखती है।

प्रधानमंत्री स्टार्मर ने कहा है कि दंगाइयों से निपटने के हरसंभव सख्त उपाय किए जाएंगे, लेकिन दंगों की आग पर काबू पाने में करीब सप्ताह भर का समय लगना अपने आप में काफी कुछ कह देता है। शासन-प्रशासन के स्तर पर आश्वासन के बावजूद हालात इतने बिगड़ गए कि लोगों को अपनी एवं अपने आवास और प्रतिष्ठान की सुरक्षा के लिए निजी स्तर पर भी कदम उठाने पड़ रहे हैं, क्योंकि हिंसा के दौरान तमाम दुकानों एवं प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। स्टार्मर ने जिन धुर दक्षिणपंथी संगठनों को इस हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया है, उनमें इंग्लिश डिफेंस लीग का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। वर्ष 2009 में अस्तित्व में आया यह संगठन अप्रवासी विरोध विशेषकर इस्लाम के खिलाफ अपने रुख के लिए जाना जाता है। पूर्व में हुई हिंसा में भी इसका नाम आता रहा है। हालांकि यह ऐसा कोई इकलौता संगठन नहीं है। मुख्यधारा की राजनीति में भी यूके रिफार्म पार्टी के नेता नाइजल फराज ने अप्रवासियों और शरणार्थियों की भड़ती भीड़ को हालिया हिंसा के लिए आड़े हाथों लिया। एक समय कंजरवेटिव पार्टी में रहे फराज ने अपनी आक्रामक राजनीति के लिए नए राजनीतिक दल का गठन किया। हालिया चुनावों में उनकी पार्टी को भले ही चार सीटें मिली हों, लेकिन कई सीटों पर वह कंजरवेटिव पार्टी की हार का कारण भी बने। उनके प्रति लामबंद होता समर्थन ब्रिटिश जनता के सोच में आ रहे बदलाव को दर्शाता है, जिसकी समय-समय पर आक्रामक अभिव्यक्ति भी देखने को मिलती रहती है। हाल के दंगे ऐसा ही एक उदाहरण रहे। हालिया दंगे दर्शाते हैं कि ब्रिटिश समाज में निराशा बढ़ रही है। उन्हें अप्रवासियों से अपने अवसरों पर आघात के साथ ही अपनी मूल सांस्कृतिक पहचान पर संकट भी दिख रहा है। चूंकि मुस्लिम समुदाय भी अपने प्रतीकों को लेकर खासा मुखर रहता है तो उसके साथ टकराव कुछ ज्यादा बढ़ रहा है।

दंगों के बाद प्रधानमंत्री स्टार्मर ने ऐसा आश्वासन दिया कि यह जिनका भी किया-धरा है, उन्हें इसकी सजा जरूर भुगतनी होगी। कानून उन पर अपना शिकंजा कसेगा। कई मामलों में दंगाइयों पर ऐसी धाराएं भी लगाई गई हैं, जो आतंकी मामलों में लगाई जाती हैं। इंटरनेट मीडिया के जरिये फर्जी सूचनाओं के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए भी कमर कसी गई है। इस सबके बावजूद कुछ सवाल जरूर उठते हैं। पहला यही कि क्या यह एक तात्कालिक आक्रामक प्रतिक्रिया थी या फिर ब्रिटेन में यह एक नया सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि वहां अब समय-समय पर दंगे भड़कते रहते हैं। इससे पूर्व भी दो साल पहले लेस्टर में दंगे हुए थे। दूसरा सवाल यह कि दुनिया को लोकतांत्रिक मूल्यों पर उपदेश देने वाला ब्रिटेन अपना ही घर दुरुस्त क्यों नहीं रख पा रहा है? जो भी हो, इन दंगों ने ब्रिटेन की साख चोट करने के साथ ही उसके पराभव के भी संकेत दिए हैं।

(लेखक आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में उपाध्यक्ष हैं)

जीवन के चौथेपन में टूटते रिश्ते

क्षमा शर्मा

इन दिनों विवाह के दशकों बाद पति-पत्नी का अलग हो जाना एक नया चलन बनता जा रहा है।

बढ़ रहे हैं अधिक उम्र में तलाक के मामले ● प्रतीकात्मक

बहुत समय से एक नामचीन नायक-नायिका के तलाक की खबरें इंटरनेट मीडिया पर छाई हुई हैं। लोग दावा कर रहे हैं कि बस ऐसा होने ही वाला है। सच क्या है, कहा नहीं जा सकता, लेकिन ग्रे डाइवोर्स यानी कि विवाह के दशकों बाद पति-पत्नी का अलग हो जाना, इन दिनों बेहद चलन में है। महिलाएं कह रही हैं कि एक खराब रिश्ते में जीवन बिताने से अच्छा है कि जब मौका मिले, अलग हो जाएं। इस लेखिका ने कई स्त्रियों को खुद देखा है। कई साल पहले यह लेखिका जिस संस्थान में काम करती थी, वहां एक महिला आई। उसे काम चाहिए था। उसकी उम्र उस समय 50 वर्ष रही होगी। उसका कहना था कि पति बहुत तंग करते हैं। सुबह शाम मार-पीट, हर रात शराब पीकर आना है। वह महिला उच्च शिक्षित भी थी, लेकिन नौकरी नहीं करती थी। वह सब कुछ इतने साल इसलिए सहन करती रही कि अपने बेटे के बड़े होने का इंतजार कर रही थी। अब वह अपने पांवों पर खड़ा होना चाहती थी। उसी समय के आसपास एक वरिष्ठ महिला पत्रकार ने अपने बहुत मशहूर पति से अलग होने पर पार्टी दी थी और अपनी आजादी का जश्न मनाया। यह कोई नई-अनोखी बात नहीं कि अब तलाक की भी पार्टी होने लगी हैं। लोग उसका जश्न मनाने लगे हैं।

ग्रे डाइवोर्स का अर्थ बताया जाता है कि जब पति-पत्नी 50 की उम्र के बाद अलग हों यानी जब बालों में सफेदी छाने लगे। हालांकि जो लोग ऐसा करते हैं, उनकी राह भी आसान नहीं होती। बहुत बार जमीन-जायदाद का फैसला करना मुश्किल हो जाता है, जो संयुक्त होती है या बैंक खाते संयुक्त होते हैं। इसके अलावा बड़े बच्चे भी माता-पिता के इस तरह से अलग होने को सह नहीं पाते। कई बार बच्चे माता-पिता को इसके लिए प्रेरित भी करते हैं। एक लड़के ने जीवन भर अपनी मां को पिता के हाथों प्रताड़ित होते देखा। बड़े होने पर उसने मां से कहा कि इतना अपमान सहने से बेहतर है कि वे दोनों अलग हो जाएं। फिल्मी दुनिया में भी जहां अक्सर पति-पत्नी एक खुशहाल परिवार की तस्वीर पेश करते हैं, वहां भी ऐसा हो रहा है। इसमें फरहान अख्तर-अधुना भबानी, अरबाज खान-मलाइका अरोड़ा, ईशा देओल-भरत तख्तानी, सोनम खान-राजीव राय, किरण राव-आमिर खान, रितिक रोशन-सुजैन खान, अर्जुन रामपाल-मेहर जेसिया जैसे जोड़े शामिल हैं। इन सबके बड़े-बड़े बच्चे भी हैं।

किरण राव ने कुछ दिनों पहले साक्षात्कार में कहा था कि आमिर से उनके संबंध बहुत मधुर हैं। तलाक ने उन्हें आजादी दी है। वह खुद के महत्व को पहचानना चाहती थीं। अपने तलाक पर अर्जुन रामपाल ने इससे बिल्कुल अलग बात की। उन्होंने कहा था कि तलाक बहुत आसान नहीं होता। यह आपके अकेलेपन को बढ़ाता है। जितने भी फिल्मी जोड़े एक-दूसरे से अलग हुए हैं, वे अपने पूर्व साथी के बारे में अच्छी बातें करते हुए यह भी कहते हैं कि वे दोनों सबसे अच्छे दोस्त हैं। फिल्मकार अनुराग कश्यप जब कल्कि कोचलीन से अलग हुए तो कुछ दिन बाद उन्होंने कहा था कि जब वे दोनों साथ थे, तो हमेशा लड़ते रहते थे, मगर अब दोनों में खूब मित्रता है। कश्यप इससे पहले भी अपनी पत्नी से अलग हो चुके थे। बहरहाल, ये जोड़े यह भी कहते हैं कि जिस साथी से अलग हुए, वह बहुत अच्छा इंसान है। क्या यह सोचकर आश्चर्य नहीं होता कि यदि कोई इतना अच्छा इंसान और मित्र है, तो फिर अलग क्यों होना पड़ा? शायद इसका जवाब किसी के पास नहीं होता।

प्यू रिसर्च ने अमेरिका में ग्रे डाइवोर्स पर एक अध्ययन किया। इसमें बताया गया कि पिछले दो दशकों में तलाक के सारे मामलों में 40 प्रतिशत मामले ऐसे थे, जिनमें 50 और उससे ऊपर के जोड़े शामिल थे। 1990 के बाद इनकी संख्या दोगुनी हो गई और अब जो लोग 65 से ऊपर हैं, उनकी संख्या तिगुनी हो गई है। विशेषज्ञ कहते हैं कि जब तक लोग अपने बच्चों को पालते हैं, तब तक वे किसी तरह साथ रह लेते हैं, मगर जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं, उनका अपना घर और परिवार होता है, तो पति-पत्नी को लगता है कि अब उन्हें एक-दूसरे की जरूरत नहीं रही। इसके अलावा अपने देश में स्त्रियों के प्रति जो हिंसा है, उसे शायद वह बच्चों के कारण झेलती रहती हैं, लेकिन आज की स्त्रियां पांच दशक पहले की स्त्रियां नहीं हैं, जो किसी भी बुरे संबंध को समाज के डर से निभा लेती थीं। आज वे पहले की तरह से अपने पति पर निर्भर नहीं हैं। निर्णय लेने की उनकी क्षमता बढ़ी है। इसलिए वे भी तलाक की पहल करती हैं और बुरे रिश्ते से आजादी चाहती हैं, लेकिन यह बात भी सच है कि बच्चों पर इसका बुरा असर पड़ता है। मेरे दफ्तर आई उसी महिला के लड़के ने एक बार कहा था कि आप ही बताइए, मैं किधर जाऊं। मुझे तो अपने माता-पिता दोनों से प्यार है। मैं एक से मिलने जाता हूं तो दूसरा बुरा मानता है।

हालांकि इस मामले में फिल्मी दुनिया के लोग अक्सर अपने बच्चों पर इस तरह का प्रतिबंध नहीं लगाते। जब वे अलग होते हैं तो कहते हैं कि अपने बच्चों के लिए वे दोनों हमेशा, हर स्थिति में मौजूद रहेंगे, लेकिन आम लोगों की दुनिया में ऐसा नहीं हो पाता। कड़वाहट इतनी ज्यादा होती है कि वे एक-दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। यह भी देखा गया है कि बहुत से जोड़े अलग होने के बाद फिर से साथ रहने लगते हैं। इसके पीछे यह सच भी है कि जीवन के चौथेपन में आपको साथी और साहचर्य भाव की जरूरत सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि बच्चे अपनी-अपनी राह चले गए होते हैं। शायद इसीलिए कुछ लोग वापस लौटकर अपना जीवन फिर से शुरू करते हैं।

(लेखिका साहित्यकार हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

अध्यात्म से उत्थान

हमारे मनीषियों ने आध्यात्मिकता का अपेक्षित प्रसार एवं महिमामंडन किया है। यही कारण है कि भौतिक शक्ति के युग में पाले-पोसे हुए हम ही नहीं, अपितु विदेशी भी संयम, साधना और आराधना के कठोर एवं कठिन मार्ग की ओर आकर्षित हो रहे हैं। अध्यात्म जगत का आकर्षण है ही कुछ ऐसा अद्भुत जो हमें सिखाता है कि जब मन-मस्तिष्क विषय रूपी वन में स्वच्छंद विचरण करना चाहता है तो उस पर ज्ञान का अंकुश लगाकर रोकें। कान जब सहज सुंदर सुर बालाओं के मधुर संगीत की स्वर लहरी सुनने के लिए उत्सुक हों तब विवेक से उन पर अधिकार करें। नेत्र आधुनिक अप्सराओं के मनमोहक दृश्य देखने के लिए जब छटपटाने लगें तब विचारों के अंकुश से उन पर लगाम लगाएं। नाक अपनी हठधर्मिता पर अड़कर प्राकृतिक पुष्पों की सुगंध सौरभ लेने के बजाय इत्र की कृत्रिम गंध के लिए उतावली हो तो अपने चिंतन की धारा से उसका प्रवाह बदल दें। काया जब-जब सुकोमल पदार्थों के संस्पर्श के लिए इच्छुक हो तो अपने सम्यक ज्ञान से उसे वश में करें। यह सब कुछ इसलिए कि मन और इंद्रियों का प्रवाह विकारों की ओर होता है और जब तक उसे मोड़ा नहीं जाएगा तब तक हमारे जीवन का उद्धार संभव नहीं।

मानव ने विज्ञान के भरोसे संसार पर विजय पताका फहराई है, किंतु अगर वह मन की मलिन वृत्तियों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता तो यह विजय उसकी सच्ची विजय नहीं है। केवल विजय का आभास मात्र है। मृगमरीचिका की भांति वह विशुद्ध भ्रम है। स्मरण रहे कि हमारा मन बहुत शक्तिमान है। वही इच्छाओं-आकांक्षाओं के रथ का सारथी भी है। बिना पंख का पक्षी है, किंतु हमारी आत्मशक्ति मन से भी अधिक बलवान है। हम चाहे तो अभ्यास और साधना से मन को हर कुमार्ग से सन्मार्ग की ओर उत्प्रेरित कर सकते हैं। अशुभ चिंतन को छोड़कर शुभ चिंतन करना ही वस्तुतः श्रेय का मार्ग है। प्रशस्त मन उत्थान का कारण है और अप्रशस्त मन पतन का निमित्त बनता है।

डा. निर्मल जैन

पाठकनामा

letter@naidunia.com

बांग्लादेश में हिंदुओं पर संकट

'संकट में बांग्लादेशी हिंदुओं का अस्तित्व' शीर्षक से लिखे आलेख में कृपाशंकर चौबे ने उचित ही लिखा कि दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहां किसी न किसी प्रकार के अल्पसंख्यक न मिलें। भाषा, नस्ल, रीति-रिवाज, मान्यताएं, धर्म, जाति के आधार पर ऐसे अल्पसंख्यकों की कुछ न कुछ मौजूदगी रहती ही है। इसका मतलब यह नहीं है कि अल्पसंख्यक आबादी को बहुसंख्यक सहन करने की स्थिति में न हो। अगर ऐसा है तो वह वास्तविक लोकतंत्र के बजाय छद्म लोकतंत्र है। लोकतंत्र तो सहिष्णुता, शांति और सौहार्द का पर्याय है, जो सह-अस्तित्व की संकल्पना को पुष्ट करता है। यही कारण है कि सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति में से एक लोकतंत्र है। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एशिया और अफ्रीका के जिन देशों ने औपनिवेशिक शासन से मुक्ति पाई वहां लोकतंत्र को अपनाया तो गया, लेकिन उसे वास्तविक अर्थों में आत्मसात नहीं किया जा सका। यह सोचने का विषय है कि वास्तविक लोकतंत्र के अनुकूल परिवेश के निर्माण के लिए क्या करने की जरूरत है? साथ ही यह समय भारत सहित समूचे अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए भी बांग्लादेश पर दबाव बनाने का भी है कि वहां हिंदुओं सहित अन्य अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न पर तत्काल विराम लगे। mukeshkr.m7542@gmail.com

एक और पड़ोसी देश बना कट्टरपंथी

सन् 1971 के मुक्ति आंदोलन के 53 वर्ष बाद अब बांग्लादेश में तख्तापलट हो गया। 1971 में मुक्ति आंदोलन में शेख मुजीबुर्रहमान, उनकी पत्नी एवं बेटों को पाकिस्तानी सेना ने हलाक कर दिया था। तब शेख हसीना इसलिए बच गई थीं, क्योंकि वह भारत में थीं। शेख हसीना ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहते हुए अपने कार्यकाल में भारत विरोधी गतिविधियों को संचालित करने वाले तत्वों को चुन-चुन कर समाप्त किया। किंतु कट्टरपंथियों ने छात्र आंदोलन की आड़ में हसीना को पद छोड़कर रातोंरात देश छोड़ने के लिए विवश कर दिया। यह घटनाक्रम बताता है कि बांग्लादेश भी अब पाकिस्तान की तरह कट्टरपंथ की राह पर है। भारत को चाहिए कि इस देश को नियंत्रण में रखे।

- श्याम सुंदर जोशी, सुदामा नगर, इंदौर

नैतिकता शर्मसार हो गई होगी

समाचार : 17 माह बाद जेल से बाहर आए आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया, शराब नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत।

टिप्पणी : जमानत पर जेल से बाहर आए सिसोदिया का ऐसा स्वागत किया जा रहा है, मानो वह ओलिंपिक में कोई पदक जीतकर आए हों। विजय जुलूस में कितनी निर्लज्जता थी। मुस्कुराते मनीष को देखकर नैतिकता शर्मसार हुई होगी।

- मधु सुभाष बुड़ावनवाला, रतलाम

बांग्लादेश हिंसा से सीख लेनी ही होगी

बांग्लादेश में भड़की हिंसा के बाद यह बात अब और स्पष्ट हो गई है कि दुनिया के किसी भी मुस्लिम बहुल देश में अन्य किसी धर्म के लोग सुरक्षित नहीं रह पाते। गनीमत है कि भारत में हिंदू बहुसंख्यक हैं इसलिए यहां सभी धर्म, मत, पंथ फलते-फूलते रहे हैं। वर्तमान समय में भी केवल भारत में ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध आदि सब सुखपूर्वक रह रहे हैं। भारत में एक दृढ़संकल्पित और मजबूत सरकार होने के कारण यहां सबकुछ नियंत्रित है। किंतु जिस तरह से पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा व अन्य ने बदजुबानी की, उससे लगता है कि ऐसे लोग देश में दंगा भड़काना चाहते हैं। बहरहाल, बांग्लादेश में हिंदुओं के हाल देखकर याद आता है कि वह बंगभूमि कभी हिंदुओं की ही थी, किंतु पहले मुस्लिमों ने अलग पाकिस्तान ले लिया और फिर बंगाली मुसलमानों ने भारत की मदद से अलग बांग्लादेश बना लिया। जिस जमीन पर कभी रवीन्द्रनाथ टैगोर की कविताएं गूंजती थीं, वहां अब हिंदुओं का रक्त बहाया जा रहा है। हिंदुओं को अब यह बात समझनी होगी कि जमीन छोड़ते जाएंगे, तो अंत में कहां जाएंगे।

- यदुनाथ सिंह राठौड़, इंदौर

X पोस्ट

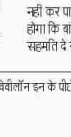

हाकी में नवीन पटनायक का योगदान विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा है और इसका प्रत्यक्ष प्रभाव 2020 और 2024 ओलिंपिक खेलों में भारत के कांस्य पदक जीतने के रूप में स्पष्ट दिखा। मरूकांतार@marukantaar

मैं फिर से कहना चाहूंगा कि नीरज चोपड़ा ट्रैक एंड फील्ड में भारत के सर्वकालिक महानतम एथलीट हैं। एक स्वर्ण और उसके बाद उनका रजत पदक कई पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। शेखर गुप्ता@ShekharGupta

नीरज गोल्ड से चूके नहीं, बल्कि उन्होंने सिल्वर जीता है। यह उनका दूसरा बेस्ट सीजन थ्रो था। अरशद नदीम का थ्रो उनसे बेहतर था, इसलिए वह गोल्ड जीते। चूकने जैसे शब्द से किसी की मेहनत पर पानी न फेरें। सिल्वर कोई रसगुल्ला नहीं कि कोई भी गटक ले। खिलाड़ी भी मनुष्य है। अणु शक्ति सिंह@AnushaktiSing

हमें नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए में 2014 की कट आफ डेट बदलनी होगी, ताकि बांग्लादेश में सताए जा रहे हिंदू भी भारत आ सकें। अगर मोदी और शाह ने ऐसा नहीं किया तो वह प्रताड़ित बांग्लादेशी हिंदुओं की कभी मदद नहीं कर पाएंगे। इस मामले में निष्क्रियता का यही अर्थ होगा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार को आप मौन सहमति दे रहे हैं। आर. जगन्नाथन@TheJaggi

आर.एन.आई. रजि. क्र. CHHHIN/2007/18897 जागरण प्रकाशन लि. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक संजय शुक्ला द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के प्रेस प्लॉट न. 47/3, भनपुरी इंडस्ट्रियल एरिया, रायपुर से मुद्रित एवं तीसरी मंजिल, कृष्णा ग्लोरी कॉम्पलेक्स, साईं नगर, होटल वेबीलॉन इन के पीछे, जेल रोड, रायपुर से प्रकाशित
फोन नं. 0771-4711000 फैक्स : 0771-4711024 इंटरनेट संस्करण : http://www.naidunia.com संपादक : सद्गुरु शरण* *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार।

****

संपादकीय

"कुछ दशकों में भारत और चीन नाटकीय और गतिशील प्रतिस्पर्धी के रूप में उभरे हैं। -पीटर मैंडेलसन

ऐसे वक्त में जब तमाम विकसित देश नीतिगत दरों में बदलाव ला रहे हैं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों को लगातार नौवीं बार अपरिवर्तित रखना अप्रत्याशित नहीं है। दरअसल, केंद्रीय बैंक महंगाई और विकास दर में तालमेल बैठाते हुए आगे बढ़ना चाहता है, ताकि आम आदमी पर बोझ न बढ़े।

महंगाई और विकास

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा खाद्य महंगाई से जुड़े जोखिमों का हवाला देते हुए लगातार नौवीं बार नीतिगत दरों को अपरिवर्तित रखना अप्रत्याशित नहीं है, लेकिन इससे वर्तमान आर्थिक परिदृश्य की अनिश्चितता के संकेत जरूर मिलते हैं। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय बैंक अमूमन रेपो दर में बढ़ोतरी कर महंगाई से लड़ने का प्रयास करता है। रेपो दर अधिक होने पर बैंकों को केंद्रीय बैंक से महंगा कर्ज मिलता है और बदले में बैंक भी ग्राहकों को महंगी दर पर कर्ज देते हैं। इससे अर्थव्यवस्था में तरलता कम होती है और लोगों की जेब हल्की होने से वस्तुओं की मांग में कमी आती है। मांग कम होने से बिक्री भी कम हो जाती है और महंगाई में भी कमी आती है। इसके विपरीत, विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए बाजार में तरलता बढ़ाने की कोशिश की जाती है। इसके लिए रेपो दर में कटौती की जाती है, ताकि बैंकों को केंद्रीय बैंक से और आम आदमी को बैंकों से सस्ता कर्ज मिल सके। लेकिन, एमपीसी ने नीतिगत दर साढ़े छह फीसदी के स्तर पर बनाए रखते हुए स्पष्ट किया है कि वर्तमान परिस्थितियों में उदारता नहीं बरती जा सकती। अनाज, दालें और सब्जियों जैसी खाद्य श्रेणियों में मुद्रास्फीति ऊंची बनी हुई है। हालांकि, मुख्य मुद्रास्फीति, जिसमें अस्थिर खाद्य और ईंधन घटकों को शामिल नहीं किया गया है, अब तक कम बनी हुई है। मई और जून में तो यह 3.1 फीसदी के ऐतिहासिक निचले स्तर पर थी। लेकिन अगर बढ़ती खाद्य महंगाई का असर इस पर पड़ा, तो यह अवश्य ही चिंता की बात होगी। उल्लेखनीय है कि रिजर्व बैंक ने ऐसे वक्त में नीतिगत दरों को अपरिवर्तित रखा है, जब इंग्लैंड, जापान और अमेरिका सहित तमाम विकसित देशों के केंद्रीय बैंक नीतिगत दरों में बदलाव ला रहे हैं। लेकिन रिजर्व बैंक का यह कहना महत्वपूर्ण है कि खाने-पीने की चीजों की बढ़ती महंगाई को अनदेखा नहीं किया जा सकता

और इसके दूसरे क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभाव को रोकने की भी जरूरत है। हालांकि केंद्रीय बैंक का यह कहना आश्वस्तकारी है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून में तेजी से खाद्य महंगाई में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। दरअसल महंगाई को लेकर के बैंक के संवेदनशील रुख को समझा जा सकता है, जिसके रेपो दर में बदलाव न करने के फैसले से संकेत मिलता है कि वह महंगाई और विकास दर में तालमेल बैठाते हुए आगे बढ़ना चाहता है, ताकि आम आदमी पर महंगाई का बोझ न बढ़े और अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक स्थिरता भी मिल सके।

चीन पर काबू रखना जरूरी है

ढाका में शेख हसीना के पतन से चीन को खुला मैदान मिल गया है। ऐसे में, भारत को सुनिश्चित करना होगा कि 'पड़ोसी पहले' की उसकी नीति नए भू-राजनीतिक बदलावों के साथ तालमेल में हो। साथ ही, चीन को काबू में रखने के लिए भारत और अमेरिका को भी संयुक्त रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा।

ढाका में शेख हसीना शासन के पतन और उसके अंतरराष्ट्रीय प्रभाव को देखते हुए चीन का मुकाबला करने के लिए भारत एवं अमेरिका को एक संयुक्त रणनीति बनाने की सख्त जरूरत है, जिसने पहले ही अपनी विस्तारवादी नीति के जरिये हमारे अधिकांश पड़ोसियों को फंसा लिया है और बांग्लादेश उस सूची में शामिल होने वाला एक नया नाम है।

विदेश नीति के विशेषज्ञों का मानना है कि पारस्परिक हित और बाध्यता के सिद्धांत के कारण भारत और अमेरिका को बांग्लादेश के प्रति अपनी मौजूदा नीति में बदलाव लाना होगा, जो चीन और पाकिस्तान की राह पर चल रहा है और जिससे दक्षिण एशिया में सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना आरोप लगा रही हैं कि उनकी सरकार को अस्थिर करने में अमेरिका का हाथ रहा है। लेकिन भारत बांग्लादेश की नई सरकार से अलग-थलग नहीं रह सकता है, जिसका नेतृत्व वही खालिदा जिया कर सकती हैं, जो खुद को भारत-विरोधी खेमे का मानती हैं।

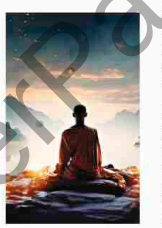

केएस तोमर
राजनीतिक विश्लेषक

ढाका की नई सरकार पर खालिदा जिया और कट्टरपंथी हावी हो सकते हैं, जिससे भारत के लिए सिरदर्द पैदा हो सकता है। अमेरिका को हसीना शासन के निष्कासन से खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे चीन मजबूत होगा, जो महाशक्ति देश के रूप में अमेरिका की जगह लेना चाहता है। इसलिए अमेरिका को भारत की मदद से चीन का मुकाबला करने की जरूरत है, क्योंकि भारत विश्व मंच पर आर्थिक ताकत के रूप में उभर रहा है। साथ ही भारत को चीन के बढ़ते प्रभाव पर नजर रखनी होगी, जिसने पहले ही मालदीव, नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान और श्रीलंका तक को अपने पाले में मिला लिया है। बांग्लादेश भी उसके पिछलग्गू बन सकते हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि चीन का मुकाबला करने के लिए भारत को अपने 'पड़ोसी पहले' की नीति में भू-राजनीतिक बदलाव की जरूरत है। चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर तनाव पैदा किया है और

भारत को कमजोर करने के लिए भारत विरोधी ताकतों को बढ़ावा दिया है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करता है। लेकिन कई क्षेत्रों में अमेरिका की करीबी देखते हुए उस पर भरोसा किया जा सकता है, जो पारस्परिक विश्वास और लाभ के सिद्धांत पर आधारित होगा। आलोचकों का मानना है कि भारत को अपनी विदेश नीति में भारी बदलाव लाने की जरूरत है, अन्यथा चीन हावी हो सकता है, जो बीआरआई के जरिये हरेक देश में भारत विरोधी ताकतों की मदद करता है, जैसा कि बांग्लादेश में दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश के संदर्भ में भारत हसीना की सत्तारूढ़ अवामी लीग के साथ ही काम करने में विश्वास करता रहा और संभावित विपक्ष खालिदा की बीएनपी को नजर अंदाज करता रहा। अब हसीना विरोधी ताकतें ढाका में सत्ता में आई हैं, जो भारत को दुश्मन समझती हैं। अगर भारत ने बीएनपी के साथ अच्छे संबंध बनाए होते, तो पाकिस्तान की आईएसआई और चीन पर अंकुश लगाया जा सकता था।

भारत और बांग्लादेश के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर बातचीत चल रही थी, क्योंकि यह दोनों देशों के व्यापार के लिए जरूरी है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2023-24 के दौरान 13 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। लेकिन अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के शासन में एफटीए का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। हालांकि ढाका की नई सरकार एफटीए चर्चा को बीच में ही छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकती, क्योंकि इससे दोनों देशों के लोगों के हितों को नुकसान होगा। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि यह समझौता जरूर होगा। राजनीतिक संकट के कारण लगभग 30 करोड़ डॉलर का निर्यात व्यापार प्रभावित हुआ है, खासकर तब, जब भारत हर दिन बांग्लादेश को तीन करोड़ डॉलर का सामान निर्यात करता है। भारत का आयात जारी है, लेकिन निर्यात रुका हुआ है, जिसका समाधान अंतरिम सरकार को करना होगा, ताकि हर दिन बढ़ने वाले घाटे को रोका जा सके। बांग्लादेश हर दिन करीब 15 ट्रक मछली निर्यात करता था, जो अब घटकर एक ट्रक रह गया है। बांग्लादेश के कस्टम विभाग ने सैकड़ों भारतीय ट्रकों को बांग्लादेश में घुसने की मंजूरी नहीं दी है, जो पार्किंग में खड़े हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरिम सरकार के नए मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस और अंतरिम सरकार को प्राथमिकता के आधार पर इन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। भारत विरोधी अभियान के जरिये सत्ता में आए मालदीव के नए राष्ट्रपति मोइज्जू के शासन में मालदीव का झुकाव चीन की तरफ हो गया है। मोइज्जू ने खुलेआम चीन की प्रशंसा की, जिसने उन्हें चुनाव में मदद की थी। लगभग यही स्थिति नेपाल की है, क्योंकि भारत ने नेपाली कांग्रेस का समर्थन किया और कम्युनिस्ट सरकारों की उपेक्षा की, जिससे वे भारत विरोधी बन गए।

1990 के दशक में छह वर्ष तक नेपाल में रहने के दौरान मैंने देखा है कि चीनी दूतावास ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को गुप्त रूप से भौतिक प्रलोभन के जरिये खुश रखा, जो सत्ता में आने पर उनके लिए फलदायी साबित हुए। चीन समर्थक और भारत विरोधी केपीएस ओली नेपाली कांग्रेस के साथ गठबंधन सरकार के प्रमुख हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि नेपाली कांग्रेस ओली को भारत विरोधी रुख त्यागने के लिए मजबूर कर सकती है।

इसी प्रकार की नीति भारत ने श्रीलंका में भी अपनाई थी। लेकिन जब श्रीलंका का आर्थिक रूप से पतन हो गया, तो भारत ने श्रीलंका की मदद की। नतीजतन भारत वहां के आम लोगों का चहेता बन गया है, जो नई दिल्ली द्वारा मुश्किल वक्त में दी गई वित्तीय सहायता की सराहना करते हैं, जबकि चीन ने खुद को इससे दूर रखा। हालांकि म्यांमार में भारत ने सैन्य शासन के साथ संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है। इसलिए भारत और अमेरिका को संयुक्त रूप सेएक कार्ययोजना बनानी होगी, जिसमें रणनीतिक साझेदारी मजबूत करना, क्वाड सहयोग बढ़ाना, व्यापार एवं बुनियादी ढांचे के विकल्प को बढ़ावा देना, संयुक्त सैन्य अभ्यास को विस्तार देना, प्रौद्योगिकी पर सहयोग देना, कूटनीतिक रूप से सहयोग करना, विकास कार्यों के लिए सहायता देना, गलत सूचनाओं के प्रसार को रोकना और एशिया में संप्रभुता का समर्थन करना शामिल है, जिसका उद्देश्य सार्क देशों में चीन के प्रभाव को कम करना और एक स्वतंत्र, मुक्त हिंद-प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करना है।

जीवन धारा

आरके नारायण

अकेलेपन और अलगाव से कोई मुक्ति नहीं है। यह एक निरंतर गति है, यह नियम उसी क्षण लागू हो जाता है, जब हम अपनी मां के गर्भ से खुद को अलग कर लेते हैं। अकेलापन ही जीवन का एकमात्र सत्य है।

अकेलापन ही सच्चा साथी इससे प्रेम करना सीखें

__मैं गांव__ से लौट आया। घर असहनीय रूप से नीरस लग रहा था। लेकिन मैंने इसे सहन किया। अकेलेपन और अलगाव से कोई मुक्ति नहीं है। पत्नी, बच्चे, भाई, माता-पिता, दोस्त सब एक साथ आते हैं, लेकिन फिर अलग हो जाते हैं। यह एक निरंतर गति है। जैसे ही हम उनसे दूर होते हैं, वे हमसे दूर चले जाते हैं। जीवन के नियम को कोई टाल नहीं सकता। यह नियम उसी क्षण लागू हो जाता है, जब हम अपनी मां के गर्भ से खुद को अलग कर लेते हैं। जीवन में सभी संघर्ष और दुख इस नियम को रोकने या इससे दूर होने या खुद को इससे आहत होने देने के हमारे प्रयास के कारण हैं। इस तथ्य को पहचानना होगा। एक गहरा, अप्रतिबंधित अकेलापन ही जीवन का एकमात्र सत्य है। बाकी सब झूठ है।

मेरी मां अपने माता-पिता से दूर हो गई, मेरी बहनें हमारे घर से दूर हो गईं, मैं और मेरा भाई एक-दूसरे से दूर हो गए, मेरी पत्नी मुझसे दूर हो गई, मेरी बेटी मेरी मां के साथ जा रही है। मेरे पिता अपने पिता से दूर हो गए, मेरे सबसे पुराने दोस्त-वे कहां हैं? वे पानी की फुहार की बूंदों की तरह बिखर जाते हैं। यह जीवन का नियम है। इसके खिलाफ लड़ने का कोई मतलब नहीं है, इस प्रकार मैंने पहले की तुलना में कम संघर्ष के साथ इस अलगाव को स्वीकार कर लिया। जीवन सही चीजें करने और आगे बढ़ने के बारे में है। हमारा हर मिनट कल बन जाता है और हमेशा के लिए खो जाता है। इसी बीच हर कोई हर समय, जानबूझकर या अनजाने में कोई न कोई भूमिका निभा रहा है। इस दुनिया में कुछ भी छिपाया या दबाया नहीं जा सकता। ऐसी सभी कोशिशें सूरज को छिपाने के लिए छाता पकड़ने के समान। जैसे सूर्य अंधकार को दूर करता है, वैसे ही भारतवर्ष धर्म, कर्तव्य, कर्म, चिंतन आदि का प्रतिपादन करके अंधकार को दूर करता है। जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा कोमल प्रकाश बिखेरकर कमल की कलियों को खिलने में मदद करता है, वैसे ही यह पुराण अपने प्रतिपादन द्वारा मानव बुद्धि का विस्तार करता है। इतिहास का दीपक प्रकृति के गर्भ के पूरे भवन को प्रकाशित करता है। प्रत्येक सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच कितनी महान मानवीय शाक्तियां एक-दूसरे से मिलती हैं और एक-दूसरे से जुड़ती हैं, लेकिन वहां कुछ ऐसे प्राणी भी हैं, जो हर पवित्र कार्य में बाधा डालने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इस संसार में हजारों तरह की बातें और समस्याएं सामने आती हैं, लेकिन हमारे देखने और समझने का नजारिया कैसा है यह बहुत जरूरी है। एक साधारण व्यक्ति और एक बुद्धिमान व्यक्ति के बीच का अंतर तब पता चलता है, जब एक साधारण व्यक्ति जो कुछ भी देखता और सुनता है, उसे पूरे दिल से स्वीकार करता है, जबकि दूसरा व्यक्ति कभी भी किसी भी बात को बहुत गहन जांच के बाद ही स्वीकार करता है। वह अपनी बुद्धि को बारीकी से बुनी गई जाली की छलनी के रूप में कल्पना करता है, जिसके माध्यम से केवल बेहतरीन चीजें ही गुजर सकती हैं।

हर पल को जीना सीखें

सूत्र

जीवन में वर्तमान ही सच्चाई है और इसी के साथ हर मिनट अतीत बन रहा है। इन्सान चाहे कितना भी प्रयत्न कर ले, अपने प्रेम करने वाले लोगों से दूर हो ही जाता है। वे पानी की फुहार की बूंदों की तरह बिखर जाते हैं। इसलिए हर पल को जीना सीखें, क्योंकि इतिहास का दीपक प्रकृति के गर्भ के पूरे भवन को प्रकाशित करता है।

दूसरा पहलू

नवीनतम शोध बताते हैं कि डार्क चॉकलेट में घातक धातुओं की मिलावट होती है, जो ज्यादा सेवन करने वालों के लिए प्राणघातक है।

डार्क चॉकलेट में छिपा मीठा जहर

चॉकलेट की मिठास भला किसे नहीं लुभाती है। लेकिन जब पता चले कि डार्क चॉकलेट में भारी धातुएं मिली हुई हैं, तो अचानक से स्वाद कसैला हो जाता है। हाल ही में प्रकाशित एक नए शोध से पता चला है कि डार्क चॉकलेट में भारी धातुएं पाई गईं, जो कोको उत्पादों में विषाक्त पदार्थों की मिलावट के बारे में चिंता जताने वाले अध्ययनों की शृंखला में नवीनतम हैं।

शोधकर्ताओं ने 72 डार्क चॉकलेट बार, कोको पाउडर और निब का परीक्षण किया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उनमें सुरक्षित मात्रा से अधिक भारी धातुओं की मिलावट की गई है। जांचे गए उत्पादों में से 43 प्रतिशत में सीसे की मात्रा अधिक पाई गई और 33 प्रतिशत में कैडमियम की मात्रा अधिक थी। दोनों धातुओं को विषाक्त माना जाता है और वे कई स्वास्थ्य समस्याओं के लिए जिम्मेदार होती हैं। अध्ययन में किसी ब्रांड का नाम नहीं बताया गया, लेकिन 'निष्पक्ष व्यापार' के रूप में प्रमाणित उत्पादों में भारी धातुओं का स्तर कम नहीं था। लेकिन शोधपत्र के मुख्य लेखक और जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन ऐंड हेल्थ साइंसेज के मेडिकल छात्र जैकब हैंड्स ने बताया कि भारी धातुओं की मात्रा इतनी ज्यादा नहीं थी कि औसत उपभोक्ता को सीमित मात्रा में डार्क चॉकलेट खाने के बारे में चिंतित होना पड़े। हालांकि कैडमियम और सीसा, दोनों ही स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा कर सकते हैं, लेकिन यहां यह स्पष्ट नहीं है कि डार्क चॉकलेट के कुछ टुकड़े खाने से अधिकांश स्वस्थ वयस्कों को कोई जोखिम हो सकता है।

डैनी ब्लम

शोधकर्ताओं की ओर से जांचे गए उत्पादों में से 43 प्रतिशत में सीसे की मात्रा अधिक पाई गई और 33 प्रतिशत में कैडमियम की मात्रा अधिक थी।

प्रोफेसर मेलिसा के अनुसार, अगर चॉकलेट आपकी दिनचर्या का एक मुख्य हिस्सा है या आप इसे बड़ी मात्रा में खाते हैं, तो यह चिंता की बात है। यदि थोड़ा बहुत खाते हैं, तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है।

डेलावेयर विश्वविद्यालय में पोषण की सहायक प्रोफेसर मेलिसा मेलोघ ने कहा कि मुझे ऐसे व्यक्ति की चिंता नहीं होगी, जो डार्क चॉकलेट का थोड़ा बहुत दीवाना हो और कुछ हफ्तों तक हर रात डार्क चॉकलेट खाता हो। लेकिन अगर यह वास्तव में आपकी दिनचर्या का एक मुख्य हिस्सा है या आप इसे बड़ी मात्रा में खाते हैं, तो जरूर यह चिंता की बात है। गर्भवती महिलाओं और बहुत छोटे बच्चों, जो भारी धातुओं के स्वास्थ्य जोखिमों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हैं, को डार्क चॉकलेट का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। शोध में पाया गया कि हर दिन एक औंस डार्क चॉकलेट खाने से स्वस्थ वयस्कों को कोई खतरा नहीं है, यदि वह गर्भवती नहीं हैं।

आंकड़े

रेलवे टिकट

बढ़ते डिजिटल प्रयोग की वजह से रेलवे में अब ऑफलाइन की अपेक्षा ऑनलाइन टिकट बुकिंग अधिक हो रही है।

2023-24	82.7%
2022-23	80.9%
2021-22	80.5%
2013-14	50.0%
2010-11	40.0%

पिछले 14 वर्षों में ऑनलाइन बुकिंग 42 फीसदी बढ़ गई है। | स्रोत : IRCTC

महाराज अंबरीश ने दुर्वासा ऋषि को भोजन कराने से पहले भगवान का चरणोदक ले लिया था। इससे नाराज ऋषि ने जटाओं से कृत्या नामक राक्षसी प्रकट की।

अंबरीश को बचाने आया सुदर्शन

महाराज अंबरीश भगवान के अनन्य भक्त थे। एक बार उन्होंने एक वर्ष तक एकादशी व्रत करने का संकल्प लिया। ग्यारह एकादशी के व्रत उनके नियम से निभ गए थे। अंतिम एकादशी पर ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद अंबरीश व्रत का पारण करना ही चाहते थे कि इतने में दुर्वासा ऋषि पहुंच गए। राजा ने उनका सत्कार कर भोजन के लिए आग्रह किया। ऋषि ने भोजन के लिए हामी भर दी, लेकिन वह नित्यकर्म के लिए चले गए।

ऋषि को लौटने में विलंब हो रहा था और द्वादशी आने में एक घड़ी समय बचा था। यदि राजा पारण न करते, तो उनका व्रत भंग हो जाता। राजा ने ब्राह्मणों से पूछकर भगवान का चरणोदक लेकर पारण कर लिया। दुर्वासा को लौटने पर पता चला कि उन्हें भोजन कराने से पहले ही राजा ने व्रत का पारण कर लिया है। इससे ऋषि ने कुपित होकर अपनी जटाओं से कृत्या नामक राक्षसी प्रकट की।

राक्षसी अंबरीश को मारने के लिए दौड़ी। इधर, अंबरीश की रक्षा के लिए भगवान का सुदर्शन चक्र आया और कृत्या को मारकर दुर्वासा के पीछे दौड़ा। ऋषि भयभीत होकर विष्णु भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने कहा कि अंबरीश ही आपको बचा सकते हैं। वह अंबरीश के पास पहुंचे और क्षमा मांगी। अंबरीश ने सुदर्शन से प्रार्थना कर उनकी रक्षा की। बताते हैं कि दुर्वासा ऋषि को वापस आने में पूरा एक वर्ष बीत गया था।

अंतर्यात्रा
संकलित

आज का इतिहास

स्पाइडरमैन का चरित्र पहली बार कॉमिक बुक में नजर आया

साल के आठवें महीने का दसवां दिन कई छोटी बड़ी घटनाओं के साथ इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इनमें एक दिलचस्प खबर यह है कि बच्चों का चहेता आभासी चरित्र स्पाइडरमैन पहली बार कॉमिक बुक में नजर आया। इसे बच्चों ने इतना पसंद किया कि बाद में यह कार्टून और फिर फिल्मों के पर्दे पर भी नजर आया। गरीबों और मजलूमों का मसीहा स्पाइडरमैन लंबे वक्त तक दुनियाभर में बच्चों का पसंदीदा चरित्र रहा। 1966 में अमेरिका ने अंतरिक्ष में रॉकेट उतारने की लिए उपयुक्त स्थान का चित्र लेने पहला अंतरिक्ष यान भेजा। 2000 में पड़ौसी देश श्रीलंका में सिरीमावो भंडारनायके का प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा, आर. विक्रमानयके नये प्रधानमंत्री नियुक्त। 2000 में आत्मनिर्णय के अधिकार पर जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया।

दिलवालों की दिल्ली बदहाल

दिल्लीवासी प्रदूषण के चलते खुली हवा में सांस लेने के लिए तरस ही रहे थे। अब जर्जर सड़कों व बदहाल ड्रेनेज सिस्टम ने जीना दुश्वार कर दिया है।

ज्ञानेंद्र रावत | **अव्यवस्था**

राजधानी दिल्ली अब रहने लायक नहीं रह गई है। दिल्लीवासी प्रदूषण के चलते साफ हवा में सांस लेने के लिए बरसों से तरस ही रहे हैं। अब सड़कों की बदहाली और दशकों पुरानी सीवेज प्रणाली की जर्जर अवस्था के होते जलभराव की समस्या से उनका जीना दूभर हो गया है। वे उस क्षण को कोस रहे हैं, जब उन्होंने यहां बसने का निर्णय लिया था। जनसुविधाओं के मामले में प्रशासनिक स्तर पर भी दिल्ली की जनता केंद्र की भाजपा सरकार और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के बीच जारी अस्तित्व की लड़ाई में पिस रही है।

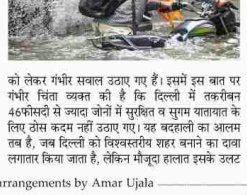

सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी कमेटी के मुताबिक, जुलाई से नवंबर 2023 के बीच आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर सड़क सुरक्षा के उद्देश्य से हुए ऑडिट में फुटपाथ की स्थिति, संरचना, डिजाइन और सीवेज सिस्टम

को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। इसमें इस बात पर गंभीर चिंता व्यक्त की है कि दिल्ली में तकरीबन 46फीसदी से ज्यादा जोनों में सुरक्षित व सुगम यातायात के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए। यह बदहाली का आलम तब है, जब दिल्ली को विश्वस्तरीय शहर बनाने का दावा लगातार किया जाता है, लेकिन मौजूदा हालात इसके उलट गवाही देते हैं। दिल्ली की सड़कें तो सड़कें, जंक्शन और फुटपाथ भी कतई सुरक्षित नहीं हैं। सड़क सुरक्षा को लेकर उठाए सवालों के उद्देश्य से 69 फीसदी सड़क संकेतक इंडियन रोड कांग्रेस के मानकों पर कतई खरे नहीं उतरते। फुटपाथ को लें, वह भी मानकों के अनुरूप नहीं हैं। इंडियन रोड कांग्रेस के मुताबिक, फुटपाथ की चौड़ाई 2.5 मीटर होनी चाहिए, जिसके अनुसार उस पर दो व्हील चेयर एक साथ गुजर सकें। 16 फीसदी फुटपाथ की चौड़ाई इंडियन रोड कांग्रेस के मानकों के मुताबिक है, जबकि 84 फीसदी फुटपाथ ऐसे हैं, जिनकी चौड़ाई तय मानकों के मुताबिक है ही नहीं। पुरानी दिल्ली की बात छोड़िए, रिंग रोड भी इस बदहाली की शिकार हैं। रिंग रोड पर जहां सबसे ज्यादा वाहन गुजरते हैं, उस पर मजनू का टीला, चंदगीराम के अखाड़े के आसपास की सड़कें जर्जर अवस्था में हैं, वे टूटी पड़ी हैं। वहां जेब्रा क्रॉसिंग की मार्किंग भी नहीं है। यही हाल पूर्वी दिल्ली की वजीराबाद रोड का है। यहां सबसे ज्यादा व्यस्त रहने वाला लोनी-गोकुलपुरी रोड वाला जंक्शन यानी गोल चक्कर है, जहां से गाजियाबाद को सड़क जाती है। सड़क के टूटे होने और जेब्रा क्रासिंग न होने के चलते हादसे की आशंका रहती है। सबसे ज्यादा खतरनाक हालात आजादपुर चौक, भलस्वा चौक, मुकरबा चौक, बुराड़ी चौक, पंजाबी बाग चौक, गाजीपुर फ्लाईओवर, मुर्गा मंडी, मुकुंदपुर चौक, मधुबन चौक और रजोकरी फ्लाईओवर की है, जहां सड़क हादसे आम हैं।

अब जरा दिल्ली की जल निकासी पर भी नजर डालें। दशकों पुराना ड्रेनेज सिस्टम इतना बदहाल हो चुका है कि अब वह राजधानी की सवा दो करोड़ से ज्यादा आबादी के जल-मल का भार सहने की क्षमता खो चुका है। फिर भी दिल्ली उसी 48 साल पुराने ड्रेनेज सिस्टम पर आश्रित है, जब दिल्ली की आबादी 60 लाख के आसपास ही हुआ करती थी। इस वजह से जरा-सी बारिश में जलभराव हो जाता है। यदि बारिश तगड़ी हो गई, तो डूब की स्थिति पैदा हो जाती है। यह हालत अब पुरानी दिल्ली की ही नहीं होती, बल्कि लुटियन जोन नई दिल्ली भी इसका शिकार हुए बिना नहीं रहती और वहां के हालात भी किसी टापू जैसे हो जाते हैं। इन सबके लिए जिम्मेदार पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था का न होना और नालों की समय-समय पर सफाई न होना है। नतीजतन सड़कों पर तेज बारिश के चलते जलभराव होने से कहीं सड़क धंसने से गड्ढे हो जाते हैं। कहीं सीवर के मैनहोल में स्कूटर समा जाते हैं, तो कभी राहगीर। कभी-कभी तो लुटियन जोन में घंटों आवाजाही तक बंद हो जाती है और लोग घरों में कैद होकर रह जाते हैं।

वह बात दीगर है कि पीडब्ल्यूडी यह दावा करते नहीं थकती कि जलभराव के चलते जल निकासी हेतु सैकड़ों पंप लगाए जाते हैं, लेकिन बारिश के विषम हालात, पुराने नालों की सफाई न होने और उनमें गंदगी भरे रहने से पंपों द्वारा जल निकासी में अधिक समय लगने से जल्दी जलभराव से निजात मिल पाना बेहद मुश्किल हो जाता है और जाम में घंटों वाहन फंसे रहते हैं।

Special arrangements by Amar Ujala

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेन्ट्स प्रा.लि. के लिए मुद्रक, प्रकाशक समीर माहेश्वरी द्वारा नवभारत प्रेस, प्लाट नंबर 24 सेक्टर-बी, रेल नीर प्लांट के पास सिरगिट्टी इंडस्ट्रीयल एरिया, बिलासपुर से मुद्रित एवं नवभारत भवन, पुराना बस स्टैण्ड के पास, बिलासपुर से प्रकाशित. प्रधान संपादक : समीर माहेश्वरी, संपादकः अरुण उपाध्याय* (पी.आर.बी. कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिये जिम्मेदार)
■ बिलासपुरः 07752-230591, 224563 फैक्सः 405338 ■ रायपुर फोनः (0771) 2535577-88-99, विज्ञापनः 2545599, फैक्सः (0771) 2535555 ■ दिल्लीः 011-23379021, फैक्स- 011-23379026 ■ मुंबईः 022-24900929, फैक्स- 022-24938684 ■ वर्ष 40 ■ अंक 314 (रजि. नं. 38549/85 आरएनआई), डाक रजिस्टर्ड क्रमांक जी. 2-112/सी.जी./बी.एल.पी./15/2022-2024

संपादकीय

इंसानियत के धागे को मजबूत बनाने में ही जीवन की सार्थकता!

जीवन तो बस जीवन जो प्रकृति प्रदत है और जिसे पैदा करने वाले कोई ऐसी शक्ति है जो इस धरा को संचालित करता है उसे आप किसी भी नाम से पुकारे और उसका सानिध्य भी एहसास होगा तभी जवाब मन से उस अदृश्य शक्ति को सब कुछ मान कर अपना सौप कर याद करेंगे, जो सब मानवीय रूप लिए व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता। क्योंकि जिन्होंने बनाया है पैदा किया है। उनके हाथ में ही सारा कुछ है और जब भी चाहेंगे तभी सब कुछ आप मानव रूप में पाएंगे चाहे श्रद्धा भक्ति हो धन दौलत हो मानवीय जीवन की सफलता हो या फिर दुर्बलता हो सभी में उनकी ही मन की मर्जी चलती है। मानव मन बस विचार कर सकता है, दूसरे का अहित कर सकता है, कल्याण भी कर सकता है, माध्यम बनकर उस परमात्मा का जिसने इस धरा पर मानव रूप दिया है। मानव जीवन हमें इस धरा पर उस अदृश्य शक्ति की देन है, जो हमें कभी दिखाई नहीं देता। मानवों में उस अदृश्य शक्ति ने जो कुछ भरा है, वह अद्वितीय है। बहुत कुछ करने की क्षमता सोचने समझने की क्षमता उस अदृश्य शक्ति से हमें प्राप्त हुआ है लेकिन हम सभी मानव जाति के लोग बस उस अदृश्य शक्ति के दिए हुए, अनमोल शक्ति का उपयोग बस अपने लिए ही करते रहते हैं। कुछ लोग हैं जो कि इस शक्ति से लोगों का भला करते हैं।भला चाहते हैं।लेकिन ज्यादातर लोग अपने ही भलाई और स्वार्थ में जीवन बिता देते हैं।हम मानव कुछ भी नहीं हैं। बस उस अदृश्य शक्ति की देन है कि हमें उसने यह शरीर बक्सा है। शरीर से हम सभी न जाने कितने गलत सलत कार्य करके, एक-दूसरे पर दोषारोपण करके, अपने जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन यह कोशिश कुछ तो नहीं दिखता किसी भी दृष्टिकोण से, इसलिए जरूरी है, वर्तमान काल को सुंदर और अच्छा बनाने की करोना को भगाने की स्वस्थ और सुरक्षित रहने की। इसलिए जरूरी है कि हम जो भी करें, वह उस अदृश्य शक्ति का दिया प्रकृति का दुरुपयोग ना करें। इसका अच्छे से उपयोग करें, सब की भलाई करें सब को सुरक्षित रखें और अपनी जीवन की जो खत्म भी होने बाला है, उसे मिटने से पहले कुछ एसा कर जाये की जगत याद करे। हम सभी आज जिस करोना को भोग रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि हम मानव इस धरा में अवतरित होकर भागवत रूपी उस अदृश्य शक्ति को का मान नहीं रख पा रहे हैं। हम भले ही पूजा-पाठ धर्म के कार्य करते रहें। लेकिन यह भी ध्यान रखें कि हमें इस जीवन को कुछ ऐसा बना करके इस धरा से उठे समाप्त हो जाएं, जो आने वाले पीढी का सही मार्ग दर्शन कर सके।लोगो के लिये एक सबक मिले और वह भी ऐसा ही कुछ करें, जो भागवत रूपी अदृश्य शक्ति की देन के अनुरूप रहे।हमें अपने जीवन में हर पल इस बात का ध्यान रखना है कि असल में हम सब एक ही धागे से जुडे हुए हैं।वह धागा न तो धर्म का है, न मजहब का है, न भाषा का है, न जातीयता का है, न सांप्रदायिकता का है। वह धागा है तो केवल इंसानियत का, मानवता का अच्छा करम हो। हम मनुष्यों ने इस धरती पर लकीरें खींचकर दिलों को बांट दिया है और इंसानियत को बांट दिया है, जबकि जरुरत है, उन्नत और आदर्श जीवन के लिए भाईचारे की, प्रेम की, आनंद की, परोपकार की।अगर हमारे जीवन में यह सब आ जाये तो हमारा जीवन अधिक सार्थक और उपयोगी बन जाएगा । संभवतः यही सच्ची मानवता के लिये जरुरी भी है और जीने का सही तरीका भी है। करोना मानव के लिए एक सबक लेकर आया है और वह सबक यह है कि प्रकृति को हम सब नष्ट ना करें, लोगों से सद्भाव और भाईचारा बनाए रखें तभी इस जीवन की सार्थकता होगी और यह जीवन सफल होगा। कोरोना ने जो कुछ किया है। वह मानव के लिए किया है। एक के लिए नहीं सबके लिये किया है। इस सेवक को सदा याद रखें और मानवता को कभी ना भूले। मानव मानव में प्रेम कि यह सीख सदा जीवन में याद रखें। यह सबक तो सदा याद रखने की जरूरत होगी कि हम मानव कुछ भी नहीं हैं, जो कुछ है वह उस अदृश्य शक्ति का की देन है।उसके आगे मानव वेवस है। वह जो कुछ भी करता है, सवके लिए करता है। सभी के लिए करता है। आज जो अन्याय अत्याचार इस जगत में फैला है। वह मानव के मन की सोच है और यह सोच तो निश्चित रूप से गलत है। इसी सोच को बदलना होगा। तभी मानव जीवन सफल होगा। अन्यथा सब कुछ बेकार हो जाएगा। मानव मन को स्थिर रखकर जगत की भलाई की सोच रखे। उसने यह शरीर बक्सा है शरीर से हम सभी न जाने कितने गलत गलत कार्य करके एक-दूसरे पर दोषारोपण करके अपने जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं लेकिन यह कोशिश कुछ तो नहीं दिखता किसी भी दृष्टिकोण से इसलिए जरूरी है वर्तमान काल को सुंदर और अच्छा बनाने की करुणा को भगाने की स्वस्थ और सुरक्षित रहने की लिए जरूरी किया भी है कि हम जो भी करें वह उस अदृश्य शक्ति भक्ति का दुरुपयोग ना करें इसका अच्छे से उपयोग करें सब की भलाई करें सब को सुरक्षित रखें और अपनी जीवन की जो कटता है उसे मिटाते रहे हम सभी आज जिस करोना को भोग रहे हैं उससे तो यही लगता है कि हम मानवों में अवतरित होकर भागवत रूपी उस अदृश्य शक्ति को का मान नहीं रख पा रहे हैं हम भले ही पूजा-पाठ धर्म के कार्य करते रहें लेकिन यह भी ध्यान रखें कि हमें इस जीवन को कुछ ऐसा बना करके इस धरा से उठे समाप्त हो जाएं जो आने वाले लोगों को आने वाली पीढ़ी को एक सबक मिले और वह भी ऐसा ही कुछ करें जो भागवत रूपी अदृश्य शक्ति की देन के अनुरूप हो दिए हुए अमूल शक्ति का उपयोग बस अपनी लिए ही करते रहते हैं कुछ लोग हैं जो किसी से शक्ति से लोगों का भला करते हैं। हमें अपने जीवन में हर पल इस बात का ध्यान रखना है कि असल में हम सब एक ही धागे से जुडे हुए हैं।वह धागा न तो धर्म का है, न मजहब का है, न भाषा का है, न जातीयता का है, न सांप्रदायिकता का है । वह धागा है तो केवल इंसानियत का, मानवता का । हम मनुष्यों ने इस धरती पर लकीरें खींचकर दिलों को बांट दिया है और इंसानियत को बांट दिया है, जबकि जरुरत है उन्नत और आदर्श जीवन के लिए भाईचारे की, प्रेम की, आनंद की, परोपकार की।अगर हमारे जीवन में यह सब आ जाये तो हमारा जीवन अधिक सार्थक और उपयोगी बन जाएगा । संभवतः यही सच्ची मानवता भी है और जीने का सही तरीका भी। सजग हो जाइए, सचेत हो जाइए। करोना को भागाइए जीवन की राह सहज सुलभ बना रहे। इसलिए सही राह अपनाई जाय और जीवन को सफल बनाई जाय। यहीं सब कुछ धरा रह जाएगा, बस कोई रह नहीं पाएगा। इसलिए समय समय के साथ चलिए और जीवन को ऐसे राह पर ले जाइए, जो सबके लिए एक उदाहरण बन कर उपस्थित हो। सबके सामने करने के लिए संसार में बहुत कुछ है और लोग कर रहे हैं। लेकिन इस करने में अगर जनमानस की भलाई है, तो वह निश्चित रूप से पुण्य का कार्य है। अन्यथा पाप कर्म से हम अपने को बचाने में सफल थोड़े ही होंगे। पाप कर्म बोलता है, इसका फल भी मिलता है। दुख सुख जीवन का एक ऐसा आधार है, जो जीने की राह दिखाता है। सभी लोग इस बात को जाने माने कि इस धरा पर आए हैं, तो कुछ अच्छा कर्म करके जाएं और यही अच्छा कर्म जीने की सच्ची राह दिखाएगा और सभी के लिए सच्चा कर्म करते जाइए।जीवन की राह सहज सुलभ हो जाएगी। हमें उस परमात्मा का गुणगान करते रहना होगा क्योंकि यह शरीर और दिमाग सब उसी ने दिया है। जिसने हमारे शरीर को कुछ ऐसा बनाया है कि हम बहुत कुछ करने लायक बन गए हैं। लेकिन इसका दुरुपयोग भी बहुत कुछ होने लगा है। मानव शरीर ही इसका दुरुपयोग भी कर रही है। जो कहीं से उचित नहीं दिखता। लोग अपने दिलो-दिमाग से ज्ञान से क्या कुछ नहीं इस धरा पर उतार रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले ने जो उतारा है उसके आगे तुच्छ है मानव का बना बनाया हुआ, ज्ञान से बनाया हुआ, इस धरा पर जो भी चीजें हैं वह मानव का देन अगर है तो वह है अपना कर्म जिसके माध्यम से देश दुनिया में मानव धर्म कर्म महान हो सकता है।

प्रभात वर्मा

रामेश्वरम के धनुषकोडी में भारतीय महासागर के गहरे और उथले पानी को बंगाल की खाड़ी के छिछले और शांत पानी से मिलते देखा जा सकता है

पुराणों में द्वादश ज्योतिलिंर्गो का वर्णन किया गया है। मान्यता है कि जहां-जहां ज्योतिलिंग है, वहां स्वयं देवाधिदेव महादेव शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं। यह भी मान्यता है कि 12 ज्योतिर्लिंग का नाम जप के रूप में करते रहने से पिछले सात जन्मों के पाप से मुक्त होकर मोंक्ष पाया जा सकता है। श्रीराम ने, युद्ध में सफलता और विजय के बाद कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए भगवान शिव की आराधना की और समुद्र किनारे की रेत से शिवलिंग का निर्माण अपने हाथ से किया था। भगवान शिव स्वयं ज्योति स्वरुप प्रकट हुए और लिंग को श्री रामेश्वरम की उपमा दी। रामेश्वरम् ज्योतिर्लिंग हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ एक सुंदर शंख आकार का द्वीप है। यहां भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले पत्थरों के सेतु का निर्माण करवाया था। भगवान राम ने सेतु निर्माण से पहले सागर से प्रार्थना की थी कि मुझे लंका जाने के लिए रास्ता दीजिए। जब समुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया तब भगवान राम ने समुंद्र को सुखाने के लिए अपने धनुष पर वाण चढ़ाया, तो समुंद्र देव ने प्रकट होकर अपनी गलती के लिए माफी मांगने के वाद सेतु बनाने की अनुमति दी। इसलिए यह मान्यता है कि यहां सागर एकदम शांत है। उसमें लहरें बहुत कम उठती है। इस कारण देखने में वह एक तालाब-सा लगता है। यहां पर बिना किसी खतरें के स्नान किया जा सकता है। यहीं हनुमान कुंड में तैरते हुए पत्थर भी दिखाई देते हैं। बाद में श्रीराम ने विभीषण के अनुरोध पर धनुषकोटि नामक स्थान पर यह सेतु तोड़ दिया था। आज भी इस ३० मील (४८ कि.मी) लंबे आदि-सेतु के अवशेष सागर में दिखाई देते हैं। रामेश्वरम् के समुद्र में तरह-तरह की कोड़ियां, शंख और सीपें मिलती है। कहीं-कहीं सफेद रंग का बड़ियास मूंगा भी मिलता है। रामेश्वरम् केवल धार्मिक महत्व का तीर्थ ही नहीं, प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से भी दर्शनीय है। रामेश्वरम् हिन्दुओं के चार धामों में से एक है। यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यहां के मंदिर का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। यह उत्तर-दक्षिण में 197 मी. एवं पूर्व-पश्चिम में 133 मी. है। इसके परकोटे की चौड़ाई 6 मी. तथा ऊंचाई 9 मी. है। मंदिर के प्रवेशद्वार का गोपुरम 38.4 मी. ऊंचा है। यह मंदिर लगभग 6 हेक्टेयर में बना हुआ है। मंदिर में विशालाक्षी जी के गर्भ-गृह के निकट ही नौ ज्योतिर्लिंग हैं, जो लंकापति विभीषण द्वारा स्थापित किया गया बताया जाता हैं। रामेश्वरम का मंदिर भारतीय निर्माण-कला और शिल्पकला का एक सुंदर नमूना है। इसके प्रवेश-द्वार चालीस फीट ऊंचा है और मंदिर के अंदर सैकड़ौ विशाल खंभें है, जो देखने में एक-जैसे लगते है; लेकिन पास जाकर जरा बारीकी से देखने पर मालूम होता है कि हर खंभे पर बेल-बूटे की अलग-अलग कारीगरी है। रामेश्वरम् के विशाल मंदिर को बनवाने और उसकी रक्षा करने में रामनाथपुरम नामक छोटी रियासत के राजाओं का बड़ा हाथ रहा है। अब तो यह रियासत तमिलनाडु राज्य में मिल गई हैं। पूरे भारत, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्व एशिया के कई देशों में हर साल दशहरे पर और राम के जीवन पर आधारित सभी तरह के नृत्य-नाटकों में सेतु बंधन का वर्णन किया जाता है। राम के बनाए इस पुल का वर्णन रामायण में तो है ही, महाभारत में भी श्रीराम के नल सेतु का जिक्र आया है। कालीदास की रघुवंश में सेतु का वर्णन है। अनेक पुराणों में भी श्रीराम सेतु का उल्लेख है।एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में इसे राम सेतु कहा गया है। नासा और भारतीय सेटेलाइट से लिए गए चित्रों में धनुषकोडि से जाफना तक जो एक पतली सी द्वीपों की रेखा दिखती है। धनुषकोडी भारत के तमिलनाडु राज्य के पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप के दक्षिणी किनारे पर स्थित है।। इसी स्थान को सेतुबंध भी कहते है। धनुषकोडी श्रीलंका में तलैमन्नार से करीब 18 मील पश्चिम में है। धनुषकोडी जीप या टेम्पो से पहुंचा जा सकता है। धनुषकोडी में भारतीय महासागर के गहरे और उथले पानी को बंगाल की खाड़ी के छिछले और शांत पानी से मिलते हुए देख सकता है। रामेश्वरम् शहर से करीब डेढ़ मील उत्तर-पूर्व में गंधमादन पर्वत नाम की एक छोटी-सी पहाड़ी है। हनुमानजी ने इसी पर्वत से समुद्र को लांघने के लिए छलांग मारी थी। बाद में श्रीराम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए यहीं पर विशाल सेना संगठित की थी। इस पर्वत पर एक सुंदर मंदिर बना हुआ है, जहां श्रीराम के चरण-चिन्हों की पूजा की जाती है। इसे पादुका मंदिर कहते हैं। तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम् द्वीप और इसके आस-पास कुल मिलाकर 64 तीर्थ स्थल है। स्कंद पुराण के अनुसार, इनमे से 24 तीर्थ स्थल ही महत्वपूर्ण तीर्थ है। इनमे से 22 तीर्थ तो केवल मंदिर के भीतर ही है। 22 की संख्या को भगवान की 22 तीर तरकशो के समान माना गया है। मंदिर के पहले और सबसे मुख्य तीर्थ को अग्नि तीर्थं नाम दिया गया है। इन तीर्थो में स्नान करना बड़ा फलदायक पाप-निवारक समझा जाता है। जिसमें श्रद्धालु पूजा से पहले स्नान करते हैं। हालांकि ऐसा करना अनिवार्य नहीं है। रामेश्वरम के इन तीर्थो में नहाना काफी शुभ माना जाता है। कोद्ण्ड स्वामि मंदिर रामेश्वरम् के टापू के दक्षिण भाग में, समुद्र के किनारे है। कहा जाता है कि विभीषण ने यहीं पर श्रीराम की शरण ली थी। रावण-वध के बाद श्रीराम ने इसी स्थान पर विभीषण का राजतिलक कराया था। इस मंदिर में श्रीराम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां के साथ ही विभीषण की भी मूर्ति स्थापित है।

दस्तक प्रभात
जितेन्द्र कुमार सिन्हा

आर्टिकल्चर ज्ञान

बी.आर्क कार्यक्रम संरचना और मूल्यांकन रणनीतियों का परिचय

बी.आर्क कार्यक्रम संरचना, उद्देश्यों और अपेक्षित परिणामों का परिचय-बी.आर्क (बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर) कार्यक्रम एक व्यापक शैक्षणिक यात्रा है, जो छात्रों को वास्तुकला के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से सुसज्जित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह कार्यक्रम आमतौर पर पाँच साल का होता है और सैद्धांतिक ज्ञान और व्यावहारिक अनुप्रयोग का मिश्रण प्रस्तुत करता है।पाठ्यक्रम संरचना बी.आर्क कार्यक्रम की पाठ्यक्रम संरचना को अच्छी तरह से तैयार किया गया है ताकि यह आवश्यक विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करे। इसमें शामिल हैं: नींव पाठ्यक्रमः प्रारंभिक पाठ्यक्रम ड्राइंग, डिजाइन सिद्धांतों और सामग्री और निर्माण तकनीकों की समझ को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।मुख्य विषयः जैसे-जैसे छात्र आगे बढ़ते हैं, वे भवन निर्माण, वास्तुकला इतिहास, पर्यावरण अध्ययन और संरचनात्मक प्रणालियों जैसे मुख्य वास्तुकला विषयों में गहराई से प्रवेश करते हैं।चयनात्मक और विशेषज्ञताः छात्र अपनी रुचियों के आधार पर चुनाव और विशेषज्ञता का चयन कर सकते हैं, जिसमें शहरी नियोजन, स्थायी डिजाइन, परिदृश्य वास्तुकला और अन्य शामिल हैं।डिजाइन स्टूडियोः कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक, डिजाइन स्टूडियो छात्रों को व्यावहारिक परियोजनाओं पर सैद्धांतिक ज्ञान को लागू करने की अनुमति देता है। ये स्टूडियो वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों और चुनौतियों का अनुकरण करते हैं, जिससे रचनात्मकता और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा मिलता है। इंटर्नशिप और व्यावहारिक प्रशिक्षणः वास्तुकला में व्यावहारिक अनुभव महत्वपूर्ण है। इंटर्नशिप और प्रशिक्षण कार्यक्रम छात्रों को व्यावहारिक अनुभव और उद्योग का अनुभव प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं। उद्देश्यों और अपेक्षित परिणामः बी. आर्क कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य हैं:वास्तुकला सिद्धांतों और डिजाइन प्रक्रियाओं में मजबूत नींव विकसित करना। आलोचनात्मक सोच और विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देना।निर्माण और सामग्री के उपयोग में तकनीकी प्रवीणता को बढ़ाना।वास्तुशिल्प डिजाइन में रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देना। छात्रों को व्यावसायिक अभ्यास और उन्नत अध्ययन के लिए तैयार करना।कार्यक्रम के अंत में, छात्रों से अपेक्षित है कि वेः वास्तुकला डिजाइन और नियोजन में प्रवीणता प्रदर्शित करें।निर्माण प्रौद्योगिकियों और स्थायी प्रथाओं की व्यापक समझ प्रदर्शित करें।अपने डिजाइनों को प्रस्तुत करने और बचाव करने के लिए प्रभावी संचार कौशल विकसित करें।आत्मविश्वास और क्षमता के साथ वास्तुकला पेशे में प्रवेश करने के लिए तैयार हों।कार्यक्रम में शामिल मूल्यांकन रणनीतियाँ और अंकगणित का अनुप्रयोग बी.आर्क कार्यक्रम में मूल्यांकन बहुआयामी है, जिसे छात्र के सैद्धांतिक समझ, व्यावहारिक कौशल और रचनात्मक क्षमताओं का आकलन करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें शामिल रणनीतियाँ हैं:निरंतर मूल्यांकन-मूल्यांकन प्रक्रिया का एक अभिन्न

हिस्सा है। इसमें नियमित असाइनमेंट, परियोजना कार्य और प्रस्तुतियाँ शामिल हैं। यह विधि सुनिश्चित करती है कि छात्र लगातार पाठ्यक्रम में संलग्न रहें और निरंतर प्रतिक्रिया और सुधार की अनुमति देती है।डिजाइन समीक्षाएँ और आलोचनाएँ-डिजाइन समीक्षाएँ और आलोचनाएँ, विशेष रूप से डिजाइन स्टूडियो पाठ्यक्रमों में, अक्सर आयोजित की जाती हैं। इन सत्रों में डिजाइनों के प्रस्तावों को संकाय और सहपाठियों के सामने प्रस्तुत करना शामिल है, जो रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं। यह प्रक्रिया छात्रों को उनके डिजाइनों को परिष्कृत करने और उनके प्रस्तुति कौशल को विकसित करने में मदद करती है।परीक्षाएँ-पारंपरिक परीक्षाएँ छात्रों के सैद्धांतिक ज्ञान का परीक्षण करती हैं। इनमें लिखित परीक्षाएँ, प्रश्नोत्तरी और मौखिक परीक्षाएँ शामिल हो सकती हैं। कवर किए गए विषयों में वास्तुकला इतिहास से लेकर भवन निर्माण के तकनीकी पहलुओं तक शामिल हैं।अंतिम वर्ष का शोध, परियोजना बी.आर्क कार्यक्रम का समापन अक्सर अंतिम वर्ष के शोध या परियोजना में होता है। छात्र एक व्यापक डिजाइन परियोजना को अंजाम देते हैं जो उनके संचयी सीखने और कौशल को प्रदर्शित करती है। इस परियोजना का मूल्यांकन रचनात्मकता, तकनीकी प्रवीणता और व्यवहार्यता के आधार पर किया जाता है।अंकगणित का अनुप्रयोग वास्तुकला में अंकगणित और गणितीय सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं। सामग्री की मात्रा और लागत की गणना से लेकर संरचनात्मक विश्लेषण और स्थानिक योजना तक, पूरे कार्यक्रम में अंकगणित का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। छात्रों को इन कौशलों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है ताकि उनके डिजाइनों में सटीकता और शुद्धता सुनिश्चित हो सके।वास्तुकला मूल्यांकन में गेमिफिकेशन की भूमिका का अन्वेषणगेमिफिकेशन, गैर-खेल संदर्भों में गेम-डिजाइन तत्वों का अनुप्रयोग, वास्तुकला शिक्षा में एक अभिनव दृष्टिकोण के रूप में उभर रहा है। मूल्यांकन रणनीतियों में गेमिफिकेशन को शामिल करने से छात्र की संलग्नता और प्रेरणा को बढ़ाया जा सकता है। गेमिफिकेशन के लाभः बढ़ी हुई संलग्नताः लीडरबोर्ड, बैज और पुरस्कार जैसे गेमिफाइड तत्व सीखने को अधिक इंटरैक्टिव और आनंददायक बना सकते हैं। प्रेरणा में वृद्धिः प्रतिस्पर्धा और मान्यता के माध्यम से गेमिफिकेशन छात्रों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित कर सकता है।तत्काल प्रतिक्रियाः गेमिफाइड सिस्टम अक्सर त्वरित प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं, जिससे छात्रों को सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलती है।सहयोग और टीम वर्कः कई गेमिफाइड गतिविधियाँ सहयोग को प्रोत्साहित करती हैं, जिससे टीम वर्क और संचार कौशल को बढ़ावा मिलता है।वास्तुकला शिक्षा में, गेमिफिकेशन को विभिन्न तरीकों से लागू किया जा सकता है, जैसे आभासी डिजाइन चुनौतियाँ, इंटरैक्टिव सिमुलेशन और सहयोगी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ये विधियाँ सीखने के अनुभव को अधिक गतिशील और प्रभावी बना सकती हैं।वास्तुकला स्टूडियो संस्कृति और डिजाइन जूरी वास्तुकला स्टूडियो बी.आर्क कार्यक्रम का दिल है। यह वह जगह है जहाँ छात्र अपने समय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बिताते हैं, डिजाइन परियोजनाओं पर काम करते हैं, सहपाठियों के साथ सहयोग करते हैं और संकाय से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं।स्टूडियो संस्कृति एक सहयोगी और रचनात्मक वातावरण की विशेषता है। छात्रों को प्रयोग करने, जोखिम उठाने और अभिनव विचारों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। खुले स्टूडियो का लेआउट बातचीत और विचारों के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करता है, जिससे सामुदायिक भावना का निर्माण होता है। डिजाइन जूरी स्टूडियो संस्कृति का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसमें परियोजनाओं को विशेषज्ञों के एक पैनल के सामने प्रस्तुत करना शामिल है, जिसमें संकाय सदस्य और उद्योग पेशेवर शामिल होते हैं। जूरी परियोजनाओं का मूल्यांकन रचनात्मकता, कार्यक्षमता, स्थिरता और प्रस्तुति कौशल जैसे मानदंडों के आधार पर करती है।डिजाइन जूरी में भाग लेने से छात्रों को उनके डिजाइन विकल्पों को व्यक्त करने और उनका बचाव करने की क्षमता विकसित करने में मदद मिलती है। यह मूल्यवान प्रतिक्रिया और अनुभवी पेशेवरों से अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जो उनके व्यावसायिक विकास में सहायक है।बी.आर्क कार्यक्रम एक कठोर और पुरस्कृत शैक्षणिक यात्रा है जो छात्रों को वास्तुकला के क्षेत्र में एक सफल करियर के लिए तैयार करता है। एक अच्छी तरह से संरचित पाठ्यक्रम, विविध मूल्यांकन रणनीतियों और समृद्ध स्टूडियो संस्कृति के माध्यम से, छात्रों को उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्राप्त होता है। गेमिफिकेशन जैसे नवाचार दृष्टिकोणों का एकीकरण सीखने के अनुभव को और बढ़ाता है, यह सुनिश्चित करता है कि स्नातक वास्तुकला पेशे की चुनौतियों का सामना करने के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं।

दस्तक प्रभात
डॉ.(प्रो.) नागेंद्र नारायण

आजादी के दीवाने

अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने में अग्रणी समर्पित व्यक्तित्व : विपिन चंद्र पाल

ब्रिटिश हुकूमत को भारत से उखाड़ फेंकने को के लिए कृत संकल्पित रहने वाले भारतीयों में बिपिन चंद्र पाल का नाम अग्रणी पंक्ति में लिया जाता है। जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई लेकिन आजादी को देखने से पूर्व ही इस संसार से विदा हो गए उनका नाम था- बिपिन चंद्र पाल।वे लेखक, पत्रकार और गुरु के साथ ही अच्छे वक्ता के रूप में जाने-माने जाने, वाले वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी रहे। जिनमें क्रान्तिकारी विचार कूट-कूट कर भरी थी। उन्हें क्रांतिकारी विचारों के जनक के रूप में भी देखा जाता है। उन्होंने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। आजादी की लड़ाई में विपिनचंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बालगंगाधर तिलक के सहयोगियों में गिने जाते रहे। बंगाल विभाजन के विरोध में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आंदोलन किया, जिसे बड़े स्तर पर जनता का समर्थन मिला थाऔर ओजपूर्ण विचारों बाले इन नेताओं ने अपनी बात तत्कालीन विदेशी शासक तक पहुँचाने के लिए कई नये-नये तरीके अपनाए जो सबसे अलग थे। इन तरीकों में ब्रिटेन में तैयार उत्पादों का बहिष्कार, मैनचेस्टर की मिलों में बने कपड़ों से परहेज, औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में हड़ताल करवाने जैसे कारनामों में उन्हें सबसे अलग देखा जाता था।उनके अनुसार विदेशी उत्पादों के कारण देश की अर्थव्यवस्था खस्ताहाल हो रही थी। भारतीय जनता को काम से भी वे दखल कल होना पड़ रहा था। पाल साहब ने अपने आंदोलन में इस नये तरिके विचार को भी लोगों में अपनी पैठ बनाई। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गर्म जोशी दिखाने वाले दलों को महत्वपूर्ण माना जाता था।जिससे आंदोलन को एक नई दिशा मिली थी। जिससे लोगों के बीच जागरुकता बढ़ती रही। आजादी आंदोलन में लोगों को जागरुक बनाने में पाल साहब की महत्त्वपूर्ण भूमिका मानी जाती थी। पाल साहब को विश्वास था कि केवल प्राथत्मक भूमिका से आजाद भारत की संकल्पना मूर्त रूप नहीं ले सकती। सुखी संपन्न बंगाली कायस्थ परिवार में पैदा विपिनचंद्र पाल सार्वजनिक जीवन के अलावा अपने निजी जीवन में भी अपने विचारों पर अमल करने वाले और स्थापित दकियानूसी मान्यताओं के खिलाफ थे। उन्होंने एक विधवा से विवाह किया था जो उस समय दुर्लभ बात थी। इसके लिए उन्हें अपने परिवार से नाता तोड़ना पड़ा। लेकिन धुन के पक्के पाल ने दबावों के बावजूद कोई समझौता नहीं किया। वे एक नहीं आने को पुस्तकों के लेखक के रूप में भी जाने जाते हैं और सजग पत्रकार की भूमिका अदा करने वालों में भी उनकी गिनती होती है। वे शिक्षा का अलख जगाने में भी लग रहे। किसी के विचारों से असहमत होने पर वह उसे व्यक्त करने में पीछे नहीं रहते। बिपिन चन्द्र पाल की स्मृति में भारत सरकार ने डाकटिकट जारी किया था। केशवचंद्र सेन, शिवनाथ शास्त्री जैसे नेताओं से प्रभावित पाल को अरविन्द के खिलाफ गवाही देने से इंकार करने पर छह महीने की सजा हुई थी। इसके बाद भी उन्होंने गवाही देने से इंकार कर दिया था। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में बिपिन चंद्र पाल ने महत्वपूर्ण योगदान किया था। ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बिपिन चंद्र पाल का निधन 20 मई 1932 को हो गई। उनका कृतित्व और व्यक्तित्व भारतवासियों के लिए सुनहरे कल को समर्पित रही।

दस्तक प्रभात/स.गंगु जी

पद यात्रा

कहा मन बिखिआ सिउ लपटाही

मानव जीवन संघर्ष और अनिश्चिताओं का प्रतिरूप है क जीवन की नैया कभी सहजता और सरलता से आगे नहीं बढती रहती बल्कि जीवन में कई तरह की समस्याएं आती-जाती रहती है क ये समस्याएं कभी कभी परिस्थिति की देन के रूप में तो कभी अपनी दुर्बलताओं के कारण उत्पन्न होती हैं क हम परिस्थिति से तो लड़ लेते हैं किंतु अपनी दुर्बलताओं पर विजय नहीं प्राप्त कर पाते क ऐसे में मनुष्य कई बार किंकर्तव्यविमूढ़ हो भटकने लगता है क मानव के भटकाव का कारण उसका मन ही नहीं अपितु उसकी वृति तथा उसे प्राप्त होने वाली विविध सुविधाएं भी हैं क अपनी वृति तथा सुविधाओं के मोह पाश में बंधा मनुष्य कई बार असंगत चाल चलने लगता है क अतः संतों ने मोह से दूर मन को प्रभु सुमिरन में सदैव आगे बढने का मार्ग दशार्या है क सिख सम्प्रदाय के नवम गुरु गुरु तेग बहादुर जी का मानना है कि ये मन एक स्थान पर कभी भी स्थिर नहीं रहता बल्कि मोह-माया, काम-वासना और इच्छाओं के जाल में उलझकर स्वयं तो भटकता ही है साथ ही समाज को भी भटकाता रहता है इसलिए वे मन को समस्त माया से दूर रहने की बात कहते हुए एक स्थल पर लिखते हैं- कहा मन बिखिआ सिउ लापटाही। या जग मै कोऊ रहनु न पावै इक आवही इक जाहि।। कांकतनु धनु संपति काँकि का सिउ नेहू लगाही।। जो दीसै सो सगल बिनासै जिउ बादर की छाही।। तजि अभिमानु सरणी संतन गहु मुकति होहि छिन माही। जन नानक भगवंत भजन बिनु सुखु सुपने भी नाही।। इस पद के माध्यम से गुरु तेगबहादुर जी कहना चाहते हैं कि मन बहुत ही चंचल है जो सदैव भटकता रहता है क अतः मन को प्रबोध देते हुए कहते हैं कि मन तू सदैव विषय-वासनाओं के मोह से लिपटा रहता है अथवा सदैव इसमें लिप्त रहता है क इस संसार में सभी एक सामान नहीं रहते और न ही जीवन में सभी वस्तुएं सदैव बनी रहने वाली हैं क जो जन्म लेगा या जो प्राप्त होगा वह साथ छोड़कर एक दिन जाएगा ही क ये शरीर सदैव रहने वाला नहीं है तथा ये धन संपत्ति भी सदैव साथ देने वाली नहीं है इसलिए शरीर एवं सम्पत्ति के मोह से दूर ही रहो क इस शरीर और सम्पत्ति से मोह करना व्यर्थ है ये सब एक दिन छीन जाएगी क इस संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह सब कुछ बादल की छाया के सामान क्षणिक और क्षणभंगुर है क इनसे जुड़े अहंकार को त्यागकर हे मन तू संत की शरण में ही जा क संत के मार्ग का अनुसरण कर उनकी शरण में जाने से ही जीवन के समस्त जंजालों से मुक्ति मिल पाएगी क गुरु जी का मानना है कि परमात्मा के भजन के बिना सपने में भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता क अतः संत शरण और हरि भजन दो ऐसे तत्व हैं जो जीव रूप मन को समस्त मोह से मुक्त रखते हैं, इसे इस रूप में भी देखा जा सकता है कि संतों का केवल कर्म करने के मार्ग का अनुसरण कर जीव कर्मठ बनता है तो हरि सुमिरन के द्वारा उसमे आंतरिक शक्ति के साथ-साथ आत्मविश्वास भी उत्पन्न होता है क अतः इस पद को इस रूप में भी देखा जा सकता है कि यदि हम अपने सत्कर्मों पर ध्यान दें, अपना कर्म करते रहें तथा आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो जीवन जीयें तो न तो हमें किसी भी प्रकार का मोह सता पाएगा और न ही हमारा मार्ग अवरुद्ध हो पाएगा क अतः मन को संत शरण तथा हरि सुमिरन में लगा रहना चाहिए।

दस्तक प्रभात
डॉ. कुलभूषण शर्मा

नवभारत टाइम्स
नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। शनिवार, 10 अगस्त 2024

पैरिस क्यों है ख़ास

तोक्यो में मिले थे 7 पदक, पैरिस में 6 मिले

पदकों की संख्या और रंग के लिहाज से भले ही पैरिस ओलिंपिक्स में भारत का अभी तक का प्रदर्शन तोक्यो के मुकाबले फीका लग रहा हो, संघर्ष की आभा इस बार पहले से भी ज्यादा निखरी हुई है। तोक्यो में भारत ने एक स्वर्ण सहित सात पदक जीते थे, जबकि इस बार पैरिस में एक सिल्वर और पांच ब्रॉन्ज सहित छह पदक जीत पाया है।

विनेश को मिला सबका साथ | पैरिस ओलिंपिक्स की सबसे चमकदार कहानी विनेश फोगाट की ही साबित हुई है। जिस तरह से उन्होंने एक ही दिन में तीन रेसलरों को हराकर फाइनल में अपनी जगह बनाई, वह इस बात की मिसाल है कि कोई भी खिलाड़ी संकल्प और कौशल के बूते किस तरह का करिश्मा कर सकता है। मगर 100 ग्राम वजन इन सब पर भारी पड़ गया। बहरहाल, उनका व्यक्तित्व और संघर्ष ऐसी मिसाल के रूप में सामने आया है जो न केवल खिलाड़ियों को बल्कि हर देश की लड़की को ताकत और प्रेरणा देता रहेगा।

हॉकी, जैवलिन में फिर पदक

प्रदर्शन में सुधार | तोक्यो ओलिंपिक्स में गोल्ड मेडल लाने वाले नीरज चोपड़ा इस बार सिल्वर साध पाए, लेकिन उन्होंने अपने पिछले परफॉरमेंस में काफी सुधार किया। तोक्यो में उन्होंने 87.58 मीटर की दूरी हासिल की थी, तो इस बार उनका प्रदर्शन 89.45 मीटर तक पहुंच गया।

खेल भावना | पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 मीटर के साथ नया ओलिपिंक्स रेकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड हासिल किया। लेकिन इस मुकाबले का सबसे खूबसूरत लम्हा इसके बाद आया जब न केवल नीरज ने अरशद की तारीफ की बल्कि उनकी मां ने नतीजों पर खुशी जताते हुए कहा कि गोल्ड जीतने वाला अरशद नदीम भी उनका ही बच्चा है।

शूटिंग की शान | शूटिंग में मनु भाकर ने एक ओलिंपिक्स में दो पदक लाने का कमाल दिखाया। दूसरे ब्रॉन्ज में सरबजोत सिंह उनके भागीदार रहे। मनु की यह उपलब्धि इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि तोक्यो ओलिंपिक्स में वह पिस्टल खराब होने के कारण कुछ कर नहीं पाई थीं। शूटिंग में स्वप्निल कुसाले का ब्रॉन्ज भी कमाल ही है। वह बेहद साधारण परिवार से आते हैं और तमाम आर्थिक दिक्कतों के बावजूद इस मकाम तक पहुंचे।

हॉकी में कमाल | हॉकी में तोक्यो के बाद लगातार दूसरा ओलिपिंक्स ब्रॉन्ज जीतना तो जैसे सोने पे सुहागा हो गया। भारतीय खिलाड़ियों ने इन मुकाबलों में जिस तरह की टीम भावना का प्रदर्शन किया, वह काबिले तारीफ है। खासकर कुल 15 में से 10 गोल दागने वाले कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पदक दिलाने वाली इस जीत के साथ हॉकी से संन्यास लेने वाले अप्रतिम गोलकीपर श्रीजेश तो खेलप्रेमियों के दिलों में हमेशा बने रहेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो पैरिस ओलिंपिक्स का हमारा अनुभव भविष्य के बेहतर प्रदर्शन को लेकर आश्वस्त करता हुआ समाप्त हो रहा है।

दो दूनी चार

कैसे रुके ठगी

रमेश तिवारी

शेयर बाजार में निवेश के नाम पर मोटे मुनाफे का झांसा देकर ठग लिया गया, इस तरह की रिपोर्ट अक्सर सामने आ रही है। इसके पीड़ित देश के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले नहीं हैं, बल्कि बड़े शहरों के भी हैं। एक तरफ ये घटनाएं हैं, दूसरी तरफ भारत में 16 करोड़ से ज्यादा डीमैट खाते खुल चुके हैं, जिनसे शेयर बाजार में सीधे कारोबार किया जा रहा होगा। म्युचुअल फंडों के जरिये शेयर बाजार में 27 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम लगाई जा चुकी है। सवाल है कि जब शेयर बाजार से सीधे या म्युचुअल फंडों के जरिये जुड़ा जा सकता है, तो कोई क्यों ठगी का शिकार हो रहा है। इसमें एक बड़ी वजह यह है कि वित्तीय साक्षरता का अभाव है, दूसरी तरफ शिकायतों को निपटाने का सिस्टम बेहद कमजोर है।

वित्तीय सेवाएं डिजिटल रूप में सामने आ रही हैं। फाइनैंस और टेक्नॉलजी के तालमेल से फिनटेक इंडस्ट्री सामने आई, जो हर मोबाइल पर मौजूद है। इस इंडस्ट्री का जो बाजार है, उनमें आम लोगों की भागीदारी बढ़ रही है। यह देखकर खुश हुआ जा सकता है, लेकिन इसने नई चुनौतियां भी पेश की हैं। सोशल मीडिया पर नकली फिनटेक इंडस्ट्री भी पनप रही है, जिसका लोग शिकार हो रहे हैं। वहां पीड़ित होने के बाद लोग चुप रहने में ही भलाई समझते हैं। इस मकड़जाल से निपटने की जिम्मेदारी सरकार की है। अभी जो पॉलिसी है, वह यही है कि लोग बाजार से ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ें। इसके लिए नियम आसान बनाए गए। लेकिन निवेशकों की अनदेखी और लापरवाही के साथ-साथ धोखाधड़ी ने इसमें बाधा खड़ी कर दी है। इस बारे में शिकायतों को दूर करने का सिस्टम अभी पुख्ता नहीं है।

शिकायतों को देखने के लिए सेबी जैसे नियामक मौजूद हैं। उनके पास भरपूर ताकत है। लेकिन अक्सर निवेशक समझ ही नहीं पाता कि शिकायत किस तरह दर्ज कराई जाए। डिजिटल मंच पर अपनी बात रखी जा सकती है, लेकिन आबादी के एक बड़े हिस्से के पास या तो जरूरी डिजिटल उपकरण नहीं हैं, या फिर उन्हें इसके इस्तेमाल की जानकारी नहीं है।अभी शिकायत करने वाला सीधे टॉप अथॉरिटी से संपर्क नहीं कर पाता। देरी के चलते भी आम लोग परेशान हो जाते हैं। अगर शिकायत निवारण का एक मजबूत तंत्र हो तो शेयर बाजार और बड़ा होगा। हो सकता है कि छोटे निवेशकों की संख्या पूरी दुनिया को हैरान कर दे।

आम लोगों के बीच वित्तीय साक्षरता बढ़ाने की जरूरत है। एक रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया भर में देखें तो 35% पुरुष वित्तीय रूप से साक्षर हैं, जबकि महिलाओं की संख्या 30% है। विकासशील देशों में देखें तो वित्तीय साक्षरता के मामले में पुरुषों और महिलाओं में अंतर बढ़ जाता है। वित्तीय साक्षरता की यह कमी केवल बुनियादी बातों को समझने के बारे में नहीं है, बल्कि शिकायतों को दूर करने के सिस्टम की समझ के बारे में भी है।

जानकारी बढ़ाने के लिए वर्चुअल असिस्टेंट के जरिये वित्तीय सेवाओं का लाभ दिलाया जा सकता है। उन्हीं के जरिये शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। दूरदराज के जिन इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की दिक्कत है, वहां कियोस्क स्थापित करने से मदद मिलेगी। मोबाइल लर्निंग ऐप में छोटे-छोटे मॉड्यूल के जरिये लोगों की समझ बढ़ाई जा सकती है। गेम के जरिये लोगों को इससे जोड़ा जा सकता है। वक्त लग सकता है, लेकिन निवेश पैसा गंवाने की जगह कमाने के काम आएगा।

ऑफ दि ट्रैक

UFOs की अहमियत

दिलीप लाल

आमतौर पर वैज्ञानिक अनआइडेंटिफाइंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट (UFO) को गंभीरता से नहीं लेते हैं और इसे अविश्वसनीय मानते हैं। लेकिन हाल ही में आई साइंस न्यूज की एक रिपोर्ट ने इस नजरिए को बदल दिया है। इसके लिए अमेरिकन्स फॉर सेफ एयरोस्पेस जैसे संगठनों ने आम नागरिक, एजेंसियों और पायलटों को इन UFOs को नजरअंदाज न करके इस पर अध्ययन करने की सलाह दी है। आसमान में होने वाली घटनाएं मनमोहक लगती हैं, कुछ डरावनी होती हैं। ये अज्ञात असामान्य घटनाएं (UAPs) हैं। इसकी चर्चा सबसे पहले 1940-50 के दशक में दुनिया में आई। 8 जुलाई 1947 को जोरदार तूफान के साथ न्यू मैक्सिको के रोसवेल में खेत में एक 'फ्लाइंग डिस्क' आकर गिरी थी, किसी अनहोनी की आशंका से तब डर का माहौल पैदा हो गया था। तब इसे उड़नतस्तरी कहकर ढेर सारी मनगढ़ंत कहानियां गढ़ी गई थीं। सचाई का का पता चलने पर कहानी बदल गई। यह रूस के परमाणु परीक्षणों की निगरानी के लिए छोड़े गए गुब्बारे का अवशेष था। पिछले साल ही अमेरिका, कनाडा और लैटिन अमेरिका के एयरस्पेस पर चीन के संदिग्ध जासूसी गुब्बारे ने खलबली मचा दी थी। बाद में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने इस स्पाई बलून से किसी खतरे की आशंका से खारिज कर दिया था। लेकिन अब उनका मानना है कि ड्रोन और अन्य हवाई हमले को बेकाबू करने में UFOs का अध्ययन मददगार होगा।

मैं मानता हूं कि यूट्यूब पर सफल होने वाली सामग्री इंसान ही बनाएंगे

क्रिएटर्स की ताक़त हैं AI टूल

*यूट्यूब के CEO नील मोहन का कहना है कि भारत यूट्यूब के कई ग्लोबल प्रॉडक्ट्स की सफलता का गढ़ रहा है, जिनमें शॉर्ट-विडियो फॉर्मेट भी शामिल है। लखनऊ में पले-बढ़े नील फरवरी में CEO बनने के बाद पहली बार भारत आए हैं। उनसे बात की **सुरभि अग्रवाल** और **अन्नपूर्णा रॉय** ने। पेश हैं बातचीत के प्रमुख अंश :*

■ भारत में यूट्यूब की कैसी तस्वीर देखते हैं?

यहां का माहौल बहुत डायनमिक है। । यूट्यूब पर क्रिएटर इकॉनमी ने 16,000 करोड़ रुपये की इकॉनमिक एक्टिविटीज के साथ-साथ 7,50,000 नौकरियां बनाई हैं। हमें इस पर बहुत गर्व है और हम इसमें भारी निवेश कर रहे हैं।

■ भारत में, नए ब्रॉडकास्टिंग बिल को लेकर बहुत चर्चा है, जो यूट्यूब को सरकार के राडार पर ला सकता है। आपका क्या कहना है?

अभी इस पर बोलना जल्दबाजी होगी। हम प्रस्तावित बिल का अध्ययन कर रहे हैं और इसके बारे में सरकार से बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भारत में मौजूद शानदार क्रिएटर इकॉनमी को सपोर्ट करने में हमारी भूमिका पॉजिटिव और वाइब्रेंट बनी रहे। जब मैं सरकार के लोगों से मिलूंगा तो यह मेरी सबसे शीर्ष प्राथमिकता होगी।

■ राजनीति में यूट्यूब एक प्रभावशाली मंच बन गया है। इस पर बढ़ते रेग्युलेशन के बारे में आपका क्या कहना है?

मेरा अनुभव सरकारों के साथ करीबी से काम करने का रहा है, जिसमें भारत भी शामिल है। हाई लेवल पर हमारे हित हमेशा मेल खाते हैं। सरकारें अपने नागरिकों और समाज के हित में सही कदम उठाना चाहती हैं और यूट्यूब भी उन देशों में पॉजिटिव फोर्स बनने की कोशिश कर रहा है। इस प्लेटफॉर्म ने क्रिएटर्स को बड़ा मौका दिया है। हम एक ओपन प्लेटफॉर्म हैं, जहां हर किसी को अपनी आवाज उठाने का मौका मिलता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कुछ भी चलेगा। हमें इस बात का संतुलन बनाना होता है कि यह एक खुला मंच बना रहे, लेकिन साथ ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भी बनाए रखा जाए।

■ हाल ही में हुए भारतीय चुनावों में यूट्यूब की भूमिका पर आपकी टिप्पणी?

कुछ समय पहले ही यहां लोकसभा चुनाव हुए। इसमें हमने यह सुनिश्चित करने के लिए काफी संसाधन लगाए कि यूट्यूब खुली राजनीतिक चर्चा की जगह तो हो, लेकिन यह चुनाव से जुड़ी गलत सूचनाओं की जगह न बने। हमारे पास एक ब्रेकिंग न्यूज शेल्फ भी थी, जो समाचार सर्च करने वालों के लिए आधिकारिक स्रोतों से सामग्री लाती है। उस शेल्फ को 250 मिलियन बार देखा गया। असल में हम यह सुनिश्चित करते हैं कि चुनावी जानकारी के बारे में आधिकारिक सामग्री आगे तो बढ़े, लेकिन कम्युनिटी गाइडलाइंस भी सख्ती से लागू रहे। मुझे लगता है कि इससे हमारे हितधारकों और सरकार व नियामकों के साथ विश्वसनीयता का रेकॉर्ड बना है।

■ भारत के बाजार में कौन सी बातें हैं जो आपको उत्साहित करती हैं?

यूट्यूब शॉर्ट्स एक उदाहरण है, जहां भारत ने वाकई लीड किया है। यूट्यूब क्रिएट एक नया ऐप आया है, जिसे लेकर मैं बहुत उत्साहित हूं। यह पहले भारत में लॉन्च किया गया, उसके बाद इसे बाकी दुनिया में लाया जाएगा। यह एक क्रिएशन ऐप है, जो इस विचार पर आधारित है कि कैसे तकनीक कंटेंट क्रिएशन के लिए टूल बना सकती है। बहुत सारे जेनरेटिव AI और बड़े भाषा मॉडल से चलने वाले क्रिएटिविटी टूल्स इसमें होंगे, क्योंकि किसी भी पर्पस-बिल्ट ऐप में ऐसा होना अच्छा है। दूसरी बात जो उत्साहित करती है, वह यह है कि भारतीय क्रिएटर्स की बहुत बड़ी ऑडियंस है और वे भारत के सच्चे राजदूत हैं, जो पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति को साझा कर रहे हैं। अब इसके विकास की इकलौती बाधा भाषा है, क्योंकि बहुत सारी अद्भुत क्रिएटिविटी भाषा के कारण दुनिया के बाकी हिस्सों में नहीं देखी जा रही है। हम जिन टूल्स पर काम कर रहे हैं उनमें से एक को मल्टीट्रैक ऑडियो कहा जाता है। यानी अगर आप ऐसे क्रिएटर हैं जो हिंदी, तेलुगु या तमिल में कंटेंट बना रहे हैं, तो न केवल यह AI का उपयोग करके अन्य भारतीय भाषाओं में इसका अनुवाद करने में सक्षम होगा, बल्कि इसमें असली ह्यूमन टच भी देगा।

Subrata Dhar

सप्ताह का इंटरव्यू

यूट्यूब के CEO नील मोहन

> भारतीय क्रिएटर्स की बहुत बड़ी ऑडियंस है और वे भारत के सच्चे राजदूत हैं, जो दुनियाभर में भारतीय संस्कृति को पहुंचा रहे है। मुझे लगता है कि अब इस ग्रोथ में इकलौती बाधा भाषा है, क्योंकि बहुत सारी अद्भुत क्रिएटिविटी भाषा के कारण दुनिया के बाकी हिस्सों में नहीं देखी जा रही है

■ आप जेनरेटिव AI को कैसे देखते हैं, जिसे एक बड़ा बदलाव लाने वाला माना जाता है?

AI कई नए अवसर पैदा करेगा, लेकिन इसके साथ कुछ बदलाव और चुनौतियां भी आएंगी। हमें इन अवसरों को अपनाने के लिए साहसिक कदम उठाने होंगे, लेकिन साथ ही इन चुनौतियों से निपटने के लिए जिम्मेदार भी रहना होगा। मैं जिस चीज़ को लेकर बहुत उत्साहित हूं, वह यह है कि AI के टूल्स क्रिएटर्स के हाथों में होंगे, जो उन्हें अपनी क्रिएटिविटी दिखाने में मदद करेंगे, लेकिन विचार और कहानियां अब भी इंसानी होंगी। हम सभी इंसानों में, दूसरों के प्रति दिलचस्पी होती है और यही यूट्यूब की असली ताकत है।

■ भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में उद्यमियों के लिए आपका क्या सुझाव होगा?

यह एक बेहद जीवंत इकोसिस्टम है। यहां की क्रिएटिविटी, आइडियाज, 'कैन डू' वाला रवैया और अविश्वसनीय वर्क एथिक जो मैंने देखा है, वह वाकई अद्भुत है। क्रिएटर्स भी अपने आप में आंट्रप्रेन्योर होते हैं। एक स्टार्टअप उद्यमी को, जो आज एक कंपनी शुरू कर रहा है, और एक क्रिएटर, जो आज एक चैनल शुरू कर रहा है- मैं एक जैसा ही सुझाव दूंगा। दोनों वास्तव में अपने जुनून के प्रति सच्चे रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है। यह इसलिए बेहतर होगा कि यह कुछ ऐसा होगा, जिसके लिए आप वास्तव में जुनूनी हैं। और अगर आपमें जुनून है, तो मेरी एकमात्र सलाह है कि इसके लिए आगे बढ़ें।

■ क्या आपको लगता है कि लोग असल और AI जेनरेटेड चीजों में अंतर नहीं कर पाते तो यह क्रिएटर इकॉनमी के लिए खतरा है?

जब भी इस तरह के बड़े तकनीकी बदलाव आते हैं, तो दो बातें होती हैं। एक, हम सभी यूट्यूब पर दर्शक के रूप में सच में मानवीय कहानियों में रुचि रखते हैं। मैं मानता हूं कि यूट्यूब पर सफल होने वाली सामग्री इंसान ही बनाएंगे। कंप्यूटर लंबे समय से शतरंज खेलने में सक्षम हैं, लेकिन हम मनुष्यों को शतरंज खेलते हुए देखने में रुचि रखते हैं। मुझे लगता है कि जेनरेटिव AI की दुनिया में भी यही सच होने जा रहा है।

कब सस्ती होगी दवा

सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया जैसी जेनेटिक बीमारियां पिछली सदी तक लाइलाज थीं। जीनोम मेडिसिन से इन बीमारियों के इलाज की उम्मीद जगी है, लेकिन इसमें कुछ मुश्किलें भी हैं, जानते हैं :

इलाज पहुंच के बाहर

कोलकाता के सरकारी अस्पताल में दो महीने पहले SMA से पीड़ित बच्चे को जीन थिरेपी दी गई। इंजेक्शन की कीमत थी 17.5 करोड़ रुपये। फिलहाल जीन थिरेपी से महंगा कोई इलाज नहीं। विकसित देश तक इनका खर्च उठाने में असमर्थ हैं।

इतना महंगा क्यों

रिसर्च और डिवेलपमेंट का काम बहुत खर्चीला है। अभी गिनती की कंपनियां जीनोम मेडिसिन डिवेलप कर रही हैं। उनका कहना है कि नई दवाएं बनाना बेहद मुश्किल और जोखिम भरा है। दवा की हर बैच अलग तरह की होती है।

AI image

उत्पादन बढ़ाना होगा

कोई भी टेक्नॉलजी समय के साथ सस्ती होती जाती है। यही चीज मेडिकल फील्ड के साथ भी है। एंटीबॉडी का उदाहरण हमारे सामने है। पिछले 20 बरसों में इनके दामों में 50 गुना तक की गिरावट दर्ज की गई है। ज्यादा से ज्यादा कंपनियां इस फील्ड में आएंगी तो प्रॉडक्शन बढ़ेगा। इससे दाम अपने आप नीचे आ जाएंगे। रिसर्च में पब्लिक फंडिंग का सहारा ले सकते हैं।

सरकार करे पहल

फार्मा कंपनियों को जीनोम मेडिसिन के फील्ड में आने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। इसमें सबसे बड़ी भूमिका है सरकार की। अभी नार्म्स और रेगुलेशन बहुत ज्यादा कड़े हैं। सुरक्षा और गुणवत्ता से समझौता किए बिना कंपनियों को सरकार कुछ सहूलियत दे सकती है। छोटी कंपनियों को इंसेंटिव दिया जाए।

इंश्योरेंस का हिस्सा बने

जीन थिरेपी को हेल्थ इंश्योरेंस का हिस्सा बनाने से बड़ी राहत मिलेगी। सरकार इस मामले में इनिशिएटिव ले सकती है। बड़े सरकारी अस्पतालों में सस्ते दर पर इलाज उपलब्ध कराया जाए। आजकल हर खरीदारी EMI पर हो सकती है, तो जीन थिरेपी क्यों नहीं?

प्रस्तुति : **शैलेंद्र पांडेय**

अयोध्या दुष्कर्म केस में न हो राजनीति

नाबालिग के साथ बलात्कार पर सियासी दलों का रवैया ठीक नहीं

अवधेश कुमार

अयोध्या जिले में जो नाबालिग दुष्कर्म कांड हुआ, वह इस मायने में ज्यादा भयावह है कि इतने वीभत्स कांड पर नेताओं के एक वर्ग ने या तो मौन धारण कर लिया है या परोक्ष रूप से आरोपी का बचाव करने उतर गया है। गौरतलब है कि इस मामले का मुख्य आरोपी कथित तौर पर एक राजनीतिक दल से जुड़ा है।

PTI

दुष्कर्म कांड के आरोपी की बेकरी पर घटना के बाद चला बुलडोजर

विक्टिम पर डाला दबाव | एफआईआर के मुताबिक, बच्ची को आरोपी ने चॉकलेट, बिस्कुट वगैरह देने के लालच से घर के अंदर बुलाया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी के नौकर ने भी यही किया। आरोपियों ने नाबालिग लड़की का विडियो भी बनाया। विडियो वायरल करने का डर दिखाकर आरोपियों ने उसे चेताया कि वह इसके बारे में किसी को न बताए। यही डर दिखाकर वे लड़की से काफी दिनों तक दुष्कर्म भी करते रहे। लड़की अगर गर्भवती नहीं होती तो शायद इसका पता भी नहीं चलता।

मां की नहीं सुनी | विडंबना देखिए कि लड़की की मां की बात सुनने वाला कोई नहीं था। थाने ने पहले तो मुकदमा दर्ज करने से ही इनकार कर दिया। बाद में कहा कि तुम केवल नौकर को आरोपी बनाओ, तभी एफआईआर दर्ज होगी। अस्पताल में आरोपियों की ओर से समझौता करने का दबाव बनाया गया। इसमें कथित तौर पर उस राजनीतिक दल के नेता शामिल हैं, जिस दल से मुख्य आरोपी को जुड़ा हुआ बताया जा रहा है।

चल गया बुलडोजर | ध्यान रहे, आरोपी के घर में ही स्थानीय थाना किराए पर चल रहा था। लड़की की मां जब थाने गई तो वह वहीं बैठा था। पुलिस वाले उसके साथ थे। एक बेहद गरीब परिवार की महिला के अंदर यह देखकर कैसा भाव पैदा हुआ होगा, इसकी कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हालांकि पुलिस-प्रशासन ने उसके अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त किया है जिसमें बेकरी भी शामिल है। इसका संकेत यही है कि लोकसभा चुनाव परिणाम से उत्तर प्रदेश सरकार दबाव में नहीं है और अपराधियों के विरुद्ध पहले की तरह ही कार्रवाई होगी।

बातें जो बेचैन करती हैं

- पुलिस का शुरुआती ढीला-ढाला रुख
- आरोपी के पक्ष में खड़ी हुई राजनीति
- बड़े नेताओं ने ओढ़ी रहस्यमय चुप्पी

DNA टेस्ट की मांग | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में अपने परिचित तेवर में कहा भी कि अपराधी कोई भी हो उसके साथ अपराधी जैसा ही व्यवहार होगा। लेकिन विपक्षी गठबंधन का इस प्रकरण में ऐसा चेहरा सामने आया है, जिसकी इनके समर्थकों ने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। यह साफ लगता है कि विपक्ष की कोशिश किसी न किसी तरह आरोपी को निर्दोष बताने और योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की है। विपक्ष की ओर से पहले तो पीड़िता के गर्भ में पल रहे बच्चे का DNA टेस्ट कराने की मांग हुई। फिर अदालत से इस मामले को अपने निगरानी में लेकर बालिका को संरक्षण देने की मांग हुई। सवाल है कि बालिका को असुरक्षा किससे है? समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने बयान दिया कि गाजीपुर में बलात्कार का आरोपी ठाकुर है तो क्या उसके घर भी बुलडोजर चलेगा? कहने का मतलब यह था कि आरोपी अल्पसंख्यक है, इसलिए उसके घर पर बुलडोजर चलाया गया।

मजहब पर ठीकरा | कुल मिलाकर विपक्ष यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि आरोपी निर्दोष है। चूंकि वह अल्पसंख्यक समुदाय से आता है, इसलिए योगी सरकार उसके विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। सच इसके विपरीत भी हो सकता है। आरोपी का मजहब इन पार्टियों को उसके विरुद्ध बोलने से रोक रहा है क्योंकि प्रश्न वोट का है। समाजवादी पार्टी की नजर में अगर आरोपी निर्दोष है, तो भी आरोप लगने के बाद उसे पार्टी से निलंबित किया जा सकता था जब तक कि जांच का नतीजा सामने नहीं आ जाता।

कथनी और करनी | खैर, इस मामले में सच और झूठ का फैसला अदालत में हो जाएगा। लेकिन क्या DNA जांच की मांग या इस तरह की बातें उस पीड़िता के आरोपों को झूठा साबित करना नहीं है? इन नेताओं का रवैया किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं हो सकता। बाल शोषण, यौन शोषण, दुष्कर्म, महिलाओं के अधिकार की बात आपके एक्शन में भी दिखना चाहिए।

क्या करे समाज : सवाल समाज पर भी है। समाज का इस पूरे घटनाक्रम पर उठकर खड़ा नहीं होना चिंता पैदा करता है। लोगों को अपने जनप्रतिनिधियों से इस मामले को लेकर सवाल करने चाहिए। वहीं, इस प्रकरण में पुलिस का शुरुआती रवैया भी ठीक नहीं था। सवाल है कि क्या यह स्थिति बदलनी नहीं चाहिए।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और विचारक हैं)

अम्मा की तरह नहीं पिटना मुझे

पति की नौकरी के सिलसिले में कुछ समय के लिए गुड़गांव में थी। उस वक्त मैं भी नौकरी करती थी। घर का काम करने के लिए एक मेड आती थी। वह सुबह-शाम खाना पकाने और साफ-सफाई का काम कर जाती। एक दिन दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला। सामने एक लड़की खड़ी थी। मैंने पूछा, 'तुम कौन?' 'मेरा नाम किरन है। अम्मा की तबीयत ठीक नहीं। उन्होंने ही भेजा है, कुछ दिन आपका काम करने के लिए।' 'अच्छा तुम सुशीला की बेटी हो।' उसने सिर हिलाया। मैंने उसे भीतर बुला लिया। वह चुपचाप काम में जुट गई।

सुशीला से मैं ज्यादा बात नहीं करती थी। मगर किरन का सहमा, उदास चेहरा देखकर मुझे अजीब लगता। एक दिन मैंने जोर देकर उसकी उदासी का कारण पूछा तो वह फफक पड़ी। कहने लगी, 'मेरे पापा शराब पीकर रोज अम्मा को मारते हैं। अम्मा मार खाते-खाते कमजोर हो गई है। इसलिए बीमार पड़ती है।' किरन की बातें सुनकर मुझे मेरा बचपन याद आ गया। घरेलू हिंसा को मैंने बहुत करीब से देखा और झेला था। और यह भी जानती थी कि गरीबी और अशिक्षा इसकी मुख्य वजह है।

किरन ने भी आठवीं तक पढ़ाई कर स्कूल जाना छोड़ दिया था। वह घर पर ही रहती थी या सुशीला बीमार पड़े तो उसकी जगह काम करने जाती। मुझे लगा, दो-चार साल में उसकी भी शादी हो जाएगी। किसी कम पढ़े-लिखे या शराबी के साथ। अपनी अम्मा की तरह उसे भी घरेलू हिंसा झेलनी पड़ सकती है। यह सब सोचकर मैं सहम गई। एक दिन मैंने उससे कहा, 'किरन, तुम्हें अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करनी चाहिए।' वह बोली, 'मैं पढ़ना तो चाहती हूं मगर अम्मा के पास पैसे नहीं है।' मैंने कहा, 'तुम पैसों की चिंता मत करो।' मैंने एक स्कूल में प्राइवेट फॉर्म भरकर उसका दाखिला कर दिया। किताबें भी लाकर दे दीं। किताबें देखकर वह बहुत खुश हुई। ऐसी खिली कि जैसे गर्मी में दिनभर के मुरझाए पौधे शाम को पानी पाकर खिल उठते हैं। अगले दिन से काम के साथ उसकी पढ़ाई भी शुरू हो गई।

खुद अपनी आंख से

सरस्वती रमेश

उसके बोर्ड के पेपर आने वाले थे। वह तैयारी में लगी थी। तभी संयोग से पति की जॉब दिल्ली में लग गई। जल्द ही हम दिल्ली आ गए। आते-आते उसे मन लगाकर पढ़ने की हिदायत मैं दे आई थी। कई साल बीत गए। मेरे एड़ियों में दर्द रहने लगा था। एक दिन मैं हड्डियों के डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने चेक करने के बाद एक्स-रे कराने को कहा। मैं एक्स-रे रूम में गई। एक्स-रे कर रही लड़की ने मुझे देखते ही नमस्ते कहा। जब मैंने उसे देखा तो हैरान रह गई। 'अरे किरन! तुम यहां?' 'हां मैम! मैं यहां जॉब करती हूं।'

फिर उसने सब कुछ विस्तार से बताया। अंत में कहने लगी, 'आपकी वजह से आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकी वरना अपनी अम्मा की तरह जिंदगी भर रोती।' मैंने उसे गले लगाकर कहा, 'तुम्हारी मेहनत के बिना कुछ भी संभव न था।' मैं एक्स-रे रूम से बाहर आ गई थी पर दिमाग में किरन घूमती रही। प्रार्थना में मेरे हाथ उठ गए, हे भगवान! जैसे किरन को नई राह मिली वैसी सभी गरीब लड़कियों को मिले।

चलते-चलते...

दुनिया की आबादी के लगभग 4% लोग विभिन्न कारणों से मारिजुआना का इस्तेमाल करते हैं। गुरुवार को JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery पत्रिका में प्रकाशित यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया की एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि इसका ज्यादा इस्तेमाल करने वाले लोगों में सिर और गर्दन के कैंसर का जोखिम तीन गुना बढ़ जाता है।

वक्फ विधेयक की बातें क्यों लग रही हैं सही

कौसर जहां

वक्फ बोर्ड अधिनियम में बदलाव काफी पहले ही हो जाना चाहिए था। अब सरकार ने नई व्यवस्था के लिए जो संशोधन प्रस्तावित किए हैं, उनसे वक्फ बोर्ड ज्यादा प्रभावी रूप से काम कर पाएगा।

मुस्लिम समुदाय के उपेक्षित तबकों की भागीदारी का इंतजाम संशोधन में किया गया है। वहीं महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने का प्रस्ताव भी सराहनीय है। वक्फ की संपत्तियों का दुरुपयोग न हो, उनका सही मूल्यांकन किया जाए, भ्रष्टाचार की आशंका खत्म कर संपत्ति के अनुपात में राजस्व की व्यवस्था हो, इन बातों का भी विधेयक में ख्याल रखा गया है।

कोई भी बोर्ड या निकाय तभी प्रभावी होता है, जब उसके संचालन और प्रबंधन में पारदर्शिता हो और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। यह कोशिश प्रस्तावित संशोधनों में दिखती है।

हालांकि, लोकसभा में विपक्षी दलों के विरोध और NDA के सहयोगी दलों की मांग पर इसे विचार के लिए गुरुवार को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया। खैर, सरकार ने संशोधन के लिए दो विधेयक तैयार किए हैं। पहले विधेयक के जरिए मुसलमान वक्फ कानून, 1923 को समाप्त किया जाएगा, जबकि दूसरे के जरिए वक्फ कानून, 1995 में महत्वपूर्ण संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है। वक्फ कानून, 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 करने की बात है। इसके तहत केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में मुस्लिम और गैर-मुस्लिम का वाजिब प्रतिनिधित्व होगा। मुस्लिम समुदायों में अन्य पिछड़ा वर्गों- शिया, सुन्नी, बोहरा, आगाखानी का प्रतिनिधित्व होगा। केंद्रीय परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में दो महिलाओं को रखना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही दो सदस्यों के साथ ट्रिब्यूनल संरचना में सुधार किया जा रहा है।

वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण के लिए सर्वे कमिश्नर का अधिकार कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा नामित डिप्टी कलेक्टर को होगा। बोहरा और आगाखानियों के लिए अलग बोर्ड की स्थापना का प्रावधान भी इसमें किया गया है। किसी भी संपत्ति को वक्फ के रूप में दर्ज करने से पहले सभी संबंधित पक्षों को नोटिस दिया जाएगा। वक्फ परिषद में केंद्रीय मंत्री, तीन सांसद, मुस्लिम संगठनों के तीन नुमाइंदे, मुस्लिम कानून के तीन जानकार, सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के दो पूर्व जज, एक जाने-माने वकील, राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चार लोग, भारत सरकार के अतिरिक्त या संयुक्त सचिव आदि होंगे। इनमें दो महिलाओं का होना जरूरी होगा।

2013 में, वक्फ अधिनियम में संशोधन करके वक्फ बोर्डों को इसकी संपत्ति के मामले में असीमित अधिकार दिए गए थे, जिसे किसी अदालत में चुनौती भी नहीं दी जा सकती। यह एक तरह से जवाबदेही और पारदर्शिता के खिलाफ था और इसमें मुस्लिम समाज के हितों का ख्याल नहीं रखा गया था। नए प्रावधानों में इन सभी चिंताओं का समाधान किया गया है।

(लेखिका दिल्ली स्टेट हज कमिटी की चेयरपर्सन हैं)

आर.एन.आई. नं. 510/57© सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। स्वत्वाधिकारी बैनेट, कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के लिए राजीव यादव द्वारा, 7 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित तथा **टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस, साइट IV, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद** और प्लॉट नंबर 7-8, सेक्टर M-11, ट्रांसपोर्ट हब, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, मानेसर, हरियाणा से मुद्रित। फोन : 23302000 फैक्सः 23492047, पंजीकृत कार्यालय : दादाभाई नौरोजी रोड, मुंबई-400001। विमान सेवा शुल्क : 1 रु. प्रति कॉपी। नेपाल में कुल मूल्य : सोमवार से शनिवार : नेपाली 5 रु. ; रविवार : नेपाली 6 रु.
संपादक (दिल्ली मार्केट) : आशीष पांडे (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी)

अनमोल वचन

अपने को संकट में डाल कर कार्य संपन्न करने वालों की विजय होती है, कायरों की नहीं
-जवाहरलाल नेहरू

खुशी का माहौल

हाकी और जेवलिन थ्रो में आए कांस्य और रजत पदकों के आने पर देश में एक बार फिर खुशी का माहौल बन गया है। असल में विनेश फोगाट के फाइनल में पहुंचने के बाद अयोग्य होने से देश सदमे की स्थिति में पहुंच गया है। यह सच है कि हाकी का पदक देशवासियों में एक अलग ही ऊर्जा पैदा करता है। इसकी वजह इस खेल में दशकों तक भारत की बादशाहत बना रहना है। इसकी वजह से ही देशवासी हाकी को दिलो-जान से चाहते हैं। भारत टोक्यो ओलंपिक में जब 41 साल बाद ओलंपिक हाकी में कांस्य पदक जीतकर पोडियम पर चढ़ा था, तो उसने टीम और देश को भावुक बनाया था, लेकिन इस बार पोडियम पर चढ़ने ने भरोसा बनाया है कि अब हम बिग लीग वाली टीमों में शामिल ही नहीं हुए हैं बल्कि किसी भी टीम को हरा सकने का माद्दा रखते हैं। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने कांस्य पदक जीतने के बाद जो कहा, वह इसकी ही तस्दीक करती है। उन्होंने कहा कि लगातार दूसरे ओलंपिक में पदक जीतना हमारे लिए बहुत बड़ा पल है पर हमें सोने का तमगा नहीं जीत पाने का अफसोस है। इस बात में दम भी है। भारत ने ग्रुप मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज टीम को हराया और क्वार्टर फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन को फतह किया। जर्मनी के खिलाफ यदि कुछ गलतियां नहीं होतीं तो फाइनल तो खेल ही रहे होते। जहां तक बात नीरज चोपड़ा की है तो उनके स्वर्ण के बजाय रजत जीतने में उनके प्रयासों में कमी का नतीजा ना होकर नदीम अशरफ के असाधारण प्रदर्शन का नतीजा है। सही मायनों में एक बार नदीम के 92.97 मीटर की थ्रो करने के बाद सभी ने मान लिया था कि गोल्ड तो गया। हालांकि नीरज ने 89.45 मीटर का सीजन का बेस्ट प्रदर्शन किया। नीरज चोपड़ा लगातार दो ओलंपिक में स्वर्ण और रजत जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। हाकी के कांस्य और नीरज के रजत से देश में खुशियां जरूर आईं हैं पर पिछले ओलंपिक से भी खराब प्रदर्शन करके एक रजत और चार कांस्य पदक जीतना अच्छा प्रदर्शन तो कतई नहीं है। इसमें विनेश का पदक और जुड़ सकता है। इतना जरूर है कि विनेश यदि सोने का तमगा ले आतीं तो प्रदर्शन पिछली बार से बेहतर हो सकता था। यह जरूर है कि हमारे चार पांच खिलाड़ी बहुत ही मामूली अंतर से पिछड़कर चौथे स्थान पर रहे और वह पदक से वंचित हो गए। पर इससे लगता है कि खिलाड़ियों की मानसिक मजबूती पर काम करने की जरूरत है। इस क्षेत्र में काम करके प्रदर्शन को सुधारा जा सकता है।

सुविचारित फैसला

केंद्र की एनडीए सरकार ने विपक्ष के भारी विरोध के बीच बृहस्पतिवार को लोक सभा में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक, 2024 पेश करने के बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजने का निर्णय लिया। सरकार का यह सुविचारित फैसला है जिसका सभी को स्वागत करना चाहिए। हालांकि देश का एक राजनीतिक वर्ग इसे सरकार की पराजय बता रहा है। उसका मानना है कि जेपीसी में भेजने का मतलब सरकार इस विधेयक को संसद से पास कराने में सफल नहीं हो पाएगी। लेकिन शुक्रवार को संसदीय कार्यमंत्री और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने इस विधेयक पर दोनों सदनों की जेपीसी के लिए 21 लोक सभा सांसदों के नाम प्रस्तावित किए। इसमें राज्य सभा से 10 सदस्य शामिल होंगे। इस विधेयक को जेपीसी में विचार-विमर्श के लिए भेजने का यही आशय है कि लोगों को याद होगा कि मोदी सरकार के पिछले दोनों कार्यकाल में अनेक विधेयक पास हुए थे। लेकिन विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाए थे कि इनमें से किसी पर भी सदन में चर्चा नहीं हुई थी। किसानों से जुड़े कृषि संबंधी तीन कानूनों का क्या हश्र हुआ इसे यहां दोहराने की जरूरत नहीं है। वक्फ संशोधन विधेयक, 2024 के मामले में सरकार का नजरिया बहुत स्पष्ट है। आरोप भी लगाया जाता है कि बहुत सी जमीनों पर भू माफिया का कब्जा है। सरकार का मानना है कि खरबों रुपए की संपत्ति पर मालिकाना हक होने के बाद भी वक्फ बोर्ड गरीब मुसलमानों की मदद नहीं कर रहा है। अगर सरकार नेक इरादे से बोर्ड को नियमित करना चाहती है तो इसमें गलत क्या है। एनडीए के सहयोगी दलों जद (यू) और तेलुगू देशम के साथ शिवसेना ने भी सरकार का समर्थन किया है। विपक्ष का आरोप सरासर गलत है कि इस विधेयक से धार्मिक स्वतंत्रता और संघीय ढांचे पर कुठाराघात हो रहा है। सिर्फ विरोध के लिए विरोध की नीति से न लोकतंत्र चलता है और न देश आगे बढ़ता है। उम्मीद की जानी चाहिए शीतकालीन सत्र में जब जेपीसी की रिपोर्ट आएगी तो सभी को सर्वमान्य हल दिखाई देगा।

कटाक्ष/ कबीरदास

विनेश हारा नहीं करतीं!

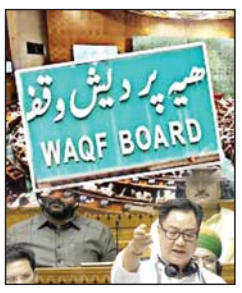

ये तो इंसाफ की बात नहीं है। विनेश फोगाट ने एक के बाद एक तीन मुकाबलों में विदेशी पहलवानों को पछाड़ कर, फाइनल तक पहुंचने का रिकार्ड बनाया पेरिस में और यहां इंडिया में भाई लोगों ने हल्ला मचा दिया कि विनेश ने, राजनीति के अखाड़े के पहलवान, ब्रजभूषण शरण सिंह को पटक दिया। कोई-कोई तो मोदी जी को पटखनी खिलवाने तक भी चला गया। कहते हैं कि इसी की खिसियाहट में तो साहब के मुंह से विनेश के लिए बधाई के दो शब्द तक नहीं निकले! यानी कुश्ती पेरिस में और हार-जीत इंडिया में; कुश्ती नहीं हुई, मजाक हो गया। पर बात इतने तक ही रहती तो फिर बात समझ में आती थी।

कहते हैं--जो जीता, सो सिकंदर। इंडिया का मुकाबला चाहे पेरिस में ही जीत रही थी, फिर भी विनेश फोगाट जीत तो रही थी। सोने की उम्मीद ही सही, पर चांदी की चमक को बाकायदा गले में डालकर दिखा रही थी। दुधारू गाय की तो दो लात भी सहन करने में ही समझदारी मानी जाती है। पर आखिर में तो वह जीत भी नहीं रही। आखिरकार, सौ ग्राम वजन ने विनो को ऐसा चित किया, ऐसा चित किया कि अर्श से उतारकर फर्श पर पटक दिया। पर उसके बाद भी भाई लोगों ने ब्रजभूषण शरण सिंह और मोदी जी का पीछा नहीं छोड़ा है। कोई षड्यंत्र-षड्यंत्र चिल्ला रहा है, तो कोई इसका इल्जाम लगा रहा है कि देश की बेटी के साथ अन्याय हो गया, और राज करने वालों से ढंग से शोर भी नहीं मचाया गया।

एक छोटे से देश ने तो अपने खिलाफ फैसला पलटवा लिया और अपना मेडल रखवा लिया, पर विश्वगुरु से उतना भी नहीं कराया गया। दुनिया में बजते डंके का क्या हुआ? छप्पन इंच की छाती कहां समा गई? पर क्यों? क्यों, क्या, इच्छा ही नहीं थी। विनेश की जीत में, देश की जीत की जगह, अपनी हार जो दिखती थी! यानी चित भी विनेश की, पट भी विनेश की, ब्रजभूषणों की केवल हार! जंतर-मंतर पर हार कर भी जीतने के बाद से इन महिला पहलवानों को हार कर जीतने की चाट लग गई है। अब इन विनेशों को कोई हरा नहीं सकता। जंतर-मंतर पर हरा दिया, तो पलट कर पेरिस में चित कर देंगी, विश्व मंच पर। लड़ने वाले की हार नहीं होती है!

मजबूती रहेगी बरकरार

शेयर बाजार

सतीश सिंह

पांच अगस्त 2024 को अमेरिका में मंदी आने की आशंका से दुनिया भर के शेयर बाजारों में कोहराम मच गया। एशिया के प्रमुख बाजार, जापान के निक्केई में सबसे अधिक 12.40 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, वहीं, कोरिया के कोस्पी में 8.77 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई. अमेरिकी शेयर बाजार नैस्डैक में सबसे अधिक 4.95 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जबकि यूरोपीय शेयर बाजार, जर्मनी के डैक्स में सबसे अधिक 2.34 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। वहीं, भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 2,222 अंक, प्रतिशत में 2.74 की गिरावट के साथ 78,759 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी में 662 अंक, प्रतिशत में 2.68 की गिरावट दर्ज की गई और यह 24,055 के स्तर पर बंद हुआ।

भारतीय शेयर बाजार में मेटल, सरकारी बैंक, जैसे-एसबीआई और मीडिया के शेयर में 4 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई, वहीं, ऑटो, आईटी, और ऑयल एंड गैस के शेयरों में 3 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। सबसे अधिक नुकसान टाटा मोटर्स, अडाणी पोर्ट, टाटा स्टील और पावर ग्रिड के शेयरों में निवेश करने वाले निवेशकों को हुई। शेयर बाजार में हाहाकार मचने के कई कारण हैं, लेकिन इनमें से सबसे प्रमुख कारण अमेरिका में मंदी आने की आशंका है।

ईरान और इस्राइल के बीच युद्ध की संभावना, भू-राजनीतिक संकट जैसे, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का लंबे समय से जारी रहना, वॉरेनबफे की कंपनी बर्कशायर हैथवे द्वारा नकदी बढ़ाने की कोशिश, वैश्विक बाजार में लगातार अनिश्चितता बना रहना आदि की वजह से भी विश्व के बड़े निवेशकों ने बिकवाली करना शुरू कर दिया, जिससे विश्व के कई देशों के शेयर बाजार में हाहाकार मच गया। भारत को छोड़कर कोरोना महामारी के बाद से विश्व के कई विकसित देश महंगाई की समस्या से जूझ रहे हैं और कुछ देशों में नरमी की स्थिति बनी हुई है तो वहीं कुछ देशों में मंदी आने की आशंका बनी हुई है। अमेरिका भी ऐसे देशों की सूची में से एक है। जापान के निक्केई शेयर बाजार में सबसे अधिक गिरावट दर्ज होने का सबसे बड़ा कारण बैंक ऑफ जापान द्वारा ब्याज दर को 0.1 प्रतिशत से बढाकर 0.25 प्रतिशत करना है, जो 15 वर्षों का उच्चतम स्तर है। वहीं, भारतीय शेयर बाजार में मिड और स्मॉल-कैप सेगमेंट में शेयरों की कीमत का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा होना है। इसलिए, इस सेगमेंट में गिरावट आने का साफ अर्थ है इस सेगमेंट में करेक्शन का दौर चल रहा है। साथ ही, रुपया भी कमजोर है। भारतीय शेयर बाजार में यह 2024 की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट है। इसके पहले 4 जून को

सेंसेक्स में 5.74 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी। शेयर बाजार में बिकवाली से निवेशकों को 16 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जिससे 5 अगस्त को सेंसेक्स में सूचीबद्ध कंपनियों का ओवरऑल मार्केट कैप घटकर 441 लाख करोड़ रुपए रह गया। भारत में घरेलू निवेशकों के दम पर शेयर बाजार की स्थिति लगातार मजबूत बनी हुई है।

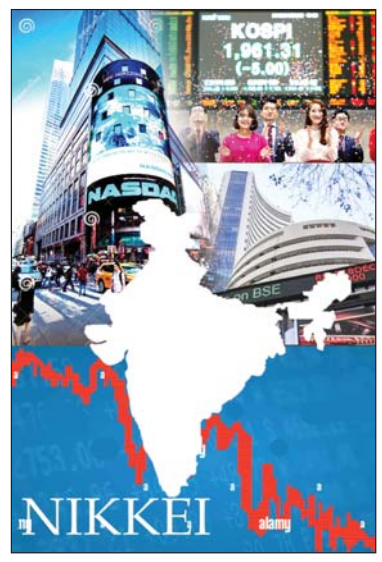

2024 में घरेलू निवेशकों ने शेयर बाजार में 2.28 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। इतना ही नहीं, सेंसेक्स को 75,000 से 80,000 के स्तर पर पहुंचाने में घरेलू निवेशकों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सेंसेक्स को 70,000 से 80,000 के स्तर पर ले जाने में रिलायंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक, भारती एयरटेल, एसबीआई और एचडीएफसी बैंक आदि कंपनियों ने भी महती भूमिका निभाई है। सेक्टर्स की बात करें तो बैंकिंग, बीएसई पावर, बीएसई रियल्टी, ऑटो, टेलीकॉम आदि ने शेयरों के उछाल को बनाए रखने में मदद की है। सेंसेक्स के अलावा निफ्टी 50 में भी लगातार तेजी का रुख बना हुआ है। आने वाले दिनों में यह 26,000 से 27,000 के स्तर को छू सकता है और इस साल के अंत तक यह 30,000 के स्तर पर बंद हो सकता है। विकास के मोर्चे पर भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2023-2024 की चौथी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 7.8 रही, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह 6.1 प्रतिशत रही थी।

वहीं, वित्त वर्ष 2023-24 में जीडीपी वृद्धि दर 8.2 प्रतिशत रही, जो भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमान से 1.2 प्रतिशत अधिक है। सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार विनिर्माण और खनन के क्षेत्र में मजबूत प्रदर्शन से आलोच्य अवधि में विकास दर तेज रही। विनिर्माण क्षेत्र में 9.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जो वित्त वर्ष 2022-23 में माइनस 2.2 प्रतिशत रही थी। इसी प्रकार खनन क्षेत्र में वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 7.1 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई, जो वित्त वर्ष 2022-23 में 1.9 प्रतिशत रही थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार जून महीने में खुदरा महंगाई मई महीने के मुकाबले 0.33 प्रतिशत बढ़कर 5.08 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई, जबकि मई महीने में यह 4.75 प्रतिशत रही थी, जो 12 महीने का निचला स्तर था। अप्रैल महीने में खुदरा महंगाई में कुछ कमी आई थी, लेकिन वह मई महीने से थोड़ी अधिक 4.83 प्रतिशत के स्तर पर थी। जून 2023 में खुदरा महंगाई 4.81 प्रतिशत थी, जबकि जुलाई 2023 में यह 4.44 प्रतिशत रही थी। मंहगाई को लेकर केंद्रीय बैंक बहुत ज्यादा संवेदनशील है और यह महंगाई और विकास दर के बीच संतुलन बनाकर अर्थव्यवस्था को मजबूत रखना चाहता है। इधर, विगत कुछ महीनों से उधारी ब्याज दर के उच्च स्तर पर बने रहने के बावजूद ऋण वितरण में तेजी आ रही है, क्योंकि बैंकिंग क्षेत्र लगातार मजबूत बना हुआ है, जिससे विकास को बल मिल रहा है।

ऐसे माहौल में सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी का रुख बना रहना लाजिमी है। तात्कालिक तौर पर वैश्विक स्तर पर होने वाली आर्थिक गतिविधियों से उत्पन्न चिंता की वजह से भारतीय शेयर बाजार ने गोते लगाए हैं, लेकिन ऐसी स्थिति की पुनरावृति की संभावना कम है। फिर भी, प्रत्येक दिन शेयर खरीद-फरोख्त करने वाले बड़े निवेशकों को देसी और विदेशी बाजार और वैश्विक हलचल पर पैनी निगाह बनाए रखने की जरूरत है। शेयर बाजार एक तरह से ऑनलाइन जुआघर है और इस प्लेटफॉर्म की मदद से अमीर बनने का ख्वाब देखने वालों को सावधान रहना होगा, अन्यथा 'सावधानी हटी, दुर्घटना घटी' वाली कहावत चरितार्थ हो सकती है, लेकिन वैसे निवेशक, जो सिर्फ प्रीमियम कंपनियों के शेयर में निवेश करते हैं, संतोष से रहते हैं, उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।

> प्रत्येक दिन शेयर खरीद-फरोख्त करने वाले बड़े निवेशकों को देसी और विदेशी बाजार और वैश्विक हलचल पर पैनी निगाह बनाए रखने की जरूरत है। शेयर बाजार एक तरह से ऑनलाइन जुआघर है और इस प्लेटफॉर्म की मदद से अमीर बनने का ख्वाब देखने वालों को सावधान रहना होगा, अन्यथा 'सावधानी हटी, दुर्घटना घटी' वाली कहावत चरितार्थ हो सकती है, लेकिन वैसे निवेशक, जो सिर्फ प्रीमियम कंपनियों के शेयर में निवेश करते हैं, संतोष से रहते हैं, उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है

भारतीय कृषि में 47 फीसद यंत्रीकरण

- भारत कृषि के यंत्रीकरण का स्तर 47 फीसद है, जबकि चीन में 59.5 फीसद, ब्राजील में 75 और अमेरिका में 95 फीसद है
- भारत में कृषि का यंत्रीकरण क्षेत्रवार भी काफी भिन्न है। उत्तरी राज्यों में यंत्रीकरण ज्यादा (70-80 फीसद) जबकि दक्षिणी और पूर्वी राज्यों में कम (35-40 फीसद) है। पूर्वोत्तर राज्य सामाजिक-आर्थिक कारकों और कृषि यंत्रों की ऊंची लागत से जूझ रहे हैं

(स्रोत : मीडिया इन्पुट्स)

शुरुआती बयान सकारात्मक और शक्तिशाली है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रधान मोहम्मद युनूस कह रहे हैं कि वह देश को तभी नेतृत्व देंगे जब हिंसा तत्काल रुकेगी और अल्पसंख्यक समुदायों पर हमले बंद हो जाएंगे! नोबेल पुरस्कार से सम्मानित युनूस ने आने के साथ अच्छा संकेत दिया है।

उर्मिलेश, पत्रकार
@UrmileshJ

बेवजह का बवाल

नजूल विधेयक

रजनीश कपूर

बीते सप्ताह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विधान सभा में नजूल संपत्ति अधिनियम पेश किया गया। इस बिल को विधान सभा में तो पास कर दिया गया परंतु उत्तर प्रदेश विधान परिषद में इसका भारी विरोध हुआ जिसके चलते बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी की मांग पर इसे सदन ने पास करने की जगह प्रवर समिति को भेजने का फैसला लेकर इसे फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया। उत्तर प्रदेश में कड़े फैसले लेने के लिए मशहूर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लिया गया यह निर्णय सही जरूर प्रतीत होता है, परंतु जिस तरह इस विधेयक का विरोध उन्हीं की पार्टी द्वारा किया जा रहा है, तो ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में शायद कुछ संशोधन के साथ इसे पुनः पेश किया जाए।

उल्लेखनीय है कि जिस भी जमीन का कोई वारिस न हो और वो सरकार के अधीन हो, उसे नजूल जमीन कहते हैं। गौरतलब है कि औपनिवेशिक शासन में अंग्रेजों द्वारा भारत में बड़ी संख्या में जमीनों पर कब्जा किया गया था, लेकिन आजादी के बाद जिस भी नागरिक के पास उसकी जमीन के दस्तावेज थे उन्हें उनकी जमीन वापस मिल गई, परंतु ऐसी कई जमीनें थीं जिनकी मिल्कियत के प्रमाण या जीवित स्वामी उपलब्ध नहीं थे। ऐसी जमीनों को सरकार ने अपने पास रखा, जिसे नजूल जमीन कहा गया। आजादी के बाद इस नजूल जमीन पर यदि कोई रह रहा था तो उससे सरकार ने किराया वसूलना शुरू किया और उस जमीन को लंबे समय के लिए लीज पर देना शुरू कर दिया। इसके बावजूद ऐसी कई नजूल जमीनें हैं जिन पर लोग अवैध कब्जा कर रह रहे हैं, परंतु जैसे ही उत्तर प्रदेश में नजूल संपत्ति अधिनियम पेश हुआ, तो सरकार ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि जिस-जिस नजूल जमीन पर लोग गैरकानूनी ढंग से रह रहे हैं या जिन नजूल जमीनों की लीज का किराया सरकार को नहीं दिया जा रहा, उस नजूल जमीन को उत्तर प्रदेश की सरकार वापस ले लेगी और इस भूमि को सरकारी विकास कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। योगी जी द्वारा उठाया गया ये कदम सही था, परंतु विपक्ष को इस बात पर शक है कि विकास कार्य के नाम पर कहीं प्रदेश की लाखों करोड़ की हजारों एकड़ जमीन को अपने खास

चुनिंदा लोगों के बीच बांट दिया जाएगा। इतना ही नहीं भाजपा के विधायक भी इस अधिनियम के विरोध में उतर आए हैं। उनका कहना है कि प्रदेश में ऐसी कई जमीनें हैं जिन पर शागिर्द-पेशा वाले परिवार रह रहे हैं, जो सदियों से वहां रह रहे हैं, परंतु उनके पास कोई भी प्रमाण नहीं है। ऐसे में उनका क्या होगा? कई भाजपा विधायकों का तो यह भी कहना है कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री आवास योजना से बेघर लोगों को घर दिए जा रहे हैं और वहीं दूसरी ओर जो गरीब दशकों से यहां रह रहे हैं उन्हें बेघर किया जा रहा है। तो भला ऐसे बिल का क्या औचित्य? जैसे ही इस अधिनियम पर राजनीति तेज हुई विपक्ष भी खुलकर सामने आया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर इसका विरोध जताते हुए लिखा, 'नजूल लैंड का मामला पूरी तरह से 'घर उजाड़ने' का फैसला है क्योंकि बुलडोजर हर घर पर नहीं चल सकता है। जनता को दुख देने में भाजपा अपनी खुशी मानती है। जब से भाजपा आई है, तब से जनता रोजी-रोटी-रोजगार के लिए भटक रही है, और अब भाजपाई मकान भी छीनना चाहते हैं। क्या भू-माफियाओं के लिए भाजपा जनता को बेघर कर देगी? अगर भाजपा को लगता है कि उनका ये फैसला सही है तो हम डंके की चोट पर कहते हैं, अगर हिम्मत है तो इसे पूरे देश में लागू करके दिखाएं क्योंकि नजूल लैंड केवल यूपी में ही नहीं पूरे देश में है।' देखा जाए तो इस अधिनियम के विरुद्ध हो रहे विवाद में भाजपा और विपक्षी नेताओं का एतराज सही है।

यदि सरकार को ऐसा अधिनियम लाना ही था तो उसे नजूल भूमि पर सदियों से बसे हुए परिवारों को पुनर्वास करने की योजना भी बनानी चाहिए थी। इसके हर पहलू पर गहन विचार के बाद ही इसे पेश किया जाना चाहिए था। चूंकि उत्तर प्रदेश और केंद्र दोनों ही जगह भाजपा की सरकार है तो योगी जी को प्रधानमंत्री मोदी से इस पर चर्चा करनी चाहिए थी। इसे भाजपा शासित किसी छोटे राज्य में लागू करना चाहिए था। इस अधिनियम को लाने से पहले सरकार द्वारा यहां पर बसे लोगों को पुनर्वास करने की योजना बना लेनी चाहिए थी। सरकार को इन नजूल भूमि पर किए जाने वाले विकास कार्यों की सूची भी बना लेनी चाहिए थी। सरकार द्वारा नजूल भूमि पर अवैध रूप से पट्टे जारी करने वाले भ्रष्ट अधिकारियों को दंड देने का भी प्रावधान बनाना चाहिए था। यदि इन सब पहलुओं पर सरकार द्वारा नहीं सोचा गया तो ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को सलाह देने वाले अधिकारियों ने आनन-फानन में इस अधिनियम को पेश करवाया। देखना यह होगा कि आने वाले समय में प्रवर समिति इस अधिनियम पर क्या सुझाव देती है?

आत्म-ज्ञान | संत राजिन्दर

आज के इस तकनीकी युग में तनाव और भागदौड़ भरे जीवन में बहुत से लोग अपने जीवन के उद्देश्य को ढूंढ रहे हैं। यह निश्चित है कि इस तकनीक ने केवल कंप्यूटर के कुछ बटन के साथ ज्ञान के सभी क्षेत्रों में जानकारी प्राप्त करने में हमें सक्षम जरूर बनाया है, लेकिन इस ज्ञान के होने के बावजूद भी ऐसे कई प्रश्न हैं जिनके उत्तर अभी भी हमें नहीं मिल रहे हैं। ज्यादातर लोगों ने अनुभव किया है कि बाहरी ज्ञान चाहे किताबें या इंटरनेट से हासिल किया हो लेकिन वह उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाता। इसलिए वे ऐसी खुशी को खोजने का एक तरीका सीखना चाहते हैं, जो सदा-सदा के लिए हो। कई बार हमें कभी-कभी ऐसे विचार आते हैं कि जैसे मैं कौन हूं? मैं यहां क्या कर रहा हूं? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? और क्या मेरी संतुष्टि होगी? क्या हम केवल वह शरीर हैं जिसके साथ हम इस दुनिया में आते हैं, जो समय के साथ ढलता जाता है और मृत्यु के बाद नष्ट हो जाता है? क्या हम वह बुद्धि हैं जो बौद्धिक खोज के साथ और कुशल होती जाती है और आखिरकार मृत्यु के समय लुप्त हो जाती है? क्या हम भावनाएं हैं जो मौसम की तरह बार-बार बदलती है? या 'हमारा' अस्तित्व इससे कहीं अधिक है? आध्यात्मिक जागृति वह क्षण है जब हम खुद से ऐसे प्रश्न पूछना शुरू करते हैं। हमारे प्रश्नों के उत्तर खोजना इस बात का प्रतीक है कि हम आध्यात्मिक जागृति को पाना चाहते हैं। संत और आध्यात्मिक गुरु अनादि काल से हमें यह याद दिलाते आए हैं कि हम इस भौतिक शरीर जिसे हम इन बाहरी आंखों से देख सकते हैं, हमारे मन या भावनाओं से कहीं अधिक है। वे हमें बताते हैं कि वास्तव में हम आत्मा हैं जोकि परमात्मा का अंश है और यह वह शक्ति है जो हमारे शरीर को जान देती है, जो हमें चेतन करती है और ताकत देती है। जब यह शक्ति हमसे अलग हो जाती है तो शरीर स्थिर हो जाता है और हमें मृत घोषित कर दिया जाता है। संत-महापुरुष हमें बताते है। कि हममें से प्रत्येक के लिए अपने वास्तविक स्वरूप को अनुभव करने का एक तरीका है, यह कोई बौद्धिक खोज नहीं है बल्कि वह ध्यान-अभ्यास करने का तरीका है, जिसमें हम अपनी आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए हमें ध्यान-अभ्यास में शांत होकर बैठना होगा।

रीडर्स मेल

शांति की अपील

नोबेल पुरस्कार विजेता और बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने गुरुवार को शपथ ली। शपथ लेने के बाद उन्होंने कहा कि हमें दूसरी बार आजादी मिली है और हमें इसकी रक्षा करनी है। बांग्लादेश में हो रहे दंगों में यहां की स्थिति अभी भी उथल-पुथल बनी हुई है। सोशल मीडिया पर आ रही अनेकों वीडियो में यहां पर रहने वाले अल्पसंख्यको पर अनेकों तरह के हमले होते दिखाई दे रहे हैं उनके घरों में आग लगाई जा रही है और उन्हें जमकर लूटा जा रहा है। इस विषय को लेकर भारत सरकार बेहद चिंतित है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हम बांग्लादेश में जल्द ही सामान्य स्थिति बहाल होने, हिन्दुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की उम्मीद करते हैं। बहलहाल, सरकार बनने के बाद बांग्लादेश सरकार की पहली प्राथमिकता अपने प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना होना चाहिए। उम्मीद है यूनुस बांग्लादेश में शांति स्थापित करने में कामयाब होंगे और भारत व अपने अन्य पड़ोसी मुल्को से बेहतर तालमेल बनाकर बांग्लादेश को प्रगति की नई दिशा दिखाएंगे।

हितेंद्र डेढ़ा, दिल्ली

सावधानी जरूरी

आदमी पूरे दिन पैसे के लिए जतन करता है। पैसे का मोल वही समझ सकता है, जो इसे मेहनत से हासिल करता है। दूसरा इसका मोल क्या जानें? पराये और अपने पैसे में यही अंतर है। आदमी अपना समझ किसी की मदद करता है। होना तो यह चाहिए उसका पैसा यथासमय वापस कर देना चाहिए, मगर ऐसा होता कहां है? दूसरे से लिया पैसा वापस करते वक्त आदमी की नीयत बदल जाती है। वह तरह-तरह के बहाने बनाने लगता है। यह भी कह सकते हैं कि वह दूसरे के मेहनत से कमाए पैसे का मोल नहीं समझता। ऐसा आदमी दूसरे का पैसा मारकर अपने को होशियार ज्यादा समझता है और मदद देने वाला बेचारगी का पात्र बन जाता है। पैसा उधार देने वाला अपने इस फैसले पर कई बार अफसोस भी जाहिर करता है। ऐसे कई लोग हैं, जो लेते समय कुछ और देते समय कुछ और का दोगला चरित्र रखते हैं। बहरहाल, आपकी कोई रकम इसी तरह मारे बैठा है, तो उसे भूल जाएं और सावधान हो जाएं। धन ऐसी चीज है जिससे रिश्ते खराब होने में वक्त नहीं लगता।

दिलीप कुमार गुप्ता, बरेली

नाग को शत्रु न मानें

दुनिया में एकमात्र भारत ही ऐसा देश है, जहां नागों की पूजा होती है। नाग देवता माता लक्ष्मी के सेवक है, और भगवान शिव का श्रृंगार। हमारे शास्त्रों में इच्छाधारी नाग का वर्णन मिलता है, जो आत्मिक क्रियाओं के निरूपण को व्यक्त करते है। युगों से भारत में नाग देवता की महिमा का गुणगान होता रहा है। नाग किसानों का सबसे बड़ा मित्र है। चूहा फसल को बर्बाद करते हैं, तो नाग चूहा को अपना शिकार बना लेते है। आज बढ़ती आबादी, शहरीकरण और संस्कृति के पराभव की वजह से नाग और इंसान एक दूसरे के शत्रु बन बैठे हैं। नागों के प्राकृतिक आवास में कमी होने की वजह से वे इंसानों के बीच आ जाते हैं। प्रकृति के संतुलन के लिए नाग भी आवश्यक जीव है, हमें अनावश्यक रूप से उन्हें अपना शत्रु नहीं मानना चाहिए।

हिमांशु शेखर, गया

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा • राष्ट्रीयता • कर्त्तव्य • समर्पण
वर्ष-33, अंक 358
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्
भगवान इस जग के कण-कण में विद्यमान हैं।

भारत का ओलम्पिक गौरव

भारत का ओलम्पिक खेलों में इतिहास 124 साल पुराना है। पेरिस 1900 से लेकर पेरिस 2024 तक ओलम्पिक के साथ भारत का रिश्ता खास रहा है। इस दौरान बहुत उतार-चढ़ाव भी आए और कई बार दिल टूटने की घटनाएं भी हुईं। देशवासियों ने आंसू भी बहाए। फिर भी ओलम्पिक भारत के लिए बेहद खास रहा। भारतीय हॉकी का इतिहास काफी समृद्ध रहा। हाकी के जादूगर मेजर ध्यान चंद को कौन भुला सकता है। पेरिस ओलम्पिक में पहलवान विनेश फोगाट के दुखद घटनाक्रम के बाद भारतीय हॉकी टीम ने ओलम्पिक में कांस्य पदक और भाला फैंक में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीतकर भारत को काफी हद तक संतोष दिया है।

भारत के लिए हॉकी में स्वर्णिम युग की शुरूआत 1928 में एम्स्टर्डम ओलम्पिक से हुई थी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने दिग्गज खिलाड़ी ध्यान चंद के नेतृत्व में 29 गोल किए और एक भी गोल खाए बिना अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद टीम ने 1932 लॉस एंजिल्स ओलम्पिक में भी स्वर्ण पदक जीता था और अपने खिताब का सफलतापूर्वक बचाव किया था। भारत ने फिर 1936 बर्लिन ओलम्पिक में लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीतकर स्वर्णिम हैट्रिक लगाई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के चलते 1940 और 1944 में ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं किया गया था और फिर 1948 में लंदन ओलम्पिक से भारत ने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपने पहले ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेलों में हिस्सा लिया। भारत ने यहां भी अपनी छाप छोड़ी और हॉकी में लगातार चौथा स्वर्ण जीता। इसके बाद 1952 और 1956 में भी टीम स्वर्ण पदक जीतने में सफल रही थी। भारत ने इस तरह लगातार छह ओलम्पिक में हॉकी में स्वर्ण पदक जीते थे।

> भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने दिग्गज खिलाड़ी ध्यान चंद के नेतृत्व में 29 गोल किए और एक भी गोल खाए बिना अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद टीम ने 1932 लॉस एंजिल्स ओलम्पिक में भी स्वर्ण पदक जीता था और अपने खिताब का सफलतापूर्वक बचाव किया था। भारत ने फिर 1936 बर्लिन ओलम्पिक में लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीतकर स्वर्णिम हैट्रिक लगाई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के चलते 1940 और 1944 में ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं किया गया था और फिर 1948 में लंदन ओलम्पिक से भारत ने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपने पहले ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेलों में हिस्सा लिया। भारत ने यहां भी अपनी छाप छोड़ी और हॉकी में लगातार चौथा स्वर्ण जीता। इसके बाद 1952 और 1956 में भी टीम स्वर्ण पदक जीतने में सफल रही थी।

भारतीय हॉकी टीम 1960 रोम ओलम्पिक में पाकिस्तान से एक गोल से हार गई थी और इस तरह उसका स्वर्ण पदक जीतने का सिलसिला टूट गया था। 1980 में मास्को ओलम्पिक में स्वर्ण जीतने के बाद से भारतीय हाकी का दबदबा गायब हो गया और टीम टोक्यो 2020 से पहले कोई पदक नहीं जीत पाई थी। मैं उस इतिहास में नहीं जाना चाहता कि भारतीय हॉकी का पतन क्यों और कैसे हुआ और इसमें हॉकी फैडरेशन की क्या भूमिका रही। भारत ने टोक्यो ओलम्पिक में हाकी में 41 साल का सूखा समाप्त किया था और मनप्रीत सिंह की कप्तानी में कांस्य पदक जीता था। इस बार हाकी टीम की कोशिश पदक का रंग बदलने की थी लेकिन हरमन प्रीत सिंह की कप्तानी में भारत ने स्पेन को 2-1 से हराकर लगातार दूसरी बार कांस्य पदक जीता है। टीम में हरमन प्रीत सिंह, अनुभवी गोलकीपर श्रीजेश, डिफैंडर जरमनप्रीत सिंह सहित सभी खिलाड़ियों ने अपना पूरा दमखम दिखाया। गोलकीपर श्रीजेश की विदाई भी कांस्य पदक के साथ हुई। श्रीजेश का खेल हॉकी प्रेमियों को वर्षों तक याद रहेगा।

जहां तक भाला फैंक एथलीट नीरज चोपड़ा का सवाल है उससे पदक की उम्मीद तो पहले से ही थीं। टोक्यो ओलम्पिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा पेरिस में अपने प्रदर्शन को दोहरा नहीं सके और उन्हें रजत पदक पर संतोष करना पड़ा। भाला फैंक में पाकिस्तान के नदीम अपने दूसरे प्रयास में 92.97 मीटर का रिकॉर्ड थ्रो कर स्वर्ण पदक जीतने में सफल रहे। इसमें कोई संदेह नहीं कि नीरज ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया लेकिन भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। एक अधिक वजन वाले 13 वर्षीय बच्चे से लेकर आत्मविश्वास हासिल करने के लिए खेलों को चुनने और ओलम्पिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एथलीट बनने तक नीरज चोपड़ा ने एक लम्बा सफर तय किया है।

टोक्यो ओलम्पिक में इतिहास रचने के एक साल बाद नीरज चोपड़ा ने अमेरिका के ओरेगन में विश्व एथलेटिक चैम्पियनशिप में रजत पदक जीतकर एक और इतिहास रचा था। नीरज चोपड़ा अब तक कई रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। हंगरी के बुडापेस्ट में विश्व एथलेटिक चैम्पियनशिप 2023 में नीरज ने स्वर्ण पदक जीता था और इस प्रतियोगिता में पाकिस्तान के नदीम अरशद को पीछे छोड़ दिया था। खेल में हार-जीत तो होती ही रहती है। बेहतर खिलाड़ी वही होता है जो उतार-चढ़ावों को खेल भावना से लेकर आगे बढ़ जाता है। नीरज खुद स्वीकार करते हैं कि कुछ कमियां जरूर रहीं फिर भी उन्हें आगे बढ़ना है। आगे बहुत कुछ जाकर ठीक करना है। जो सोचा था वो भले ही नहीं हो पाया लेकिन पदक पदक होता है। नीरज का यह कहना महत्वपूर्ण है कि पेरिस में न सही कहीं और सही, फिर से बजेगा हमारा राष्ट्रगान। यही जज्बा खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। भारतीय युवा भाला फैंक में ज्यादा रुचि नहीं रखते थे। नीरज चोपड़ा की लगातार विजय ने एथलीटों को भाला फैंक की ओर आकर्षित किया है। एशिया अब जेवेलिन थ्रो का हब बन चुका है। जरूरत है एथलीटों को ज्यादा स्पोर्ट और प्रोत्साहन की। भारतीय हॉकी के भी स्वर्णिम दिन लौट सकते हैं। अगर प्रतिभाओं को खोजकर तराशे जाने का सिलसिला तीव्र गति से जारी रहे। देशवासियों को पदक विजेता खिलाड़ियों पर गर्व है और वे भारतीय खिलाड़ियों के लिए आदर्श बनेंगे।

आदित्य नारायण चोपड़ा
Adityachopra@punjabkesari.com

चुनाव से पहले एमवीए के मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान किए जाने पर जोर दिया

मुंबई, (पंजाब केसरी) शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) सांसद संजय राउत ने शुक्रवार को इस बात पर बल दिया कि विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाडी (एमवीए) को विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद के चेहरे का ऐलान करना चाहिए। उनकी यह टिप्पणी पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे द्वारा कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ हुई बैठक के बाद आई है। अब तक, एमवीए राज्य में मुख्यमंत्री चेहरे के लिए सामूहिक रूप से पैरवी करने से परहेज करती रही है। महाराष्ट्र में अक्टूबर में चुनाव होने हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या वह शीर्ष पद के लिए ठाकरे की उम्मीदवारी पर जोर दे रहे हैं, राउत ने सीधा जवाब देने से बचते हुए कहा कि उनकी पार्टी के अध्यक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने में सबसे आगे रहे हैं।नयी दिल्ली में शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सदस्य ने कहा कि ठाकरे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार केंद्र के ''दमनकारी'' रवैये के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। राउत ने कहा, ''राज्य (चुनाव) के लिए एक चेहरा होना जरूरी है।

बंगलादेश का ताना-बाना और भारत

राकेश कपूर
संसद से सड़क तक
kapurakesh@gmail.com

बंगलादेश जाने का मुझे दो बार अवसर मिला। पहली बार में 2012 में तत्कालीन राष्ट्रपति स्व. प्रणव मुखर्जी के साथ गया और दूसरी बार 2018 में इस देश के राष्ट्रीय चुनाव की पूर्व बेला में राजनैतिक आंकलन करने। दोनों ही बार मुझे महसूस हुआ कि बंगलादेश सच्चा लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष देश है जिसमें हिन्दू निर्भय होकर रहते हैं। इस देश की विशेषता यह है कि यहां हिन्दू व मुसलमान दोनों ही बंगला संस्कृति को अपनी जीवन शैली मानते हैं। इस देश की राजधानी ढाका का नाम शहर में स्थित ढाकेश्वरी देवी के मन्दिर के नाम पर ही पड़ा। ढाका शहर के भीतर ही सड़कों के नाम से लेकर भवनों तक के नाम हिन्दू नामों पर हैं। पूरे शहर में लोग हिल-मिल कर रहते हैं।

2012 में जब स्व. प्रणव मुखर्जी बंगलादेश गये थे तो वह इस देश के एक गांव में भी गये थे जहां उनकी ससुराल के लोग रहते हैं। सुसराल पहुंचने पर प्रणव दा का भव्य स्वागत हुआ था और ग्राम निवासी सभी हिन्दू मुसलमानों ने उनकी आवभगत में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। परन्तु 2012 में ढाका के शाहबाग में युवाओं का आन्दोलन चल रहा था और वे मांग कर रहे थे कि 1971 के मुक्ति युद्ध में पाकिस्तानी फौजों का साथ देने वाले गद्दारों को फांसी पर लटकाया जाना चाहिए। बाद में जाकर उन लोगों को फांसी की सजा ही हुई मगर उस दौरान शाह बाग में भारतीय फइलमी गायक भूपेन हजारिका का यह गीत गाया जा रहा था कि 'युद्ध चाहे कि बुद्ध'। यह सुन-देख कर एक भारतीय को रोमांच होना स्वाभाविक था। इसके साथ ही अन्य भारतीय बंगला कलाकारों के गाने भी बंगला भाषा में चल रहे थे।

2018 के चुनावों में अवामी लीग की नेता व प्रधानमन्त्री शेख हसीना वाजेद का जीतना लगभग निश्चित माना जा रहा था हालांकि उनकी विरोधी बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की नेता बेगम खालिदा जिया तब भी चुनावों का बहिष्कार करने की बात कर रही थीं। बंगलादेश 1947 में पूर्वी पाकिस्तान जरूर बन गया था मगर वहां के मुस्लिम बहुसंख्या के लोग बंगला संस्कृति को अपनी प्रथम वरीयता पर रखते थे। जब पाकिस्तान निर्माता जिन्ना 1948 में ढाका यात्रा पर गये थे तो कह कर आ गये थे कि पूरे पाकिस्तान की राजकीय भाषा उर्दू ही होगी। इसका बंगालियों ने बहुत बुरा माना था और पाकिस्तान से अलग होने का बीज तभी पड़ गया था।

बंगालियों को अपनी भाषा व संस्कृति से बहुत प्रेम होता है। यही वजह रही कि 1971 में बंगलादेश का निर्माण भाषा की वजह से ही हुआ। हालांकि इसके राजनैतिक कारण कुछ और भी थे । इनमें सबसे प्रमुख था कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय एसेम्बली के 1970 में हुए चुनावों में शेख मुजीबुर्रहमान की अवामी लीग पार्टी के पूर्ण बहुमत पा जाने के बावजूद उन्हें संयुक्त पाकिस्तान का प्रधानमन्त्री न बनाया जाना। इसके बाद ही बंगलादेशियों ने पाकिस्तान से मुक्ति पाने के लिए आन्दोलन चलाया जो बाद में सशस्त्र संघर्ष में परिवर्तित हुआ और बंगलादेश मुक्ति वाहिनी का गठन हुआ। 2012 व 2018 दोनों ही दौरों के दौरान मैंने बंगलादेश की कट्टरपंथी राजनैतिक पार्टी जमाते इस्लामी को भी सक्रिय देखा परन्तु इसका प्रभाव नगण्य ही कहा जा सकता था। कुछ बड़ी उम्र के लोगों तक ही इसका प्रभाव था। बंगलादेश की परंपरा के अनुसार उनका वार्षिक कलेंडर इस्लामी नहीं होता बल्कि बंगला होता है। जिसमें पहला पौष बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन सभी हिन्दू मुसलमान तस्वीरें लेकर जुलूस निकालते हैं। और पौष मास के पहले दिन को उत्सव रूप मे मनाते हैं। बोलचाल की भाषा में मुसलमान बन्धू आपको कहते मिलेंगे कि 'अल्लाह महान है'। बंगलादेश के किसी भी हिस्से में आप चले जाइये वहां आपको हिन्दू मन्दिर जरूर मिल जायेंगे।

बंगलादेश की सरकार अपने पुराने हिन्दू मन्दिरों और बौद्ध विहारों को अपनी राष्ट्रीय धरोहर मानती है। इस देश के 'काक्स बाजार' इलाके में जहां दस लाख से अधिक म्यामांर के रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थी रहते हैं, कई ऐसे हिन्दू मन्दिर हैं जिनके लिए मुसलमानों ने अपनी जमीनें दी हैं। अत: शेख हसीना का तख्ता पलटे जाने के बाद वहां जिस प्रकार कुछ स्थानों पर हिन्दुओं को निशाना बनाया गया और एक-दो स्थानों पर हिन्दू मन्दिरों को भी लक्ष्य किया गया वह जमाते इस्लामी जैसी पार्टी के प्रभाव का ही द्योतक लगता है। जमाते इस्लामी पार्टी पर शेख हसीना ने कई बार प्रतिबन्ध लगाया था। इस देश में आधा दर्जन बार रहे सैनिक शासन के दौरान कट्टरपंथी ताकतों को खूब फलने-फूलने का मौका दिया गया और इसी दौरान बंगलादेश का राजधर्म भी इस्लाम घोषित कर दिया गया। मगर शेख हसीना ने अपने शासन के दौरान हिन्दू भावनाओं का सदैव आदर किया और बंगालियों के दुर्गा पूजा उत्सव को पूरा संरक्षण दिया। यहां तक कि पूजा के दिनों मे वह ढाका के ढाकेश्वरी मन्दिर भी जाती थी।

स्व. प्रणव मुखर्जी ने 2012 में जब ढाका विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह को अंग्रेजी के स्थान पर बंगला में सम्बोधित किया तो छात्रों में उत्साह देखने वाला था। इस अवसर पर सर्वप्रथम एक मौलवी ने प्रार्थना की उसके बाद एक हिन्दू पंडित ने और बाद में बौद्ध भिक्षु ने। बंगलादेश की यह मूल संस्कृति शेख हसीना के शासन काल में पूरी तरह सुरक्षित रही। मगर देश में लोकतन्त्र होते हुए भी हमेशा सेना का डर भी बना रहा क्योंकि सेना व इस्लामी कट्टर पंथियों की भीतर खाने साठ- गांठ मानी जाती थी। चाह कर भी शेख हसीना ऐसे तत्वों के विरुद्ध कठोर कदम नहीं उठा सकती थीं क्योंकि हमेशा सेना के सक्रिय होने का भय लगा रहता था।

वैसे शेख हसीना ने अपने देश की धरती का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए कभी नहीं होने दिया और पाकिस्तानी आई एस आई की शह पर गठित आतंकवादी संस्था इंडियन मुजाहीदीन को समाप्त कर दिया। यह संस्था बेगम खालिदा के शासनकाल में खूब पनपी थी क्योंकि वह भी पांच साल इस देश की प्रधानमन्त्री रही थीं। बंगलादेश में वर्तमान में जो तख्ता पलट हुआ है उसके पीछे पश्चिमी विदेशी ताकतों का हाथ माना जा रहा है। इन ताकतों ने इस देश के कट्टर पंथियों को बारस्ता पाकिस्तान बढावा दिया । जमाते इस्लामी के लोग पाकिस्तान परस्त समझे जाते हैं और इस्लामी जेहाद की बात करते हैं।

जमात के लोग सैनिक शासन और बेगम खालिदा के शासन के दौरान सरकारी महकमों में भी घुस गये थे। ये तत्व वर्तमान में छात्र आन्दोलन के दौरान भी प्रवेश कर गये और इन्होंने बंगलादेश मुक्ति संग्राम की धरोहर को आग की भेंट चढ़ाने में और लूटपाट मचाने में भी कोई कसर नहीं छोडी और हद तो तब हो गई जब इन लोगों ने शेख मुजीबुर्रहमान की प्रतिमा को ही धराशायी कर दिया और उस मूर्ति को अपवित्र तक किया। परेशानी यह है कि बंगलादेश की वर्तमान आबादी 50 प्रतिशत उन लोगों की है जिनका जन्म 1971 के बाद हुआ है अत: इन्हें अपने पुरखों के बलिदान के बारे में कोई अनुभव नहीं है। यही वजह रही कि ये पीढ़ी सरकारी नौकरियों में मुक्ति योद्धाओं के परिवारों को मिले आरक्षण का विरोध कर रही थी। बंगलादेश में अब अंतरिम सरकार है वैसे पहले भी 2006 से 2008 तक इस देश में अंतरिम सरकार रही है जिसके बाद यहां लोकतन्त्र आया था। उम्मीद की जानी चाहिए कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में गठित अंतरिम सरकार अपने देश में लोकतन्त्र की पुन: बहाली जल्दी ही करेगी और अत्याचार के दौर का अन्त करेगी

हसीना-खालिदा के बेटे आएंगे राजनीति में

ताक-झांक
आर.आर. जैरथ

बंगलादेश की राजनीति में एक नेता का बेटा अपनी जड़ें जमा रहा है तो दूसरी नेता के बेटे की राजनीतिक संभावनाओं को चोट पहुंची है। शेख हसीना के बेटे साजिब वजीद जॉय अपदस्थ बंगलादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी के नेता हैं। वे कई सालों से अमेरिका में रह रहे हैं। उन्हें अपनी मां का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जा रहा था, हसीना पहले से ही 78 साल की हैं। वर्तमान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों और उनकी मां के बंगलादेश से अपमानजनक तरीके से बाहर निकलने ने कम से कम फिलहाल तो इस पर रोक लगा दी है। इस बीच, निर्वासन में रह रहे एक और बेटे तारिक रहमान बंगलादेश लौटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

रहमान शेख हसीना की कट्टर प्रतिद्वंद्वी बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी की बेगम खालिदा जिया के बेटे हैं और उन्हें उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जाता है। अब जबकि खालिदा जिया जेल से रिहा हो चुकी हैं और बीएनपी से अगली सरकार के गठन में प्रमुख भूमिका निभाने की उम्मीद है। रहमान के वापस लौटने और पार्टी के प्रमुख के रूप में उनकी जगह लेने की उम्मीद है। उनकी मां न केवल बूढ़ी हैं, बल्कि जेल में लंबे समय तक रहने के कारण बीमार भी हैं। अगर रहमान हसीना के बाद बंगलादेश में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं, तो यह भारत के लिए एक चुनौती होगी, क्योंकि उन्हें भारत के सख्त विरोधी माना जाता है।

इस बीच बंगलादेश में बीएनपी की बड़ी भूमिका के साथ, जॉय ने अपना सुर बदल दिया है। उन्होंने कहा था कि हसीना बंगलादेश से 'खत्म' हो गई हैं और रिटायर हो जाएंगी। अब वे कह रहे हैं कि वह बंगलादेश लौट सकती हैं। उनके हालिया बयानों ने अटकलों को हवा दी है कि रहमान की बंगलादेश की राजनीति में आसन्न वापसी के संदर्भ में वह खुद के लिए एक सक्रिय राजनीतिक भूमिका की तैयारी कर रहे हैं।

तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष लेंगे तीन माह की छुट्टी

जब राहुल गांधी हर चुनावी असफलता के बाद विदेश में गायब हो जाते थे, तो भाजपा उन्हें 'अनिच्छुक' राजनेता कहकर उनका मजाक उड़ाती थी। अब भाजपा के तमिलनाडु प्रमुख के अन्नामलाई हाल के लोकसभा चुनावों में राज्य में पार्टी के विनाशकारी प्रदर्शन के बाद तीन महीने की छुट्टी के लिए ब्रिटेन जाने की तैयारी कर रहे हैं। भाजपा न केवल एक भी सीट जीतने में विफल रही, बल्कि अन्नामलाई खुद कोयंबटूर से हार गए, जबकि उनके इर्द-गिर्द बहुत चर्चा थी। अन्नामलाई तीन महीने के नेतृत्व पाठ्यक्रम के लिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जा रहे हैं। जाहिर है, उन्होंने एक महीने पहले ही पार्टी हाईकमान से छुट्टी मांगी थी, नतीजे आने के तुरंत बाद।

भाजपा के लोग हैरान हैं कि उन्हें इतनी लंबी छुट्टी दी जा रही है। पार्टी के लिए अपने शीर्ष नेताओं को लंबी अवधि के लिए विदेश जाने की अनुमति देना असामान्य है। विडंबना यह है कि अन्नामलाई की ब्रिटेन यात्रा अध्ययन अवकाश के रूप में मानी जा रही है, लेकिन भाजपा ने इस यात्रा को अन्नामलाई के लिए 'ब्रेक' बताया है, मानो उन्हें राजनीति से दूर छुट्टी की जरूरत है। अभी तक, उनकी जगह किसी और को लाने की कोई योजना नहीं है। हालांकि, राजनीति में तीन महीने का समय बहुत लंबा होता है और कोई भी अपरिहार्य नहीं होता। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव सिर्फ डेढ़ साल दूर हैं।

शेख हसीना को राजनीतिक शरण दिलाने की कोशिश में भारत

ऐसा लग रहा है कि भारत को कुछ समय के लिए बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की मेजबानी करनी पड़ सकती है। ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों से अनौपचारिक संचार से पता चलता है कि वे उन्हें अपनी सीमाओं में प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए गहरी अनिच्छा रखते हैं, राजनीतिक शरण लेने की तो बात ही छोड़ दें। माना जाता है कि भारत अनौपचारिक रूप से शेख हसीना को दक्षिण एशिया से दूर सुरक्षित पनाहगाह खोजने में मदद करने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश में चरमपंथी तत्वों से उनकी सुरक्षा को खतरा है। साथ ही, भारत चाहेगा कि वह जल्द से जल्द चले जाएं ताकि भारत ढाका में नई सरकार के साथ व्यापार करने के काम को आगे बढ़ा सके। यह एक कूटनीतिक चुनौती होगी क्योंकि बांग्लादेश में यह धारणा है कि भारत ने हसीना का समर्थन किया था और पिछले चुनाव में उन्हें जीतने में मदद की थी। विशेष रूप से ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देश भी दक्षिणपंथी समूहों के दबाव में हैं कि इस्लामी देशों से प्रवास को रोका जाना चाहिए।

शेख हसीना एक हाई प्रोफाइल प्रवासी हैं और यूरोप में बदलते लोकप्रिय मूड ने वहां की सरकारों के लिए उनका स्वागत करना मुश्किल बना दिया है। पूर्व बांग्लादेशी पीएम के लिए राजनीतिक शरण पाना आसान नहीं हो रहा है। शेख हसीना की बेटी सैमा वाजेद नई दिल्ली में रहती हैं, जहां वह विश्व स्वास्थ्य संगठन में दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक हैं। हालांकि, सुरक्षा कारणों से मां और बेटी को मिलने की अनुमति नहीं दी गई है और यह संभावना नहीं है कि सैमा वाजेद शेख हसीना को अपने यहां आश्रय दे सकें।

दिलचस्प बात यह है कि डब्ल्यूएचओ पद पर सैमा वाजेद के नामांकन में भारत का बड़ा हाथ था। नई दिल्ली ने नेपाल के शंभू आचार्य के खिलाफ उनका समर्थन किया, हालांकि उन्हें इस पद के लिए अधिक योग्य माना जाता था। हालांकि मोदी सरकार शेख हसीना को अपने यहां ज्यादा देर तक रखने में समर्थ नहीं दिख रही, लेकिन वह उन्हें दूर नहीं कर सकती। भारत के पड़ोस में शत्रुतापूर्ण माहौल के बीच हसीना ने दोनों देशों के बीच दोस्ती को परवान चढ़ाया था।

काकोरी कांड के 100 साल

नई दिल्ली, (आईएएनएस): आज हम अपने देश में खुली हवा में सांस ले रहे हैं तो इसमें हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का बहुत बड़ा हाथ है। हमारी स्वतंत्रता के लिए इन आजादी के मतवालों ने क्या कुछ नहीं किया। चाहें इंग्लिश अधिकारी सांडर्स की हत्या हो, गांधी जी के एक आह्वान पर देशवासियों का एक पंक्ति में खड़ा हो जाना हो या चौरीचौरा में 3 भारतीय नागरिकों की मौत के बाद गुस्साई भीड़ का थाना फूंकना हो या फिर उसके दो साल बाद काकोरी में क्रांतिकारियों का ट्रेन को लूटना हो।

● **अंग्रेजी हुकूमत का लूटा खजाना**

अंग्रेजों का खजाना लूटने की हिमाकत 10 युवा क्रांतिकारियों ने दिखाई थी। योजनाबद्ध तरीके से हमला बोला, अपने बुद्धि विवेक के बल पर एक स्टेशन पर धावा बोला और अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां से असहयोग आंदोलन के समापन का ऐलान हुआ था। 1922 में चौरी चौरा कांड में 22 पुलिसकर्मियों की हत्या से दुखी होकर गांधी जी ने अपने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया।

गरम दल का मानना था कि आजादी अहिंसा से नहीं बल्कि बंदूक से ली जाएगी, जिसके लिए उन्हें हथियार खरीद के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी और यहीं रच दी गई काकोरी ट्रेन लूट कांड की पटकथा। साल 1925 और तारीख थी 9 अगस्त। सहारनपुर से चलने वाली 8 डाउन पैसेंजर में रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफ़ाक़ुल्लाह खां , राजेंद्र लाहिड़ी, दुर्गा भगवती चंद्र वोहरा, सचींद्र बक्शी, चंद्रशेखर आजाद, बनवारी लाल, मुकुंदी लाल, सचिंद्र नाथ सान्याल और मन्मथ नाथ गुप्ता को मिलाकर कुल 10 क्रांतिकारी सवार हुए।

योजना के अनुसार अशफ़ाकुल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी और सचींद्र बक्शी सेकंड क्लास में और बाकी सब थर्ड क्लास में बिठाए गए। यूं ही नहीं ऐसी रणनीति बनाई गई बल्कि इन तीन क्रांतिकारियों के सेकंड क्लास में यात्रा करने की वजह ट्रेन को रोकना था। ट्रेन की जंजीर खींच कर तय समय पर, तय जगह पर रोकने की योजना थी। पंजाबी पत्रिका किरती में भगत सिंह ने बताया था कि उन्हें पता था कि थर्ड क्लास की जंजीर भी थर्ड क्लास सी ही होती है इसलिए सेकेंड क्लास में बैठे क्रांतिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई।

ट्रेन जैसे ही हरदोई की सीमा को पार करते हुए काकोरी पहुंची तय योजना के मुताबिक चेन खींच दी गई। गार्ड के डिब्बें में रखे सरकारी खजाने को लूट लिया गया। अंग्रेजी पुलिसकर्मियों और क्रांतिकारियों के बीच गोलीबारी शुरू हुई। इस दौरान क्रांतिकारियों के लाख मना करने के बावजूद एक शख्स डिब्बे से निकला और मन्मथ नाथ गुप्ता की गोली का शिकार हो गया।

गोलीबारी के बीच पास ही मौजूद आम के बाग में 200 किलो खजाने से भरे बक्से को ले जाया गया। यहीं अशफ़ाक़ुल्लाह खां ने इसे कुल्हाड़ी से काटा। सब कुछ एक चादर में बांध आजादी के मतवाले वहां से फरार हो गए। इस खजाने में कुल 4601 रुपए थे।

बंगलादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, क्या है 'रियल हिंदू' और 'रील हिंदू'

● **हिन्दुओं पर हो रहे हैं अत्याचार मगर राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी ने मौन धारण कर रखा है**

नई दिल्ली, (आईएएनएस): शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद यूनुस ने गुरुवार को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया के रूप में शपथ ली। मोहम्मद यूनुस के शपथ लेने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें बधाई दी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हमले के विरोध में आवाज उठाई और मोहम्मद यूनुस से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया।

वहीं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी मोहम्मद यूनुस को बधाई दी। लेकिन, उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अत्याचार पर कुछ भी नहीं कहा। सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, बल्कि कांग्रेस के तमाम नेताओं ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में एक शब्द भी नहीं बोला।

हैरान, करने वाली बात ये है कि जब गाजा हवाई हमले में मुस्लिम समुदाय के लोग मारे गए तो उन्होंने खुलकर विरोध किया। मगर, जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उनके घर, दुकानें और मंदिरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तब राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी ने मौन धारण कर रखा है।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83
पंजाब केसरी
दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com

स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रेस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रैस, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

हिन्दुस्तान 1936 सत्य • सार्थक • सदैव

एक और जमानत

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को सर्वोच्च न्यायालय में मिली जमानत राजनीतिक रूप से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय राजधानी के व्यापक समाज ने एक समय मनीष सिसोदिया को भी बहुत उम्मीद के साथ देखा था। नैतिकता के बल से ही वह अपने नेता अरविंद केजरीवाल के साथ एक वैकल्पिक ताकत बनकर उभरे थे। वह लगभग 17 महीनों की जद्दोजहद के बाद जेल से बाहर आए हैं। न्यायालय ने पूरी तरह से आश्वस्त होने के बाद ही दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मामलों में जमानत दी है। दरअसल, पहले ही लगने लगा था कि सिसोदिया को ज्यादा समय तक सलाखों के पीछे रखना जांच एजेंसियों के लिए संभव नहीं होगा। आश्चर्य नहीं कि न्यायमूर्ति बीआर गवई और के वी विश्वनाथन की पीठ ने जमानत याचिका को विचारणीय मानते हुए कहा कि सिसोदिया को अब जमानत मांगने के लिए सुनवाई अदालत भेजना न्याय का मखौल होगा। वास्तव में, यह सिसोदिया के लिए पूरी रिहाई नहीं है, उन्हें आरोप मुक्त होने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ सकता है। हालांकि, यह माना जा रहा है कि सशर्त नियमित जमानत उनकी राजनीतिक ताकत को लौटा लाएगी।

प्रवर्तन निदेशालय जमानत से खुश नहीं है, अंततः उसकी कोशिश थी कि सिसोदिया को दिल्ली सचिवालय या मुख्यमंत्री कार्यालय जाने से रोका जाए, पर न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय की याचना पर ध्यान नहीं दिया। अब यह इतिहास में दर्ज हो गया है कि सीबीआई और ईडी ने आखिर तक यही प्रयास किया कि जमानत न हो सके, पर सर्वोच्च न्यायालय पहुंचकर जमानत मांगने की यह तीसरी कोशिश रंग लाई है। वैसे, एजेंसियों को जमानत रोकने पर जोर लगाने के बजाय दोष सिद्ध करने पर जोर देना चाहिए था, अगर पूरे प्रमाण के साथ मुकदमा शुरू हो जाता, तो सिसोदिया का बाहर आना मुश्किल हो जाता। अतः परोक्ष रूप से ईडी व सीबीआई की सुस्त चाल ने सिसोदिया की रिहाई को मुमकिन बनाया। एक पूर्व उप-मुख्यमंत्री को लगभग 17 महीने जेल में रखने के बावजूद सुनवाई और सजा की प्रक्रिया का किसी मुकाम पर न पहुंच पाना चिंता व विचार का विषय है। चिंता इसलिए कि जांच एजेंसियों की ऐसी कार्रवाई पर देश का खूब समय और संसाधन खर्च होता है, पर लोग कोई ठोस धारणा नहीं बना पाते हैं। एक लंबी फेहरिस्त है, ऐसे नेताओं की, जो सनसनीखेज ढंग से फंसे, जेल गए और बाहर निकल आए। एजेंसियां देखती रह गईं। इसी फेहरिस्त में अब एक नया नाम जुड़ गया है।

एक पूर्व उप-मुख्यमंत्री को लगभग 17 महीने जेल में रखने के बावजूद सुनवाई और सजा की प्रक्रिया का किसी मुकाम पर न पहुंच पाना चिंता एवं विचार का विषय है।

कुल मिलाकर, अभी न दूध का दूध हुआ है और न पानी का पानी। इंतजार करना होगा। यह भारतीय राजनीति के लिए चिंता की बात है। शक की चादर ओढ़े न जाने कितने नेता सक्रिय हैं। गौर कीजिए, तो राजनीतिक बिरादरी भी अपनी पूरी सफाई के पक्ष में नहीं है। सबके पास अपने-अपने दागी हैं, जिनके बचाव की त्रासद राजनीति लोगों और लोकतंत्र के समग्र विश्वास में सेंध लगा रही है। दाग छुड़ाने के बजाय छिपाने की राजनीति अब पीछे छूट जानी चाहिए। देश में विकास की गति बढ़ गई है, तो नेताओं से उम्मीदें भी बढ़ गई हैं, पर क्या जांच व कानून-व्यवस्था लागू करने वाली एजेंसियां देश के साथ कदमताल के लिए तैयार हैं?

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले

10 अगस्त, 1949

राष्ट्रभाषा और राष्ट्रलिपि

राष्ट्रभाषा पर व्यवस्था देने के लिए विभिन्न भाषाओं के विद्वानों की जो परिषद् राजधानी में आयोजित की गई थी, वह सफलता के साथ हो गई। सफलता के साथ हम इसलिए कहते हैं, क्योंकि जिस काम के लिए उसका आयोजन किया गया था, वह काम उसने बड़ी सुन्दरता के साथ किया है। दो दिन के सम्मेलन में कड़वे वाद-विवाद और आक्षेप-आरोपों की जगह रास्ता निकालने और लक्ष्य पर पहुंचने की उत्सुकता ही दृष्टिगोचर हुई। यह सचमुच श्रेय की बात है कि विभिन्न भाषा-भाषियों और विभिन्न प्रांतवासियों के सम्मेलन में अपनी भाषा और अपने प्रांत के पक्षपात का कुदृश्य देखने को नहीं मिला, बल्कि सबने एक राष्ट्रीयता और राष्ट्र-हित की दृष्टि से ही विचार किया। यही कारण है कि निर्णय में सर्वसम्मति है और वह असंतुलित या अव्यावहारिक नहीं है।

राष्ट्रभाषा का निर्णय जब देश को स्वतंत्र हुए दो वर्ष हो जाने पर भी नहीं हो रहा है, तब यह उचित ही था कि विभिन्न भाषाओं के विद्वानों को एकत्र करके इस बारे में उनसे व्यवस्था ली जाती। हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने इस आयोजन द्वारा विभिन्न भाषा-भाषियों को ऐसा अवसर दिया, इसके लिए देश को उसका अनुगृहीत होना चाहिए। चूंकि हिन्दी ही संभावित राष्ट्रभाषा है, इसलिए यह भी उचित ही हुआ कि एक अहिन्दीभाषी विद्वान को सभापति पद पर आसीन किया गया और विचार-विमर्श में अहिन्दीभाषियों को ही प्रधानता दी गई। यही कारण था कि कार्रवाई हिन्दी में ही सीमित नहीं रही और संस्कृत, बंगला, मलयालम के थोड़े नमूनों के साथ अंग्रेजी का प्राधान्य रहा। अंग्रेजी राज्य न रहने पर भी अंग्रेजी का ऐसा सहारा हमारी इस दुरावस्था का ही द्योतक है कि कोई स्वीकृत राष्ट्रभाषा हमारी नहीं है। हमें यह देखकर संतोष हुआ कि इस स्थिति पर गर्वानुभव किसी ने नहीं किया बल्कि इस पर लज्जानुभव ही किया और इसमें जो राष्ट्रीय अपमान है, उसी से प्रेरित होकर बिना किसी मतभेद के उपस्थित विद्वानों ने राष्ट्रभाषा और राष्ट्रलिपि के संबंध में निर्णय किये।

राष्ट्रभाषा के बारे में किया गया प्रस्ताव यह है- ''नई दिल्ली में सम्मिलित भारतवर्ष की मुख्य भाषाओं के विद्वानों की यह परिषद् निश्चय करती है कि भारतीय संविधान में भारत संघ की राष्ट्रभाषा हिन्दी, जिसकी लिपि देवनागरी होगी, स्वीकृत की जाये।''

मनीष की रिहाई के सियासी मायने

आम आदमी पार्टी को नए सिरे से खड़ा करने की जरूरत है। इसे पुरानी मानसिकता से निकलने की आवश्यकता है। टकराव और तकरार की जगह इसे सहकार का रास्ता अपनाना होगा।

यहां स्कैन करें

आशुतोष | वरिष्ठ पत्रकार

दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। सतरह महीने जेल में रहने के बाद अब वह खुली हवा में सांस लेंगे। कोर्ट प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई से नाराज दिखा। उसने फटकार भी लगाई और यह संदेश भी दिया कि इतने लंबे समय तक सिसोदिया को जेल में नहीं रखा जाना चाहिए। कोर्ट निचली अदालत से भी खफा नजर आया, लेकिन इन नाराजगियों और टिप्पणियों का हासिल क्या है? क्या इससे सिसोदिया के जेल में बिताए दिन वापस आ जाएंगे या ईडी अधिकारी हर तरह के दबाव से मुक्त होकर ईमानदारी से काम करने लगेंगे या फिर निचली अदालतें तुरंत जमानत दे देंगी और सिर्फ असाधारण परिस्थितियों में आरोपी को जेल की सैर करनी होगी?

यकीन मानिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा और सब कुछ पहले की तरह ही चलता रहेगा, जब तक कि इस पूरे तंत्र की समीक्षा नहीं होगी और इसमें बुनियादी बदलाव नहीं किए जाएंगे। दरअसल, आजादी के बाद लोकतंत्र की बात करते हुए हमारा पूरा तंत्र ही लोकतंत्र विरोधी होता गया, जो सरकार और शासन की जिम्मेदारी तय करने की जगह आम नागरिक की जिम्मेदारी तय कर रहा है। ये स्थितियां आने वाले दिनों में सुधरने वाली नहीं हैं, क्योंकि सत्ता को यह सूट करता है और सत्ता कैसी भी हो, उसका स्वभाव ऐसा है कि वह नागरिक अधिकारों के हनन को अपनी मूल जिम्मेदारी समझती है।

बहरहाल, मैं मनीष के मुकदमे की 'मेरिट' पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन यदि सिस्टम ऐसा हो जाए, तो फिर यह सवाल लोगों के बीच जरूर उठेगा और उठना चाहिए कि क्या मनीष को फंसाया गया है? कथित शराब घोटाले में संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल के बाद मनीष सिसोदिया तीसरे हाई प्रोफाइल नेता हैं, जिन्हें ईडी के मामलों में जमानत मिली है। संजय सिंह के मामले में कोर्ट ने एक तरह से

उन्हें निर्दोष ही कह दिया था। केजरीवाल और सिसोदिया के मामले अलग हैं। ये दोनों नेता सरकार में थे, जब दिल्ली की शराब नीति बनी और इन पर गंभीर आरोप लगे।

बहरहाल, जांच एजेंसियों की कोई भी कार्रवाई संविधान प्रदत्त नागरिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से ऊपर नहीं हो सकती। इस आधार पर किसी की नागरिक स्वतंत्रता को लंबे समय तक निरस्त नहीं किया जा सकता कि अभी जांच पूरी नहीं हुई है, क्योंकि यह अधिकार किसी अधिकारी या जांच संस्था को नहीं दिया जा सकता कि वह तय करे कि किसी की नागरिक स्वतंत्रता पर वह कब तक अंकुश रखेगी। अदालत संविधान की संरक्षक होने के नाते ऐसे मामलों में दखल दे सकती है, जैसा कि मनीष के मामले में उसने किया है।

मनीष सिसोदिया ने जेल जाने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन केजरीवाल अभी भी मुख्यमंत्री हैं और जेल से ही सरकार चलाने का दावा कर रहे हैं। लिहाजा अब केजरीवाल को ही यह तय करना है कि वह मनीष को फिर उप-मुख्यमंत्री बनाते हैं या नहीं? बेहतर तो यही है कि दिल्ली को एक सक्रिय सरकार मिले, न कि ऐसी सरकार, जो जेल से चलाई जा रही हो। यह स्थिति खुद केजरीवाल की छवि के लिए भी अच्छी नहीं है और न ही दिल्ली की जनता के लिए। फिर आम आदमी पार्टी को भी जेल से सरकार चलाने का कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिल रहा है। गौर कीजिए, लोकसभा चुनाव के ठीक पहले केजरीवाल जेल गए थे और अदालती फैसले से वह चुनाव प्रचार के लिए बाहर भी आए, मगर दिल्ली की जनता पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। कांग्रेस से गठबंधन के बावजूद आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक भी सीट नहीं जीत पाई। पंजाब में भी वह सिर्फ तीन सीट निकाल पाई, जबकि वहां कांग्रेस ने सात सीटें जीतीं, यानी केजरीवाल को जेल जाने की कोई सहानुभूति नहीं मिल रही है।

अगले साल की शुरुआत में ही दिल्ली विधानसभा के चुनाव हैं। अगर यही हालात बने रहे, तो आप को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। 2013, 2015 और 2020 के विधानसभा चुनावों की तुलना में अब माहौल में काफी अंतर आ चुका है। उन तीनों चुनावों में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप नहीं लगे थे। ऐसे में, मनीष सिसोदिया को जमानत मिलना आपदा में अवसर जैसा हो सकता है। दिल्ली की राजनीति में कुछ बदलाव करके पार्टी अपनी खोई जमीन दोबारा हासिल करने की कोशिश कर सकती है।

आप को नए सिरे से खड़ा करने की जरूरत है। इसे पुरानी मानसिकता से निकलने की आवश्यकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह केजरीवाल से छुटकारा पा ले। वह बड़े नेता हैं और रहेंगे। पार्टी तो उनके ही नेतृत्व में चलेगी, लेकिन 2013 से अब तक जो मानसिकता आप को चला रही थी, उसे बदलना होगा। उसे टकराव और तकरार की जगह सहकार का रास्ता अपनाना होगा। मनीष यह काम कर सकते हैं। वह पार्टी और नौकरशाही को भी भरोसे में लेकर चल सकते हैं।

एक उम्मीद का नाम थी आम आदमी पार्टी। पिछले वर्षों में वह उम्मीद धूमिल हुई है। इसी का नतीजा है कि केजरीवाल के जेल जाने पर दिल्ली-पंजाब की जनता सड़कों पर नहीं आई। वही जनता, जो 2011 में अन्ना हजारे और केजरीवाल को तिहाड़ भेजे जाने के बाद आंदोलन पर उतर आई थी और मनमोहन सरकार को उन्हें जेल से रिहा करने के लिए मजबूर कर दिया था। आप की पूंजी उसकी नैतिक सत्ता है। राजनीति उसका प्रतिफल है, अंत नहीं। अफसोस! केजरीवाल और उनकी पार्टी राजनीति को ही अपनी ताकत समझ बैठी है, लिहाजा जनता उदासीन है।

सबसे पहले आम आदमी पार्टी को यह समझना होगा कि पार्टी आईसीयू की तरफ जा रही है। केजरीवाल एकमात्र शख्स हैं, जो उसे बचा सकते हैं। देर-सबेर उन्हें भी जमानत मिल ही जाएगी। मगर सत्ता का मोह छोड़ वह भी राहुल गांधी की तरह जनता के बीच घूमना शुरू करें। यह काम उन्हें 2015 में ही करना था, जब देश उनका इंतजार कर रहा था। देश को अभी भी उस केजरीवाल का इंतजार है, जो हवाई चप्पल में ढीली पैंट-शर्ट पहने घूमा करते थे। वह केजरीवाल कहीं गुम हो गए हैं। उन्हें खोजने की जरूरत है। मनीष सिसोदिया को मिली जमानत, वह दरवाजा खोल सकती है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

वक्फ बोर्ड अधिनियम से जुड़ा संशोधन फिर चर्चा में है और इससे जुड़े विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया है। इसमें 1995 में बड़े संशोधन किए गए थे और तब 29 मई को राज्यसभा में हुई बहस पर गौर करें, तो वैसी ही चिंताएं और समस्याएं आज भी बरकरार हैं।

आमने-सामने

वक्फ बोर्ड में सेकुलरिटी जैसा शब्द कैसे आया

यहां स्कैन करें

सिकंदर बख्त | भाजपा सांसद व तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष

- वक्फ जायदाद पर लूटमार मची हुई है, तो उसे लूटमार से बचाने का सवाल है।
- जब सब कुछ मुस्लिम कानून के तहत होना है, तो सेकुलरिटी शब्द क्यों?
- वक्फ जायदाद को बर्बाद होने से रोकने का बंदोबस्त करना चाहिए।

मैं बहुत नाजुक जमीन पर इजहारे-खयाल करने के लिए हाजिर हुआ हूं। बहुत तजुबजुब है मुझे कि केसरी जी ने जो कोशिश की है, उस कोशिश की तारीफ करूं या कुछ शिकायत को शामिल करके तारीफ करूं। ...बुनियादी सवाल केवल एक ही है कि वक्फ बोर्ड की जायदाद की हिफाजत के लिए क्या कदम उठाए जाएं, इसको महफूज कैसे रखा जाए? क्या हमने उन तमाम क्षेत्रों पर नजर डाल ली है कि जहां से वक्फ बोर्ड की जायदादों से बेतहाशा पिल्फरिज हो रहा है? मुसलमान वक्फ का जिक्र है। मुसलमान वक्फ की जायदाद की हिफाजत का जिक्र है। अगर किसी हिस्से में, किसी एक दायरे में इस जायदाद पर लूटमार मची हुई है, तो उसको उस लूटमार से बचाने का सवाल है।

यह जायदाद गरीब मुसलमानों की बेवाओं की, यतीम बच्चों की अमानत है। उसमें अगर खयानत हो रही है, तो इस बिल के लाने में उस खयानत से इस जायदाद को महफूज रखने के कौन-कौन से तरीके रख गए हैं? मेरी राय में पूरे नहीं रखे गए हैं।...

तमाम विवरणों को ठीक से पढ़ने का मौका नहीं मिला। उसके बावजूद संशोधन बहुत सारे आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैंने अभी यह कहा कि मैं बहुत नाजुक जमीन पर इजहारे-खयाल कर रहा हूं। इसलिए कर रहा हूं कि जो लोग वक्फ की जायदाद के इंतजाम में लगे हुए हैं, उनकी बदइंतजामी ने वक्फ की जायदाद को बेतहाशा नुकसान पहुंचाया है। अब भी उसमें कोई मुनासिब बंदोबस्त किया गया हो, मुझे ऐसा नजर नहीं आता है।... यहां सेकुलर एक्टिविटी के क्या मायने हैं? मैं नहीं समझा हूं। कोई वक्फ अगर स्कूल खोलता है और उस स्कूल में हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई बच्चे पढ़ें, बिल्कुल मुनासिब है, लेकिन तमाम कानून का गवर्नेंस मुस्लिम लॉ के मातहत होना, मुझे पता नहीं, किस किस्म की चीजें हैं और किस-किस किस्म की नाराजनी (नारेबाजी) को हम मिलाना चाह रहे हैं। यह वक्फ खालिसन मुस्लिम कम्युनिटी के औकाफ हैं, जिनका मैनेजमेंट मुस्लिम लॉ के मातहत ही होना है, तो सेकुलरिज्म का लफ्ज इसमें कहां से आ गया? यहां सियासी नाराजनी की क्या जरूरत है?...

आपने कहा है कि 50 हजार रुपये सालाना से ऊपर की आमदनी का हिसाब-किताब मुतवल्ली को बोर्ड की मंजूरी के लिए भेज देना चाहिए। ... पूरे का पूरा अकाउंट बोर्ड के पास मंजूरी के लिए क्यों नहीं जाना चाहिए? यानी गुंजाइश आपने छोड़ दी है कि 50 हजार रुपये सालाना से कम की आमदनी हो, तो मुतवल्ली इसमें जो चाहे, सो करे। ...निहायत गड़बड़ हो रही है। ...1977 में पंजाब वक्फ बोर्ड के पास कई सौ करोड़ रुपये होने चाहिए थे, लेकिन सिर्फ 40 लाख रुपये उसके पास थे। बाकी रुपये कहां गए? रुपये किसी मुस्लिम ट्रस्ट, किसी मुस्लिम कल्याण या किसी मदरसे के लिए इस्तेमाल नहीं किए गए। तो पैसा कहां गया? इसलिए जो इंतजामी ढांचा है, उस इंतजामी ढांचे के हाथों वक्फ की जायदाद को बर्बाद होने से रोकने का बंदोबस्त पूरी तौर पर करना चाहिए। ...यह जहन बनाइए हमारी कम्युनिटी का कि वक्फ की जायदाद का एक पैसा किसी को बर्बाद करने का हक न हो। जहन बनाने की बात है। यह तादाद और कीमत की बात नहीं है कि कितना पैसा किसने दिया? एक-एक पैसा अमानत समझा जाए और उसमें खयानत न होने दी जाए।

(राज्यसभा में दिए गए उद्बोधन से)

सहमति बनाकर चलना ही हमारी बड़ी कोशिश

यहां स्कैन करें

सीताराम केसरी | तत्कालीन केंद्रीय कल्याण मंत्री

- इस विधेयक का मकसद वक्फ बोर्डों को अधिक लोकतांत्रिक बनाना है।
- गांधी के सेकुलरिज्म को जानता हूं, किताबी सेकुलरिज्म को नहीं।
- हमने वादा किया था, वक्फ अधिनियम को संशोधन से कारगर बनाएंगे।

साल 1991 के लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चुनाव घोषणापत्र में हमने वादा किया था कि हम इस वक्फ अधिनियम की समीक्षा के बाद संशोधन करके इसे और भी कारगर बनाएंगे। 1991 में कल्याण मंत्रालय का कार्यभार लेते हुए मैंने इस दिशा में कार्रवाई शुरू कर इस मुद्दे पर माननीय मुसलमान भाइयों, संसद सदस्यों, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मुस्लिम सदस्यों, मुस्लिम समुदाय के अन्य गणमान्य नेताओं के साथ विचार किया और इसमें काफी समय लगा।

मैं याद दिलाना चाहूंगा कि मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 वक्फ अधिनियम 1954 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। वक्फ अधिनियम 1954 का मूल प्रयोजन देश में वक्फ संपत्तियों को कुशल प्रशासन प्रदान करना था। फिर भी 1954 के अधिनियम को लागू होने के तत्काल बाद ही इसके विभिन्न प्रावधानों के विरुद्ध प्रतिवेदन एवं आपत्तियां आनी शुरू हो गईं। इस अधिनियम के कुछ प्रावधानों को स्पष्ट करने के लिए इस कानून में 1959, 1964 एवं 1969 में संशोधन किए गए। वक्फ संशोधन विधेयक 1969 पर विचार के दौरान संसद में जोरदार मांग की गई कि देश में वक्फ प्रशासन के समग्र कार्य का एक समिति द्वारा गहराई से अध्ययन किया जाए।

... इस विधेयक में जम्मू-कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में वक्फ कानून को एक समान रूप से लागू करने का प्रावधान किया गया है।... इस विधेयक का मकसद वक्फ बोर्डों को और अधिक लोकतांत्रिक बनाना है। वक्फ बोर्डों के अधिकांश सदस्यों का निर्वाचन संबंधित निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा, जिसमें मुस्लिम सांसद, मुस्लिम विधायक, राज्य अधिवक्ता, परिषद् और मुतवल्लियों के सदस्यगण शामिल होंगे, जिनकी आय एक लाख रुपये वार्षिक या इससे अधिक होगी।...

सिकंदर बख्त साहब, मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने यह कहा कि उन्होंने पढ़ा नहीं, मगर पूरे पन्नों को उलट करके हमारे सामने रख दिया, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं। दूसरी बात, मैं ज्यादा लंबी-चौड़ी तकरीर नहीं देना चाहता। ...तकरीबन सभी मुस्लिम भाइयों से बात हमने की है, इसमें समय लगा, ...अगर हम समय नहीं लगाते, जल्दी में लाते, तो आपने देखा कि मंडल कमीशन की घोषणा पर कितना विशाल बवंडर हो गया था, पर उसका क्रियान्वयन आम सहमति के आधार पर किया गया, तो कहीं बवंडर नहीं हुआ। इसलिए आम सहमति की अनिवार्य आवश्यकता होती है। ...

हमारे सिकंदर बख्त साहब ने सेकुलरिज्म की बात कही। मैं यह साफ कहना चाहता हूं कि सेकुलरिज्म के संबंध में कि यह बड़ा भारी बौद्धिक शब्द है और बहुत साधारण शब्द भी है। साधारण शब्द दुख और सुख या जो भी कहिए। मेरी जिंदगी की एक संख्या है, मैं तकरीबन 78 से ऊपर हो चुका हूं, 65 साल से ज्यादा मेरी राजनीतिक जिंदगी रही है, आजादी की लड़ाई में हमने गांधी जी से जो सीखा, जवाहरलाल से सीखा, वह सकुलरिज्म मैं जानता हूं। मैं किताबों के सेकुलरिज्म को नहीं जानता। ... अगर मेरे शब्दों से किसी भी माननीय सदस्य को चोट लगती है, तो मैं साफ तौर से कहता हूं कि मुझे दुख होगा। चूंकि चाहे तो मैंने कान में गलत समझा या चूंकि मैंने जैसा कहा, मैं कम पढ़ा-लिखा आदमी हूं, जरा कम समझा होगा, मगर सेकुलर शब्द इस्तेमाल हुआ है। वही मैंने समझा है, जो 65-66 साल की सियासत की जिंदगी में मैंने पढ़ा है।...

(राज्यसभा में दिए गए उद्बोधन से)

अनुलोम-विलोम

नीरज चोपड़ा

नीरज का मतलब ही पदक की गारंटी

तुम चांदी लाए हो, तुम्हें दुख हो रहा होगा, यह स्वाभाविक है, पर हम तो चार साल पहले तक बस मेडल सोचा करते थे। यह तुम्हारी बदौलत है कि आज हम मेडल के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, बल्कि कन्फर्म मानकर चल रहे थे कि इस बार भी हमें सोना मिलने वाला है। यह विश्वास कमाया है तुमने नीरज; यह कमाई है तुम्हारी। साढ़े पांच करोड़ लोग रात के एक बजे संभवतः पहली बार क्रिकेट के अलावा कुछ और देखने के लिए बैठे थे, तो यह तुम्हारी बदौलत ही संभव हुआ। करीब डेढ़ अरब लोगों की उम्मीदों को पूरा करने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी दोस्त, तुमने सब कुछ झोंक दिया। बस यह दिन किसी और का था, पर यह याद रखना कि यह दशक तुम्हारा है। सोना-चांदी छोड़ो, तुम हम सबका दिल जीतकर बैठे हो यार। शाबाश, मेरे दोस्त, हीरा हो तुम, हीरो हो तुम हमारे। तुम्हारी इस ताकत को कोई तुमसे छीन नहीं सकता।

रंजीत के चौबे, टिप्पणीकार

चमकदार चांदी

नीरज चोपड़ा की मां सरोज देवी ने कहा, जिसने गोल्ड जीता, वह भी अपना ही लड़का है। यही वह जज्बा है, जो एक पायदान फिसलने पर भी हमें मायूस नहीं करता, बल्कि पूरा देश फख्र करता है कि हमने जरा सा कुछ हारकर भी सब कुछ जीत लिया है। नीरज चोपड़ा भारतीय इतिहास के पहले ऐसे एथलीट बन चुके हैं, जिन्होंने लगातार दो ओलंपिक में स्वर्ण व रजत पदक जीते। वास्तव में, इस बार भी नीरज कमतर साबित नहीं हुए, बल्कि उनका प्रतिस्पर्द्धी बहुत अच्छा खेल गया। नीरज चोपड़ा ने अपने छह प्रयासों में से पांच फाउल कर दिए, मगर जो एक कामयाब थ्रो (89.45 मीटर) किया, वह उनके करियर का दूसरा सबसे श्रेष्ठ थ्रो था। पड़ोसी प्रतिद्वंद्वी अरशद नदीम ने पहले प्रयास में फाउल करने के बाद जो दूसरा थ्रो फेंका, वह पूरी दुनिया को हैरत में डालने वाला रहा। 92.97 मीटर दूर भाला फेंकना एक ओलंपिक रिकॉर्ड था और यह थ्रो फेंककर उन्होंने नीरज चोपड़ा सहित बाकी 11 प्रतिद्वंद्वियों को जबरदस्त दबाव में डाल दिया, जिसके कारण वे सभी नर्वस हो गए और अतिरिक्त प्रयास करने के चक्कर में उलझकर नदीम से बहुत पीछे रह गए। स्पष्ट है, नीरज चोपड़ा ने अपने शानदार खेल को जारी रखते हुए पूरे देश को गर्व से भर दिया है। अंतर सिर्फ इतना रहा कि अरशद नदीम के लिए यह दिन 'ख्वाबों की ताबीर (नतीजा)' जैसा रहा, जिसके लिए वह तारीफ के मुस्तहिक (हकदार) हैं। अरशद नदीम को सोना मुबारक हो। हमारे लिए चांदी भी सोने से कम चमकदार नहीं है।

आगाज सिद्दीकी, टिप्पणीकार

हमें तो उनसे सिर्फ सोना चाहिए साहब

निस्संदेह, नीरज की एक बार फिर ओलंपिक में सफलता भारत के लिए खुशी की बात है और उनकी इस उपलब्धि को आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी, लेकिन आम जनमानस का यही विश्वास था कि नीरज इस बार फिर से देश के लिए सोना जीतकर आएंगे। यह विश्वास यूं ही नहीं जमा था। क्वालिफाइंग मुकाबले में ही उन्होंने जिस तरह का प्रदर्शन किया था, उससे यह धारणा पुख्ता होने लगी थी कि उनके जैसा भाला कोई दूसरा नहीं फेंक सकता। मगर मुकाबले में पाकिस्तान के अरशद नदीम उन पर बीस साबित हुए और नीरज को चांदी से ही संतोष करना पड़ा। दुखद तो यह रहा कि नीरज ने कुल छह प्रयासों में से पांच फाउल किए। अगर वह प्रयास भी दुर्भाग्यवश फाउल हो जाता, तो हमारी रही-सही उम्मीद भी जाती रहती। इससे यही जान पड़ता है कि एकाग्रता की कमी नीरज को ले डूबी। अरशद नदीम ने 92.97 मीटर दूर ज्योंही भाला फेंका, नीरज बदहवास से होने लगे। उनकी यह बदहवासी फाउल के रूप में सामने आई, जबकि एक अच्छे खिलाड़ी को अपने लक्ष्य को लेकर एकाग्रचित्त होना चाहिए, तभी उसे सफलता मिल सकती है।

कुछ लोग तर्क दे रहे हैं कि सभी का अपना दिन होता है और वह दिन अरशद का था। ऐसी बातें गले नहीं उतर सकतीं। यह ठीक उसी तरह का तर्क है कि जब आप सफल नहीं हो सके, तो कहने लगे कि अंगूर खट्टे हैं या फिर ईश्वर का यही विधान था, आखिर कर भी क्या कर सकते हैं? ऐसे वाक्य सिर्फ दिलासा देने के काम आते हैं और एक निराशावादी तस्वीर पेश करते हैं। अलबत्ता, कहना तो यह चाहिए था कि नीरज के खेल में कुछ कमी रह गई कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी को मात नहीं दे सके, इसलिए उनके खेल की समीक्षा की जानी चाहिए। यह इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि 90 मीटर को एक आदर्श दूरी मानकर वह तैयारी कर रहे थे, लेकिन वह इस सीमा तक पहुंच ही नहीं सके।

हालांकि, मेरे इस विचार का यह अर्थ न निकाला जाए कि मैं नीरज चोपड़ा की उपलब्धि को कमतर मान रहा हूं। निस्संदेह, उन्होंने अच्छा खेल दिखाया, लेकिन उनसे इससे कहीं बेहतर की उम्मीद थी और वह इस उम्मीद पर खरे उतरने में सक्षम भी हैं। जाहिर है, कहीं न कहीं चूक हुई है और उन्हें अब इसी चूक पर मेहनत करनी होगी, तभी अगले ओलंपिक में वह स्वर्ण की दूरी नाप सकेंगे। नीरज से हमें सिर्फ सोना की उम्मीद है। चांदी का बहुत मतलब नहीं है, सिवाय इसके कि यह मेडल पदक-तालिका में हमारी स्थिति कुछ हद तक मजबूत बनाता है।

सुमित कुमार, टिप्पणीकार

https://t.me/AllNewsPaperPaid

दैनिक जागरण
शांति समृद्धि की पहली सीढ़ी है

संसद में चर्चा का स्तर

तय समय से पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित संसद के अंतिम दिन राज्यसभा में सपा सांसद जया बच्चन और सभापति जगदीप धनखड़ के बीच जो तीखी तकरार हुई, वह यही बताती है कि सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच संबंध कितने अधिक कटुतापूर्ण हो गए हैं। सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच कटु संबंध केवल राज्यसभा में ही नहीं, बल्कि लोकसभा में भी देखने को मिल रहे हैं। गत दिवस जया बच्चन सभापति जगदीप धनखड़ से इसलिए नाराज हो गईं, क्योंकि उन्हें उनका लहजा पसंद नहीं आया। उन्होंने उनके लहजे पर आपत्ति जताई तो सभापति ने भी उन्हें मर्यादा में रहने का पाठ पढ़ा दिया। इससे वह आपे से बाहर हो गईं। संसद के भीतर और बाहर उनकी तुनकमिजाजी नई नहीं है। वह कभी अपने आधिकारिक नाम जया अमिताभ बच्चन कहे जाने से चिढ़ जाती हैं और कभी इस पर गर्व करने लगती हैं। इस पर हैरानी नहीं कि विपक्ष ने जया बच्चन का साथ देना बेहतर समझा। उसने न केवल सदन का बहिष्कार कर दिया, बल्कि सभापति को हटाने के लिए प्रस्ताव लाने पर भी विचार करने लगा। इसके जवाब में नेता सदन जेपी नड्डा विपक्ष के आचरण के खिलाफ निंदा प्रस्ताव ले आए। फिलहाल कहना कठिन है कि विपक्ष सभापति को हटाने को लेकर कितना गंभीर है और इस मामले में वह कहां तक जाएगा, लेकिन यह स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में दोनों पक्षों के रिश्तों में और अधिक कड़वाहट घुल सकती है। यह कड़वाहट पहले भी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद वह और अधिक बढ़ गई है। इसका असर संसद के कामकाज पर भी पड़ रहा है।

अब संसद में ऐसे सदस्यों की संख्या बढ़ती दिख रही है, जो हंगामा करने की कोशिश में रहते हैं और संसद के नियम-कानूनों और पीठासीन अधिकारी के आदेश-निर्देश की कहीं कोई परवाह नहीं करते। संसद में अब किसी भी विषय पर कठिनाई से ही कोई सार्थक बहस होती है। अधिकांश समय पक्ष-विपक्ष के सदस्य आपस में उलझे रहते हैं। किसी विषय पर धीर-गंभीर चर्चा करने के बजाय वे छींटाकशी करने, मिथ्या आरोप लगाने और एक-दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में रहते हैं। अब तो संसद में अपनी बात कहने के स्थान पर नारेबाजी करने पर अधिक जोर दिया जाने लगा है। कभी-कभी ऐसा लगता है कि यह सब इस कारण अधिक होता है, क्योंकि संसद की कार्यवाही का सीधा प्रसारण होता है। चूंकि संसद में सार्थक चर्चा करने और कराने की कोई ठोस पहल नहीं होती, इसलिए वहां हंगामा और शोर-शराबा ही अधिक होता है। यदि संसद में लोक महत्व के विषयों पर गंभीर चर्चा नहीं होगी तो जनता से यह अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए कि वह उसे अपनी आकांक्षाओं का मंच और लोकतंत्र का मंदिर माने। यह भी तय है कि यदि संसद में सार्थक चर्चा नहीं होगी तो उसका असर विधेयकों की गुणवत्ता पर भी पड़ेगा।

जोखिम में जिंदगी

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर के निकट दो जर्जर मकान गिरने के दूसरे ही दिन एक अन्य मकान की सीढ़ियां गिर जाने की घटना को चेतावनी के तौर पर लिया जाना चाहिए। इनमें दो मकान 80 साल पुराने थे, जबकि एक डेढ़ सौ साल से भी अधिक पुराना और नगर निगम इन्हें पूरी तरह जर्जर घोषित करके खाली करने की नोटिस भी जारी कर चुका था। फिर भी लोग अपनी जिंदगी खतरे में डालकर इनमें रह रहे थे। वस्तुतः ऐसा केवल वाराणसी में ही नहीं है, बल्कि लगभग हर महानगर में बड़ी संख्या में ऐसे मकान हैं जो काफी पुराने हैं। उनके कभी भी गिर जाने की आशंका बनी हुई है, लेकिन अदालती विवादों की वजह से न उन्हें गिराया जा सका, न ही खाली कराया जा सका और न ही मरम्मत कराई जा सकी। कुछ तो मजबूरी में और कुछ अपना स्वामित्व बनाए रखने के लिए ऐसे मकानों में रह रहे हैं। नगर निगम भी ऐसे मकानों को गिराने की नोटिस जारी कर औपचारिकता का निर्वाह कर लेता है। जर्जर हो चुके मकानों में रहना अपनी जिंदगी को खतरे में डालना है। ऐसे मकानों से आसपास के लोग भी असुरक्षित हो जाते हैं। इसका कितना बड़ा दुष्परिणाम सामने आ सकता है इसे लखनऊ में पिछले साल हुई घटना से समझा जा सकता है, जब एक रेलवे कालोनी में एक जर्जर मकान गिरने से पांच लोगों की मौत हो गई थी। इसी तरह के हादसे अन्य महानगरों में भी हो चुके हैं। बारिश में ऐसे मकान और भी जर्जर हो जाते हैं और दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे मकानों में रहनेवालों को जल्द विकल्प की तलाश करनी चाहिए। यदि कोई मकान विवादित है तो सभी पक्षों को मिलकर उसकी मरम्मत के लिए समवेत प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी है तभी संपत्ति के भी मायने हैं।

वर्षों पुराने और पूरी तरह जर्जर हो चुके मकानों में रहना अपनी जिंदगी को खतरे में डालना है

पराभव की ओर बढ़ता ब्रिटेन

हर्ष वी. पंत

हालिया दंगे यही दर्शाते हैं कि दुनिया को लोकतांत्रिक मूल्यों पर उपदेश देने वाला ब्रिटेन अपना ही घर दुरुस्त नहीं रख पा रहा है

अवधेश राजपूत

बीते कुछ दिनों के दौरान ब्रिटेन के तमाम हिस्सों में बड़े पैमाने पर दंगे भड़क गए। दंगों की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन पर काबू पाने में करीब सप्ताह भर का समय लग गया। सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी और तमाम कड़े कदम उठाने के बावजूद स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। पता नहीं कहां विवाद की छोटी सी चिंगारी किसी विकराल दंगे का रूप धारण कर ले। हालिया प्रकरण 29 जुलाई को एक नृत्य कार्यक्रम के बाद शुरू हुआ। उत्तरी इंग्लैंड के साउथपोर्ट में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान तीन बच्चियों की हत्या कर दी गई। जबकि कुछ अन्य घायल हो गए। हमलावर के बारे में इंटरनेट मीडिया पर यह अफवाह उड़ी कि वह मुस्लिम समुदाय से जुड़ा है, जो ब्रिटेन में शरण पाने वाला एक अप्रवासी है। इसके बाद मुस्लिम समुदाय और अप्रवासी स्थानीय लोगों के निशाने पर आ गए। हालांकि बाद में यह स्पष्ट हुआ कि 17 वर्षीय मुख्य हमलावर एक्सल रुदाकुबाना वेल्स में ही पैदा हुआ है, जिसके माता-पिता रवांडा से ब्रिटेन आए थे। जब तक तस्वीर साफ होती, उससे पहले ही लोगों ने साउथपोर्ट में एक मस्जिद को निशाना बनाने का प्रयास किया।

हमलावर भले ही पकड़ लिया गया हो, मगर इस मामले ने ब्रिटिश लोगों को भड़का दिया। आक्रोशित भीड़ ने रादरम में उस होटल पर भी हमला बोला, जिसमें राजनीतिक शरण मांगने वालों को रखा जाता है। इतना ही नहीं, लिवरपूल, ब्रिस्टल, मैनचेस्टर और ब्लैकपूल में भी हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। ऐसे करीब 20 वाकयों में कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। इस प्रकार के हिंसक प्रदर्शन भले ही एक तात्कालिक प्रतिक्रिया हों, लेकिन इसकी सुगबुगाहट ब्रिटिश समाज में काफी पहले से महसूस की जा रही थी। यही कारण है कि सरकार संवेदनशील वर्गों को लेकर सक्रिय हुई है। मिसाल के तौर पर अप्रवासी मामलों को देखने वाले वकीलों की सुरक्षा को लेकर भी उठते सवालों पर ध्यान दिया जा रहा है। सतही तौर पर कानून एवं व्यवस्था से संबंधित दिखने वाले इस मामले की जड़ें अप्रवास विरोध और ब्रिटिश समाज में गहराती विभाजक रेखाओं से जुड़ी हैं। अभी इसके और घातक परिणाम देखने को मिल सकते हैं।

अप्रवासियों को लेकर ब्रिटेन में पिछले कुछ समय से असंतोष बढ़ रहा है। तमाम ब्रिटिश नागरिक ऐसा सोचते हैं कि अप्रवासियों की बढ़ती संख्या के चलते हाउसिंग, शिक्षा, और स्वास्थ्य से जुड़ी सरकारी कल्याणकारी योजनाओं में उनके हितों में सेंधमारी हो रही है। उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन में यूरोपीय संघ से अलग होने वाले ब्रेक्जिट अभियान को भी इसी पहलू के चलते सफलता मिली थी कि इससे अप्रवासियों पर अंकुश लगाने के साथ नीति-निर्माण में ब्रिटिश स्वायत्तता बढ़ेगी। हालांकि कंजरवेटिव पार्टी ने अप्रवासियों के चलते पनप रहे असंतोष पर काबू पाने के लिए कुछ उपाय जरूर किए, लेकिन लगता नहीं कि ब्रिटिश जनता उन उपायों से संतुष्ट हुई होगी। हालिया चुनावों में लेबर पार्टी की जीत ने भी इस मामले में उन दक्षिणपंथी समूहों को भावनाएं भड़काने की गुंजाइश दी होगी, जिन्हें ब्रिटिश प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर बीते दिनों हुए दंगों का दोषी ठहरा रहे हैं। ऐसी धारणा है कि लेबर पार्टी अप्रवासियों के प्रति अपेक्षाकृत नरम रवैया रखती है।

प्रधानमंत्री स्टार्मर ने कहा है कि दंगाइयों से निपटने के हरसंभव सख्त उपाय किए जाएंगे, लेकिन दंगों की आग पर काबू पाने में करीब सप्ताह भर का समय लगना अपने आप में काफी कुछ कह देता है। शासन-प्रशासन के स्तर पर आश्वासन के बावूजद हालात इतने बिगड़ गए कि लोगों को अपनी एवं अपने आवास और प्रतिष्ठान की सुरक्षा के लिए निजी स्तर पर भी कदम उठाने पड़ रहे हैं, क्योंकि हिंसा के दौरान तमाम दुकानों एवं प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। स्टार्मर ने जिन धुर दक्षिणपंथी संगठनों को इस हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया है, उनमें इंग्लिश डिफेंस लीग का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। वर्ष 2009 में अस्तित्व में आया यह संगठन अप्रवासी विरोध विशेषकर इस्लाम के खिलाफ अपने रुख के लिए जाना जाता है। पूर्व में हुई हिंसा में भी इसका नाम आता रहा है। हालांकि यह ऐसा कोई इकलौता संगठन नहीं है। मुख्यधारा की राजनीति में भी यूके रिफार्म पार्टी के नेता नाइजल फराज ने अप्रवासियों और शरणार्थियों की भड़ती भीड़ को हालिया हिंसा के लिए आड़े हाथों लिया। एक समय कंजरवेटिव पार्टी में रहे फराज ने अपनी आक्रामक राजनीति के लिए नए राजनीतिक दल का गठन किया। हालिया चुनावों में उनकी पार्टी को भले ही चार सीटें मिली हों, लेकिन कई सीटों पर वह कंजरवेटिव पार्टी की हार का कारण भी बने। उनके प्रति लामबंद होता समर्थन ब्रिटिश जनता के सोच में आ रहे बदलाव को दर्शाता है, जिसकी समय-समय पर आक्रामक अभिव्यक्ति भी देखने को मिलती रहती है। हाल के दंगे ऐसा ही एक उदाहरण रहे। हालिया दंगे दर्शाते हैं कि ब्रिटिश समाज में निराशा बढ़ रही है। उन्हें अप्रवासियों से अपने अवसरों पर आघात के साथ ही अपनी मूल सांस्कृतिक पहचान पर संकट भी दिख रहा है। चूंकि मुस्लिम समुदाय भी अपने प्रतीकों को लेकर खासा मुखर रहता है तो उसके साथ टकराव कुछ ज्यादा बढ़ रहा है।

दंगों के बाद प्रधानमंत्री स्टार्मर ने ऐसा आश्वासन दिया कि यह जिनका भी किया-धरा है, उन्हें इसकी सजा जरूर भुगतनी होगी। कानून उन पर अपना शिकंजा कसेगा। कई मामलों में दंगाइयों पर ऐसी धाराएं भी लगाई गई हैं, जो आतंकी मामलों में लगाई जाती हैं। इंटरनेट मीडिया के जरिये फर्जी सूचनाओं के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए भी कमर कसी गई है। इस सबके बावजूद कुछ सवाल जरूर उठते हैं। पहला यही कि क्या यह एक तात्कालिक आक्रामक प्रतिक्रिया थी या फिर ब्रिटेन में यह एक नया सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि वहां अब समय-समय पर दंगे भड़कते रहते हैं। इससे पूर्व भी दो साल पहले लेस्टर में दंगे भड़के थे। दूसरा सवाल यह कि दुनिया को लोकतांत्रिक मूल्यों पर उपदेश देने वाला ब्रिटेन अपना ही घर दुरुस्त क्यों नहीं रख पा रहा है? जो भी हो, इन दंगों ने ब्रिटेन की साख चोट करने के साथ ही उसके पराभव के भी संकेत दिए हैं।

(लेखक आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में उपाध्यक्ष हैं)

response@jagran.com

जीवन के चौथेपन में टूटते रिश्ते

क्षमा शर्मा

इन दिनों विवाह के दशकों बाद पति-पत्नी का अलग हो जाना एक नया चलन बनता जा रहा है

बढ़ रहे हैं अधिक उम्र में तलाक के मामले। प्रतीकात्मक

बहुत समय से एक नामचीन नायक-नायिका के तलाक की खबरें इंटरनेट मीडिया पर छाई हुई हैं। लोग दावा कर रहे हैं कि बस ऐसा होने ही वाला है। सच क्या है, कहा नहीं जा सकता, लेकिन ग्रे डाइवोर्स यानी कि विवाह के दशकों बाद पति-पत्नी का अलग हो जाना, इन दिनों बेहद चलन में है। महिलाएं कह रही हैं कि एक खराब रिश्ते में जीवन बिताने से अच्छा है कि जब मौका मिले, अलग हो जाएं। इस लेखिका ने कई स्त्रियों को खुद देखा है। कई साल पहले यह लेखिका जिस संस्थान में काम करती थी, वहां एक महिला आई। उसे काम चाहिए था। उसकी उम्र उस समय 50 वर्ष रही होगी। उसका कहना था कि पति बहुत तंग करते हैं। सुबह शाम मार-पीट, हर रात शराब पीकर आना है। वह महिला उच्च शिक्षित भी थी, लेकिन नौकरी नहीं करती थी। वह सब कुछ इतने साल इसलिए सहन करती रही कि अपने बेटे के बड़े होने का इंतजार कर रही थी। अब वह अपने पांवों पर खड़ा होना चाहती थी। उसी समय के आसपास एक वरिष्ठ महिला पत्रकार ने अपने बहुत मशहूर पति से अलग होने पर पार्टी दी थी और अपनी आजादी का जश्न मनाया। यह कोई नई-अनोखी बात नहीं कि अब तलाक की भी पार्टी होने लगी हैं। लोग उसका जश्न मनाने लगे हैं।

ग्रे डाइवोर्स का अर्थ बताया जाता है कि जब पति-पत्नी 50 की उम्र के बाद अलग हों यानी जब बालों में सफेदी छाने लगे। हालांकि जो लोग ऐसा करते हैं, उनकी राह भी आसान नहीं होती। बहुत बार जमीन-जायदाद का फैसला करना मुश्किल हो जाता है, जो संयुक्त होती है या बैंक खाते संयुक्त होते हैं। इसके अलावा बड़े बच्चे भी माता-पिता के इस तरह से अलग होने को सह नहीं पाते। कई बार बच्चे माता-पिता को इसके लिए प्रेरित भी करते हैं। एक लड़के ने जीवन भर अपनी मां को पिता के हाथों प्रताड़ित होते देखा। बड़े होने पर उसने मां से कहा कि इतना अपमान सहने से बेहतर है कि वे दोनों अलग हो जाएं। फिल्मी दुनिया में भी जहां अक्सर पति-पत्नी एक खुशहाल परिवार की तस्वीर पेश करते हैं, वहां भी ऐसा हो रहा है। इसमें फरहान अख्तर-अधुना भबानी, अरबाज खान-मलाइका अरोड़ा, ईशा देओल-भरत तख्तानी, सोनम खान-राजीव राय, किरण राव-आमिर खान, रितिक रोशन-सुजैन खान, अर्जुन रामपाल-मेहर जेसिया जैसे जोड़े शामिल हैं। इन सबके बड़े-बड़े बच्चे भी हैं।

किरण राव ने कुछ दिनों पहले साक्षात्कार में कहा था कि आमिर से उनके संबंध बहुत मधुर हैं। तलाक ने उन्हें आजादी दी है। वह खुद के महत्व को पहचानना चाहती थीं। अपने तलाक पर अर्जुन रामपाल ने इससे बिल्कुल अलग बात की। उन्होंने कहा था कि तलाक बहुत आसान नहीं होता। यह आपके अकेलेपन को बढ़ाता है। जितने भी फिल्मी जोड़े एक-दूसरे से अलग हुए हैं, वे अपने पूर्व साथी के बारे में अच्छी बातें करते हुए यह भी कहते हैं कि वे दोनों सबसे अच्छे दोस्त हैं। फिल्मकार अनुराग कश्यप जब कल्कि कोचलीन से अलग हुए तो कुछ दिन बाद उन्होंने कहा था कि जब वे दोनों साथ थे, तो हमेशा लड़ते रहते थे, मगर अब दोनों में खूब मित्रता है। कश्यप इससे पहले भी अपनी पत्नी से अलग हो चुके थे। बहरहाल, ये जोड़े यह भी कहते हैं कि जिस साथी से अलग हुए, वह बहुत अच्छा इंसान है। क्या यह सोचकर आश्चर्य नहीं होता कि यदि कोई इतना अच्छा इंसान और मित्र है, तो फिर अलग क्यों होना पड़ा? शायद इसका जवाब किसी के पास नहीं होता।

प्यू रिसर्च ने अमेरिका में ग्रे डाइवोर्स पर एक अध्ययन किया। इसमें बताया गया कि पिछले दो दशकों में तलाक के सारे मामलों में 40 प्रतिशत मामले ऐसे थे, जिनमें 50 और उससे ऊपर के जोड़े शामिल थे। 1990 के बाद इनकी संख्या दोगुनी हो गई और अब जो लोग 65 से ऊपर हैं, उनकी संख्या तिगुनी हो गई है। विशेषज्ञ कहते हैं कि जब तक लोग अपने बच्चों को पालते हैं, तब तक वे किसी तरह साथ रह लेते हैं, मगर जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं, उनका अपना घर और परिवार होता है, तो पति-पत्नी को लगता है कि अब उन्हें एक-दूसरे की जरूरत नहीं रही। इसके अलावा अपने देश में स्त्रियों के प्रति जो हिंसा है, उसे शायद वह बच्चों के कारण झेलती रहती हैं, लेकिन आज की स्त्रियां पांच दशक पहले की स्त्रियां नहीं हैं, जो किसी भी बुरे संबंध को समाज के डर से निभा लेती थीं। आज वे पहले की तरह से अपने पति पर निर्भर नहीं हैं। निर्णय लेने की उनकी क्षमता बढ़ी है। इसलिए वे भी तलाक की पहल करती हैं और बुरे रिश्ते से आजादी चाहती हैं, लेकिन यह बात भी सच है कि बच्चों पर इसका बुरा असर पड़ता है। मेरे दफ्तर आई उसी महिला के लड़के ने एक बार कहा था कि आप ही बताइए, मैं किधर जाऊं। मुझे तो अपने माता-पिता दोनों से प्यार है। मैं एक से मिलने जाता हूं तो दूसरा बुरा मानता है।

हालांकि इस मामले में फिल्मी दुनिया के लोग अक्सर अपने बच्चों पर इस तरह का प्रतिबंध नहीं लगाते। जब वे अलग होते हैं तो कहते हैं कि अपने बच्चों के लिए वे दोनों हमेशा, हर स्थिति में मौजूद रहेंगे, लेकिन आम लोगों की दुनिया में ऐसा नहीं हो पाता। कड़वाहट इतनी ज्यादा होती है कि वे एक-दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। यह भी देखा गया है कि बहुत से जोड़े अलग होने के बाद फिर से साथ रहने लगते हैं। इसके पीछे यह सच भी है कि जीवन के चौथेपन में आपको साथी और साहचर्य भाव की जरूरत सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि बच्चे अपनी-अपनी राह चले गए होते हैं। शायद इसीलिए कुछ लोग वापस लौटकर अपना जीवन फिर से शुरू करते हैं।

(लेखिका साहित्यकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

अध्यात्म से उत्थान

हमारे मनीषियों ने आध्यात्मिकता का अपेक्षित प्रसार एवं महिमामंडन किया है। यही कारण है कि भौतिक शक्ति के युग में पाले-पोसे हुए हम ही नहीं, अपितु विदेशी भी संयम, साधना और आराधना के कठोर एवं कठिन मार्ग की ओर आकर्षित हो रहे हैं। अध्यात्म जगत का आकर्षण है ही कुछ ऐसा अद्भुत जो हमें सिखाता है कि जब मन-मस्तिष्क विषय रूपी वन में स्वच्छंद विचरण करना चाहता है तो उस पर ज्ञान का अंकुश लगाकर रोकें। कान जब सहज सुंदर सुर बालाओं के मधुर संगीत की स्वर लहरी सुनने के लिए उत्सुक हों तब विवेक से उन पर अधिकार करें। नेत्र आधुनिक अप्सराओं के मनमोहक दृश्य देखने के लिए जब छटपटाने लगें तब विचारों के अंकुश से उन पर लगाम लगाएं। नाक अपनी हठधर्मिता पर अड़कर प्राकृतिक पुष्पों की सुगंध सौरभ लेने के बजाय इत्र की कृत्रिम गंध के लिए उतावली हो तो अपने चिंतन की धारा से उसका प्रवाह बदल दें। काया जब-जब सुकोमल पदार्थों के संस्पर्श के लिए इच्छुक हो तो अपने सम्यक ज्ञान से उसे वश में करें। यह सब कुछ इसलिए कि मन और इंद्रियों का प्रवाह विकारों की ओर होता है और जब तक उसे मोड़ा नहीं जाएगा तब तक हमारे जीवन का उद्धार संभव नहीं।

मानव ने विज्ञान के भरोसे संसार पर विजय पताका फहराई है, किंतु अगर वह मन की मलिन वृत्तियों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता तो यह विजय उसकी सच्ची विजय नहीं है। केवल विजय का आभास मात्र है। मृगमरीचिका की भांति वह विशुद्ध भ्रम है। हमारा मन बहुत शक्तिमान है। वही इच्छाओं-आकांक्षाओं के रथ का सारथी भी है। बिना पंख का पक्षी है, किंतु हमारी आत्मशक्ति मन से भी अधिक बलवान है। हम चाहें तो अभ्यास और साधना से मन को हर कुमार्ग से सन्मार्ग की ओर उत्प्रेरित कर सकते हैं। अशुभ चिंतन को छोड़ शुभ चिंतन करना श्रेय का मार्ग है।

डा. निर्मल जैन

महाविस्फोट की परिस्थितियों का निर्माण

प्रदीप

पदार्थ की उत्पत्ति के संबंध में विज्ञानी हमारी समझ को बेहतर बनाने में जुटे हुए हैं

प्रारंभिक ब्रह्मांड हमारे सूर्य के केंद्र से ढाई लाख गुना अधिक गर्म था। यह प्रोटान और न्यूट्रान बनाने के लिए बहुत अधिक गर्म है, जिसके संयोजन से हमारे आसपास नजर आने वाले पदार्थ बने हैं। शोधकर्ता अपनी प्रयोगशालाओं में लगभग प्रकाश की गति से परमाणुओं को आपस में टकराकर कण त्वरक (पार्टिकल एक्सेलेरेटर) में प्रारंभिक ब्रह्मांड या महाविस्फोट की परिस्थितियों के पुनर्निर्माण की कोशिशों में जुटे हुए हैं। कणों की परिणामी बौछार को मापने से विज्ञानियों को यह समझने में मदद मिलती है कि पदार्थ कैसे बना।

वर्तमान में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त सिद्धांत 'बिग बैंग' या 'महाविस्फोट' है। इस सिद्धांत के मुताबिक हमारा ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले एक अतिसूक्ष्म बिंदु में सिमटा हुआ था। इस बिंदु में एक आकस्मिक विस्फोट हुआ और इसमें सिमटा प्रत्येक कण फैलने लगा, जिससे कालांतर में ब्रह्मांड का सृजन हुआ। आखिर इस महाविस्फोट के पीछे कौन सी शक्ति थी और प्रारंभिक क्षणों में ब्रह्मांड कैसा दिखता था जैसे कई प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। सच तो यह है कि हम ब्रह्मांड के बारे में केवल चार प्रतिशत ही जानते हैं, बाकी 96 प्रतिशत के बारे में हमें न के बराबर जानकारी है!

जैसा कि बैंग से अर्थ निकलता है कि यह प्रारंभिक विस्फोट बेहद प्रचंड रहा होगा, जिसकी वजह से ब्रह्मांड का तापमान भी बहुत अधिक हो गया होगा। वर्ष 1946 में भौतिक विज्ञानी जार्ज गैमो ने अपनी गणना में पाया था कि जब ब्रह्मांड एक सेकेंड आयु का था, इसका तापमान लगभग 10 अरब डिग्री सेल्सियस था। इतने भीषण तापमान में पदार्थ न तो ठोस अवस्था में रह सकता है और न ही द्रव अवस्था में। इस स्थिति में पदार्थ इलेक्ट्रानों, प्रोटानों, न्यूट्रानों और फोटोन्स की गैसीय अवस्था में था। पार्टिकल एक्सेलेरेटर की सुरंग में परमाणु के प्रोटान कणों या लेड आयनों को अति उग्र ऊर्जा देकर तकरीबन प्रकाश की गति से दौड़ाते हुए आपस में टकराया जाता है। इस टक्कर के फलस्वरूप कणों के भीतर के और भी सूक्ष्म कण बहुत ही कम समय के लिए टूटकर बिखर जाते हैं। इस तरह ऐसे और भी मूलभूत कणों का पता चलता है, जो अज्ञात थे या जिनके अस्तित्व को अभी तक सिद्ध नहीं किया जा सका था।

जर्नल 'फिजिक्स लेटर्स बी' में प्रकाशित अध्ययन पदार्थ की उत्पत्ति के बारे में हमारी समझ को बेहतर बनाती है। यह पहचानने में मदद करती है कि हमारे आसपास का कितना पदार्थ बिग बैंग के बाद सेकेंड के पहले कुछ अंशों में बना, और कितना ब्रह्मांड के विस्तार के बाद की प्रतिक्रियाओं से बना। बहरहाल, वर्तमान पद्धतियों की सीमाओं से आगे बढ़कर, भविष्य के अध्ययनों में विभिन्न कणों के आपसी संबंध तथा ब्रह्मांड को आकार देने में उनकी भूमिका का पता चल सकता है।

(लेखक विज्ञान संचारक हैं)

मेलबाक्स

बांग्लादेश में हिंदुओं पर संकट

'संकट में बांग्लादेशी हिंदुओं का अस्तित्व' शीर्षक से लिखे आलेख में कृपाशंकर चौबे ने उचित ही लिखा कि दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहां किसी न किसी प्रकार के अल्पसंख्यक न मिलें। भाषा, नस्ल, रीति-रिवाज, मान्यताएं, धर्म, जाति के आधार पर ऐसे अल्पसंख्यकों की कुछ न कुछ मौजूदगी रहती ही है। इसका मतलब यह नहीं है कि अल्पसंख्यक आबादी को बहुसंख्यक सहन करने की स्थिति में न हो। अगर ऐसा है तो वह वास्तविक लोकतंत्र के बजाय छद्म लोकतंत्र है। लोकतंत्र तो सहिष्णुता, शांति और सौहार्द का पर्याय है, जो सह-अस्तित्व की संकल्पना को पुष्ट करता है। यही कारण है कि सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति में से एक लोकतंत्र है। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एशिया और अफ्रीका के जिन देशों ने औपनिवेशिक शासन से मुक्ति पाई वहां लोकतंत्र को अपनाया तो गया, लेकिन उसे वास्तविक अर्थों में आत्मसात नहीं किया जा सका। यह सोचने का विषय है कि वास्तविक लोकतंत्र के अनुकूल परिवेश के निर्माण के लिए क्या करने की जरूरत है? साथ ही यह समय भारत सहित समूचे अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए भी बांग्लादेश पर दबाव बनाने का भी है कि वहां हिंदुओं सहित अन्य अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न पर तत्काल विराम लगे।

mukeshkr.m7542@gmail.com

संसदीय मर्यादा का पालन

शुक्रवार को प्रकाशित लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का आलेख ''समय की मांग है संसदीय मर्यादा का पालन'' बहुत ही सटीक और सारगर्भित लगा। संसद के हर सदस्य के लिए संसदीय मर्यादा का पालन का पालन करना अनिवार्य होना चाहिए। तभी संसद और उसके सदस्यों का सम्मान बरकरार रहेगा। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष की निष्पक्षता उसके पद की गरिमा को बनाए रखता है। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पी. ए. संगमा और सोमनाथ चटर्जी ने इसका अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। वर्तमान में कुछ हद तक इस बात की कमी खटक रही है, जिस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

शशि रंजन समदर्शी, हरिद्वार

वक्फ संपत्तियों का सही उपयोग हो

वक्फ अधिनियम में सुधार की चर्चा केवल कानूनी बदलाव नहीं है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और स्थानीय समस्या का समाधान भी है। वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग और अवैध कब्जों की समस्या ने वर्षों से गरीब मुस्लिम समाज को उनके अधिकारों से वंचित रखा है। इस समस्या का समाधान व्यापक और ठोस सुधार के बिना संभव नहीं है। वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि वक्फ अधिनियम में संशोधन किए जाएं। वर्तमान में वक्फ बोर्डों के पास असीमित अधिकार हैं, जिनका कई बार गलत इस्तेमाल होता है। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद द्वारा वक्फ की जमीन पर कब्जा इसका ज्वलंत उदाहरण है। तमिलनाडु में 1,500 वर्ष पुराने मंदिर की जमीन पर वक्फ बोर्ड का दावा यह दर्शाता है कि वक्फ बोर्डों के असीमित अधिकारों का किस प्रकार दुरुपयोग हो सकता है। वक्फ अधिनियम में संशोधन का विरोध करने वाले नेताओं का तर्क है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। लेकिन क्या यही तर्क बिना किसी ठोस प्रमाण के विरोध करने के लिए पर्याप्त है? सरकार का यह दायित्व है कि वह पारदर्शिता से काम करे और वक्फ अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों पर संसद में व्यापक बहस कराए। इससे आम जनता व मुस्लिम समाज में इससे जुड़ी भ्रांतियों का निवारण होगा। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि वक्फ संपत्तियों का सदुपयोग हो और उनकी निगरानी भी मजबूत हो। वक्फ संपत्तियों के सही उपयोग से मुस्लिम समाज के गरीब तबके को वास्तविक लाभ पहुंच सकता है। इसलिए वक्फ अधिनियम में सुधार हो और इसे एक पारदर्शी और जवाबदेह भरी प्रक्रिया के तहत लागू किया जाए। विपक्षी नेताओं को विरोध की राजनीति से बाहर निकलकर समाज की भलाई के लिए व्यावहारिक और तार्किक दृष्टिकोण अपनाना होगा।

अवनीश कुमार गुप्ता, नई दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक- संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

शांति समृद्धि की पहली सीढ़ी है

संसद में चर्चा का स्तर

तय समय से पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित संसद के अंतिम दिन राज्यसभा में सपा सांसद जया बच्चन और सभापति जगदीप धनखड़ के बीच जो तीखी तकरार हुई, वह यही बताती है कि सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच संबंध कितने अधिक कटुतापूर्ण हो गए हैं। सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच कटु संबंध केवल राज्यसभा में ही नहीं, बल्कि लोकसभा में भी देखने को मिल रहे हैं। गत दिवस जया बच्चन सभापति जगदीप धनखड़ से इसलिए नाराज हो गईं, क्योंकि उन्हें उनका लहजा पसंद नहीं आया। उन्होंने उनके लहजे पर आपत्ति जताई तो सभापति ने भी उन्हें मर्यादा में रहने का पाठ पढ़ा दिया। इससे वह आपे से बाहर हो गईं। संसद के भीतर और बाहर उनकी तुनकमिजाजी नई नहीं है। वह कभी अपने आधिकारिक नाम जया अमिताभ बच्चन कहे जाने से चिढ़ जाती हैं और कभी इस पर गर्व करने लगती हैं। इस पर हैरानी नहीं कि विपक्ष ने जया बच्चन का साथ देना बेहतर समझा। उसने न केवल सदन का बहिष्कार कर दिया, बल्कि सभापति को हटाने के लिए प्रस्ताव लाने पर भी विचार करने लगा। इसके जवाब में नेता सदन जेपी नड्डा विपक्ष के आचरण के खिलाफ निंदा प्रस्ताव ले आए। फिलहाल कहना कठिन है कि विपक्ष सभापति को हटाने को लेकर कितना गंभीर है और इस मामले में वह कहां तक जाएगा, लेकिन यह स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में दोनों पक्षों के रिश्तों में और अधिक कड़वाहट घुल सकती है। यह कड़वाहट पहले भी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद वह और अधिक बढ़ गई है। इसका असर संसद के कामकाज पर भी पड़ रहा है। अब संसद में ऐसे सदस्यों की संख्या बढ़ती दिख रही है, जो हंगामा करने की कोशिश में रहते हैं और संसद के नियम-कानूनों और पीठासीन अधिकारी के आदेश-निर्देश की कहीं कोई परवाह नहीं करते। संसद में अब किसी भी विषय पर कठिनाई से ही कोई सार्थक बहस होती है। अधिकांश समय पक्ष-विपक्ष के सदस्य आपस में उलझे रहते हैं। किसी विषय पर धीर-गंभीर चर्चा करने के बजाय वे छींटाकशी करने, मिथ्या आरोप लगाने और एक-दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में रहते हैं। अब तो संसद में अपनी बात कहने के स्थान पर नारेबाजी करने पर अधिक जोर दिया जाने लगा है। कभी-कभी ऐसा लगता है कि यह सब इस कारण अधिक होता है, क्योंकि संसद की कार्यवाही का सीधा प्रसारण होता है। चूंकि संसद में सार्थक चर्चा करने और कराने की कोई ठोस पहल नहीं होती, इसलिए वहां हंगामा और शोर-शराबा ही अधिक होता है। यदि संसद में लोक महत्व के विषयों पर गंभीर चर्चा नहीं होगी तो जनता से यह अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए कि वह उसे अपनी आकांक्षाओं का मंच और लोकतंत्र का मंदिर माने। यह भी तय है कि यदि संसद में सार्थक चर्चा नहीं होगी तो उसका असर विधेयकों की गुणवत्ता पर भी पड़ेगा।

निवेश का सदुपयोग हो

यह सही है कि हर काम वाले हाथ को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती है। इसका विकल्प यह है कि लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए जाएं। इसके लिए उद्योग और छोटे-छोटे कारोबार को बढ़ावा दिया जाता है। अच्छी बात यह है कि राज्य और केंद्र सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है। इसके परिणाम भी आ रहे हैं। अभी नवादा में सीमेंट की एक बड़ी फैक्ट्री का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिलान्यास किया। बताया गया कि इससे साढ़े बारह सौ लोगों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से नौकरी मिल सकती है। रोजगार मिल सकता है। सरकार उद्यमियों को निवेश के लिए प्रोत्साहित कर रही है। उन्हें आधारभूत संरचना सहित अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। यह तो बड़े उद्यमियों की बात हुई। छोटे और कम लागत वाले उद्योगों को बढ़ावा देने की भी सरकार की नीति है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से बड़ी संख्या में छोटे उद्यमियों को पूंजी उपलब्ध कराई जा रही है। जाति आधारित गणना के दौरान राज्य में 94 लाख से अधिक अति गरीबों की पहचान हुई है। सरकार इन परिवारों को भी दो-दो लाख रुपये देने जा रही है। उद्देश्य है कि लोग इस राशि से उद्यम-कारोबार करें। इधर एक बुरी प्रवृत्ति यह उभर कर सामने आ रही है कि लोग सरकारी कर्ज को आमदनी समझ कर खर्च कर रहे हैं। राज्य में यह प्रवृत्ति वर्षों से पनप रही है। हमें समझना होगा कि दूसरे राज्यों में, जहां हम रोजी-रोजगार के लिए जाते हैं, वहां कर्ज को आमदनी समझने की भूल नहीं की जाती है। अगर आज भी हम सतर्क होकर निवेश करें तो कोई कारण नहीं है कि राज्य की बड़ी आबादी को नौकरी या मजदूरी के लिए राज्य के बाहर जाना पड़े।

बुरी प्रवृत्ति यह उभर कर सामने आ रही है कि लोग सरकारी कर्ज को आमदनी समझ कर खर्च कर रहे

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या विनेश फोगाट को संन्यास के अपने फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए?

आज का सवाल
क्या भारत को बांग्लादेश से भाग रहे हिंदुओं को शरण देनी चाहिए?

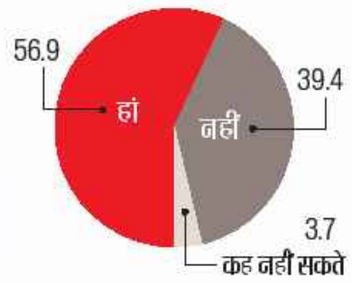

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

पराभव की ओर बढ़ता ब्रिटेन

हर्ष वी. पंत

हालिया दंगे यही दर्शाते हैं कि दुनिया को लोकतांत्रिक मूल्यों पर उपदेश देने वाला ब्रिटेन अपना ही घर दुरुस्त नहीं रख पा रहा है

अवधेश राजपूत

बीते कुछ दिनों के दौरान ब्रिटेन के तमाम हिस्सों में बड़े पैमाने पर दंगे भड़क गए। दंगों की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन पर काबू पाने में करीब सप्ताह भर का समय लग गया। सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी और तमाम कड़े कदम उठाने के बावजूद स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। पता नहीं कहां विवाद की छोटी सी चिंगारी किसी विकराल दंगे का रूप धारण कर ले। हालिया प्रकरण 29 जुलाई को एक नृत्य कार्यक्रम के बाद शुरू हुआ। उत्तरी इंग्लैंड के साउथपोर्ट में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान तीन बच्चियों की हत्या कर दी गई। जबकि कुछ अन्य घायल हो गए। हमलावर के बारे में इंटरनेट मीडिया पर यह अफवाह उड़ी कि वह मुस्लिम समुदाय से जुड़ा है, जो ब्रिटेन में शरण पाने वाला एक अप्रवासी है। इसके बाद मुस्लिम समुदाय और अप्रवासी स्थानीय लोगों के निशाने पर आ गए। हालांकि बाद में यह स्पष्ट हुआ कि 17 वर्षीय मुख्य हमलावर एक्सल रुदाकुबाना वेल्स में ही पैदा हुआ है, जिसके माता-पिता रवांडा से ब्रिटेन आए थे। जब तक तस्वीर साफ होती, उससे पहले ही लोगों ने साउथपोर्ट में एक मस्जिद को निशाना बनाने का प्रयास किया।

हमलावर भले ही पकड़ लिया गया हो, मगर इस मामले ने ब्रिटिश लोगों को भड़का दिया। आक्रोशित भीड़ ने रादरम में उस होटल पर भी हमला बोला, जिसमें राजनीतिक शरण मांगने वालों को रखा जाता है। इतना ही नहीं, लिवरपूल, ब्रिस्टल, मैनचेस्टर और ब्लैकपूल में भी हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। ऐसे करीब 20 वाकयों में कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। इस प्रकार के हिंसक प्रदर्शन भले ही एक तात्कालिक प्रतिक्रिया हों, लेकिन इसकी सुगबुगाहट ब्रिटिश समाज में काफी पहले से महसूस की जा रही थी। यही कारण है कि सरकार संवेदनशील वर्गों को लेकर सक्रिय हुई है। मिसाल के तौर पर अप्रवासी मामलों को देखने वाले वकीलों की सुरक्षा को लेकर भी उठते सवालों पर ध्यान दिया जा रहा है। देखा जाए तो सतही तौर पर कानून एवं व्यवस्था से संबंधित दिखने वाले इस मामले की जड़ें अप्रवास विरोध और ब्रिटिश समाज में गहराती विभाजक रेखाओं से जुड़ी हैं। आने वाले दिनों में इसके और घातक परिणाम देखने को मिल सकते हैं।

अप्रवासियों को लेकर ब्रिटेन में पिछले कुछ समय से असंतोष बढ़ रहा है। तमाम ब्रिटिश नागरिक ऐसा सोचते हैं कि अप्रवासियों की बढ़ती संख्या के चलते हाउसिंग, शिक्षा, और स्वास्थ्य से जुड़ी सरकारी कल्याणकारी योजनाओं में उनके हितों में सेंधमारी हो रही है। उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन में यूरोपीय संघ से अलग होने वाले ब्रेक्जिट अभियान को भी इसी पहलू के चलते सफलता मिली थी कि इससे अप्रवासियों पर अंकुश लगाने के साथ नीति-निर्माण में ब्रिटिश स्वायत्तता बढ़ेगी। हालांकि कंजरवेटिव पार्टी ने अप्रवासियों के चलते पनप रहे असंतोष पर काबू पाने के लिए कुछ उपाय जरूर किए, लेकिन लगता नहीं कि ब्रिटिश जनता उन उपायों से संतुष्ट हुई होगी। हालिया चुनावों में लेबर पार्टी की जीत ने भी इस मामले में उन दक्षिणपंथी समूहों को भावनाएं भड़काने की गुंजाइश दी होगी, जिन्हें ब्रिटिश प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर बीते दिनों हुए दंगों का दोषी ठहरा रहे हैं। ऐसी धारणा है कि लेबर पार्टी अप्रवासियों के प्रति अपेक्षाकृत नरम रवैया रखती है।

प्रधानमंत्री स्टार्मर ने कहा है कि दंगाइयों से निपटने के हरसंभव सख्त उपाय किए जाएंगे, लेकिन दंगों की आग पर काबू पाने में करीब सप्ताह भर का समय लगना अपने आप में काफी कुछ कह देता है। शासन-प्रशासन के स्तर पर आश्वासन के बावजूद हालात इतने बिगड़ गए कि लोगों को अपनी एवं अपने आवास और प्रतिष्ठान की सुरक्षा के लिए निजी स्तर पर भी कदम उठाने पड़ रहे हैं, क्योंकि हिंसा के दौरान तमाम दुकानों एवं प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। स्टार्मर ने जिन धुर दक्षिणपंथी संगठनों को इस हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया है, उनमें इंग्लिश डिफेंस लीग का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। वर्ष 2009 में अस्तित्व में आया यह संगठन अप्रवासी विरोध विशेषकर इस्लाम के खिलाफ अपने रुख के लिए जाना जाता है। पूर्व में हुई हिंसा में भी इसका नाम आता रहा है। हालांकि यह ऐसा कोई इकलौता संगठन नहीं है। मुख्यधारा की राजनीति में भी यूके रिफार्म पार्टी के नेता नाइजल फराज ने अप्रवासियों और शरणार्थियों की भड़ती भीड़ को हालिया हिंसा के लिए आड़े हाथों लिया। एक समय कंजरवेटिव पार्टी में रहे फराज ने अपनी आक्रामक राजनीति के लिए नए राजनीतिक दल का गठन किया। हालिया चुनावों में उनकी पार्टी को भले ही चार सीटें मिली हों, लेकिन कई सीटों पर वह कंजरवेटिव पार्टी की हार का कारण भी बने। उनके प्रति लामबंद होता समर्थन ब्रिटिश जनता के सोच में आ रहे बदलाव को दर्शाता है, जिसकी समय-समय पर आक्रामक अभिव्यक्ति भी देखने को मिलती रहती है। हाल के दंगे ऐसा ही एक उदाहरण रहे। हालिया दंगे दर्शाते हैं कि ब्रिटिश समाज में निराशा बढ़ रही है। उन्हें अप्रवासियों से अपने अवसरों पर आघात के साथ ही अपनी मूल सांस्कृतिक पहचान पर संकट भी दिख रहा है। चूंकि मुस्लिम समुदाय भी अपने प्रतीकों को लेकर खासा मुखर रहता है तो उसके साथ टकराव कुछ ज्यादा बढ़ रहा है।

दंगों के बाद प्रधानमंत्री स्टार्मर ने ऐसा आश्वासन दिया कि यह जिनका भी किया-धरा है, उन्हें इसकी सजा जरूर भुगतनी होगी। कानून उन पर अपना शिकंजा कसेगा। कई मामलों में दंगाइयों पर ऐसी धाराएं भी लगाई गई हैं, जो आतंकी मामलों में लगाई जाती हैं। इंटरनेट मीडिया के जरिये फर्जी सूचनाओं के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए भी कमर कसी गई है। इस सबके बावजूद कुछ सवाल जरूर उठते हैं। पहला यही कि क्या यह एक तात्कालिक आक्रामक प्रतिक्रिया थी या फिर ब्रिटेन में यह एक नया सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि वहां अब समय-समय पर दंगे भड़कते रहते हैं। इससे पूर्व भी दो साल पहले लेस्टर में दंगे भड़के थे। दूसरा सवाल यह कि दुनिया को लोकतांत्रिक मूल्यों पर उपदेश देने वाला ब्रिटेन अपना ही घर दुरुस्त क्यों नहीं रख पा रहा है? जो भी हो, इन दंगों ने ब्रिटेन की साख चोट करने के साथ ही उसके पराभव के भी संकेत दिए हैं।

(लेखक आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में उपाध्यक्ष हैं)

response@jagran.com

जीवन के चौथेपन में टूटते रिश्ते

क्षमा शर्मा

इन दिनों विवाह के दशकों बाद पति-पत्नी का अलग हो जाना एक नया चलन बनता जा रहा है

बढ़ रहे हैं अधिक उम्र में तलाक के मामले ● प्रतीकात्मक

https://t.me/AllNewsPaperPaid

बहुत समय से एक नामचीन नायक-नायिका के तलाक की खबरें इंटरनेट मीडिया पर छाई हुई हैं। लोग दावा कर रहे हैं कि बस ऐसा होने ही वाला है। सच क्या है, कहा नहीं जा सकता, लेकिन ग्रे डाइवोर्स यानी कि विवाह के दशकों बाद पति-पत्नी का अलग हो जाना, इन दिनों बेहद चलन में है। महिलाएं कह रही हैं कि एक खराब रिश्ते में जीवन बिताने से अच्छा है कि जब मौका मिले, अलग हो जाएं। इस लेखिका ने कई स्त्रियों को खुद देखा है। कई साल पहले यह लेखिका जिस संस्थान में काम करती थी, वहां एक महिला आई। उसे काम चाहिए था। उसकी उम्र उस समय 50 वर्ष रही होगी। उसका कहना था कि पति बहुत तंग करते हैं। सुबह शाम मार-पीट, हर रात शराब पीकर आना है। वह महिला उच्च शिक्षित भी थी, लेकिन नौकरी नहीं करती थी। वह सब कुछ इतने साल इसलिए सहन करती रही कि अपने बेटे के बड़े होने का इंतजार कर रही थी। अब वह अपने पांवों पर खड़ा होना चाहती थी। उसी समय के आसपास एक वरिष्ठ महिला पत्रकार ने अपने बहुत मशहूर पति से अलग होने पर पार्टी दी थी और अपनी आजादी का जश्न मनाया। यह कोई नई-अनोखी बात नहीं कि अब तलाक की भी पार्टी होने लगी हैं। लोग उसका जश्न मनाने लगे हैं।

ग्रे डाइवोर्स का अर्थ बताया जाता है कि जब पति-पत्नी 50 की उम्र के बाद अलग हों यानी जब बालों में सफेदी छाने लगे। हालांकि जो लोग ऐसा करते हैं, उनकी राह भी आसान नहीं होती। बहुत बार जमीन-जायदाद का फैसला करना मुश्किल हो जाता है, जो संयुक्त होती है या बैंक खाते संयुक्त होते हैं। इसके अलावा बड़े बच्चे भी माता-पिता के इस तरह से अलग होने को सह नहीं पाते। कई बार बच्चे माता-पिता को इसके लिए प्रेरित भी करते हैं। एक लड़के ने जीवन भर अपनी मां को पिता के हाथों प्रताड़ित होते देखा। बड़े होने पर उसने मां से कहा कि इतना अपमान सहने से बेहतर है कि वे दोनों अलग हो जाएं। फिल्मी दुनिया में भी जहां अक्सर पति-पत्नी एक खुशहाल परिवार की तस्वीर पेश करते हैं, वहां भी ऐसा हो रहा है। इसमें फरहान अख्तर-अधुना भबानी, अरबाज खान-मलाइका अरोड़ा, ईशा देओल-भरत तख्तानी, सोनम खान-राजीव राय, किरण राव-आमिर खान, रितिक रोशन-सुजैन खान, अर्जुन रामपाल-मेहर जेसिया जैसे जोड़े शामिल हैं। इन सबके बड़े-बड़े बच्चे भी हैं।

किरण राव ने कुछ दिनों पहले साक्षात्कार में कहा था कि आमिर से उनके संबंध बहुत मधुर हैं। तलाक ने उन्हें आजादी दी है। वह खुद के महत्व को पहचानना चाहती थीं। अपने तलाक पर अर्जुन रामपाल ने इससे बिल्कुल अलग बात की। उन्होंने कहा था कि तलाक बहुत आसान नहीं होता। यह आपके अकेलेपन को बढ़ाता है। जितने भी फिल्मी जोड़े एक-दूसरे से अलग हुए हैं, वे अपने पूर्व साथी के बारे में अच्छी बातें करते हुए यह भी कहते हैं कि वे दोनों सबसे अच्छे दोस्त हैं। फिल्मकार अनुराग कश्यप जब कल्कि कोचलीन से अलग हुए तो कुछ दिन बाद उन्होंने कहा था कि जब वे दोनों साथ थे, तो हमेशा लड़ते रहते थे, मगर अब दोनों में खूब मित्रता है। कश्यप इससे पहले भी अपनी पत्नी से अलग हो चुके थे। बहरहाल, ये जोड़े यह भी कहते हैं कि जिस साथी से अलग हुए, वह बहुत अच्छा इंसान है। क्या यह सोचकर आश्चर्य नहीं होता कि यदि कोई इतना अच्छा इंसान और मित्र है, तो फिर अलग क्यों होना पड़ा? शायद इसका जवाब किसी के पास नहीं होता।

प्यू रिसर्च ने अमेरिका में ग्रे डाइवोर्स पर एक अध्ययन किया। इसमें बताया गया कि पिछले दो दशकों में तलाक के सारे मामलों में 40 प्रतिशत मामले ऐसे थे, जिनमें 50 और उससे ऊपर के जोड़े शामिल थे। 1990 के बाद इनकी संख्या दोगुनी हो गई और अब जो लोग 65 से ऊपर हैं, उनकी संख्या तिगुनी हो गई है। विशेषज्ञ कहते हैं कि जब तक लोग अपने बच्चों को पालते हैं, तब तक वे किसी तरह साथ रह लेते हैं, मगर जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं, उनका अपना घर और परिवार होता है, तो पति-पत्नी को लगता है कि अब उन्हें एक-दूसरे की जरूरत नहीं रही। इसके अलावा अपने देश में स्त्रियों के प्रति जो हिंसा है, उसे शायद वह बच्चों के कारण झेलती रहती हैं, लेकिन आज की स्त्रियां पांच दशक पहले की स्त्रियां नहीं हैं, जो किसी भी बुरे संबंध को समाज के डर से निभा लेती थीं। आज वे पहले की तरह से अपने पति पर निर्भर नहीं हैं। निर्णय लेने की उनकी क्षमता बढ़ी है। इसलिए वे भी तलाक की पहल करती हैं और बुरे रिश्ते से आजादी चाहती हैं, लेकिन यह बात भी सच है कि बच्चों पर इसका बुरा असर पड़ता है। मेरे दफ्तर आई उसी महिला के लड़के ने एक बार कहा था कि आप ही बताइए, मैं किधर जाऊं। मुझे तो अपने माता-पिता दोनों से प्यार है। मैं एक से मिलने जाता हूं तो दूसरा बुरा मानता है।

हालांकि इस मामले में फिल्मी दुनिया के लोग अक्सर अपने बच्चों पर इस तरह का प्रतिबंध नहीं लगाते। जब वे अलग होते हैं तो कहते हैं कि अपने बच्चों के लिए वे दोनों हमेशा, हर स्थिति में मौजूद रहेंगे, लेकिन आम लोगों की दुनिया में ऐसा नहीं हो पाता। कड़वाहट इतनी ज्यादा होती है कि वे एक-दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। यह भी देखा गया है कि बहुत से जोड़े अलग होने के बाद फिर से साथ रहने लगते हैं। इसके पीछे यह सच भी है कि जीवन के चौथेपन में आपको साथी और साहचर्य भाव की जरूरत सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि बच्चे अपनी-अपनी राह चले गए होते हैं। शायद इसीलिए कुछ लोग वापस लौटकर अपना जीवन फिर से शुरू करते हैं।

(लेखिका साहित्यकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

अध्यात्म से उत्थान

हमारे मनीषियों ने आध्यात्मिकता का अपेक्षित प्रसार एवं महिमामंडन किया है। यही कारण है कि भौतिक शक्ति के युग में पाले-पोसे हुए हम ही नहीं, अपितु विदेशी भी संयम, साधना और आराधना के कठोर एवं कठिन मार्ग की ओर आकर्षित हो रहे हैं। अध्यात्म जगत का आकर्षण है ही कुछ ऐसा अद्भुत जो हमें सिखाता है कि जब मन-मस्तिष्क विषय रूपी वन में स्वच्छंद विचरण करना चाहता है तो उस पर ज्ञान का अंकुश लगाकर रोकें। कान जब सहज सुंदर सुर बालाओं के मधुर संगीत की स्वर लहरी सुनने के लिए उत्सुक हों तब विवेक से उन पर अधिकार करें। नेत्र आधुनिक अप्सराओं के मनमोहक दृश्य देखने के लिए जब छटपटाने लगें तब विचारों के अंकुश से उन पर लगाम लगाएं। नाक अपनी हठधर्मिता पर अड़कर प्राकृतिक पुष्पों की सुगंध सौरभ लेने के बजाय इत्र की कृत्रिम गंध के लिए उतावली हो तो अपने चिंतन की धारा से उसका प्रवाह बदल दें। काया जब-जब सुकोमल पदार्थों के संस्पर्श के लिए इच्छुक हो तो अपने सम्यक ज्ञान से उसे वश में करें। यह सब कुछ इसलिए कि मन और इंद्रियों का प्रवाह विकारों की ओर होता है और जब तक उसे मोड़ा नहीं जाएगा तब तक हमारे जीवन का उद्धार संभव नहीं।

मानव ने विज्ञान के भरोसे संसार पर विजय पताका फहराई है, किंतु अगर वह मन की मलिन वृत्तियों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता तो यह विजय उसकी सच्ची विजय नहीं है। केवल विजय का आभास मात्र है। मृगमरीचिका की भांति वह विशुद्ध भ्रम है। स्मरण रहे कि हमारा मन बहुत शक्तिमान है। वही इच्छाओं-आकांक्षाओं के रथ का सारथी भी है। बिना पंख का पक्षी है, किंतु हमारी आत्मशक्ति मन से भी अधिक बलवान है। हम चाहे तो अभ्यास और साधना से मन को हर कुमार्ग से सन्मार्ग की ओर उत्प्रेरित कर सकते हैं। अशुभ चिंतन को छोड़कर शुभ चिंतन करना ही वस्तुतः श्रेय का मार्ग है। प्रशस्त मन उत्थान का कारण है और अप्रशस्त मन पतन का निमित्त बनता है।

डा. निर्मल जैन

पाठकनामा

pathaknama@pat.jagran.com

बांग्लादेश में हिंदुओं पर संकट

'संकट में बांग्लादेशी हिंदुओं का अस्तित्व' शीर्षक से लिखे आलेख में कृपाशंकर चौबे ने उचित ही लिखा कि दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहां किसी न किसी प्रकार के अल्पसंख्यक न मिलें। भाषा, नस्ल, रीति-रिवाज, मान्यताएं, धर्म, जाति के आधार पर ऐसे अल्पसंख्यकों की कुछ न कुछ मौजूदगी रहती ही है। इसका मतलब यह नहीं है कि अल्पसंख्यक आबादी को बहुसंख्यक सहन करने की स्थिति में न हो। अगर ऐसा है तो वह वास्तविक लोकतंत्र के बजाय छद्म लोकतंत्र है। लोकतंत्र तो सहिष्णुता, शांति और सौहार्द का पर्याय है, जो सह-अस्तित्व की संकल्पना को पुष्ट करता है। यही कारण है कि सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति में से एक लोकतंत्र है। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एशिया और अफ्रीका के जिन देशों ने औपनिवेशिक शासन से मुक्ति पाई वहां लोकतंत्र को अपनाया तो गया, लेकिन उसे वास्तविक अर्थों में आत्मसात नहीं किया जा सका। यह सोचने का विषय है कि वास्तविक लोकतंत्र के अनुकूल परिवेश के निर्माण के लिए क्या करने की जरूरत है? साथ ही यह समय भारत सहित समूचे अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए भी बांग्लादेश पर दबाव बनाने का भी है कि वहां हिंदुओं सहित अन्य अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न पर तत्काल विराम लगे।

mukeshkr.m7542@gmail.com

कौशल विकास की चुनौती

संपादकीय आलेख युवाओं में कौशल विकास की चुनौती पढ़ा। लेखक ने उचित बिंदुओं पर ध्यानाकर्षण किया। यह सही है कि भारत में रोजगार की नहीं, बल्कि कुशल श्रमिकों की कमी है। बढ़ती श्रमशक्ति और कुशल श्रमिकों की मांग एवं आपूर्ति में संतुलन की दृष्टि से पांच वर्षों में देश की 500 दिग्गज कंपनियों द्वारा एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करना एक बाजी पलटने वाली योजना सिद्ध हो सकती है, लेकिन तभी जब कंपनियां इस योजना में रुचि दिखाएं। इस योजना में 5,000 रुपये के मासिक भत्ते और 6,000 रुपये की एकमुश्त सहायता आकर्षक पहलू हैं। इसके माध्यम से सरकार का उद्देश्य पांच वर्षों में 20 लाख लोगों को कौशल प्रदान करना है। उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण प्रदान करने के साथ ही हर साल एक लाख छात्रों को सीधे ऋण राशि के तीन प्रतिशत ब्याज में छूट भी मिलेगी। कौशल विकास पर विशेष ध्यान देने के लिए 1000 आइटीआइ को और अधिक सक्षम एवं सशक्त बनाया जाएगा। उद्योगों की कौशल संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप ही विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा, जिससे नई उभरती हुई जरूरतों के साथ सामंजस्य स्थापित किया जा सके। रोजगार सृजन के लिहाज से महत्वपूर्ण एमएसएमई और विनिर्माण क्षेत्र में श्रम प्रधान तकनीक भी सरकार की प्राथमिकता सूची में शामिल है। एमएसएमई क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने एवं उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार के लिए ऋण गारंटी योजना प्रारंभ करने के साथ-साथ इस क्षेत्र के डिजिटलीकरण पर जोर देने से इस क्षेत्र को संजीवनी मिलने के आसार हैं। एमएसएमई क्षेत्र में 50 मल्टी प्रोडक्ट्स फूड इकाइयां स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता भी सराहनीय है। कौशल विकास के क्षेत्र में रोजगार की प्रबल संभावनाएं हैं। इस दिशा में सरकार आगे बढ़ी है।

राकेश सिंह, आरा

बांग्लादेश में अराजकता

बांग्लादेश में पिछले एक साल में हालात बहुत तेजी से बदले। आरक्षण विरोध वास्तव में आरक्षण को लेकर नहीं था। इसे इससे समझा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण को घटाकर दो प्रतिशत करने के बावजूद प्रदर्शन नहीं रुके। कोर्ट द्वारा आरक्षण का मुद्दा सुलझाने के बावजूद प्रदर्शन और उग्र हो गए। प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग की जाने लगी। इन प्रदर्शनों के दौरान ही हिंदू अल्पसंख्यकों के धर्म स्थलों और घरों पर व्यापक हमले भी शुरू हो गए। बड़ी बात नहीं कि विरोध प्रदर्शनों के पीछे अमेरिकी एजेंसियों और इस्लामी कट्टरपंथियों का गठजोड़ भी काम कर रहा हो और जिसका उद्देश्य शेख हसीना सरकार का तख्तापलट करना हो। यह इससे लगता है कि शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के राष्ट्रपिता माने जाने वाले शेख मुजीब से जुड़े स्मृति चिह्नों को निशाना बनाना शुरू किया। शेख हसीना सरकार अपदस्थ होने के बाद बांग्लादेश घोर हिंसा और अराजकता में डूब गया है। इस्लामिक कट्टरपंथी अवामी लीग के नेताओं-समर्थकों और हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं। बांग्लादेश जब 1971 में बना था, तब वहां हिंदू जनसंख्या 22 प्रतिशत थी जो आज घटकर 7-8 प्रतिशत के बीच रह गई है। आज भी बांग्लादेश में 1.3 करोड़ हिंदू रहते हैं। उनका अस्तित्व खतरे में है। शेख हसीना के जाने के बाद भी सेना ने हिंदुओं की हत्याओं को रोकने के लिए कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की है।

अशोक कुमार, पटना

X पोस्ट

हाकी में नवीन पटनायक का योगदान विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा है और इसका प्रत्यक्ष प्रभाव 2020 और 2024 ओलिंपिक खेलों में भारत के कांस्य पदक जीतने के रूप में स्पष्ट दिखा। मरूकांतार@marukantaar

मैं फिर से कहना चाहूंगा कि नीरज चोपड़ा ट्रैक एंड फील्ड में भारत के सर्वकालिक महानतम एथलीट हैं। एक स्वर्ण और उसके बाद उनका रजत पदक कई पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। शेखर गुप्ता@ShekharGupta

नीरज गोल्ड से चूके नहीं, बल्कि उन्होंने सिल्वर जीता है। यह उनका दूसरा बेस्ट सीजन थ्रो था। अरशद नदीम का थ्रो उनसे बेहतर था, इसलिए वह गोल्ड जीते। चूकने जैसे शब्द से किसी की मेहनत पर पानी न फेरें। सिल्वर कोई रसगुल्ला नहीं कि कोई भी गटक ले। खिलाड़ी भी मनुष्य हैं। अणु शक्ति सिंह@AnushaktiSing

हमें नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए में 2014 की कट आफ डेट बदलनी होगी, ताकि बांग्लादेश में सताए जा रहे हिंदू भी भारत आ सकें। अगर मोदी और शाह ने ऐसा नहीं किया तो वह प्रताड़ित बांग्लादेशी हिंदुओं की कभी मदद नहीं कर पाएंगे। इस मामले में निष्क्रियता का यही अर्थ होगा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार को आप मौन सहमति दे रहे हैं। आर. जगन्नाथन@TheJaggi

जनपथ

बाबर लाया लादकर शायद साथ जमीन,
वही वक्फ में दर्ज है लोग रहे हैं छीन!
लोग रहे हैं छीन तभी होता हंगामा,
संसद में भी खूब चल रहा इस पर ड्रामा।
सदियों से हैं आप हिंद की ही धरती पर,
बसा सोच में किंतु वही आक्रांता बाबर!!

- ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व.पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त
जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प. बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073
E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 25 अंक 120

****

प्रवाह

महोत्सव विश्वास का 75
निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

कुछ दशकों में भारत और चीन नाटकीय और गतिशील प्रतिस्पर्धी के रूप में उभरे हैं। -पीटर मैंडेलसन

ऐसे वक्त में जब तमाम विकसित देश नीतिगत दरों में बदलाव ला रहे हैं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों को लगातार नौवीं बार अपरिवर्तित रखना अप्रत्याशित नहीं है। दरअसल, केंद्रीय बैंक महंगाई और विकास दर में तालमेल बैठाते हुए आगे बढ़ना चाहता है, ताकि आम आदमी पर बोझ न बढ़े।

महंगाई और विकास

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा खाद्य महंगाई से जुड़े जोखिमों का हवाला देते हुए लगातार नौवीं बार नीतिगत दरों को अपरिवर्तित रखना अप्रत्याशित नहीं है, लेकिन इससे वर्तमान आर्थिक परिदृश्य की अनिश्चितता के संकेत जरूर मिलते हैं। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय बैंक अमूमन रेपो दर में बढ़ोतरी कर महंगाई से लड़ने का प्रयास करता है। रेपो दर अधिक होने पर बैंकों को केंद्रीय बैंक से महंगा कर्ज मिलता है और बदले में बैंक भी ग्राहकों को महंगी दर पर कर्ज देते हैं। इससे अर्थव्यवस्था में तरलता कम होती है और लोगों की जेब हल्की होने से वस्तुओं की मांग में कमी आती है। मांग कम होने से बिक्री भी कम हो जाती है और महंगाई में भी कमी आती है। इसके विपरीत, विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए बाजार में तरलता बढ़ाने की कोशिश की जाती है। इसके लिए रेपो दर में कटौती की जाती है, ताकि बैंकों को केंद्रीय बैंक से और आम आदमी को बैंकों से सस्ता कर्ज मिल सके। लेकिन, एमपीसी ने नीतिगत दर साढ़े छह फीसदी के स्तर पर बनाए रखते हुए स्पष्ट किया है कि वर्तमान परिस्थितियों में उदारता नहीं बरती जा सकती। अनाज, दालें और सब्जियों जैसी खाद्य श्रेणियों में मुद्रास्फीति ऊंची बनी हुई है। हालांकि, मुख्य मुद्रास्फीति, जिसमें अस्थिर खाद्य और ईंधन घटकों को शामिल नहीं किया गया है, अब तक कम बनी हुई है। मई और जून में तो यह 3.1 फीसदी के ऐतिहासिक निचले स्तर पर थी। लेकिन अगर बढ़ती खाद्य महंगाई का असर इस पर पड़ा, तो यह अवश्य ही चिंता की बात होगी। उल्लेखनीय है कि रिजर्व बैंक ने ऐसे वक्त में नीतिगत दरों को अपरिवर्तित रखा है, जब इंग्लैंड, जापान और अमेरिका सहित तमाम विकसित देशों के केंद्रीय बैंक नीतिगत दरों में बदलाव ला रहे हैं। लेकिन रिजर्व बैंक का यह कहना महत्वपूर्ण है कि खाने-पीने की चीजों की बढ़ती महंगाई को अनदेखा नहीं किया जा सकता और इसके दूसरे क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभाव को रोकने की भी जरूरत है। हालांकि केंद्रीय बैंक का यह कहना आश्वस्तकारी है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून में तेजी से खाद्य महंगाई में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। दरअसल महंगाई को लेकर के बैंक के संवेदनशील रुख को समझा जा सकता है, जिसके रेपो दर में बदलाव न करने के फैसले से संकेत मिलता है कि वह महंगाई और विकास दर में तालमेल बैठाते हुए आगे बढ़ना चाहता है, ताकि आम आदमी पर महंगाई का बोझ न बढ़े और अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक स्थिरता भी मिल सके।

चीन पर काबू रखना जरूरी है

ढाका में शेख हसीना के पतन से चीन को खुला मैदान मिल गया है। ऐसे में, भारत को सुनिश्चित करना होगा कि 'पड़ोसी पहले' की उसकी नीति नए भू-राजनीतिक बदलावों के साथ तालमेल में हो। साथ ही, चीन को काबू में रखने के लिए भारत और अमेरिका को भी संयुक्त रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा।

केएस तोमर
राजनीतिक विश्लेषक

ढाका में शेख हसीना शासन के पतन और उसके अंतरराष्ट्रीय प्रभाव को देखते हुए चीन का मुकाबला करने के लिए भारत एवं अमेरिका को एक संयुक्त रणनीति बनाने की सख्त जरूरत है, जिसने पहले ही अपनी विस्तारवादी नीति के जरिये हमारे अधिकांश पड़ोसियों को फंसा लिया है और बांग्लादेश उस सूची में शामिल होने वाला एक नया नाम है।

विदेश नीति के विशेषज्ञों का मानना है कि पारस्परिक हित और बाध्यता के सिद्धांत के कारण भारत और अमेरिका को बांग्लादेश के प्रति अपनी मौजूदा नीति में बदलाव लाना होगा, जो चीन और पाकिस्तान की राह पर चल रहा है और जिससे दक्षिण एशिया में सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना आरोप लगा रही हैं कि उनकी सरकार को अस्थिर करने में अमेरिका का हाथ रहा है। लेकिन भारत बांग्लादेश की नई सरकार से अलग-थलग नहीं रह सकता है, जिसका नेतृत्व वही खालिदा जिया कर सकती हैं, जो खुद को भारत-विरोधी खेमे का मानती हैं।

ढाका की नई सरकार पर खालिदा जिया और कट्टरपंथी हावी हो सकते हैं, जिससे भारत के लिए सिरदर्द पैदा हो सकता है। अमेरिका को हसीना शासन के निष्कासन से खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे चीन मजबूत होगा, जो महाशक्ति देश के रूप में अमेरिका की जगह लेना चाहता है। इसलिए अमेरिका को भारत की मदद से चीन का मुकाबला करने की जरूरत है, क्योंकि भारत विश्व मंच पर आर्थिक ताकत के रूप में उभर रहा है। साथ ही भारत को चीन के बढ़ते प्रभाव पर नजर रखनी होगी, जिसने पहले ही मालदीव, नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान और श्रीलंका तक को अपने पाले में मिला लिया है। बांग्लादेश भी उसके पिछलग्गू बन सकते हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि चीन का मुकाबला करने के लिए भारत को अपने 'पड़ोसी पहले' की नीति में भू-राजनीतिक बदलाव की जरूरत है। चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर तनाव पैदा किया है और भारत को कमजोर करने के लिए भारत विरोधी ताकतों को बढ़ावा दिया है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करता है। लेकिन कई क्षेत्रों में अमेरिका की करीबी देखते हुए उस पर भरोसा किया जा सकता है, जो पारस्परिक विश्वास और लाभ के सिद्धांत पर आधारित होगा। आलोचकों का मानना है कि भारत को अपनी विदेश नीति में भारी बदलाव लाने की जरूरत है, अन्यथा चीन हावी हो सकता है, जो बीआरआई के जरिये हरेक देश में भारत विरोधी ताकतों की मदद करता है, जैसा कि बांग्लादेश में दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश के संदर्भ में भारत हसीना की सत्तारूढ़ अवामी लीग के साथ ही काम करने में विश्वास करता रहा और संभावित विपक्ष खालिदा की बीएनपी को नजर अंदाज करता रहा। अब हसीना विरोधी ताकतें ढाका में सत्ता में आई हैं, जो भारत को दुश्मन समझती हैं। अगर भारत ने बीएनपी के साथ अच्छे संबंध बनाए होते, तो पाकिस्तान की आईएसआई और चीन पर अंकुश लगाया जा सकता था।

भारत और बांग्लादेश के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर बातचीत चल रही थी, क्योंकि यह दोनों देशों के व्यापार के लिए जरूरी है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2023-24 के दौरान 13 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। लेकिन अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के शासन में एफटीए का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। हालांकि ढाका की नई सरकार एफटीए चर्चा को बीच में ही छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकती, क्योंकि इससे दोनों देशों के लोगों के हितों को नुकसान होगा। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि यह समझौता जरूर होगा। राजनीतिक संकट के कारण लगभग 30 करोड़ डॉलर का निर्यात व्यापार प्रभावित हुआ है, खासकर तब, जब भारत हर दिन बांग्लादेश को तीन करोड़ डॉलर का सामान निर्यात करता है। भारत का आयात जारी है, लेकिन निर्यात रुका हुआ है, जिसका समाधान अंतरिम सरकार को करना होगा, ताकि हर दिन बढ़ने वाले घाटे को रोका जा सके। बांग्लादेश हर दिन करीब 15 ट्रक मछली निर्यात करता था, जो अब घटकर एक ट्रक रह गया है। बांग्लादेश के कस्टम विभाग ने सैकड़ों भारतीय ट्रकों को बांग्लादेश में घुसने की मंजूरी नहीं दी है, जो पार्किंग में खड़े हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरिम सरकार के नए मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस और अंतरिम सरकार को प्राथमिकता के आधार पर इन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। भारत विरोधी अभियान के जरिये सत्ता में आए मालदीव के नए राष्ट्रपति मोइज्जू के शासन में मालदीव का झुकाव चीन की तरफ हो गया है। मोइज्जू ने खुलेआम चीन की प्रशंसा की, जिसने उन्हें चुनाव में मदद की थी। लगभग यही स्थिति नेपाल की है, क्योंकि भारत ने नेपाली कांग्रेस का समर्थन किया और कम्युनिस्ट सरकारों की उपेक्षा की, जिससे वे भारत विरोधी बन गए।

1990 के दशक में छह वर्ष तक नेपाल में रहने के दौरान मैंने देखा है कि चीनी दूतावास ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को गुप्त रूप से भौतिक प्रलोभन के जरिये खुश रखा, जो सत्ता में आने पर उनके लिए फलदायी साबित हुए। चीन समर्थक और भारत विरोधी केपीएस ओली नेपाली कांग्रेस के साथ गठबंधन सरकार के प्रमुख हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि नेपाली कांग्रेस ओली को भारत विरोधी रुख त्यागने के लिए मजबूर कर सकती है।

इसी प्रकार की नीति भारत ने श्रीलंका में भी अपनाई थी। लेकिन जब श्रीलंका का आर्थिक रूप से पतन हो गया, तो भारत ने श्रीलंका की मदद की। नतीजतन भारत वहां के आम लोगों का चहेता बन गया है, जो नई दिल्ली द्वारा मुश्किल वक्त में दी गई वित्तीय सहायता की सराहना करते हैं, जबकि चीन ने खुद को इससे दूर रखा। हालांकि म्यांमार में भारत ने सैन्य शासन के साथ संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है। इसलिए भारत और अमेरिका को संयुक्त रूप सेएक कार्ययोजना बनानी होगी, जिसमें रणनीतिक साझेदारी मजबूत करना, क्वाड सहयोग बढ़ाना, व्यापार एवं बुनियादी ढांचे के विकल्प को बढ़ावा देना, संयुक्त सैन्य अभ्यास को विस्तार देना, प्रौद्योगिकी पर सहयोग देना, कूटनीतिक रूप से सहयोग करना, विकास कार्यों के लिए सहायता देना, गलत सूचनाओं के प्रसार को रोकना और एशिया में संप्रभुता का समर्थन करना शामिल है, जिसका उद्देश्य सार्क देशों में चीन के प्रभाव को कम करना और एक स्वतंत्र, मुक्त हिंद-प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करना है।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

आरके नारायण

अकेलेपन और अलगाव से कोई मुक्ति नहीं है। यह एक निरंतर गति है, यह नियम उसी क्षण लागू हो जाता है, जब हम अपनी मां के गर्भ से खुद को अलग कर लेते हैं। अकेलापन ही जीवन का एकमात्र सत्य है।

अकेलापन ही सच्चा साथी इससे प्रेम करना सीखें

मैं गांव से लौट आया। घर असहनीय रूप से नीरस लग रहा था। लेकिन मैंने इसे सहन किया। अकेलेपन और अलगाव से कोई मुक्ति नहीं है। पत्नी, बच्चे, भाई, माता-पिता, दोस्त सब एक साथ आते हैं, लेकिन फिर अलग हो जाते हैं। यह एक निरंतर गति है। जैसे ही हम उनसे दूर होते हैं, वे हमसे दूर चले जाते हैं। जीवन के नियम को कोई टाल नहीं सकता। यह नियम उसी क्षण लागू हो जाता है, जब हम अपनी मां के गर्भ से खुद को अलग कर लेते हैं। जीवन में सभी संघर्ष और दुख इस नियम को रोकने या इससे दूर होने या खुद को इससे आहत होने देने के हमारे प्रयास के कारण हैं। इस तथ्य को पहचानना होगा। एक गहरा, अप्रतिबंधित अकेलापन ही जीवन का एकमात्र सत्य है। बाकी सब झूठ है।

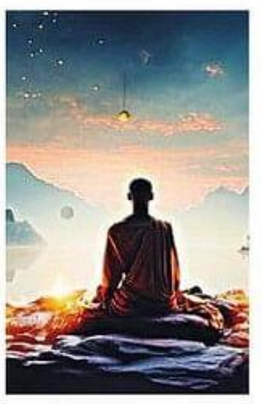

मेरी मां अपने माता-पिता से दूर हो गई, मेरी बहनें हमारे घर से दूर हो गईं, मैं और मेरा भाई एक-दूसरे से दूर हो गए, मेरी पत्नी मुझसे दूर हो गई, मेरी बेटी मेरी मां के साथ जा रही है। मेरे पिता अपने पिता से दूर हो गए, मेरे सबसे पुराने दोस्त-वे कहां हैं? वे पानी की फुहार की बूंदों की तरह बिखर जाते हैं। यह जीवन का नियम है। इसके खिलाफ लड़ने का कोई मतलब नहीं है, इस प्रकार मैंने पहले की तुलना में कम संघर्ष के साथ इस अलगाव को स्वीकार कर लिया। जीवन सही चीजें करने और आगे बढ़ने के बारे में है। हमारा हर मिनट कल बन जाता है और हमेशा के लिए खो जाता है। इसी बीच हर कोई हर समय, जानबूझकर या अनजाने में कोई न कोई भूमिका निभा रहा है। इस दुनिया में कुछ भी छिपाया या दबाया नहीं जा सकता। ऐसी सभी कोशिशें सूरज को छिपाने के लिए छाता पकड़ने के समान। जैसे सूर्य अंधकार को दूर करता है, वैसे ही भारतवर्ष धर्म, कर्तव्य, कर्म, चिंतन आदि का प्रतिपादन करके अंधकार को दूर करता है। जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा कोमल प्रकाश बिखेरकर कमल की कलियों को खिलने में मदद करता है, वैसे ही यह पुराण अपने प्रतिपादन द्वारा मानव बुद्धि का विस्तार करता है। इतिहास का दीपक प्रकृति के गर्भ के पूरे भवन को प्रकाशित करता है। प्रत्येक सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच कितनी महान मानवीय शक्तियां एक-दूसरे से मिलती हैं और एक-दूसरे से जुड़ती हैं, लेकिन वहां कुछ ऐसे प्राणी भी हैं, जो हर पवित्र कार्य में बाधा डालने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इस संसार में हजारों तरह की बातें और समस्याएं सामने आती हैं, लेकिन हमारे देखने और समझने का नजारिया कैसा है यह बहुत जरूरी है। एक साधारण व्यक्ति और एक बुद्धिमान व्यक्ति के बीच का अंतर तब पता चलता है, जब एक साधारण व्यक्ति जो कुछ भी देखता और सुनता है, उसे पूरे दिल से स्वीकार करता है, जबकि दूसरा व्यक्ति कभी भी किसी भी बात को बहुत गहन जांच के बाद ही स्वीकार करता है। वह अपनी बुद्धि को बारीकी से बुनी गई जाली की छलनी के रूप में कल्पना करता है, जिसके माध्यम से केवल बेहतरीन चीजें ही गुजर सकती हैं।

हर पल को जीना सीखें

सूत्र

जीवन में वर्तमान ही सच्चाई है और इसी के साथ हर मिनट अतीत बन रहा है। इन्सान चाहे कितना भी प्रयत्न कर ले, अपने प्रेम करने वाले लोगों से दूर हो ही जाता है। वे पानी की फुहार की बूंदों की तरह बिखर जाते हैं। इसलिए हर पल को जीना सीखें, क्योंकि इतिहास का दीपक प्रकृति के गर्भ के पूरे भवन को प्रकाशित करता है।

दूसरा पहलू

नवीनतम शोध बताते हैं कि डार्क चॉकलेट में घातक धातुओं की मिलावट होती है, जो ज्यादा सेवन करने वालों के लिए प्राणघातक है।

डार्क चॉकलेट में छिपा मीठा जहर

चॉकलेट की मिठास भला किसे नहीं लुभाती है। लेकिन जब पता चले कि डार्क चॉकलेट में भारी धातुएं मिली हुई हैं, तो अचानक से स्वाद कसैला हो जाता है। हाल ही में प्रकाशित एक नए शोध से पता चला है कि डार्क चॉकलेट में भारी धातुएं पाई गईं, जो कोको उत्पादों में विषाक्त पदार्थों की मिलावट के बारे में चिंता जताने वाले अध्ययनों की श्रृंखला में नवीनतम हैं।

डैवी ब्लम

शोधकर्ताओं ने 72 डार्क चॉकलेट बार, कोको पाउडर और निब का परीक्षण किया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उनमें सुरक्षित मात्रा से अधिक भारी धातुओं की मिलावट की गई है। जांचे गए उत्पादों में से 43 प्रतिशत में सीसे की मात्रा अधिक पाई गई और 33 प्रतिशत में कैडमियम की मात्रा अधिक थी। दोनों धातुओं को विषाक्त माना जाता है और वे कई स्वास्थ्य समस्याओं के लिए जिम्मेदार होती हैं। अध्ययन में किसी ब्रांड का नाम नहीं बताया गया, लेकिन 'निष्पक्ष व्यापार' के रूप में प्रमाणित उत्पादों में भारी धातुओं का स्तर कम नहीं था। लेकिन शोधपत्र के मुख्य लेखक और जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन ऐंड हेल्थ साइंसेज के मेडिकल छात्र जैकब हैंड्स ने बताया कि भारी धातुओं की मात्रा इतनी ज्यादा नहीं थी कि औसत उपभोक्ता को सीमित मात्रा में डार्क चॉकलेट खाने के बारे में चिंतित होना पड़े। हालांकि कैडमियम और सीसा, दोनों ही स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा कर सकते हैं, लेकिन यहां यह स्पष्ट नहीं है कि डार्क चॉकलेट के कुछ टुकड़े खाने से अधिकांश स्वस्थ वयस्कों को कोई जोखिम हो सकता है।

शोधकर्ताओं की ओर से जांचे गए उत्पादों में से 43 प्रतिशत में सीसे की मात्रा अधिक पाई गई और 33 प्रतिशत में कैडमियम की मात्रा अधिक थी।

प्रोफेसर मेलिसा के अनुसार, अगर चॉकलेट आपकी दिनचर्या का एक मुख्य हिस्सा है या आप इसे बड़ी मात्रा में खाते हैं, तो यह चिंता की बात है। यदि थोड़ा बहुत खाते हैं, तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है।

डेलावेयर विश्वविद्यालय में पोषण की सहायक प्रोफेसर मेलिसा मेलोघ ने कहा कि मुझे ऐसे व्यक्ति की चिंता नहीं होगी, जो डार्क चॉकलेट का थोड़ा बहुत दीवाना हो और कुछ हफ्तों तक हर रात डार्क चॉकलेट खाता हो। लेकिन अगर यह वास्तव में आपकी दिनचर्या का एक मुख्य हिस्सा है या आप इसे बड़ी मात्रा में खाते हैं, तो जरूर यह चिंता की बात है। गर्भवती महिलाओं और बहुत छोटे बच्चों, जो भारी धातुओं के स्वास्थ्य जोखिमों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हैं, को डार्क चॉकलेट का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। शोध में पाया गया कि हर दिन एक औंस डार्क चॉकलेट खाने से स्वस्थ वयस्कों को कोई खतरा नहीं है, यदि वह गर्भवती नहीं हैं। हैंड्स ने कहा कि जो लोग भारी धातुओं से बचना चाहते हैं, वे ज्यादा न खाएं, लेकिन चॉकलेट को पूरी तरह से छोड़ने की जरूरत नहीं है।

©The New York Times 2024

आंकड़े

रेलवे टिकट

बढ़ते डिजिटल प्रयोग की वजह से रेलवे में अब ऑफलाइन की अपेक्षा ऑनलाइन टिकट बुकिंग अधिक हो रही है।

2023-24	82.7%
2022-23	80.9%
2021-22	80.5%
2013-14	50.0%
2010-11	40.0%

पिछले 14 वर्षों में ऑनलाइन बुकिंग 42 फीसदी बढ़ गई है। | स्रोत : IRCTC

महाराज अंबरीश ने दुर्वासा ऋषि को भोजन कराने से पहले भगवान का चरणोदक ले लिया था। इससे नाराज ऋषि ने जटाओं से कृत्या नामक राक्षसी प्रकट की।

अंबरीश को बचाने आया सुदर्शन

महाराज अंबरीश भगवान के अनन्य भक्त थे। एक बार उन्होंने एक वर्ष तक एकादशी व्रत करने का संकल्प लिया। ग्यारह एकादशी के व्रत उनके नियम से निभ गए थे। अंतिम एकादशी पर ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद अंबरीश व्रत का पारण करना ही चाहते थे कि इतने में दुर्वासा ऋषि पहुंच गए। राजा ने उनका सत्कार कर भोजन के लिए आग्रह किया। ऋषि ने भोजन के लिए हामी भर दी, लेकिन वह नित्यकर्म के लिए चले गए।

ऋषि को लौटने में विलंब हो रहा था और द्वादशी आने में एक घड़ी समय बचा था। यदि राजा पारण न करते, तो उनका व्रत भंग हो जाता। राजा ने ब्राह्मणों से पूछकर भगवान का चरणोदक लेकर पारण कर लिया। दुर्वासा को लौटने पर पता चला कि उन्हें भोजन कराने से पहले ही राजा ने व्रत का पारण कर लिया है। इससे ऋषि ने कुपित होकर अपनी जटाओं से कृत्या नामक राक्षसी प्रकट की।

राक्षसी अंबरीश को मारने के लिए दौड़ी। इधर, अंबरीश की रक्षा के लिए भगवान का सुदर्शन चक्र आया और कृत्या को मारकर दुर्वासा के पीछे दौड़ा। ऋषि भयभीत होकर विष्णु भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने कहा कि अंबरीश ही आपको बचा सकते हैं। वह अंबरीश के पास पहुंचे और क्षमा मांगी। अंबरीश ने सुदर्शन से प्रार्थना कर उनकी रक्षा की। बताते हैं कि दुर्वासा ऋषि को वापस आने में पूरा एक वर्ष बीत गया था।

अंतर्यात्रा
संकलित

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 01 जून, 1957

पोस्टकार्ड के बजाय लिफाफे की कीमत में बढ़ोतरी

पोस्टकार्ड के बजाय लिफाफे की कीमत में वृद्धि की गई

लोकसभा में आम बजट पर तीन दिन से हो रही बहस का उत्तर देते हुए वित्त मंत्री टीटी कृष्णमाचारी ने नए करों में जिन रियायतों की घोषणा की, उनके अनुसार पोस्टकार्ड के बजाय लिफाफे की कीमतों में वृद्धि होगी।

दिलवालों की दिल्ली बदहाल

दिल्लीवासी प्रदूषण के चलते खुली हवा में सांस लेने के लिए तरस ही रहे थे। अब जर्जर सड़कों व बदहाल ड्रेनेज सिस्टम ने जीना दुश्वार कर दिया है।

ज्ञानेंद्र रावत

अव्यवस्था

राजधानी दिल्ली अब रहने लायक नहीं रह गई है। दिल्लीवासी प्रदूषण के चलते साफ हवा में सांस लेने के लिए बरसों से तरस ही रहे हैं। अब सड़कों की बदहाली और दशकों पुरानी सीवेज प्रणाली की जर्जर अवस्था के होते जलभराव की समस्या से उनका जीना दूभर हो गया है। वे उस क्षण को कोस रहे हैं, जब उन्होंने यहां बसने का निर्णय लिया था। जनसुविधाओं के मामले में प्रशासनिक स्तर पर भी दिल्ली की जनता केंद्र की भाजपा सरकार और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के बीच जारी अस्तित्व की लड़ाई में पिस रही है।

सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी कमेटी के मुताबिक, जुलाई से नवंबर 2023 के बीच आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर सड़क सुरक्षा के उद्देश्य से हुए ऑडिट में फुटपाथ की स्थिति, संरचना, डिजाइन और सीवेज सिस्टम को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। इसमें इस बात पर गंभीर चिंता व्यक्त की है कि दिल्ली में तकरीबन 46फीसदी से ज्यादा जोनों में सुरक्षित व सुगम यातायात के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए। यह बदहाली का आलम तब है, जब दिल्ली को विश्वस्तरीय शहर बनाने का दावा लगातार किया जाता है, लेकिन मौजूदा हालात इसके उलट गवाही देते हैं। दिल्ली की सड़कें तो सड़कें, जंक्शन और फुटपाथ भी कतई सुरक्षित नहीं हैं। सड़क सुरक्षा को लेकर उठाए सवालों के उद्देश्य से 69 फीसदी सड़क संकेतक इंडियन रोड कांग्रेस के मानकों पर कतई खरे नहीं उतरते। फुटपाथ को लें, वह भी मानकों के अनुरूप नहीं हैं। इंडियन रोड कांग्रेस के मुताबिक, फुटपाथ की चौड़ाई 2.5 मीटर होनी चाहिए, जिसके अनुसार उस पर दो व्हील चेयर एक साथ गुजर सकें। 16 फीसदी फुटपाथ की चौड़ाई इंडियन रोड कांग्रेस के मानकों के मुताबिक है, जबकि 84 फीसदी फुटपाथ ऐसे हैं, जिनकी चौड़ाई तय मानकों के मुताबिक है ही नहीं। पुरानी दिल्ली की बात छोड़िए, रिंग रोड भी इस बदहाली की शिकार हैं। रिंग रोड पर जहां सबसे ज्यादा वाहन गुजरते हैं, उस पर मजनू का टीला, चंदगीराम के अखाड़े के आसपास की सड़कें जर्जर अवस्था में हैं, वे टूटी पड़ी हैं। वहां जेब्रा क्रॉसिंग की मार्किंग भी नहीं है। यही हाल पूर्वी दिल्ली की वजीराबाद रोड का है। यहां सबसे ज्यादा व्यस्त रहने वाला लोनी-गोकुलपुरी रोड वाला जंक्शन यानी गोल चक्कर है, जहां से गाजियाबाद को सड़क जाती है। सड़क के टूटे होने और जेब्रा क्रासिंग न होने के चलते हादसे की आशंका रहती है। सबसे ज्यादा खतरनाक हालात आजादपुर चौक, भलस्वा चौक, मुकरबा चौक, बुराड़ी चौक, पंजाबी बाग चौक, गाजीपुर फ्लाईओवर, मुर्गा मंडी, मुकुंदपुर चौक, मधुबन चौक और रजोकरी फ्लाईओवर की है, जहां सड़क हादसे आम हैं।

अब जरा दिल्ली की जल निकासी पर भी नजर डालें। दशकों पुराना ड्रेनेज सिस्टम इतना बदहाल हो चुका है कि अब वह राजधानी की सवा दो करोड़ से ज्यादा आबादी के जल-मल का भार सहने की क्षमता खो चुका है। फिर भी दिल्ली उसी 48 साल पुराने ड्रेनेज सिस्टम पर आश्रित है, जब दिल्ली की आबादी 60 लाख के आसपास ही हुआ करती थी। इस वजह से जरा-सी बारिश में जलभराव हो जाता है। यदि बारिश तगड़ी हो गई, तो डूब की स्थिति पैदा हो जाती है। यह हालत अब पुरानी दिल्ली की ही नहीं होती, बल्कि लुटियन जोन नई दिल्ली भी इसका शिकार हुए बिना नहीं रहती और वहां के हालात भी किसी टापू जैसे हो जाते हैं। इन सबके लिए जिम्मेदार पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था का न होना और नालों की समय-समय पर सफाई न होना है। नतीजतन सड़कों पर तेज बारिश के चलते जलभराव होने से कहीं सड़क धंसने से गड्ढे हो जाते हैं। कहीं सीवर के मैनहोल में स्कूटर समा जाते हैं, तो कभी राहगीर। कभी-कभी तो लुटियन जोन में घंटों आवाजाही तक बंद हो जाती है और लोग घरों में कैद होकर रह जाते हैं।

वह बात दीगर है कि पीडब्ल्यूडी यह दावा करते नहीं थकती कि जलभराव के चलते जल निकासी हेतु सैकड़ों पंप लगाए जाते हैं, लेकिन बारिश के विषम हालात, पुराने नालों की सफाई न होने और उनमें गंदगी भरे रहने से पंपों द्वारा जल निकासी में अधिक समय लगने से जल्दी जलभराव से निजात मिल पाना बेहद मुश्किल हो जाता है और जाम में घंटों वाहन फंसे रहते हैं। कहीं-कहीं तो हादसों की आशंका के मद्देनजर रास्ते और अंडरपास तक बंद करने पड़ते हैं। ज्यादातर ऐसी स्थिति से लोगों को आजाद नगर मार्केट ब्रिज, मूलचंद अंडरपास, जखीरा अंडरपास, मिंटो ब्रिज, आईटीओ, गणेश नगर, मदर डेयरी, प्रगति मैदान आदि जगहों पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिससे कभी-कभी कार्यस्थल पर भी समय से पहुंचना उनके लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। बदहाली की यह स्थिति तो कमोबेश दिल्ली वालों की नियति बन चुकी है। ऐसे में दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी की संज्ञा देना बेमानी है।

कल्पमेधा

साधनों द्वारा नहीं, बल्कि नैतिकता के बल द्वारा ही मनुष्यों और उनके कर्मों पर अधिकार प्राप्त किया जा सकता है।

– कार्लाइल

सलाखों पर सवाल

आखिरकार दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत दे दी। हालांकि इसमें कुछ शर्तें भी जोड़ी हैं, पर अदालतों को एक बार फिर नसीहत दी है कि जमानत नियम है और जेल अपवाद। किसी की जमानत सजा के तौर पर नहीं टाली जानी चाहिए। हालांकि यह बात सर्वोच्च न्यायालय पहले भी कई बार कह चुका है, मगर निचली अदालतें इसे गंभीरता से लेती नजर नहीं आतीं। मनीष सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति में भ्रष्टाचार के आरोप में पहले प्रवर्तन निदेशालय और फिर सीबीआइ ने जेल में बंद कराया था। सिसोदिया निचली अदालत से उच्च न्यायालय के बीच अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते और जमानत की अपील करते रहे, मगर किन्हीं तकनीकी कारणों से उन्हें सलाखों के पीछे ही रहने पर मजबूर होना पड़ा। करीब सत्रह महीने उन्होंने जेल में बिताए। जाहिर है, उनकी जमानत से आम आदमी पार्टी में उत्साह का माहौल है। मगर यह सवाल अपनी जगह बना हुआ है कि जब एक निर्वाचित सरकार के जिम्मेदार पद का निर्वाह कर रहे व्यक्ति को इतने लंबे समय तक जेल में रहने पर मजबूर होना पड़ता है, तो सामान्य नागरिक के बारे में क्या उम्मीद की जा सकती है। ये सवाल बेवजह नहीं उठ रहे हैं कि आखिर सिसोदिया के सत्रह महीनों का हिसाब कौन देगा।

सिसोदिया अकेले ऐसे नेता नहीं हैं, जिन्हें इस तरह सीखचों के पीछे लंबा वक्त गुजारना पड़ा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी जेल में रह चुके हैं। सत्येंद्र जैन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी तक जमानत की आस लगाए हुए हैं। इस मामले में जांच एजंसियों के कामकाज पर गहरे सवाल उठे हैं। दिल्ली आबकारी मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सेना की जमीन खरीद घोटाले के आरोप में हेमंत सोरेन को जांच एजंसियों ने बिना पुख्ता आधार और दोषसिद्धि के लंबे समय तक जेल में डाले रखा। इसमें निचली अदालतों ने भी गंभीरता से विचार नहीं किया कि इस तरह जिम्मेदार पदों का निर्वाह करने वालों को जेलों में डालने से आखिरकार सार्वजनिक महत्त्व के कामकाज बाधित होते हैं। किसी को जमानत देने का यह अर्थ कतई नहीं होता कि उसे दोषमुक्त कर दिया गया। उसके खिलाफ लगे आरोपों की जांच तो चलती रह सकती है और दोषसिद्धि पर उसे सजा भुगतनी ही पड़ेगी। इस तरह केवल आरोप और आशंका के आधार पर लोगों को लंबे समय तक जेलों में बंद रखना एक तरह से नाहक सजा देने के बराबर ही माना जाता है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय की नसीहत पर गंभीरता से पालन के अपेक्षा की जाती है।

पिछले कुछ वर्षों से प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकंजा कसने के नाम पर जिस तरह अंधाधुंध छापे मारे और गिरफ्तारियां की, उसे लेकर उन पर आरोप लगते रहे हैं कि वे सत्तापक्ष के इशारे पर, उसकी राजनीतिक मंशा के अनुरूप काम करती हैं। वे जानबूझ कर तकनीकी अड़चनें पैदा कर अदालत को जमानत देने से रोकने का प्रयास करती देखी जाती हैं। भ्रष्टाचार और धनशोधन पर अंकुश लगाना निस्संदेह बड़ी चुनौती है, इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई से शायद ही कोई इनकार करे, मगर इसके लिए बने कानूनों का राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल होगा, तो असल मकसद हाशिये पर ही बना रहेगा। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय की नसीहत पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

अभाव के सामने

देश में गरीबी और खासकर भूख से जूझते तबकों को राहत दिलाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। हालांकि इसके संचालन में अक्सर भ्रष्टाचार के मामलों के मद्देनजर व्यापक सुधार की गुंजाइश बनी रही, लेकिन नीतिगत तौर पर यह एक ऐसी व्यवस्था है, जिसके जरिए अभावग्रस्त बड़े तबके को नाममात्र की राशि या नियंत्रित मूल्यों पर अनाज मुहैया कराया जाता है। आधुनिक तकनीकी के विस्तार के दौर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भी डिजिटल तौर-तरीके अपनाए गए। अपने राज्य से पलायन करके या विस्थापित होकर देश की राजधानी में पहुंचे लोगों के लिए 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' की व्यवस्था भी लागू की गई, ताकि इसका लाभ आम लोगों को मिल सके। विडंबना है कि तकनीकी सुविधाओं से लैस होने के बावजूद अब एक नई समस्या खड़ी हो रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अपने हक का राशन उठाने में मुश्किलें पेश आ रही हैं या फिर वे इस सुविधा से वंचित रह जाते हैं।

गौरतलब है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन यानी आइएमपीडीएस के सर्वर में तकनीकी दिक्कतों की वजह से पिछले कई महीने से उत्तर प्रदेश के राशन कार्ड धारकों को दिल्ली में अपने हिस्से का राशन लेने में कई तरह की परेशानी हो रही थी। मगर अब बिहार के राशन कार्ड धारकों को उनके हक का राशन न मिल पाने की शिकायत सामने आई है। यों अलग-अलग राज्यों के करीब चार लाख राशन कार्डधारकों को हर महीने दिल्ली में तकनीकी दिक्कतों की वजह से राशन लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ा है। व्यवस्थागत खामियों की वजह से बहुत सारे राशन कार्डधारक राशन लेने से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि दिल्ली में राशन की दुकानों में अनाज खत्म हो चुका होता है। सुविधा में इजाफे और पारदर्शिता के लिए इसमें डिजिटल तंत्र को बढ़ावा दिया गया है, लेकिन हकीकत यह है कि मशीनों में कभी 'दुबारा प्रयास करें' तो कभी 'लेन-देन विफल' आदि की सूचना आती है। सवाल है कि अगर तकनीकी दिक्कतों की वजह से अभाव से जूझते लोगों के सामने समस्याएं आ रही हैं तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर निर्भर रहने वालों के सामने फिलहाल और क्या विकल्प है?

बुजुर्ग पीढ़ी की बुनियादी समस्याएं

देश के वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत से वरिष्ठ नागरिक गंभीर आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। उनकी कोई नियमित आय नहीं है, पेंशन या सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं तक उनकी पहुंच सुलभ नहीं है।

अजय जोशी

देश की जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग वरिष्ठ नागरिकों का है। वे अपने ज्ञान और अनुभव से समाज के लिए अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। इस दृष्टि से उनका कल्याण भी सरकारों और समाज की प्राथमिकता में होना चाहिए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में साठ वर्ष और इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों की जनसंख्या 10.38 करोड़ थी। फिलहाल वरिष्ठ नागरिकों की आबादी कुल आबादी का लगभग दस फीसद है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा गठित जनसंख्या अनुमानों पर तकनीकी समूह की रपट के मुताबिक वर्ष 2026 तक देश में साठ वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों की संख्या 17.32 करोड़ होने की संभावना है। एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2050 में हर चौथा व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक होगा। इस वर्ग के अधिकांश नागरिक अपने परिवार, समाज और सरकार से किसी न किसी रूप में असहज, उपेक्षित और असहाय महसूस करते हैं। उनकी अपनी आर्थिक, शारीरिक और मानसिक समस्याएं हैं।

केंद्र और राज्य सरकारों ने वरिष्ठ नागरिकों का सहयोग करने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। उन्हें परिवहन, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य सेवाओं पर छूट तथा लाभ प्रदान किए जाते हैं। केंद्र और राज्य स्तर पर उनके लिए कई तरह की पेंशन योजनाएं भी हैं, जिनके माध्यम से उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। उनके स्वास्थ्य देखभाल हेतु चिकित्सा व्यय पर छूट, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में उनको प्राथमिकता देने जैसी सुविधाएं सम्मिलित हैं। उन्हें आय कर में सामान्य कर दाताओं की तुलना में अधिक कर छूट प्रादान की जाती रही है।

वरिष्ठ नागरिकों के हित सरंक्षण हेतु सरकार ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 बनाया, जिसके अंतर्गत वृद्ध व्यक्तियों और माता-पिता के भरण-पोषण तथा देखरेख के लिए प्रभावी व्यवस्था का प्रावधान है। इस अधिनियम के अंतर्गत वे अभिभावक और वरिष्ठ नागरिक, जो अपनी आय या अपनी संपत्ति द्वारा होने वाली आय से भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं, वे अपने व्यस्क बच्चों या संबंधितों से भरण-पोषण प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस अधिनियम के तहत वरिष्ठ नागरिकों की उपेक्षा और परित्याग को एक संगीन अपराध माना गया है, जिसके लिए पांच हजार रुपए का जुर्माना या तीन माह की सजा या दोनों हो सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक के भरण-पोषण हेतु दस हजार रुपए प्रतिमाह राशि देने का आदेश भी किया जा सकता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई संगठन और गैर-सरकारी संस्थाएं भी विभिन्न रूपों में सेवाएं प्रदान करती हैं। इनमें 'डे केयर' केंद्र वृद्धाश्रम, कानूनी मामलों में सहायता और आर्थिक-सामाजिक गतिविधियां तथा सामुदायिक सहभागिता जैसे कार्य किए जाते हैं।

यह सब होते हुए भी देश के वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत से वरिष्ठ नागरिक गंभीर आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। उनकी कोई नियमित आय नहीं है, पेंशन या सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं तक उनकी पहुंच सुलभ नहीं है। इनकी स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित समस्याएं भी कम नहीं हैं। उनके लिए पर्याप्त

आरोग्य परामर्श सेवाएं उपलब्ध नहीं होतीं। उनको विशेष चिकित्सा सुविधाएं और निश्शुल्क दवाएं पाने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वरिष्ठ नागरिक समाज में अलगाव की स्थिति से भी त्रस्त हैं। उनमें समाजिक संपर्कों की कमी के कारण अकेलापन बना रहता है। उनको अपनी संपत्ति की

> **वरिष्ठ नागरिकों की एक बड़ी संख्या के जीवन यापन का आधार उनकी सेवानिवृत्ति पर मिली पीएफ और ग्रेच्युटी की राशि पर मिलने वाला ब्याज है। उनको अन्य किसी तरह की पेंशन आदि नहीं मिलती। बैंकों में जमा राशियों पर मिलने वाले ब्याज की दरों में विगत दस-बारह साल से निरंतर कमी आ रही है। ब्याज दरें इस अवधि में लगभग तीन से पांच फीसद कम हो गईं। हालांकि बैंकों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को आधा फीसद ब्याज अधिक दिया जाता है, लेकिन दस वर्ष पूर्व की ब्याज दरों की तुलना में यह आधा फीसद जोड़ने के बाद भी वास्तविक ब्याज दर कम ही हुई है।**

सुरक्षा और अपने साथ होने वाले अपराधों से बचाव की भी जरूरत होती है। वरिष्ठ नागरिकों, खासकर अकेले रहने वाले व्यक्तियों, के साथ उनकी संपत्ति से जुड़े और उनके साथ होने वाले अपराधों के समाचार आते रहते हैं।

विगत कुछ वर्षों में वरिष्ठ नागरिकों को सरकारों से मिलने वाली सुविधाओं में कटौती देखी जा रही है। उन्हें इस वर्ष के आम बजट से काफी उम्मीदें थीं। कोरोना काल में वर्ष 2020 में रेल किराए में वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं को मिलने वाली छूट को बंद कर दिया गया। आम चुनाव के दौरान सत्तर वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त इलाज हेतु स्वास्थ बीमा कवर देने का वादा किया गया, मगर उसके संबंध में बजट में कोई घोषणा नहीं हुई। वरिष्ठ नागरिक आयकर में और अधिक छूट की उम्मीद लगाए हुए थे, लेकिन उन्हें मानक कटौती में 25 हजार रुपए की मामूली वृद्धि के अलावा कुछ नहीं मिला। अस्सी वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली अतिरिक्त छूट में भी कोई वृद्धि नहीं हुई। स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी की वर्तमान दर 18 फीसद है, जिसका भार किसी न किसी रूप में बीमाधारकों को ही वहन करना पड़ता है, उसे घटा या हटा कर स्वास्थ्य बीमा की लागत कम करने की अपेक्षा थी, लेकिन बजट में इस बारे में कोई घोषणा नहीं हुई। अब स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा के प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी को पूरी तरह हटाने की मांग जोर पकड़ रही है। सरकार को इस दिशा में विचार करने की जरूरत है।

वरिष्ठ नागरिकों की एक बड़ी संख्या के जीवन यापन का आधार उनकी सेवा निवृत्ति पर मिली पीएफ और ग्रेच्युटी की राशि पर मिलने वाला ब्याज है। उनको अन्य किसी तरह की पेंशन आदि नहीं मिलती। बैंकों में जमा राशियों पर मिलने वाले ब्याज की दरों में विगत दस-बारह साल से निरंतर कमी आ रही है। ब्याज दरें इस अवधि में लगभग तीन से पांच फीसद कम हो गईं। हालांकि बैंकों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को आधा फीसद ब्याज अधिक दिया जाता है, लेकिन दस वर्ष पूर्व की ब्याज दरों की तुलना में यह आधा फीसद जोड़ने के बाद भी वास्तविक ब्याज दर कम ही हुई है। एक तरफ महंगाई बढ़ी, दूसरी तरफ ब्याज दरों में कमी आई, इससे वरिष्ठ नागरिकों पर दोहरी मार पड़ी है।

संगठित क्षेत्र में नई पेंशन योजना यानी एनपीएस में आने वाले ऐसे कर्मचारी, जिनका वेतन कम था या उनकी सेवा अवधि कम रही, उनको इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली पेंशन तीन-चार सौ रुपए प्रतिमाह मिलने के समाचार भी आते रहते हैं। यह राशि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा गरीब वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं आदि को मिलने वाली पेंशन से भी बहुत कम रहती है। एनपीएस में आने वाले वरिष्ठ नागरिकों को एक न्यूनतम पेंशन देने की मांग भी समय-समय पर उठती रही है, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई घोषणा नहीं हुई है। कुल मिलाकर केंद्रीय बजट और सरकारी घोषणाओं में वरिष्ठ नागरिकों के हित में कुछ भी नहीं हुआ। समाज के अन्य कमजोर वर्गों की तरह वरिष्ठ नागरिकों का बड़ा वर्ग अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम नहीं है, कई मामलों में उनके भूखों मरने की नौबत तक आ रही है।

आज जरूरत है कि वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक जीवन यापन करते रहने के लिए उनकी न्यूनतम जरूरतों की पूर्ति के लिए सक्रिय प्रयास हों। इसके लिए ऐसे वरिष्ठ नागरिक, जो शारीरिक, आर्थिक और मानसिक दृष्टि से सक्षम हैं, वे स्वयं, सरकार और समाजसेवी संगठन इस दिशा में सक्रिय प्रयास करें, तो आम वरिष्ठ नागरिक अपने जीवन का शेष समय स्वस्थ, प्रसन्न रहते हुए बिता सकते हैं।

स्मृतियों का घेरा

अमित कुमार

बीते समय की याद आना और भावुक हो जाना बेहद प्राकृतिक संदर्भ है। यदा-कदा हमारे भीतर अतीत की सुथरी छाप को फिर से जीने की तलब उठती रहती है। वर्तमान से क्षणिक दुराव के लिए हमारा मन यादों के किले में वह खुशी का कोना चुन लेता है, जहां घंटों बैठ वह उकताता नहीं। जब हम उन स्मृतियों की नाजुक बांहों में होते हैं तो कहीं न कहीं अपने वर्तमान और भविष्य में उनकी आवृत्ति की उम्मीद पाल लेते हैं। इसलिए यह जांचना अनिवार्य है कि कहीं हमारे सुखद अनुभव किसी भी तरह से दूषित तो नहीं... कहीं हमारा मन चीजों को टुकड़ों में याद करने के लिए बाध्य तो नहीं!

गहराई से देखने पर मालूम होता है कि हम अपने जीवन के किसी विशेष कालखंड की एक तस्वीर गढ़ लेते हैं और उसी से उस दौर को याद करने की चेष्टा करते हैं। तस्वीर की सीमा उसके फ्रेम का आकार तय करता है। उसकी परिधि में सब कुछ नहीं अंट पाता और जो अंट पाता है, हम उसे तटस्थ होकर देख भी नहीं पाते। 'नास्टेल्जिक' या अतीतजीवी होते हुए तटस्थ हो पाना जटिल है। जब सामाजिक धारणाएं और परंपराएं समेकित रूप से कई लोगों के लिए अतीतजीविता का कारण बनती हैं। तब उनके पक्षपाती होने के बावजूद उन्हें ढहाना या उन पर प्रश्न तक करना मुश्किल हो जाता है।

महिलाओं का उत्पीड़न सदियों से इस आधार पर भी होता आया कि पूर्वजों ने ऐसा ही जीवन व्यतीत किया और कहीं न कहीं उनका बचपन जीवन का वही स्वरूप देखते हुए बीता। एक पति द्वारा अपनी पत्नी में मां की छवि तलाशना और उस पर वैसा ही पहनने-ओढ़ने का दबाव बनाना कितना आमफहम है। लोग यह कहते पाए गए हैं कि मेरी मां हमेशा घर के बड़े पुरुषों के आगे माथे पर आंचल रखती थी और अपने जेठ से दूर रहती थी। वे अपनी जीवनसाथी के समक्ष अतीतजीविता में लपेट कर उत्पीड़न पेश करते हैं। सुविधा के खात्मे से तिलमिलाती पितृसत्ता तानें गढ़ती है कि जींस पहनने वाली मांएं अपने बच्चों को आंचल का सुख कहां से दे पाएंगी'! यादों की तासीर इतनी पुख्ता होती है कि पीड़ित का दुख उसके समक्ष गौण हो जाता है। तभी व्यवस्था औरतों को मोटरसाइकिल पर भी बगैर साड़ी पहने सहजता से बैठने की अनुमति नहीं देती। कई स्थितियों में अतीतजीविता की दहलीज को लांघ पाना क्रांतिकारी कदम से कम नहीं होता। रूढ़ियों को तोड़ने में लोगों के मन में अनजान भय होता है कि वे अपनी यादों के साथ अन्याय कर रहे हैं, लेकिन किसी मनुष्य के साथ होता अन्याय उन्हें नागवार नहीं गुजरता।

अब मध्यवर्गीय घरों में लोग शौक से अपने भनसाघर यानी रसोईघर में तरह-तरह के टाइल खरीद कर लगाते हैं। चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि दुकानों में टाइलों के तमाम विकल्पों में एक टाइल ऐसी भी है, जिसकी तस्वीर असहज करती है। उस टाइल में एक महिला चक्की चला रही है, एक गेहूं फटक रही है, एक सिलबट्टे पर कुछ पीस रही है और एक चूल्हे में फुकनी से हवा कर रही है। इस टाइल की खूब बिक्री बिसराए अतीत के नाम पर होती है। लोग यह नहीं समझ पाते कि उनकी याद का यह स्वरूप चूल्हा, सूप, चक्की, सिलबट्टे से नहीं, बल्कि उन्हें चलाती औरतों की मौजूदगी से पूरा होता है। उस घर में बड़े हो रहे बच्चे जब भी रसोई में जाते हैं, तब उस तस्वीर को देखते हैं। गैरइरादतन उन्हें यह सीख मिलती है कि रसोई में होना औरतों की परिभाषित भूमिका है। तब अतीतजीविता सिर्फ हम तक सीमित नहीं रहता, बल्कि बुरे तरीके से अगली पीढ़ी को हस्तांतरित हो जाता है।

सोशल मीडिया पर कुछेक दिनों के अंतराल पर एक तस्वीर घूमती रहती है। इसमें दशकों पहले का एक भरा-पूरा परिवार एक साथ हाजिर है। समय और पेट की मांग के हिसाब से परिवार से दूर हुए लोगों को वह तस्वीर भावनात्मक रूप से छू जाती है। उस तस्वीर में बच्चे थाली से कुछ खाते हुए लेटकर टीवी देख रहे हैं। घर का पुरुष आरामकुर्सी में टांगों को एक के ऊपर चढ़ा अखबार पढ़ रहा है। वहीं घर की महिला इस दौरान भी जमीन पर बैठ फूलों की माला गूंथ रही है। परिवार के साथ बिताए जाने वाले गुणवत्तापूर्ण समय की उस तस्वीर में भी औरत घर का कोई काम ही निपटा रही है और पुरुष आदतन पढ़ाई कर रहा है। यह तस्वीर लोगों को इसलिए अपील करती है, क्योंकि उनके बचपन में सच में मां-पिता की यही भूमिका रही। सबके रविवार को रविवार बनाने की जवाबदेही महिलाओं की रही और वे हमेशा रसोई के आसपास विचरती पाई गईं। लोगों के लिए भले ही अपने मानसिक ढांचे को तोड़ पाना भगीरथ कार्य हो, लेकिन पनप रही पीढ़ियों के लिए ऐसी तस्वीर साझा कर गुणवत्तापूर्ण समय के प्रतिगामी आयाम नहीं फैलाए जाने चाहिए। ऐसी तस्वीरों को सराहा जाना चाहिए जहां पुरुष खाना पकाते हुए दिखें और महिलाएं कुर्सी पर बैठ कर समाचार पढ़ते-देखते। 'रोहित पोंछा लगाता है' और 'सीमा होमवर्क करती है' जैसे वाक्य पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने चाहिए।

दुनिया मेरे आगे

> **समानता और मानवाधिकारों का हनन किसी भी कारण से न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। अतीतजीविता बहुतायत में उन्हें पसंद होती है, जिनका व्यवस्था में कम योगदान है। वरना महिलाओं के जितने दुख रहे हैं, ऐसी तस्वीरों और यादों को देख कर खीझ और टीस उठती है।**

ऐसे तमाम उदाहरण हैं जहां छोटे लड़कों और लड़कियों की शादी इसलिए रचा दी गई, कि घर के वृद्ध अपने पुरखों की तरह उनकी शादी देख कर मरना चाहते थे। समानता और मानवाधिकारों का हनन किसी भी कारण से न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। अतीतजीविता बहुतायत में उन्हें पसंद होती है, जिनका व्यवस्था में कम योगदान है। वरना महिलाओं के जितने दुख रहे हैं, ऐसी तस्वीरों और यादों को देख कर खीझ और टीस उठती है। किसी वर्ग के उत्पीड़न पर बनी मीनार की ऊंचाई की शेखी कब तक बघारी जाएगी? यह जानते हुए कि उम्रदराज पीढ़ियों की अपनी सीमाएं हैं, उन्हें अपनी मान्यताओं को न थोपने की धीमी कोशिश करनी चाहिए। इन मामलों में व्यवस्था तर्कों से संचालित हो, कोरी भावनाओं से नहीं, तो कितनी सुंदर बात होगी।

समाज में हम

'रिश्तों के धागे' (दुनिया मेरे आगे, 2 अगस्त) पढ़ा। मनुष्य को समाज में रहने के लिए अपने विचारों और भावों को व्यक्त करना और दूसरों के द्वारा व्यक्त विचारों और भावों को समझना पड़ता है। मनुष्य सामाजिक रिश्तों के बीच इसलिए रहता है कि उसकी आवश्यकता उसे ऐसा करने के लिए बाध्य करती है। अपने मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए समाज और रिश्ते अहम हैं। समाज हमारी संस्कृति को संरक्षित करता है और इसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाता है। यह व्यक्तियों के रूप में हमारी क्षमताओं को मुक्त और सीमित करता है और हमारे दृष्टिकोण, विश्वासों, हमारी नैतिकता और आदर्शों को आकार देता है। आत्म-संरक्षण की आवश्यकता, जिसे हर प्राणी द्वारा महसूस किया जाता है, मनुष्य को सामाजिक बनाती है। इसलिए यह केवल उसकी प्रकृति के कारण नहीं है, बल्कि उसकी आवश्यकताओं के कारण भी मनुष्य समाज में रहता है। रिश्तों के समाज से ही नए विचार नए आदर्श और नई सोच का आविर्भाव होता है। समाज से जुड़कर समाज के अंदर बुराइयों को दूर किया जाए, तभी जाकर नए समाज में नए विचारों नए भावों का संकलन हो पाएगा।

– समराज चौहान, असम

नियम बनाम उम्मीद

भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने तीन दिग्गज पहलवानों को चित कर इतिहास तो रच दिया, पर यह खुशी कुछ समय की रहेगी, यह न तो विनेश ने सोचा होगा और देश ने। नियमों के मापदंड में खुशियां और उम्मीदें दबकर रह गईं। सौ ग्राम का भार देश की खुशियों पर भारी पड़ा और विनेश को अयोग्य घोषित कर दिया। सुझाव के तौर पर कहा जा सकता है कि किसी प्रतिभागी की किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से पहले ही सौ फीसद जांच-परख करनी चाहिए। वजन का मापदंड एक बार ही निर्धारित होना चाहिए। खिलाड़ी योग्य होने के बाद अयोग्य घोषित होता है तो उम्मीदों पर पानी फिरता है। विनेश फोगाट का स्वर्ण पदक का सपना अधूरा रह गया, लेकिन उनकी जीत देश के गौरव का विषय रहेगा। हालांकि पहले भी ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई थीं। अन्य देशों के उदाहरण हैं। फिर भी सफलता के करीब पहुंचकर ऐसी स्थिति गले से नहीं उतरती।

– योगेश जोशी, बड़वाह

धारणाओं की दीवारें

देश में कुछ लोग आस्था के नाम पर बढ़ती अव्यवस्था में सुधार के बजाय आज भी इतने उत्साहित दिखते हैं कि मानो वे वर्षों की परंपरा का निर्वहन बरकरार रखने में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। समय के साथ हर कुछ परिवर्तनशील है, गतिशील है। मगर आज भी लोग बरसों पुरानी और कुछ अर्थों में अंधविश्वास जैसी परंपरा को भी संजोए हुए दिखते हैं। इससे आस्था का ही नुकसान होता है। कई ऐसी बातें हैं जो समकालीन दौर में प्रासंगिक नहीं रह गई हैं। शिक्षित लोगों को अपनी सोच, क्षमता, विवेक, बुद्धि के अनुसार जीवन यापन करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। इसके बावजूद कभी-कभी प्रथाओं की जंजीरें इस तरह आत्मसात-सी होती दिखती हैं कि वैज्ञानिकता की कसौटी नजरअंदाज हो जाती है। विचित्र है कि लोग किसी परंपरा या प्रथाओं का सिर्फ इसलिए पालन करते हैं कि वह चिरकाल से चली आ रही है। विवेक की जगह कम है।

– मिथिलेश कुमार, भागलपुर

पारिस्थितिकी पर संकट

'कुदरत पर कहर बनता मानव निर्माण' (लेख, 8 अगस्त) पढ़ा। धरती पर मनुष्य निर्मित वस्तुओं का कुल वजन धरती पर जीवित प्रजातियों के कुल वजन के बराबर हो गया है। इससे प्राकृतिक विपदाएं आ रही हैं। मानव निर्मित वस्तुओं का वजन हर दो दशक में दो गुना हो जा रहा है। वहीं वैश्विक जैवभार का वजन लगभग स्थिर बना हुआ है। मानव निर्मित वस्तुओं में कुछ प्रमुख वस्तुओं में प्लास्टिक का इस्तेमाल इस कदर व्यापक हो चुका है कि अब तक लगभग आठ अरब टन प्लास्टिक का निर्माण हो चुका है। हालांकि प्लास्टिक का कुल वजन मानव निर्माण का मात्र एक फीसद है। फिर भी एक अनुमान के मुताबिक धरती पर मौजूद कुल प्लास्टिक का वजन सारे जानवरों के वजन का दो गुना हो चुका है। विकास का असर पारिस्थितिकी तंत्र पर भी बड़े पैमाने पर पड़ा है। इसमें संतुलन बनाने की आवश्यकता है।

– वेद सिंह यादव, लखनऊ

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

https://t.me/AllNewsPaperPaid

हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। –वाल्तेयर

राजस्थान पत्रिका
संस्थापक
कर्पूर चन्द्र कुलिश

वक्फ कानून में बदलाव पर खुले मन से हो चर्चा

लगता है मुद्दा कोई भी हो, सुधार या बदलाव के किसी भी प्रयास के पीछे राजनीतिक टकराव हमारी संसद का स्थायी अंग बनता जा रहा है। मुद्दा चाहे आरक्षण का हो अथवा कोई और, सत्ता पक्ष और विपक्ष सुधार पर चर्चा करने के बजाए अपना राजनीतिक फायदा तलाशते दिखते हैं। सत्ता पक्ष व प्रतिपक्ष में ताजा टकराव लोकसभा में पेश किए गए वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर सामने आया है। विपक्ष जहां विधेयक को संविधान के खिलाफ बता रहा है वहीं सत्तापक्ष का मानना है कि विधेयक के प्रावधानों में न तो संविधान का उल्लंघन हो रहा है और न ही इससे किसी का हक छीना जा रहा है।

वक्फ बोर्ड के मौजूदा कानूनों में संशोधन को लेकर सदन में आई सरकार के अपने तर्क हैं। सरकार का मानना है कि वक्फ बोर्ड से जुड़े जमीन के मामले ट्रिब्यूनल कोर्ट के अलावा रेवेन्यू कोर्ट एवं सिविल कोर्ट में भी सुने जाने चाहिए। मौजूदा कानून के अनुसार, वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम माना जाता है और इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके अलावा वक्फ बोर्ड में महिलाओं और अन्य धर्म के लोगों को शामिल करने का प्रावधान भी नए कानून में है जिसका विपक्ष विरोध कर रहा है। विपक्ष की मांग के अनुसार, इस विधेयक को शुक्रवार को संयुक्त संसदीय समिति को सौंप दिया गया। इकतीस सदस्यीय समिति संसद के अगले सत्र में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के विवाद को लेकर इसके कानूनों में बदलाव की मांग लंबे समय से की जाती रही है। वक्फ बोर्ड को दान में मिली संपत्ति का उपयोग शिक्षा एवं दूसरे कल्याण कार्यों में किया जाता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश में अभी वक्फ बोर्ड के पास नौ लाख एकड़ से अधिक संपत्ति है। यहां सवाल सिर्फ वक्फ बोर्ड तक सीमित नहीं है। धर्म से जुड़े तमाम संस्थानों में भी संपत्ति को लेकर आए दिन विवाद सामने आते रहे हैं। सत्तापक्ष और विपक्ष को संयुक्त संसदीय समिति में इन मुद्दों पर खुलकर विचार करना चाहिए। रही बात वक्फ बोर्ड की, इसकी संपत्तियों के दुरुपयोग को लेकर समय-समय पर खबरें आती रहती हैं। ट्रिब्यूनल में हजारों मामले विचाराधीन हैं। सरकार की मंशा अगर इसमें सुधार लाने की है तो विपक्ष को अपने सुझाव देने चाहिए। हर मुद्दे पर राजनीति करने से समस्या का समाधान मुश्किल है।

जरूरत यह है कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का उपयोग जरूरतमंदों के लिए हो। वक्फ बोर्ड में महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिला तो इससे वे अपने हकों की लड़ाई बेहतर ढंग से लड़ सकेंगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि दोनों पक्ष प्रस्तावित कानून की खूबियों-खामियों पर चर्चा कर बेहतर रास्ता निकालेंगे।

हर प्राणी अर्द्धनारीश्वर है। दक्षिण भाग शिव तथा वाम भाग शक्ति है। वृषा और योषा है। भोग योनियों में प्राणी कुछ अलग से प्रयास नहीं कर सकता। मनुष्य योनि में अपने स्वरूप को समझ सकता है। अपने कामना के स्वरूप का विकास कर सकता/सकती है।

वामन ही बनता विराट्

गुलाब कोठारी
प्रधान संपादक
पत्रिका समूह
@patrika.com

शरीर ही ब्रह्माण्ड

दुर्गा सप्तशती में बहिरंग और अन्तरंग दोनों ही दृष्टियां रखी गई हैं। बहिरंग भाव में असुरों के साथ युद्ध है, अन्तरंग भाव में असुरों की वास्तविकता और योषा का प्रभाव है। ब्रह्मा-विष्णु-इन्द्र प्राण अक्षर की अन्तरंग अथवा अमृत अक्षर कलाएं कहलाती हैं। अग्नि-सोम बहिरंग या पृष्ठ्य कलाएं हैं।

''अग्निषोमात्मकं जगत्'' में सोम को जीवनीय रस कहा जाता है। अग्नि का धर्म विश्कलन है। इसके खण्डित स्वरूप को प्रतिष्ठित करने का कार्य सोम करता है। सूर्य को जगत का पिता कहा जाता है—**सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च।** सूर्य की प्रतिष्ठा का आधार पारमेष्ठ्य सोम है जो निरन्तर सूर्य में आहुत होता है। साथ ही चान्द्र सोम भी इस कार्य में निरन्तर सहयोग करता है। सोम ही पोषक, स्वरूप निर्मापक तथा स्वरूप रक्षक है। नित्य आहुत होता हुआ सोम नित्य निर्माण करता रहता है।

आहुति द्रव्य से जो निर्माण होता है, उसके संबंध में तीन नियम हैं- पहला है वृद्धि- भूत और प्राण के संयोग से वृद्धि होती है। वृद्धि का अर्थ है छोटे से बड़ा होना- वामन से विराट् होना। जो वामन हैं, वही विराट् बनता है। **वामनो हि विष्णुरास** (शत. 1.2.5.5) । जो वामन था- वह वस्तुत: विष्णु ही था। वामन ही विराट् भाव में महिमा भाव रूप विष्णु होता है। गर्भ में स्थित भ्रूण वामन है। वही क्रमश: वृद्धि को प्राप्त होता हुआ विष्णु बनता है। शरीर बन जाता है। वामन से विष्णु का रूप गति के कारण प्राप्त होता है, जो देश-काल में प्रकट होती है। तीन लोक-तीन काल ही विष्णु के तीन पाद हैं। ऋग्वेद में वामन को युवाकुमार तथा विष्णु को वृद्ध शरीर कहा गया है।

जीवन का दूसरा लक्षण है- अन्न ग्रहण। जहां भूत में प्राण की सत्ता है, वहां अन्न और अन्नादरूप यज्ञ होता है। प्राण/अग्नि अन्नाद है, इसे जीवित रहने के लिए सोम-अन्न चाहिए। अग्नि बाहर से आए अन्न को ग्रहण करता है। उसे अपनी शक्ति से पचाकर अपने लिए, बल पैदा करता है। स्थूल अन्न से सूक्ष्म शक्ति का निर्माण शरीर के अनेक अंगों के रासायनिक क्रमों से होता है। चींटी-हाथी वृक्ष आदि भी अन्न-जल से ही जीवित रहते हैं। गर्भ में सारा अन्न मां से प्राप्त होता है। अन्न खाना और शक्ति उत्पन्न करना ही प्रकृति का यज्ञ है, शरीर का धर्म है। जैसे ही अन्न का पाचन होता है, पुन: वैश्वानर अग्नि अन्न मांगता है।

जीवन का तीसरा लक्षण है–प्रजनन। घृत को रेतस् कहते हैं। **रेत: कृत् वाज्यं देवा: पुरुषमाविशन्।** (अथर्व 11.8.29)। शुक्र या रेतस् के माध्यम से पार्थिव शक्तियां तथा देव शरीर में प्रविष्ट होते हैं। रेत-आज्य-शुक्र पर्याय हैं। जिस शुक्र तत्त्व से विश्व का जन्म होता है वह '**भुवनस्यरेत:**' कहलाता है। इसी से विश्व का भी एवं प्राणियों का भी जन्म होता है। रेत ही प्रजनन का प्रतीक है। जहां बीज से जीवन उत्पन्न होता है, स्वयं परिपक्व होने पर उसी प्रकार के बीज का निर्माण करता है। यही जीवन का चक्र है। पिता-माता के युग्म से ही सन्तान होती है। अर्द्धनारीश्वर सृष्टि रचना के लिए अपने वामांग से मातृ रूप भी धारण किए हुए है। प्रकृति ने सन्तान पैदा करने के लिए दो योनियों—स्त्री और पुरुष का निर्माण किया है। दोनों मिलकर एक योनिता है। अग्नि-सोम को एक योनि कहा है क्योंकि अग्नि ही सोम बनता है तथा सोम ही अग्नि बनता है। मूल रूप में तत्त्व एक ही है। अग्नि व सोम की सम्मिलित अवस्था से ही अपूर्व की उत्पत्ति होती है। इन्हीं अरणियों के घर्षण से सन्तान होती है।

अरण्योर्निहितो जातवेदा गर्भइवसुधितो गर्भिणिषु।
दिवेदिवे ईड्यो जागृवभ्दि: हविष्मभ्दि: मनुष्यभिराग्नि:।।
(ऋ. 3.29.2)

माता स्रष्टा भी है और सृष्टि (माया) भी है। यही उसकी शक्ति का स्वरूप भी है। पति के अंश को उसी की सन्तान बना देना ही दिव्यता है उसकी। आत्मा स्त्री-पुरुष दोनों का समान है। ईश्वर प्रजापति भी समान भाव (द्रष्टा) में है। जीव पिता के रेत से माता के शोणित में होता हुआ- शरीर धारण करके बाहर निकल जाता है। माता-पिता दोनों जीव की यात्रा का मार्ग बनकर रह जाते हैं, किन्तु प्राण रूप में संतति में प्रवाहित रहते हैं।

हर प्राणी अर्द्धनारीश्वर है। दक्षिण भाग शिव तथा वाम भाग शक्ति है। वृषा और योषा है। भोग योनियों में प्राणी कुछ अलग से प्रयास नहीं कर सकता। मनुष्य योनि में अपने स्वरूप को समझ सकता है। अपने कामना के स्वरूप का विकास कर सकता/सकती है। वृषा में आग्नेय तत्त्वों का और योषा में सौम्य भावों का विकास किया जाता है। सोम की अग्नि में आहुति ही यज्ञ कहलाती है। वाम भाग की दक्षिण भाग में आहुति होती जाती है। वाम भाग के सारे अवयव आकार एवं भार में दक्षिण (दाएं) भाग के अवयवों से कम होते हैं। शरीर से स्त्री- पत्नी- सौम्या है जबकि भीतर आग्नेय है। अर्द्धांगिनी रूप में वाम भाग से सौम्या (पुरुष के संदर्भ में), स्वयं वाम भाग में भारी-भीतर में अग्नि है, पुरुष भीतर सोम है। हृदय में तीन अग्नि (पुरुष) प्राण—ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र हैं। पुराणों में इन्द्र को ही महेश कहा है। हृदय रूप तीनों अग्नि प्राण दोनों ही शरीरों में स्थित हैं। तीनों की तीन सौम्य शक्तियां- क्रमश: सरस्वती, लक्ष्मी, काली हैं।

ये तीनों शक्तियां ही प्रकृति के तीन गुण हैं—सत-रज और तम। प्रत्येक नारी इन्हीं त्रिगुणों के आवरणों के सहारे अपने मायाभाव को प्रकट कर पाती है। ये बाहरी स्त्री के साथ भीतरी स्त्री के शक्ति रूप भी हैं। अर्द्धनारीश्वर का यही नारी अंश शक्ति बनता है। इन तीनों शक्तियों के शक्तिमान यानी कि विष्णु-ब्रह्मा-इन्द्र ही क्रमश: पोषक-नियामक व संहारक प्राण हैं। इन तीनों के कार्य शक्तियां ही करती हैं। तब कहते हैं कि पुरुष और प्रकृति मिलकर सृष्टि चलाते हैं। अत: इन दोनों का संतुलन बहुत आवश्यक है।

शिव है तो शक्ति है। शक्ति शिव के भीतर ही है। जब शक्ति सुप्त है, तब शिव भी शव की तरह निष्क्रिय है। पुरुष भी शिव है, नारी भी शिव है। दोनों की अपनी-अपनी शक्तियां हैं। ये शक्तियां ही दोनों के जीवन को चलाती हैं। शक्ति या ऊर्जा का कोई लिंग नहीं होता। देवी-देवता भी सृष्टि के पॉजिटिव-नेगेटिव तत्त्व होते हैं, किन्तु इनका भी लिंग भेद नहीं होता। बुद्धि या भावना का कोई लिंग भेद हो सकता है क्या? प्राणों का कोई भेद नहीं होता, सिवाय स्थूल और सूक्ष्म के।

'अग्निषोमात्मकं जगत्' के सिद्धान्त के आधार पर प्रकृति और पुरुष रूप दो मुख्य श्रेणियां हैं जो जीवन व्यवहार में योषा-वृषा रूप में दिखाई पड़ते हैं। योषा तो सूक्ष्म-तरंग ही है किन्तु परिणाम स्थूल होते हैं। ब्रह्म की माया ही सुप्त अवस्था में बल, जाग्रत अवस्था में शक्ति तथा कार्य अवस्था में क्रिया कहलाती है। ब्रह्म और माया सृष्टि की आरम्भिक अवस्था है। यहां क्रिया का अभाव है। अत: सम्पूर्ण सृष्टि 'मानसी' कहलाती है। चेतना तथा चिन्तन पर आधारित है। दुर्गा सप्तशती में इसी चेतना स्वरूप की स्तुति करते हुए कहा गया है–

या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम:।।
(दुर्गासप्तशती)

शक्ति रूप भी मात्र कामना है- क्रिया का अभाव यहां भी है, गुणों का अभाव भी है। अत: सृष्टि का निमित्त कारण बनती है। हमारे जीवन में कामना या तो सात्विक-विद्यामय (अंतरंग) होती है, अथवा तामसिक-अविद्यामय (बहिरंग)। दुर्गा सप्तशती में बहिरंग और अन्तरंग दोनों ही दृष्टियां रखी गई हैं। बहिरंग भाव में असुरों के साथ युद्ध है, अन्तरंग भाव में असुरों की वास्तविकता और योषा का प्रभाव है। ब्रह्मा-विष्णु-इन्द्र प्राण अक्षर की अन्तरंग अथवा अमृत अक्षर कलाएं कहलाती हैं। अग्नि-सोम बहिरंग या पृष्ठ्य कलाएं हैं। अक्षर ही अमृत और मर्त्य क्षर में परिवर्तित होता है। ब्रह्म ही कर्म रूप ले रहा है। ब्रह्मा केन्द्र में प्रतिष्ठित रहते हैं, विष्णु और इन्द्र अग्नि और सोम से युक्त होते हुए क्षर सृष्टि में निर्माण में कारण बनते हैं। क्षर ब्रह्म से आगे स्थूल सृष्टि का क्रम बनता है। **क्रमश:**

gulabkothari@epatrika.com

स्पाइडर सीजन: मकड़ियों के जाले, ज्यादा बारिश या बाढ़ से बचने के लिए!

ऑस्ट्रेलिया के गिप्सलैंड क्षेत्र में, कई दिनों तक भारी बारिश के कारण मकड़ियां 'बलूनिंग' नामक जीवित रहने की रणनीति का उपयोग करते हुए ऊंचे भू-भागों का रुख करती हैं। इस रणनीति के तहत मकड़ियां मुख्यत: बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सड़क किनारे स्थित संकेतकों, पेड़ों या ऊंची घास या वनस्पतियों के सहारे अपना जाला बुनती जाती हैं और इस तरह उन्हें भागने में मदद मिलती है। दरअसल, मकड़ियां कई तरह के जाले बुनने में माहिर होती हैं। 'बलूनिंग' के तहत मकड़ियां बहुत ही पतले-से रेशम के जरिए हवा के साथ मानो उड़ती हैं और इस तरह वे 100 किलोमीटर तक की उड़ान भरने में सक्षम होती हैं। गौरतलब है कि गिप्सलैंड दक्षिण-पूर्वी ऑस्ट्रेलिया का एक क्षेत्र है, जो मेलबर्न के पूर्वी उपनगरों से लेकर न्यू साउथ वेल्स की सीमा तक फैला हुआ है, और इसमें समुद्र तट, खेत, पहाड़ और झीलें शामिल हैं। इसके सबसे दक्षिणी छोर पर विल्सन्स प्रोमोन्टोरी नेशनल पार्क है।

सेहत 'सिर्फ एल्ब्युटेरोल' से अब 'स्टेरॉयड युक्त इनहेलर' की ओर स्थानांतरित हो रही हैं अस्थमा इलाज की गाइडलाइंस

अस्थमा के इलाज के कई कारगर विकल्प, सीमाओं में न बंधें

लीना एस. वेन
जॉर्ज वाशिंगटन विश्वविद्यालय के मिलकेन इंस्टीट्यूट स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में प्रोफेसर
द वाशिंगटन पोस्ट से विशेष अनुबंध के तहत

ओरल स्टेरॉयड के दुष्प्रभावों में हड्डियों का क्षय, मोतियाबिंद होना, वजन बढ़ना, भावनात्मक स्थिति में तीव्र परिवर्तन और इम्यूनोसप्रेशन (संक्रमण और घातक बीमारियों से लड़ने की क्षमता में कमी) शामिल हैं।

वर्षों से, अस्थमा के लिए मानक दवा एल्ब्युटेरोल है और साथ में इन्हेलर भी। अगर इतने से भी आराम नहीं मिलता है तो अन्य दवाएं भी साथ में दी जाती हैं। यदि लक्षण और भी खराब दिखते हैं तो मरीज को स्टेरॉयड (तरल पदार्थ या गोलियों के रूप में) दिया जाता है। इस तरीके से मरीज के इलाज में कई समस्याएं आती हैं। सबसे पहले तो यह कि दवा जो दी गई है वह ठीक से काम कर रही है या नहीं। 2019 में सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन से मिले आंकड़ों से सामने आया कि 60 प्रतिशत से ज्यादा अस्थमा पीड़ित वयस्कों की बीमारी नियंत्रण से बाहर थी। उन्हें बार-बार इमरजेंसी डिपार्टमेंट में भेजा जाता है या उन्हें काम छोड़ने के लिए कहा जाता है। गंभीर किस्म का अस्थमा घातक भी हो सकता है। औसतन 10 अमरीकियों को हर दिन इस कारण जान से हाथ धोना पड़ता है। लगभग हर मामले में इसे रोका जा सकता है यदि सही इलाज मिले तो।

एल्ब्युटेरोल वास्तविक समस्या के लिए कारगर हल नहीं है। अस्थमा फेफड़ों में सूजन से जुड़ी बीमारी है जो काफी समय तक सूजन रहने के कारण होती है। बाह्य कारकों जैसे वायु प्रदूषण के गंभीर प्रभाव, एलर्जी या संक्रमण से अस्थमा बढ़ जाता है जिससे श्वासनली में वायु प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है, सांस लेने में कठिनाई, घरघराहट होती है और खांसी आती है। एल्ब्युटेरोल वायु प्रवाह में रुकावट दूर करता है और इसकी खुराक से मरीज को अस्थायी राहत मिलती है। पर इसकी खुराक से सूजन का समाधान नहीं होता।

बड़ा सवाल, स्टेरॉयड क्या हैं और ये कैसे काम करते हैं। ओरल स्टेरॉयड सूजन कम करने में बेहद प्रभावी हैं, पर इसके साइड इफेक्ट की लम्बी सूची है। इन दुष्प्रभावों में हड्डियों का क्षय, मोतियाबिंद होना, वजन बढ़ना, भावनात्मक स्थिति में तीव्र परिवर्तन और इम्यूनोसप्रेशन (संक्रमण और घातक बीमारियों से लड़ने की क्षमता में कमी) शामिल हैं। ऐसे में बहुत जरूरी होने पर ही इसे दिया जाना चाहिए। इनके बजाय इन्हेलर स्टेरॉयड ज्यादा सुरक्षित हैं। इसकी खुराक भी कई गुना कम होती है और ये सीधे ही फेफड़ों में पहुंच कर आराम देते हैं। अनेक अध्ययनों से सामने आया है कि स्टेरॉयड इन्हेलर सांस लेने में तकलीफ को कम करने के साथ ओरल स्टेरॉयड की जरूरत को भी कम करते हैं। नए शोध के चलते अस्थमा इलाज की गाइडलाइंस एल्ब्युटेरोल से अब स्टेरॉयड युक्त इनहेलर की ओर स्थानांतरित हो रही हैं। 2022 में, ग्लोबल इनीशिएटिव फॉर अस्थमा (जीआइएनए) ने विश्व स्वास्थ्य संगठन और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के सहयोग से अस्थमा केयर के प्रतिमान बदलने के लिए ऐतिहासिक सिफारिशें कीं।

नई गाइडलाइंस एल्ब्युटेरोल का समर्थन नहीं करतीं जो कि थोड़े समय के लिए ही कारगर रहती हैं। अनुशंसा की गई है कि सभी वयस्कों, किशोरों और बच्चों को स्टेरॉयड युक्त इनहेलर और फेफड़ों की मांसपेशियों को आराम देने के लिए लंबे समय तक काम करने वाली दवा दी जाए। जीआइएनए की मानें तो स्टेरॉयड इनहेलर मरीजों को 'सुरक्षा की झूठी भावना' से भी बचाते हैं। एल्ब्युटेरोल मरीजों के फेफड़ों की बीमारी का इलाज नहीं करता है। वास्तव में, इसके नियमित सेवन से श्वासनली की सूजन बढ़ जाती है जो मृत्यु का जोखिम लिए भी होती है। चूंकि ये दिशा-निर्देश हाल ही में आए हैं, ऐसे में संभव है कि कई चिकित्सकों ने अभी तक इसे न अपनाया हो। कई मरीजों को भी इसकी जानकारी नहीं है। जीआइएनए ने अनियंत्रित गंभीर अस्थमा मरीजों के लिए दवाओं के एक वर्ग 'मस्कैरेनिक एंटागोनिस्ट्स' की सिफारिश की है।

जाहिर है कि अनेक उपलब्ध चिकित्सीय विकल्पों के साथ, अस्थमा पीड़ित लोगों को अपनी जीवनराह में किसी बाधा का सामना नहीं करना चाहिए। थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी में फैमिली एंड कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर और श्वास रोगों के विशेषज्ञ नील एस. स्कोलनिक कहते हैं - जो अस्थमा से पीड़ित नहीं हैं, वे अंदाजा नहीं लगा सकते कि यह जीवन पर किस तरह गहरा असर डालता है। हर दिन बड़ी संख्या में लोग बहुत कष्टदायक खांसी से लेकर सांस लेने में भी कठिनाई जैसी समस्याओं से जूझते हैं। अस्थमा से पीड़ित हर व्यक्ति को यह जान-समझ लेना चाहिए कि उन्हें अस्थमा के कारण अपने जीवन को सीमाओं में नहीं बांधना है बल्कि इसे खुलकर जीना है।

आर्ट एंड कल्चर

जहां है दृश्य से बड़ी अदृश्य की सत्ता

असल बात यह है कि कलाओं में बड़ा यथार्थ वह नहीं होता जो दिखाई देता है

न्यूयॉर्क टाइम्स की हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्वभर के युवाओं में बीते जमाने की बात रही सुलेखन कला या कहें कैलिग्राफी के प्रति रुचि तेजी से बढ़ रही है। सुलेखन दृश्य कला है। इसमें कलम, स्याही, ब्रश से अक्षरों में डिजाइन कर कुछ कहा जाता है। माने जितना दृश्य महत्त्वपूर्ण है, उतना ही अदृश्य भी है। असल में युवाओं में यह सुलेखन की रुचि भर नहीं है। यह ध्यान के ज्ञान से जुड़ने की प्रक्रिया है।

कलाओं में बड़ा यथार्थ वह नहीं होता है जो दिखाई देता है, वह होता है जो दिखने के बाद मन में घटता है। वैचारिक रूप से संपन्न कलाकृतियां इसीलिए आकृष्ट करती हैं। कुछ दिन पहले कोलकाता जाना हुआ। यह देखकर सुखद अचरज हुआ कि देश के ख्यात कलाकार युसूफ की कलाकृतियों को देखने के लिए महानगर का बहुत बड़ा युवा वर्ग आया। उनकी कलाकृतियों को मुम्बई, लखनऊ, चेन्नई, पांडिचेरी, कोलकाता आदि शहरों में प्रदर्शित किया जा रहा है। महत्त्वपूर्ण यह भी है कि कलादीर्घाओं में हर बार उनकी नई कलाकृतियां प्रदर्शित होती रही हैं।

डॉ. राजेश कुमार व्यास
संस्कृतिकर्मी, कवि और कला समीक्षक
@patrika.com

मसलन कोलकाता की आकृति आर्ट गैलरी में युसूफ की कलाकृतियां सुलेखन की भांति अर्थ की विरल छटाएं बिखेरती लुभा रही थीं। प्रकृति और जीवन वहां एकाकार हो रहा था। एक कलाकृति में बड़ी सी गर्दन और फिर कोई चेहरा। पर थोड़ा ठहरकर, ठिठककर देखेंगे तो पाएंगे वृक्ष है, भरी पूरी डालों का, कुछ टेढ़ा हुआ सा। यही होता है, एब्सट्रेक्ट अर्थ के आग्रह से मुक्त होती है। रंग, रूप और रेखाएं वहां स्वयं प्रतिष्ठित होकर अर्थ की भांति-भांति की छटाएं रचती हैं।

युसूफ की कलाकृतियां घूंट-घूंट आस्वाद के लिए उकसाती हैं। वहां जैसे कथा कोलाज हैं। गोल-मटोल पृथ्वी इंक से बरती रंग लय में औचक अंडाकार होती दो भागों में विभक्त हो रही हैं। उन्हें देखने से कड़कती बिजली, पेड़, पानी, आकाश और ग्रह-नक्षत्रों की अनुभूति होती है। कहीं रंग लहर से निकल स्वयमेव लेटे हुए व्यक्ति की नींद से हमें साक्षात करा रहे हैं तो कहीं टेढ़े और खड़ी लाइन के आकार में इमारत, व्यक्ति, सीढ़ी और जमीन के टुकड़े संग कहीं कोई कस्बाई जीवन सांस लेता नजर आता है।

भारत भवन के पूर्व निदेशक जगदीश स्वामीनाथन के साथ युसूफ ने आरंभ में आदिवासी कलाओं का निरंतर अन्वेषण किया तो वहां का भी बहुत-कुछ उनकी कला में बाद में समाता चला गया। पेड़ की शाखाओं और उनसे झरते पत्तों की अनुभूतियों को टेक्सचर में जैसे उन्होंने घोल दिया है। वह कहते भी हैं, पेंटिंग जीवंत होती है। इसलिए कि उसमें ऊर्जा होती है। ऊर्जा का कोई एक रूप नहीं होता। वह बदलता रहता है। इसी तरह कला ऊर्जा के रूपाकार ग्रहण कर हमें लुभाती है।

युसूफ की कलाकृतियां संवेदना से भरी-पूरी हैं, दृश्य आख्यान सरीखी। जो कुछ वहां है, लयात्मक है। एक खास तरह की एकांतिका वहां है। औचक कोई पहाड़ पेड़ में रूपांतरित हो जाता है, पेड़ पहाड़ में। फन फैलाए नाग और उसको मनुष्य की दो बाहों का घेरा जैसे आगे बढ़ने से रोक रहा है। इसी तरह पत्तियां हैं, पेड़ से बिछड़ी पर हवा में ठहरी सी। कला में यही होता है, दृश्य से बड़ी वहां अदृश्य की सत्ता होती है। युसूफ की कलाकृतियां इसका उदाहरण हैं। युवाओं में कला के जरिए ध्यान के ज्ञान में प्रवेश कराती हुई।

आपकी बात

जानकारी होगी डिजिटल

वक्फ कानून में प्रस्तावित संशोधन से वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी। संशोधन से वक्फ की सभी जानकारी डिजिटल हो जाएगी। इस संशोधन से अब कोई भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति हड़प नहीं पाएगा और न ही वक्फ बोर्ड हर किसी की संपत्ति को अपना बता पाएगा। प्रस्तावित संशोधन से विवाद कम होंगे।

-ओमप्रकाश श्रीवास्तव, उदयपुरा, मप्र

बढ़ जाएगी पारदर्शिता

वक्फ बोर्ड से जुड़े कानून में प्रस्तावित संशोधन से पारदर्शिता बढ़ेगी। इससे मुस्लिम महिलाओं एवं बच्चों का हित होगा। वक्फ बोर्ड मनमानी नहीं कर सकेगा। उसे अपनी संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके फैसलों को अदालत में चुनौती दी जा सकेगी। यह कानून मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता को प्रभावित नहीं करता।

-ललित महालकरी, इंदौर, मप्र

अवैध कब्जे रोकने में मददगार

भारत में वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन एक संवेदनशील विषय है। वक्फ से जुड़े कानून में संशोधन से संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता आएगी। वक्फ संपत्ति पर अवैध कब्जों को रोकने में मदद मिलेगी। इनका सही ढंग से उपयोग हो पाएगा। इसलिए इस विषय पर विवाद नहीं होना चाहिए।

-मीना सनाढ्य, उदयपुर

संपत्ति से जुड़े विवाद कम होंगे

वक्फ से जुड़े कानून में संशोधन का मुख्य उद्देश्य वक्फ बोर्डों के कामकाज में पारदर्शिता लाना है। वक्फ बोर्ड को अब किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने से पहले उसका सत्यापन करना अनिवार्य होगा। इससे वक्फ संपत्ति को लेकर विवाद कम होंगे। विवाद होने पर अदालत जाने के रास्ते भी खुल जाएंगे।

-गिरीश ठक्कर, राजनंदगांव, छत्तीसगढ़

आज का सवाल

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न को रोकने के लिए भारत क्या करे?

ईमेल करें: edit@epatrika.com

कल का सवाल था: वक्फ से जुड़े कानून में संशोधन का क्या असर होगा?

चिंतन

बैंक में चार नॉमिनी बनाने से खाताधारकों को होगा लाभ

मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद सरकार ने बैंकिंग कानून संशोधन 2024 संसद में पेश कर दिया। इसके पास हो जाने के बाद बैंकिंग नियमों में कई बड़े बदलाव हो जाएंगे, जिनकी लंबे समय से मांग की जा रही थी। सबसे बड़ा बदलाव तो यह होगा कि अब बैंक में खाते खुलवाने के दौरान चार नॉमिनी बनाए जा सकेंगे। कुछ समय पहले आरबीआई ने खाता खुलवाते समय ही नॉमिनी का नाम भरा जाना अनिवार्य किया था। उससे पहले बिना नॉमिनी के भी खाते खुल सकते थे, क्योंकि फार्म में इस कॉलम को भरा जाना वैकल्पिक था। नॉमिनी के बिना खोले गए खातों की बड़ी संख्या के चलते ही आज देश के बैंकों में 78,000 करोड़ रुपये यूं ही रखे हैं, मगर कोई दावा करने नहीं आता। अनेक मामले तो ऐसे भी हैं, जहां न तो अब नॉमिनी है और न ही खाताधारक। इसलिए ये पैसे बैंकों में ही पड़े हैं। नियमों के हिसाब से यह पैसा परिवार के अन्य सदस्यों को दिया ही नहीं जा सकता। अभी नियम यह है कि जब आप बैंक खाता खुलवाते हैं तो आपको एक नॉमिनी का नाम दर्ज करना होता है। इसका मकसद आपकी मृत्यु के बाद खाते में जमा पैसे को उस व्यक्ति को देना होता है। अभी आप इसके लिए एक ही शख्स का नाम नॉमिनी में लिख सकते थे, लेकिन अब नए नियम के तहत आप एक से ज्यादा लोगों को अपने खाते में नॉमिनी बना सकेंगे। इसके अलावा, बीमा और हिंदू अविभाजित परिवार खाते की तरह, लगातार और एक साथ नॉमिनी बनाने की सुविधा से संयुक्त खाताधारक और वारिसों को खाताधारक की मौत के बाद पैसा मिल सकेगा। इन बदलावों का मकसद ग्राहक को किसी भी तरह की परेशानी से बचाना है। आरबीआई द्वारा बैंकों में पड़े धन को लेकर विशेष अभियान भी चलाया गया था। उसके संतोषजनक परिणाम सामने न आने से नियमों में बदलाव करने की तैयारी की गई। अब सार्वजनिक भविष्य निधि खाते यानी पीपीएफ में भी एक से ज्यादा नॉमिनी तय करना संभव होगा। आरबीआई ने म्यूचुअल फंड और दूसरी वित्तीय कंपनियों को यह आदेश दिया था कि वे दावारहित राशि को उनके सही मालिकों को लौटाएं, लेकिन इसके बावजूद मार्च 2024 के अंत तक ऐसी राशि बढ़कर 78,000 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गई है। बैंकों ने कई बार ऐसी रकम के दावे निपटाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 में सहकारी बैंकों के संबंध में भी कुछ बदलाव किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा, विधेयक में वैधानिक लेखा परीक्षकों को भुगतान किए जाने वाले पारिश्रमिक को तय करने में बैंकों को अधिक स्वतंत्रता देने का प्रावधान है। इस विधेयक की घोषणा वित्त मंत्री ने अपने 2023-24 के बजट भाषण में की थी। हालांकि विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि सहकारी बैंक राज्यों के तहत आते हैं। उनके लिए नियम कानून बनाना राज्यों के अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन होगा। जिसे वित्तमंत्री निर्मला सीमारमण ने सीधे-सीधे रिज कर दिया। इस विधेयक में एक और बड़े बदलाव का प्रावधान किया गया है। इसके तहत कंपनी के निदेशकों के सबस्टेंशियल इंटरेस्ट को फिर से परिभाषित किया गया। इसके तहत 3 लाख की राशि को बढ़ाकर दो करोड़ कर दिया है। लंबे समय बाद इसमें बदलाव किया गया। असल में हमारे बैंकिंग सिस्टम में अनेक खामियां हैं। जिन्हें समय-समय पर दुरुस्त करने की जरूरत है। इन कमियों के कारण खाताधारकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब नए नियमों से कुछ सुधार की उम्मीद जगी है।

मंथन

रोहित कौशिक

विनेश और बेटियों का सम्मान

भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने कुश्ती को अलविदा कह दिया है। विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा -'मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना। आपका सपना मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं। इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब। अलविदा कुश्ती 2001-2024'। विनेश फोगाट को लेकर सोशल मीडिया पर भी तरह-तरह के बयान आ रहे हैं। भले ही वह ज्यादा वजन के कारण ओलंपिक से बाहर हो गई हों लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जो कुछ उन्होंने झेला है, वह संकेत करने के लिए काफी है कि हम अभी भी बेटियों को सम्मान देना नहीं सीख पाए हैं। विनेश पर जिस तरह की राजनीति की गई वह भी सभी के सामने है। इस प्रगतिशील दौर में हमें यह सोचना होगा कि महिलाओं के संदर्भ में बड़ी-बड़ी बातें करने वाला यह समाज इस मुद्दे पर खोखला आदर्शवाद क्यों अपना लेता है ? लेकिन महिलाएं हमारे इस व्यवहार से बेपरवाह हमें सम्मान देने में जुटी हुई हैं। महिलाएं आसमां छू रही हैं और हम जमीन पर उन्हें दबोच कर उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। हमारे देश की बेटियों ने यह कई बार सिद्ध किया है कि यदि उन्हें प्रोत्साहन और सम्मान दिया जाए तो वे हमारे देश को अन्तरराष्ट्रीय फलक पर एक नई पहचान दिला सकती हैं। लेकिन हमारे समाज में आजादी के इतने वर्षों बाद भी बेटियां वह सम्मान प्राप्त नहीं कर पाईं जिसकी वे हकदार थीं। यह विडम्बना ही है कि शिक्षित होने के बावजूद हम अभी आत्मिक रूप से विकास नहीं कर पाए हैं। पितृसत्तात्मक समाज में लड़कियों को रोज नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

इस दौर में हमारे समाज के एक छोटे से तबके में लड़कियों को पूर्ण छूट दी जाने लगी है लेकिन यहां उनकी चुनौतियां अलग तरह की होती हैं। कुल मिलाकर पितृसत्तात्मक समाज लड़कियों के लिए अनेक तरह के अवरोध खड़े कर रहा है। यह समाज इन अवरोधों के समर्थन में अलग तरह के तर्क गढ़ता है। यह जानते हुए भी कि इन तर्कों का कोई आधार नहीं है, यह समाज इन तर्कों को नियमों की तरह लड़कियों पर लादता है। जब हम इन आधारहीन नियमों को सिर्फ लड़कियों पर लादते हैं तो एक तरह से हम पितृसत्ता को पुनः प्रतिष्ठापित करते हैं। 21वीं सदी में भी यदि लड़कियों को आगे बढ़ने की कोशिश करने पर ताने सुनने पड़ें तो हमें यह सोचना होगा कि हमारी प्रगतिशीलता में कहां कमी रह गई है? केवल भाषणबाजी से समाज में प्रगतिशीलता नहीं आती है। इसके लिए हमें बहुत सी सड़ी-गली परम्पराओं को दांव पर लगाना पड़ता है। शिक्षा ग्रहण कर समाज के हर वर्ग के उत्थान में उसका उपयोग करना ही सच्ची प्रगतिशीलता है।

इस दौर में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या हम लड़कियों और महिलाओं के संदर्भ में सच्चे अर्थों में प्रगतिशील हैं ? दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि खेलों में भी लड़कियों को अनेक स्तरों पर चुनौतियां झेलनी पड़ती हैं। छोटी उम्र में अनेक लड़कियों को समाज के डर से अपने शौक की कुर्बानी देनी पड़ती है। इसीलिए हमारे देश में बहुत सारी महिला प्रतिभाएं जन्म ही नहीं ले पाती हैं या फिर असमय दम तोड़ देती हैं। खेल जगत में भी महिला खिलाड़ियों को पग-पग पर पितृसत्ता की चुनौती झेलनी पड़ती है और बार-बार महिला होने का खामियाजा भुगतना पड़ता है। प्रशिक्षण के दौरान और मैदान पर महिला खिलाड़ियों से छेड़छाड़ की घटनाएं आम हैं। ऐसी घटनाओं और ऐसे वातावरण को देखकर अन्य परिवारों का मनोबल भी टूट जाता है और वे अपनी बेटियों को खेल के क्षेत्र में भेजने से कतराने लगते हैं। रही सही कसर खेल जगत में पसरी राजनीति पूरी कर देती है। एक तरफ बेटियां खेलों में पसरी राजनीति से जूझती हैं तो दूसरी तरफ समाज में पसरी राजनीति उनकी राह में कांटे बिछा देती है। बेटियों और महिलाओं के खिलाफ यह राजनीति अन्ततः सामाजिक विकास को पीछे धकेलती है। फलस्वरूप बेटों और बेटियों में अनेक स्तरों पर एक अंतर बना रहता है। यह अन्तर विद्यमान रहने के कारण ही उन्हें 'देह' भर माना जाता है। इस दौर में महिलाओं से बलात्कार की बढ़ती घटनाएं और उन पर हो रहे हमले इस बात का प्रमाण है कि हम आज भी बेटियों को मात्र भोग की वस्तु मानते हैं। इस तथ्य को गलत सिद्ध करने के लिए यह कहा जा सकता है कि सारा समाज ऐसा नहीं है लेकिन वास्तविकता यह है कि सामने लड़की को देखकर सभ्य लोगों के चेहरे पर भी एक कुटिल मुस्कान बिखर जाती है। सुखद यह है कि इस माहौल में भी लड़कियों और महिलाओं के हौसले बुलन्द हैं और वे लगातार सफलता की नई कहानियां लिख रही हैं। दुखद यह है कि इस मुश्किल समय में भी विनेश फोगाट पर अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं। क्या हम इसी तरह बेटियों और महिलाओं का सम्मान करते हैं ? कहां गई हमारी प्रगतिशीलता ? अब समय आ गया है कि हम बेटियों को सच्चा सम्मान दें।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

श्रद्धांजलि

उमेश चतुर्वेदी

उदारवादी वामपंथी थे बुद्धदेव..

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए बुद्धदेव भट्टाचार्य ने आर्थिक उदारीकरण की ओर कदम बढ़ाया। उन्होंने राज्य के औद्योगीकरण की ओर भी कदम बढ़ाया। सिंगूर में टाटा का कारखाना लगाने के लिए उन्होंने जमीन का अधिग्रहण किया, जिसके खिलाफ बंगाल व्यापी आंदोलन छिड़ा और उसकी आंच में ही 2011 में हुए विधानसभा चुनावों में वाम मोर्चे की हार हुई। पैरोकार और ताजिंदगी सादगी के प्रतीक रहे बुद्धदेव को एक ऐसे उदार वामपंथी के रूप में याद किया जाएगा, जो शिष्ट था, शालीन था। अपने इन्हीं मानवीय गुणों की वजह से वह अपना लालगढ़ बचा नहीं पाए। उनके निधन से वामपंथी राजनीति का एक अध्याय समाप्त हो गया है।

साल 2000...नई सदी करवट बदल रही थी। इक्कीसवीं सदी के स्वागत के साथ ही भारतीय राजनीतिक आसमान में एक सवाल रह-रहकर उछल उठता...बंगाल के लालगढ़ का उत्तराधिकारी कौन होगा। धान, केला और ताड़ की भूमि बंगाल की माटी को लाल सलाम की आदत डालने वाले ज्योति बसु के रिटायरमेंट की चर्चाएं जारी थीं। महज चार साल पहले गैर बीजेपी विपक्ष की नजर में प्रधानमंत्री पद की पहली पसंद रहे वामपंथी दिग्गज इस चर्चा के सिर्फ चार साल बाद ही रिटायर होने जा रहे थे।

सोशल मीडिया के दौर में राजनीतिक रूप से चेतन हो रही और अक्सर कांग्रेस की बलैया लेने वाली नई पीढ़ी को जानना चाहिए..तब सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस को भी समूचा विपक्ष अछूत बनाने के लिए उतावला रहता था। ऐसा अछूत, जिसके कंधे की सवारी में उसे छूत नहीं लगती थी लेकिन सत्ता में उसे दूर रखने की भरपूर कोशिश होती थी। उन दिनों वामपंथ के देश में तीन गढ़ थे। तीनों गढ़ तीनों कोनों पर..पहला सुदूर दक्षिण स्थित भगवान के अपने घर में..कितना बड़ा विरोधाभास है कि भगवान के अपने घर में वामपंथ का किला आज भी गड़ा हुआ है, उस वामपंथ का, जो भगवान को नहीं मानता, जो धर्म को अफीम मानता है। खैर, दूसरा गढ़ पश्चिम बंगाल था तो तीसरा त्रिपुरा। तब बंगाल को सबसे बड़ा गढ़ माना जाता था। माना भी क्यों न जाए, वहां लगातार 23 सालों से लाल सरकार चल रही थी।

ज्योति बसु के उत्तराधिकारी का नाम हवा में उछलता तो था, लेकिन उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाती थी। इसी बीच इन पंक्तियों के लेखक को फ्रीलांस के तौर पर सीपीएम के तत्कालीन महासचिव हरकिशन सिंह सुरजीत का साक्षात्कार का मौका मिला। साल था 2000, मार्च का महीना और तारीख थी 23 मार्च। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत का दिन, भारतीय राजनीति के चिर विद्रोही राममनोहर लोहिया की जयंती...दिन भी याद है..वह दिन था गुरुवार...तो उस गुरुवार की ठंडाती शाम को राजधानी दिल्ली के तीनमूर्ति लेन स्थित सुरजीत के बंगले के सन्नाटे के बीच इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू इतना दमदार रहा कि बुखार में तपता शरीर जैसे उत्साह से भर उठा। पत्रकारों को पता है कि उनकी जिंदगी में स्कूप का क्या महत्व था। इंटरव्यू से इन पंक्तियों के लेखक को स्कूप हाथ लग गया था। सुरजीत रौ में बोल गए थे..बुद्धदेव भट्टाचार्य होंगे ज्योति बसु के उत्तराधिकारी..यानी बंगाली लालगढ़ के अगले सेनापति। तब कोलकाता से लेकर दिल्ली तक की फिजाओं में अनिल विस्वास और विमान बसु के भी नाम तैरते रहते थे लेकिन उसकी पुष्टि नहीं हो पाती थी। सुरजीत के सामने बसु के उत्तराधिकारियों के तौर पर इन दोनों के नाम रखे गए। इससे वे झल्ला गए और बुद्धदेव भट्टाचार्य का नाम उन्होंने ले लिया। दैनिक हिंदुस्तान ने इस इंटरव्यू को तो रविवार 26 मार्च 2000 के अंक में छापा, लेकिन खबर दो दिन पहले ही स्कूप के रूप में छाप दी। तब सीपीएम की रिपोर्टिंग पर केरल के मलयालम और पश्चिम बंगाल के बंगला अखबारों के साथ ही कुछ राष्ट्रीय अंग्रेजी अखबारों का दबदबा था। वामपंथ से जुड़ी ब्रेकिंग कहानियां उन्हें ही मिलती थीं और वे ही उसे छापते भी थे लेकिन हिंदी वाले को वामपंथ से

जुड़ी बड़ी कहानी मिल गई तो वे चौंक उठे। खैर...इतना वितान रचने की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि 11 साल तक पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार की कमान संभालने वाले बुद्धदेव भट्टाचार्य अब नहीं रहे। लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। भट्टाचार्य ज्योति बसु सरकार में करीब 18 साल तक मंत्री रहे थे। उन्होंने गृह मंत्रालय समेत कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों में काम किया। पश्चिम बंगाल में बुद्धदेव भट्टाचार्य सीपीएम के दूसरे और अंतिम मुख्यमंत्री थे। जाधवपुर विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने लगातार जीत हासिल की थी। बुद्धदेव भट्टाचार्य पहली बार साल 1977 में विधानसभा चुनाव जीतकर कोसीपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने थे। इतना ही नहीं, वे लगातार 24 साल तक विधायक रहे। उन्होंने 2015 में सीपीआई (एम) के पोलित ब्यूरो और केंद्रीय समिति से इस्तीफा दे दिया था और 2018 में राज्य सचिवालय की सदस्यता छोड़ दी थी। उनके निधन से वामपंथी राजनीति का एक अध्याय समाप्त हो गया है। यहां बता दें कि बुद्धदेव भट्टाचार्य चेन स्मोकर थे...उनका सिगरेट का खर्च इतना था कि मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें सीपीएम से जो छह हजार का भत्ता मिलता था, वह भत्ता उनके सिगरेट के लिए कम पड़ता था। यहां नई पीढ़ी के लिए यह बताना जरूरी है कि वामपंथी दलों में विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री को पार्टी की ओर से तय भत्ते मिलते हैं। उन्हें अपनी पूरी तनख्वाह पार्टी को देनी होती है। यहां तक कि अगर वे बंगले के अधिकारी हैं तो उन्हें अपने बंगले में पार्टी द्वारा तय किए लोगों को भी रहने देना होता है।

ऐसे में सवाल यह है कि बुद्धदेव भट्टाचार्य का बाकी खर्च कैसे चलता था। उनकी पत्नी मीरा भट्टाचार्य कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थीं। मुख्यमंत्री का घर उनकी पत्नी के पैसे से चलता था। बुद्धदेव भट्टाचार्य का जन्म एक मार्च 1944 को उत्तरी कोलकाता में हुआ था। उनका पुश्तैनी घर बांग्लादेश में है। बुद्धदेव ने कोलकाता के प्रतिष्ठित प्रेसीडेंसी कॉलेज से बांग्ला साहित्य से बांग्ला में बीए (ऑनर्स) की डिग्री प्राप्त की थी। 1966 में वे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) से जुड़ गए। पार्टी ने उन्हें जून, 1968 में युवा शाखा डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन का राज्य सचिव बनाया, जिसका बाद में डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया में विलय हो गया था। बुद्धदेव ने अपनी जिंदगी की शुरुआत अध्यापक के रूप में की। लेकिन बाद में वे पूरी तरह राजनीति में समाहित हो गए।

वामपंथी दलों को उदारीकरण का विरोधी माना जाता है। साल 2000 से 2011 तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए बुद्धदेव भट्टाचार्य ने आर्थिक उदारीकरण की ओर कदम बढ़ाया। उन्होंने राज्य के औद्योगीकरण की ओर भी कदम बढ़ाया। सिंगूर में टाटा का कारखाना लगाने के लिए उन्होंने जमीन का अधिग्रहण किया, जिसके खिलाफ बंगाल व्यापी आंदोलन छिड़ा और उसकी आंच में ही साल 2011 में हुए विधानसभा चुनावों में वाम मोर्चे की हार हुई। उनकी एक बेटी थीं सुचेतना भट्टाचार्य। थीं इसलिए कि उन्होंने अपना लिंग परिवर्तन करवा लिया और अब वे लड़का हो गई हैं । अब वह सुचेतन भट्टाचार्य के नाम से जानी जाती हैं। उन्होंने ही बुद्धदेव के निधन की जानकारी लोगों को दी। वामपंथ में उदारीकरण के पैरोकार और ताजिंदगी सादगी के प्रतीक रहे बुद्धदेव भट्टाचार्य को राजनीति और देश किस रूप में याद करेगा, यह तो बाद की बात है। लेकिन इतना जरूर है कि एक ऐसे उदार वामपंथी के रूप में याद किया जाएगा, जो शिष्ट था, शालीन था, वामपंथी वैचारिकी की उत्तेजनाओं से दूर था और उससे भी कहीं ज्यादा उदारीकरण का पैरोकार था। और अपने इन्हीं मानवीय गुणों की वजह से वह अपना लालगढ़ बचा नहीं पाए।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया **edit@haribhoomi.com** पर दे सकते हैं।

कष्टों से भागें नहीं उनका सामना करें

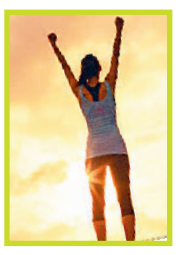

संकलित

दर्शन

हमारे रोजमर्रा के जीवन में समस्याओं का पैदा होना स्वाभाविक है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्याएं वे हैं, जिनका हमें सामना करना पड़ता है, जैसे— बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु। इन समस्याओं से बचने या उनके विषय में न सोचने से अस्थायी आराम तो मिल सकता है लेकिन, अगर आप अपने कष्ट का खुलकर सामना करते हैं तो आप अपनी समस्या को ज्यादा अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। यदि आप कोई युद्ध लड़ रहे हैं तो जब तक आप अपने शत्रु की स्थिति और उसकी सैन्य क्षमता पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक आपकी तैयारी पूरी नहीं होगी और आप डर के कारण शिथिल हो जाएंगे। यदि आपको अपने शत्रु की सैन्य क्षमता और उसके हथियारों आदि के बारे में पता लग जाए तो युद्ध के समय आपकी स्थिति बेहतर हो जाएगी। इसी तरह यदि आप अपनी समस्याओं से बचने के बजाय उनका सामना करेंगे तो उनसे निपटने में आपको आसानी होगी। उदाहरण के लिए आपको बुढ़ापा और मृत्यु नकारात्मक या अवांछित लगें और आप उन्हें भूलना चाहें, फिर भी ये चीजें तो आएंगी। यदि आप इनके बारे में सोचने से बचते रहें तो जिस दिन इनमें से कोई भी घट गई तो आपको असहनीय मानसिक पीड़ा हो सकती है। यदि आप बुढ़ापा, मृत्यु और इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण चीजों पर सोचने में कुछ समय लगाएंगे तो इनके होने पर भी आपका मस्तिष्क स्थिर रहेगा। एक बात व्यक्ति को ध्यान में रखनी है, वह यह है कि कष्ट के बारे में विचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे बचने की संभावना है; एक विकल्प है।

जहां पवन है, वहां मन

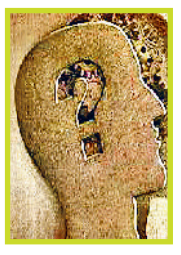

संकलित

प्रेरणा

मन शब्द से हर कोई परिचित है। मन का साम्राज्य विशाल है। योग की एक प्रसिद्ध सूक्ति है— 'यत्र पवनस्तत्र मन' अर्थात जहां पवन है, वहां मन है। मन क्या है? यह प्रश्न सहज ही उठता है। सामान्य शब्दों में कहें तो जो चेतना बाहर जाती है, उसका प्रवाहात्मक अस्तित्व ही मन है। मन का अर्थ है— संकल्प-विकल्प। मन का अर्थ 'स्मृति और चिंतन' के इर्द-गिर्द घूमता है। मन का अर्थ समय की परिधि में तीनों कालों में बंटा हुआ है। मन अतीत की स्मृति करता है, भविष्य की कल्पना करता है तथा वर्तमान का चिंतन करता है। मन की प्रकृति चंचल है, इसीलिए कभी व्यग्र होता है,कभी एकाग्र। मन के स्थान के संबंध में पृथक-पृथक धारणाएं प्रचलित हैं। कोई इसे हृदय के नीचे, कोई हृदय के बीच तो कोई समूचे शरीर में व्याप्त बताता है। शरीर शास्त्र के अनुसार मन का स्थान मस्तिष्क है। वस्तुत मन का शासन सर्वत्र व्याप्त है। मन के स्वरूप को जानना इसलिए आवश्यक है कि वह हमारी साधना का मुख्य आधार है। उसी के आधार पर ध्यान, उपलब्धियों, अनुपलब्धियों का लेखा-जोखा होता है। मन के साथ चेतना का योग न हो तो ध्यान की कोई आवश्यकता नहीं है। मन का स्वरूप चेतना की धारा से निर्मित होता है। वह न चंचल है; न स्थिर है। जैसा उत्पादन होता है, वैसा ही वह निर्मित हो जाता है। हमारे मन में हजारों अवस्थाएं प्रतिदिन घटित होती हैं। जब मन बाह्य-साक्षात्कार में लगता है, तब मन में हजारों घटनाएं घटित होती हैं। अकारण प्रेम, शत्रुता व भय के भाव आ जाते हैं।

अंतर्मन

आज की पाती

नाबालिग वाहन चालकों के लिए सख्ती

एक अगस्त से नाबालिग वाहन चालकों के लिए सख्ती की जा रही है। इस दिन से अगर कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पुलिस पकड़ लेती है तो इसके लिए सख्त कानून का इस्तेमाल किया जाएगा। इस कानून के तहत लगभग 25 हजार जुर्माना और लगभग तीन साल की सजा का भी प्रावधान है। हालांकि सरकार और प्रशासन ने इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाए, स्कूलों में इसके लिए बच्चों को जागरूक भी किया और स्कूलों ने विद्यार्थियों के माता-पिता को इसके लिए नोटिस भी भेजे हैं कि वो अपने नाबालिग बच्चों को वाहन न दें। दोपहिया वाहन एक्सीडेंट का आंकड़ा भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। दोपहिया वाहन चलाते समय हैल्मेट का प्रयोग अपनी जान की सुरक्षा के लिए जरूर करना चाहिए, न कि चालान के डर से। **- प्रीतिम सिंह**

करंट अफेयर

9 साल की उम्र में शादी, मुस्लिम देश के नए 'कानून' पर बवाल

इराक की संसद में पेश हुए विधेयक को लेकर आजकल जोरदार हंगामा हो रहा है। इस विधेयक में लड़कियों की शादी के लिए न्यूनतम आयु घटाकर 9 साल करने का प्रस्ताव रखा गया है। इराक के कानून मंत्रालय की तरफ से इस कानून का प्रस्ताव संसद में रखा गया है। फिलहाल इराक में भी महिलाओं की शादी के लिए न्यूनतम आयु 18 साल है। इस विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति खुद चुन सकता है कि उसके पारिवारिक मामले धार्मिक अथॉरिटी तय करेगी या फिर न्यायालय। इस विधेयक के आलोचकों का कहना है कि इससे उत्तराधिकार, तलाक और बच्चों की कस्टडी समेत कई अधिकारों का हनन होगा। अगर यह विधेयक पास हो जाता है तो लड़कियों की शादी 9 साल और लड़कों की 15 साल की आयु में ही की जा सकेगी। ऐसे में लोगों में यह भी डर है कि इससे बाल विवाह का प्रचलन बढ़ जाएगा। जो संगठन कई सालों से महिला और बाल अधिकार की जंग लड़ रहे हैं, यह उनके लिए बड़ा झटका होगा। मानवाधिकर संगठनों, महिला संगठनों और सिविल सोसाइटी के कार्यकर्ता इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज पर बुरा असर पड़ेगा। बाल विवाह से स्कूली शिक्षा कमजोर हो जाएगी, वहीं इससे जल्द गर्भधारण और घरेलू हिंसा के मामले बढ़ेंगे। बता दें कि यूनीसेफ के आंकड़ों का कहना है कि अब भी इराक में 28 फीसदी आबादी की शादी 18 साल से पहले ही हो जाती है।

ऑफ बीट

अब जंग के मैदान में 'युद्ध के कुत्ते' उतारेगा यूक्रेन

रूस के साथ जारी युद्ध के बीच यूक्रेन एक बेहद बड़ी तैयारी में जुटा है। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। तब से दोनों ओर से सैकड़ों सैनिक मारे गए हैं। रूस के मुकाबले बेहद छोटा देश के कारण यूक्रेन को अब मानव संसाधनों की कमी से जूझना पड़ रहा है। यही वजह है कि सैनिकों की कमी के कारण अब यूक्रेन ने युद्ध के कुत्तों को मैदान में उतारने का फैसला किया है। यूक्रेन अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसी क्रम में अब यह यूरोपीय देश अपने फ्रंटलाइन पर रोबोटिक कुत्तों की तैनात करेगा। ये अत्याधुनिक मशीनें हैं जिन्हें "बैड वन" (BAD One) के नाम से जाना जाता है। इन रोबोटिक कुत्तों को विशेष रूप से हाई रिस्क वाले मिशनों जैसे कि टोही और बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, हाल ही में यूक्रेन ने एक अज्ञात स्थान इन रोबोट कुत्तों को टेस्ट किया था जहां वे बेहद असरदार पाए गए। रिमोट कमांड का जवाब देते हुए, रोबोट खड़ा हुआ, झुका, भागा और कूदा। रोबोट ने अपनी अद्भुत फुर्ती का प्रदर्शन किया। उन्होंने ऐसी क्षमताएं प्रदर्शित कीं जो रूस के साथ चल रहे संघर्ष में अमूल्य साबित हो सकती हैं।

ट्रेंड

हर घर तिरंगा

आइए फिर से #हरघरतिरंगा को यादगार जन आंदोलन बनाएं। मैं अपनी प्रोफाइल तस्वीर बदल रहा हूं और मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप भी ऐसा करके हमारे तिरंगे का जश्न मनाने में मेरे साथ शामिल हों। **- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

मोदी जी का कथन उचित

माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा यह आश्वासन देना कि एससी-एसटी वर्ग में क्रीमी लेयर को लागू नहीं करने तथा उनके आरक्षण में कोई उप-वर्गीकरण भी नहीं करने की मांगों पर गौर किया जाएगा, यह उचित व ऐसा किए जाने पर स्वागत योग्य है। **- मायावती, बसपा सुप्रीमो**

नीरज का बेहतर प्रदर्शन

कल रात पूरा भारत जाग रहा था, सुनहरे हाथ वाले लड़के के लिए। नीरज चोपड़ा ने अपने टोक्यो ओलंपिक 2020 के स्वर्ण पदक थ्रो में सुधार करते हुए अपना सीज़न सर्वश्रेष्ठ दिया। फिर भी वह स्वर्ण पदक जीतने से चूक गए। **- अनिल अग्रवाल, उद्योगपति**

बदलाव के लिए कहें हां

मेरा मानना है कि आप या तो बाहर से स्थायी रूप से आलोचक हो सकते हैं, या आलोचना का हिस्सा बन सकते हैं और चीजों को बदलने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप चीजों में थोड़ा सा भी बदलाव कर सकते हैं, तो आपको हां कहना चाहिए। **- शेखर कपूर, फिल्म निर्माता**

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-42422221 पर या सीधे मेल से **aapkepatra.haribhoomi@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid